

षोडश माला, खंड 9, अंक 26

मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015

08 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 26, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 / 08 वैशाख, 1937 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 486	21-49
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 487 से 500	
अतारांकित प्रश्न संख्या 5521 से 5750	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	51-61
राज्यसभा से संदेश	62
प्राक्कलन समिति	
दूसरा से चौथा प्रतिवेदन	63
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
तीसरे से छठा प्रतिवेदन	64
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
पाँचवां तथा छठा प्रतिवेदन	65
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	65
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
11 वें से 14 वां प्रतिवेदन	66
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
117 वां तथा 118 वां प्रतिवेदन	67
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	

268 वां तथा 269 वां प्रतिवेदन

67

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

218 वें से 222 वां प्रतिवेदन

68

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

75 वां तथा 76 वां प्रतिवेदन

68

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2014-15) पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री रामविलास पासवान

69

- (2) निःशक्तता कार्य विभाग (अब निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 35वें और 40वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री थावर चंद गहलोत

70

- (3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'उर्वरक का मूल्य निर्धारण' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर

70

नियम 377 के अधीन मामले

99-115

- (एक) राजस्थान को रावी और व्यास नदियों को उसके आवंटित हिस्से के जल को जारी किये जाने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां

99

- (दो) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 को चार लेनों में परिवर्तित करने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह

101

- (तीन) बीज विधेयक, 2004 को अधिनियमित करने तथा स्वदेशी बीजों के संरक्षण हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यपाल सिंह

102

- (चार) राजस्थान में लोहारू-झुंझुनू-सीकर-जयपुर रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के काम में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष अहलावत

104

- (पाँच) रांची और नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस रेल सेवा प्रतिदिन चलाये जाने तथा रांची और दिल्ली/मुंबई के बीच विमान सेवा की बारंबारता बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम

105

- (छः) अहमदाबाद और खेडब्रह्मा के बीच रेल सेवा को राजस्थान में अंबाजी होते हुए आबू तक बढ़ाये जाने तथा इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता

श्री डी. एस. राठौड़

106

- (सात) निजी अस्पतालों में निम्न आय वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश बिधूड़ी

107

- (आठ) महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सैफन कार्ड धारकों को रियायतों दर पर अनाज और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले

108

- (नौ) मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल को राजभाषा के रूप में प्रयोग किये जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.आर. विजय कुमार

109

- (दस) तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मनुष्यों और मवेशियों पर आक्रमण करने वाले आवारा घड़ियालों के लिये अस्थायी बचाव केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री ए. अरूणमणिदेवन

110

- (ग्यारह) ओडिशा में पर्याप्त संख्या में आई.पी.एस अधिकारी आवंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब

111

- (बारह) घरेलू विमान सेवा के परिचालन हेतु भागलपुर हवाई अड्डे का विकास किये जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार

112

(तेरह) बिहार में विशेष रूप से नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनसीसी कैडेटों को उचित वर्दी प्रदान करने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार

113

(चौदह) करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही बेमौसम वर्षा के कारण फसल को हुए नुकसान का आकलन करने हेतु एक केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिश्वास

114

(पंद्रह) संघर्ष से जूझ रहे देशों से निकाले गए भारतीय पैरामेडिकल के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाये जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि

115

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2015-16**(एक) गृह मंत्रालय****116-198**

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

116

श्री एस.आर. विजय कुमार

117

श्री अर्जुन राम मेघवाल

119

श्री बिद्युत बरन महतो

120

श्री देवजी एम. पटेल	121
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमेगौड़ा	123
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	126
श्री आर. ध्रुवनारायण	128
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	133
श्री अर्का केशरी देव	135
श्री रामेश्वर तेली	138
श्री विष्णु दयाल राम	140
श्री सुनील कुमार सिंह	145
श्री बी.एन. चन्द्रप्पा	148
श्री गजानन कीर्तिकर	154
श्री प्रह्लाद जोशी	150
श्री राजनाथ सिंह	155
कटौती प्रस्ताव - अस्वीकृत हुए	194
मांग-स्वीकृत हुए	197

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**19-453**

श्री निनोंग ईरिंग	200
कटौती प्रस्ताव	204
श्री भगत सिंह कोश्यारी	205
श्री शिवकुमार उदासी	210
श्री सुधीर गुप्ता	215
श्री निशिकांत दुबे	216
श्री रवीन्द्र कुमार जेना	223
श्री जी. हरि	231
डॉ. किरिट पी. सोलंकी	232
श्री नलीन कुमार कटील	233
श्री टी. राधाकृष्णन	235
श्रीमती रमा देवी	239
डॉ. ममताज़ संघमिता	242
श्री गौरव गोगोई	245

श्री पी. कुमार	246
डॉ. वीरेंद्र कुमार	247
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	250
श्री राम प्रसाद शर्मा	254
श्री तथागत सत्पथी	255
कुमारी शोभा कारान्दलाजे	260
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	264
श्री के. परसुरमन	268
श्री शिवाजी अधलराव पाटील	271
श्री रतन लाल कटारिया	274
श्री राहुल शेवाले	277
श्री थोटा नरसिम्हम	280
श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी	283
श्री लडू किशोर स्वाई	287
श्री एस.आर. विजय कुमार	291

श्री वी. एलुमलाई	293
श्री एम. बी. राजेश	294
श्री पी.पी. चौधरी	298
श्री आर. ध्रुवनारायण	300
श्री सी.आर. चौधरी	304
श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी	306
श्री नारणभाई काछड़िया	309
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमेगौड़ा	311
श्री बी.एन. चन्द्रप्पा	313
कुमारी सुष्मिता देव	315
श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी	318
श्री दुष्यंत सिंह	321
श्रीमती सुप्रिया सुले	324
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	329
श्री धर्मवीर गांधी	331

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	333
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	336
योगी आदित्यनाथ	341
श्री पी.आर. सुंदरम	344
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	346
श्री वीरेन्द्र कश्यप	347
श्री देवजी एम. पटेल	348
श्रीमती जयश्री बेन पटेल	351
श्री दुष्यंत चौटाला	356
श्री कौशलेन्द्र कुमार	357
श्री असादुद्दीन ओवैसी	360
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	362
श्री अर्का केशरी देव	366
श्री सी. एन. जयदेवन	368
श्री अजय टम्टा	370

श्रीमती संतोष अहलावत	372
श्री अजय मिश्रा टेनी	373
श्री सुमेधानन्द सरस्वती	375
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	377
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	384
श्री डी.के. सुरेश	385
एडवोकेट जोइस जॉर्ज	391
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	394
श्री बिद्युत बरन महतो	399
श्री रमेश चन्द्र कौशिक	400
श्री बदरुद्दीन अजमल	401
श्री दद्वन मिश्रा	404
श्री देवेन्द्र सिंह भोले	406
श्री सुनील कुमार सिंह	407
श्री ओम बिरला	410

श्री शरद त्रिपाठी	413
श्री अर्जुन राम मेघवाल	417
श्रीमती कमला पाटले	418
डॉ. कुलमणि सामल	420
श्री प्रकाश जावड़ेकर	422
कटौती प्रस्ताव - अस्वीकृत हुए	451
मांग-स्वीकृत हुई	452
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	453

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुकुमदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 / 08, वैशाख 1937 (शक)

लोक सभा की बैठक पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री पी. करुणाकरन, श्री गौरव गोगोई और श्री अधीर रंजन चौधरी से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं।

यह मामला काफी महत्वपूर्ण होने के बावजूद बिजनेस ऑफ द डे में व्यवधान की गारंटी नहीं देता है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेकैया नायडू): महोदया, मैंने सचिवालय के साथ चर्चा की है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया बाधा न डालें। मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

श्री एम. वेकैया नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, मैंने सुझाव दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता ने सहमति व्यक्त की है कि हम सभी नेपाल और भारत में प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्यों में अपने एक महीने के वेतन का योगदान करेंगे। मुझे बताया गया है कि किसी भी प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी ने इस पर सहमति व्यक्त की है। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक पत्र लिखूंगा जिसमें उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपना एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करें। हम इसे किसी अन्य देश में भेजेंगे। कानूनी जटिलताएं आएंगी। इसलिए हम इसे प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य: महोदया, हम इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे**प्रश्नों के मौखिक उत्तर***

माननीय अध्यक्ष: अब, हम प्रश्न काल लेंगे। प्रश्न सं. 481 – श्रीमती रमा देवी।

(प्रश्न संख्या 481)

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी: अध्यक्ष महोदया, मुझे बड़े विस्तार से प्रश्न का उत्तर मिला है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि जम्मू एवं कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हम भारतीय इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। संविधान की धारा 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। हम जब भी जम्मू एवं कश्मीर की चर्चा करते हैं तो खूबसूरती के साथ-साथ हिंसा, आतंकवाद एवं अलगाववाद का मामला भी हमारे मन में आ जाता है। पाकिस्तान की साजिश से 1947 से लगातार शुरू हुआ आतंकवाद और अलगाववाद का सिलसिला आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती रमा देवी : कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने कश्मीर मुद्दे को ठीक ढंग से देश हित में हल नहीं किया। परिणामस्वरूप हजारों निर्दोष लोग एवं सुरक्षा बलों के जवानों की जानें चली गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभालने के बाद जम्मू एवं कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया और कश्मीरियों को देश की

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से वहां गठबंधन की सरकार बनाई तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को निष्क्रिय कर दिया।

14 अप्रैल को जब एक देशद्रोही ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये तो उसे जेल भेज दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : यह क्या भाषण हो रहा है?

श्रीमती रमा देवी : मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जम्मू एवं कश्मीर के अंदर पिछले पांच वर्षों में कितने लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मामले चलाये गये हैं और उनमें से कितने लोगों को सजा मिली है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरें रिजजू): अध्यक्ष महोदया, जो समस्या माननीय सदस्य ने उठाई है, वह तो बहुत पुरानी समस्या है। उन्होंने जो देशद्रोह का सवाल पूछा है, वहां पर अलग-अलग कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी समस्या और कोई गतिविधि सामने आती है तो उसका केस दर्ज होता है। मैं उसका पूरा ब्योरा तो अभी नहीं दे पाऊंगा, माननीय सदस्य अलग से अगर मांगेंगे तो उसका प्रावधान कर के दिया जाएगा।

श्रीमती रमा देवी: महोदया, मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से क्या सहायता पहुंचाई गई और कैसे उन लोगों का जीवन-यापन चल रहा है? आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों की जो लिस्ट है, उसमें आम नागरिक मरे हैं, घायल हुए नागरिक मरे हैं, सुरक्षाबलों के कर्मी मरे हैं, जितने लोग मरे हैं, उनके परिवारों को किस तरह की सुरक्षा मिली है, जो देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, उनको कैसी सुरक्षा मिली है, उनके परिवारों की किस तरह से देख-रेख हो रही है?

श्री किरें रिजजू : अध्यक्ष महोदया, सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनके तहत लोगों को मुआवज़ा मिलता है। एक चीज़ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि क्रॉस फायरिंग जो होती है, उसमें मारे गए परिवारजनों के लिए अभी तक अलग से कुछ प्रावधान नहीं किया गया था। भारत सरकार की एक नीति है, जिसमें चाहे लेफ्ट विंग एक्ट्रिमिज्म हो, बाद में कम्युनल वॉयलेस में भी मरने वालों के परिवारजनों को, नैक्ट टू किन एण्ड किथ को मुआवज़ा देने का प्रावधान है। सरकार के पास यह प्रस्ताव है, जिसके तहत क्रॉस फायरिंग में जो मारा जाता है, उसके परिवारजनों को भी मुआवज़ा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई: महोदया, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खतरे तथा नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सली हमलों में कमी आने के कोई संकेत नहीं हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में तीन या अधिक नक्सल हमले हुए जिसमें कई लोग हताहत हुए। चूंकि प्रश्न जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, इसलिए मैं केवल जम्मू और कश्मीर से संबंधित अपने पूरक को सीमित करना चाहूंगा।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से तभी निपटा जा सकता है जब सेना, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस मिलकर काम करें। अन्य सभी स्रोतों से बुद्धिमान इनपुट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन सभी बलों को संयुक्त रूप से निर्देशित करने, बुद्धिमान प्रतिवेदन साझा करने और इसे तुरंत लागू करने पर विचार कर रही है।

श्री किरन रिजिजू : महोदया, सभी एजेंसियां, चाहे वे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, निकट समन्वय में प्रभावी ढंग से एक साथ काम कर रही हैं। मैं माननीय सभा को सूचित कर सकता हूं कि उनके प्रयासों से, वर्ष 2014-15 में ही, कुल 80 आतंकवादी-वे विदेशी आतंकवादी थे, स्वदेशी आतंकवादी नहीं-समाप्त हो गए थे। ये सभी खुफिया और सुरक्षा बलों के एक साथ काम करने के संयुक्त प्रयासों का परिणाम थे। अब, जम्मू और कश्मीर में नई राज्य सरकार के साथ, हम बेहतर समन्वय में काम कर रहे हैं।

श्रीमती मौसम नूर : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। क्या सरकार सीमा बाड़ लगाने की नीति या अन्य देशों के साथ भूमि सीमाओं के लिए एक एकीकृत सीमा प्रबंधन नीति लागू करने का इरादा कर रही है?

श्री किरन रिजिजू : महोदया, यह प्रश्न सामान्य सीमा प्रबंधन से संबंधित है और जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। हम भौतिक बाड़, सुरक्षा तैनाती के साथ-साथ खुफिया प्रतिवेदन और तकनीकी का उपयोग करके अपनी सीमाओं को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विनोद लखमशी चावड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि देश के सरहदी क्षेत्रों में आतंकवादी एवं घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं? जैसे कि गुजरात का कच्छ जिला है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, जो कि जमीन एवं सामुद्रिक सीमा से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की विशेष सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कोई खास कदम उठाए हैं?

श्री किरन रिजिजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित है। वह इस प्रमुख सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी कोस्टल सिक्योरिटी का मामला भी गृह मंत्रालय के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं और पूरा काम कर रहे हैं।

(प्रश्न संख्या 482)

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेटी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मैं समाधानी जरूर हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। ...*(व्यवधान)* क्योंकि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मिलने से किसानों की समस्या हल होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र की समस्या हो या फिर देश भर के किसानों की समस्या हो, गन्ना उत्पादन करने वाले सभी किसानों की समस्या एक जैसी है। कभी बारिश का कम होना, कभी बारिश का ज्यादा होना, कभी उत्पादन कम होना तो कभी उत्पादन का बढ़ना। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि किसान आधिकतर परेशान इसलिए भी है क्योंकि सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकार के टैक्सेज किसानों पर लगाए जाते हैं। इससे भी किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि खास कर चीनी उत्पादन करने वाले किसानों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहे वहां की नगर पालिका, महानगर पालिका हो या अन्य मंत्रालयों द्वारा कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं? क्या सरकार आने वाले दिनों में टैक्सेज के संदर्भ में किसी प्रकार की राहत देने वाली है? क्या जीएसटी आने के बाद किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही जटिल प्रश्न है और गन्ना से डायरेक्ट इसका संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यह बात सही है कि अलग-अलग राज्यों में जो टैक्सेज प्रणाली है, वह अलग-अलग तरीके से हैं। इसके कारण एक ही जगह पर, जहां चीनी ही नहीं, जहां प्याज की उपज ज्यादा होती है, जैसे नासिक में, वहीं दूसरी जगह पर उसकी दिक्कत भी हो जाती है, तो इसलिए एक नैशनल कॉमन मार्केट बने, यह हम लोगों के दिमाग में है और जीएसटी का जो मामला आपने उठाया है, मैं समझता हूँ कि इससे समस्या का पूरी तरह से तो समाधान नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हो जाएगा।

श्री गोपाल शेटी: अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस एक शक्कर कंपनी का उद्घाटन गत सप्ताह जब कर रहे थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को इस प्रकार से संबोधित

किया कि आने वाले दिनों में एफ.आर.पी. कायदा में बदलाव लाने के बारे में महाराष्ट्र की सरकार सोच रही है। क्या केंद्र सरकार भी इससे सहमत है और उसमें अन्य राज्यों को केंद्र सरकार मदद करेगी? साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ी चिंता भी व्यक्त की है कि गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में गन्ना उत्पादन ज्यादा होगा और किसानों की समस्या बढ़ने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि बहुत सालों से एक प्रश्न हम सबके सामने है। शक्कर के माध्यम से, गन्ना उत्पादन के माध्यम से, इथेनॉल एवं अन्य प्रकार डिस्टिलरी और बायो प्रोडक्ट बनाने के बारे में कुछ सोच विचार हो रहा है? क्या केंद्र सरकार गंभीरता से सभी राज्य सरकारों को साथ में ले कर इसके बारे में तुरंत कोई कदम उठाएगी?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूँ कि इस संबंध में बहुत शीघ्र ही हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिले थे और उन्होंने चार-पांच पॉइंट हमारे सामने रखे थे और एक मेमोरेंडम भी दिया था, जिसका जिक्र इन्होंने प्रश्न में किया है। वे चार-पांच बिंदु इस प्रकार थे -

- निर्यात और कच्चे माल के लिए सब्सिडी;
- ऋण पर उत्पाद शुल्क;
- कच्ची चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाएँ ;
- इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम
- बफर स्टॉक का निर्माण;
- चीनी ऋण की शर्तों का पुनर्गठन;
- सॉफ्ट लोन।

[हिन्दी] जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि हमने किसानों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद राज्यों के भी जितने मंत्री थे, हालांकि हमने मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, लेकिन महाराष्ट्र के भी मिनिस्टर आए थे और यही चार-पांच पॉइंट हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को हम लोगों ने बढ़ा कर 15 % से 25 % कर दिया है। मांग है 40% की। वह सरकार के एक्टिव कंसिडरेशन में है। दूसरा सॉफ्ट लोन का मामला है। सॉफ्ट लोन ऑलरेडी दिया जा रहा है। उसमें रीस्ट्रक्चरिंग का सब्जेक्ट है। तीसरा, जो इथेनॉल का मामला है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5% कंपलसरी और 10% तक किया है। दूसरा जो सब्सिडी का मामला है, जिसको आप उठाना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, उसी के मुताबिक एथेनॉल पर भी सब्सिडी दी जाए। वह भी सरकार के अंडर कंसिडरेशन में है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव या सॉफ्ट लोन के संबंध में है, एफ.आर.पी. के संबंध में भी आपने कहा है। उस पर हम इसलिए विचार नहीं कर सकते हैं कि हम एफ.आर.पी. तय करते हैं और यदि कोई राज्य सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह किसान को अधिक कीमत देना चाहे और अपने खजाने से देना चाहे तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रो. के.वी. थॉमस जी, आप केवल गन्ने के बारे में पूछते हैं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: वह एक पूर्व मंत्री थे।

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है।

प्रो. के. वी. थॉमस: महोदया, गन्ना किसान, मिल मालिक और उद्योग पिछले 15 वर्षों से सबसे खराब संकट का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ, आज किसानों को 16,000 करोड़ रुपये का बकाया दिया जाना है और इसका आधा हिस्सा यूपी में है माननीय मंत्री, पासवान जी इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कई बार चर्चा की है। सरकार पहले ही कुछ प्रस्ताव पेश कर चुकी है। माननीय मंत्री ने जिन सुझावों का जवाब दिया, उनके अलावा मेरा सवाल यह है कि, क्या एफ.सी.आई. द्वारा मिल मालिकों से कुछ स्टॉक खरीद कर एक बफर स्टॉक बनाया जा सकता है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

अब, पी.डी.एस. प्रणाली में, आप राज्यों के माध्यम से 500 ग्राम की आपूर्ति कर रहे हैं। क्या इसे प्रति परिवार एक किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है? और, तीसरा, क्या कुछ तंत्र का पता लगाया जा सकता है ताकि निर्यात प्रोत्साहन दिया जा सके और कुछ चीनी का निर्यात किया जा सके? आपने अब जो जवाब दिया है, उसके अलावा ये मेरे सुझाव हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदया, जो माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि जो आपने 16 हजार करोड़ कहा, वह बकाया बढ़कर के 21 हजार करोड़ हो गया है और जितने आप चिन्तित हैं, सदन चिन्तित है, हम सब लोग चिन्तित हैं कि किसान की बकाया राशि का भुगतान कैसे किया जाए। भारत सरकार में हाई लेवल तक, मैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बात कर रहा हूँ, कोई मेरे लेवल की बात नहीं है, जितना भी हम लोगों से बन पा रहा है, उस पर दिन-रात हम मंथन कर रहे हैं। आपने बफर स्टॉक का मामला कहा, उसमें डिमांड आई भी थी कि कम से कम 10% बफर स्टॉक के लिए रख दिया जाए। अब उसमें कई एक मामले हैं कि बफर स्टॉक जो है, एफ.सी.आई. खरीदकर उनके पास रखे या वे अपने पास में रखें, उनका जो सूद होगा, वे बैंक से लोन लें और बैंक का सूद हम दें। ये सारे के सारे मामले हैं, उस पर अध्ययन हो रहा है और उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है।

तीसरी चीज आपने एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव्स की कही। आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव पहले 3300 रुपए देते थे, अब बढ़ाकर हम लोगों ने 4000 रुपया कर दिया है। उसमें री-स्ट्रक्चरिंग की माँग वे लोग कर रहे हैं जो कि अभी पाँच साल का है, उसे बढ़ाकर के एकआद साल और कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि वह हमारे सामने मुद्दा है, लेकिन उस पर हम कोई एश्योरेंस अभी नहीं दे सकते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: आपने प्रति परिवार चीनी को 500 ग्राम से बढ़ाकर एक किलोग्राम करने के मेरे सुझाव का जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम गेहूँ देते हैं और जहाँ-जहाँ राज्य सरकारें चीनी देती हैं, उस चीनी के ऊपर साढ़े अठारह रूपए हम सब्सिडी देते हैं और साढ़े तेरह रूपया उपभोक्ता से लिया जाता है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदया, पहले चीनी बेचने के लिए खाद्य विभाग द्वारा चीनी मिलों के लिए रिलीज मैकेनिज्म के तहत चीनी बेचने का निर्णय होता था। इसके कारण सरकारी कारखानों को चीनी बेचना आसान होता था। डी-कंट्रोल करने से चीनी होने के बावजूद सरकारी मिल चीनी नहीं बेच सकती हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार सरकारी चीनी मिलों की हालत देखते हुए डी-कंट्रोल हटाकर रिलीज मैकेनिज्म लाना चाहती है?

श्री राम विलास पासवान : इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है और मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। एक तरफ डी-कंट्रोल हो गया है, फिर उसको कंट्रोल करके फिर उसमें डी-कंट्रोल मैकेनिज्म को लागू करना, मैं समझता हूँ कि अभी यह सरकार, मतलब हमारे पास डिमांड आई है, लेकिन अभी वे हमारे विचाराधीन नहीं हैं।

योगी आदित्यनाथ: महोदया, देश के गन्ना किसानों की स्थिति अत्यंत खराब है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के उस क्षेत्र से आता हूँ, जिसे कभी "चीनी का कटोरा" कहा जाता था। वहाँ की चीनी मिलों ने उस क्षेत्र के पलायन को रोका था और किसानों को काफी समृद्ध किया था। गोरखपुर मंडल में आज से 20 वर्ष पूर्व तक 36 चीनी मिलें चलती थीं। आज मात्र 13 चीनी मिलें चल पा रही हैं और उन पर भी किसानों का हज़ारों करोड़ रुपया पिछला गन्ना मूल्य का बकाया है। वर्तमान सीज़न का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं हो पाया है।

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के बारे में, उनके पुनरुद्धार के बारे में, शुगर डेवलपमेंट फंड से उनको ऋण आदि मिलने के बारे में यथोचित समय पर यथोचित निर्णय लेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह यथोचित निर्णय सरकार कब लेगी क्योंकि किसान

आज तबाह है? उसके घर में शादी नहीं हो पा रही है। वह हर प्रकार से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यथोचित निर्णय का समय कब आएगा जिससे किसानों को ठीक समय पर सही सहायता मिल सके और वहाँ की चीनी मिलों का पुनरुद्धार हो सके और किसान के पलायन को रोकने में पहले चीनी मिलों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसी प्रकार किसानों के पलायन को रोका जा सके।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, अभी तक हमारे पास टोटल 709 चीनी मिलें हैं। इन 709 में से कार्यरत चीनी मिलें 529 हैं। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, वहाँ कार्यरत चीनी मिलें 118 हैं और बंद चीनी मिलें 40 हैं। इनके अलग अलग आँकड़े हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया, हमने कहा कि हमारे सामने जो डिमांड आई थी, वह एक ही आई थी। किसान की भी वही डिमांड थी, मिल मालिक की भी वही डिमांड थी और जो स्टेट के मिनिस्टर को बुलाया था, उनकी भी वही डिमांड थी। कुल मिलाकर पाँच डिमांड्स थीं कि आप ड्यूटी फ्री कर दीजिए 40 परसेंट तक, हम उस पर विचार कर रहे हैं और पॉज़िटिव तरीके से कर रहे हैं। दूसरा था सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन आलरेडी दिया जा रहा है। तीसरा था इथेनॉल, वह ऑलरेडी हम कर रहे हैं। सब्सिडी का मामला है। हमने कहा कि वह अंडर एक्टिव कंसिडरेशन में है। चौथा बफर स्टॉक का मामला है, वह हमारे विचाराधीन है। एफ.आर.पी. का मामला है। तो उसमें हमने कह दिया कि एफ.आर.पी. हम तय करते हैं, लेकिन राज्य सरकार यदि एक्स्ट्रा देती है तो हम उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इन पर हम काम कर रहे हैं। और भी छोटी-मोटी डिमांड्स हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो मिल मालिक है, उनसे बकाया पैसे का भुगतान करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। राज्य सरकार के पास इतनी पावर है कि बैंक ज़ब्त कर सकता है, उसको जेल भेज सकता है, उसके सामान को बेचकर किसान को पेमेंट कर सकता है। इसलिए जब हम पिछली बार आए थे, तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार ने इसमें जितना इनीशियेटिव लिया है, वह हम मैक्सिमम कर रहे हैं। हम जब पिछली बार आए थे, तो उस समय वह 53 करोड़ रुपये था, अंत में 1600 करोड़ रुपये बचे। इस बार भी 2100 करोड़ रुपये है। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास जितने प्रपोज़ल्स आए हैं, उन सारे प्रपोज़ल्स को मान भी लिया जाए तो किसान को पेमेन्ट होने वाला है या

नहीं। क्योंकि हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किसान को मिल रहा है या नहीं। चूँकि एक तरफ मिल मालिक हैं और दूसरी तरफ किसान हैं। इसलिए जो प्रपोज़ल है, उसमें जो यथोचित शब्द है, यथोचित का मतलब हम यथोचित नहीं रखते हैं। यथोचित का मतलब हो गया तत्काल कार्रवाई।

श्री हुकुम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि चीनी वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए, तो हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह: हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए नाम भी दिया हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको किसी प्रकार की चर्चा चाहिए तो लिखकर देना पड़ेगा, फिर चर्चा होगी।

... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: यह महत्वपूर्ण मामला है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, इस तरीके से नहीं होता है।

... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग चर्चा मांगेंगे तो मिलेगी। चिल्लाकर क्या होगा?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)... *

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होता है प्रश्न काल में।

प्रश्न 483, श्री राजेश कुमार दिवाकर।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 483)

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार दिवाकर: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या स्वतंत्र निदेशक और गैर सरकारी निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों को केवल और केवल नियमों, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है ताकि वे अपनी योग्यता के आधार पर कंपनियों को लाभान्वित कर सकें, तथा निदेशकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उन्होंने आज इस सदन में उठाया है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उस सन्दर्भ में जैसी अपेक्षा सदस्य ने की है, उसी प्रकार से यह नियुक्ति होती है। जो भिन्न-भिन्न हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन उपक्रमों के लिए आवश्यक जो अनुभव उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को होना चाहिए या उस उपक्रम के बारे में या उसके उत्पादन के बारे में जो जानकारी उसे होनी चाहिए, इन सारी बातों को देखते हुए जो उपक्रम के लिए हितकारी है या हो सकता है, इसी प्रकार के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों की नियुक्ति की जाती है और यह लगातार सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है।

श्री राजेश कुमार दिवाकर: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले कुछ वर्षों में नियुक्त किए गए कुछ स्वतंत्र निदेशक अथवा गैर-सरकारी निदेशक योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए हैं या उन्हें किसी दबाव के चलते हुए इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है? क्या ऐसे नियुक्त किए गए गैर-सरकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का सम्बन्धित कम्पनी के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध था? इसमें निर्धारित संहिता कोड के साथ-साथ व्यवहारिक आचार, भूमिका, कार्यों आदि की जांच हेतु कोई नीति निर्धारित की जा सकती है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया जी, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, वे योग्यता के अनुसार ही किए गए हैं। किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यदि उस उद्योग के साथ या उस सार्वजनिक

उपक्रम के साथ कोई रिश्ता है तो ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वहां नियुक्त नहीं किया जाता है और इसलिए जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब तक नियुक्त किए गए हैं, वे सारे के सारे योग्यतानुसार ही किए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई आशंका नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा : अध्यक्ष महोदया, निदेशक मंडल में सर्वश्रेष्ठ नियुक्तियों के बावजूद, विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में, बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। अथवा, वे स्वतंत्र निदेशक, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल में, सर्वश्रेष्ठ नियुक्तियों के बावजूद लगभग बंद होने के कगार पर हैं।

भारत सरकार 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का गंभीरता से प्रचार कर रही है। यदि ऐसा है, तो भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने के निर्णय के बावजूद जिनके पास सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा और मूल्यवान भूमि और संपत्ति है, क्या भारत सरकार उन उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के बारे में सोच सकती है जिनके संबंध में उन्होंने पहले ही उन्हें बंद करने का निर्णय ले लिया है?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, यह जो मूल प्रश्न है, इससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न मर्यादित है, जो सार्वजनिक उपक्रमों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है, उसको लेकर है। फिर भी सदस्य ने जो चिन्ता यहां पर जताई है, यह वास्तविकता है कि हमारे कई उद्योग हैं, वे आज बीमार हैं और कितने दिन तक सरकार इन बीमार उद्योगों को चलाए, इस पर सरकार विचार कर रही है और उसी दिशा में कुछ निर्णय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। यदि किसी विशेष पी.एस.यू. के बारे में सदस्य जानना चाहें, तो वे अलग से यह सवाल कर सकते हैं। उसका उत्तर निश्चित रूप में दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, हम सभी जानते हैं कि परिवार के गहनों को हर परिवार द्वारा संरक्षित और संरक्षित किया जाता है। नाल्को नामक एक कंपनी है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, अंगुल, ओडिशा में है। कंपनी को लगातार ऐसे प्रबंध निदेशक प्राप्त करने का दुर्भाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है जो भारी मात्रा में काला धन/नकदी ले जाते हुए पकड़े गए हैं। सी.एम.डी. की एक श्रृंखला थी जो बहुत सारी गलत चीजें करते हुए पकड़े गए थे और उन्हें दंडित किया गया था जिसके लिए 25 साल पुरानी कंपनी-- जो इस देश का गौरव रही है, मैं कहूंगा-- को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।

आज, भयानक कुप्रबंधन के कारण, ऐसा लगता है कि सरकार, कंपनी को पुनर्जीवित करने की कोशिश किए बिना, सभी सी.पी.एस.यू. के गौरव, नाल्को को बेचने के संदर्भ में बात कर रही है, क्योंकि नाल्को के पास ओडिशा में सबसे अच्छी बॉक्साइट खदानों में से एक है। इसके पास सभी साधन हैं, लेकिन नाल्को को उसके ही निदेशकों द्वारा बार-बार लूटा और लूटा गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सभी पारिवारिक रत्नों को बेचने के बारे में सोच रही है या क्या वे कंपनी के प्रबंधन में बदलाव लाने में रुचि रखते हैं जिसके द्वारा नाल्को को पुनर्जीवित किया जा सके; यह केंद्र सरकार के पास रहेगा; और यह गर्व की बात होगी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसे व्यावसायिक निदेशकों के साथ व्यावसायिक रूप से प्रबंधित कंपनी बनाने की कोई योजना है। मैं नाल्को की बात कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से यह कहूंगा कि माननीय सदस्य काफी अनुभवी हैं। वे स्वयं जानते हैं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। यह नाल्को से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं उनकी एक बात से सहमत हूँ कि हमारे जितने भी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं, ये एक तौर से हमारे देश के लिए ज्वेल्स के बराबर हैं। इन ज्वेल्स को प्रिज़र्व करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने आवश्यक हैं, वे सरकार

द्वारा उठाए जाते हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब मैं इस समय उन्हें नहीं दे पाऊंगा। वे अलग-से इस प्रश्न का उत्तर पूछें तो निश्चित रूप में इसका उत्तर दिया जाएगा।

श्रीमती रक्षाताई खाडसे: मैडम, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पी.एस.यू. में गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक में प्राधान्य से महिला की नियुक्ति हेतु कोई नीति सरकार के विचाराधीन है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद दूंगा। कम्पनी एक्ट के मुताबिक सारे उपक्रमों में गैर सरकारी महिला निदेशक की नियुक्ति करना आनिवार्य है। इस दिशा में मेरे मंत्रालय की ओर से, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उद्यम विभाग की ओर से सारे सी.पी.एस.यू. को इसकी सूचना दी गयी है। निश्चित रूप में, हर पी.एस.यू. में गैर सरकारी महिला निदेशक की नियुक्ति होना आवश्यक है और इस दिशा में सही कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: महोदया, कृपया मुझे एक पूरक दें।

श्री एम. आई. शनवास: महोदया, कृपया मुझे एक सवाल पूछने दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस समय दो बड़े-बड़े लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं।

डॉ. शशि थरूर जी।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: महोदया, मेरा प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न से संबंधित है। जबकि, हमारे देश के 68 सार्वजनिक उपक्रमों में से 64 ने मार्च 2015 के अंत में स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता को पूरा कर लिया है, लेकिन तथ्य यह है कि सार्वजनिक उपक्रम अभी भी महिला निदेशकों की नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड(एस. ई. बी. आई.) द्वारा दिया गया जनादेश है। निदेशक मण्डल में

कम से कम एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति का निर्देश देते हुए पिछले साल 17 अप्रैल को एक परिपत्र जारी किया गया था। यह समय सीमा 1 अक्टूबर 2014 थी, जिसे बाद में सभी सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2015 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन 1 अप्रैल की समय सीमा लंबे समय से चली गई है, श्रीमान मंत्री जी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 68 सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में से लगभग 30 बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति करने में विफल रहे हैं। क्या आपने इस आवश्यकता का अनुपालन न करने के लिए इन सार्वजनिक उपक्रमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू करने के बारे में सोचा है? इस विलंब का मुख्य कारण क्या है? सरकार वास्तव में इस आवश्यकता को कब पूरा करने जा रही है? आपने महिला सांसद को यह कहते हुए जवाब दिया है कि आपने निर्देश दिया है, लेकिन यदि निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, श्रीमान मंत्री जी? धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, सदस्य ने जो प्रश्न के माध्यम से जानकारी दी है, मैं उस जानकारी से पूरी तरह सहमत हूँ। सेबी के निर्देश भी हैं, कंपनी एक्ट में भी इस प्रकार का प्रावधान है और जो मेरा विभाग सार्वजनिक लोक उद्यम है, इस विभाग ने भी सारे पी.एस.यू. को महिला गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के बारे में सूचनाएं दी हैं। मैं सदस्य से सहमत हूँ कि समय पर यह नियुक्ति होनी आवश्यक थी, नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य और सदन को भविष्य के लिए विश्वास देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इसकी ओर विशेष ध्यान देकर समय-सीमा के तहत महिला संचालकों की नियुक्ति की जाएगी। मैं सदन को यह विश्वास देता हूँ।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्र निदेशक की जो सूची दी गई है, इसके अलावा भी महारत्न और नवरत्न कंपनियां ऐसी हैं, जहां स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। वे कंपनी लॉ में भी हैं। अगर नवरत्न और महारत्न कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो उनका स्टैटस छिन सकता है।

इस लिस्ट के अलावा ऐसी नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं जिनमें स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण, हमारे कई अच्छे पी.एस.यू. हैं, जैसे महारत्न और नवरत्न का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके लिए अपने क्रियान्वयन और कार्रवाई में बाधा आती है, मैं इससे सहमत हूं। मैं सदन और सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हर पी.एस.यू. के ऊपर गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी और उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षा: प्रश्न संख्या 484,

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत- उपस्थित नहीं;

श्रीमती सुप्रिया सुले।

(प्रश्न संख्या 484)

श्रीमती सुप्रिया सुले : गाजियाबाद में जो हुआ वह बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जवाब के अनुसार, ऐसा लगता है कि मंत्रालय ने कार्रवाई की है। मैं माननीय मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूँ कि इस तरह की चीज कभी नहीं होती है क्योंकि दिव्यांग लोग हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लोग हैं जो बहुत कम मदद, बुनियादी ढांचे और कोचिंग के साथ भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि भविष्य में सभी बुनियादी ढांचा, यह सब, अखिल भारतीय स्तर पर, समावेशी होना चाहिए और हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उनके पास इसकी पर्याप्त पहुँच होनी चाहिए। क्या मंत्रालय की उन्हें विशेष कोचिंग देने की कोई योजना है क्योंकि वे जाना पसंद करते हैं लेकिन वास्तव में कोई कोचिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है?

श्री सर्वानंद सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले, मैं इस विशेष संवेदनशील मुद्दे को सदन के संज्ञान में लाने के लिए माननीय संसद सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा। गाजियाबाद में जो कुछ भी हुआ वह राष्ट्रीय खेल महासंघ की ओर से एक खेदजनक स्थिति है। यह कुप्रबंधन, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के कृत्य का प्रदर्शन था। हम इस मुद्दे पर आपसे सहमत हैं। इसलिए, हमारी ओर से, हमने उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की है। हमने महासंघ को निलंबित कर दिया है। साथ ही, हमने मान्यता रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

निकट भविष्य में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैरा एथलीटों को इस तरह के कुप्रबंधन या असुविधा का सामना न करना पड़े, मेरी सभी राज्य सरकारों से विशेष अपील है और, साथ ही, राष्ट्रीय खेल महासंघ से भी, विशेष ध्यान रखने की अपील है। जैसा कि आप जानते हैं, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 'खेल' राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस संबंध में, हमारी ओर से, जो भी सबसे अच्छा संभव है, हम हमेशा उसे पूरी सीमा तक करेंगे।

साथ ही, उनकी बेहतर कोचिंग के लिए, हमने गुजरात के गांधीनगर में, एक कोचिंग कैंप लगाने का फैसला किया है। यह देश में सभी पैरा एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा और हमने एस.ए.आई. प्रशिक्षण केंद्र के साथ-साथ विशेष क्षेत्र खेल केंद्र में पैरा एथलीटों को शामिल करने का भी निर्णय लिया है ताकि निकट भविष्य में उन्हें अन्य एथलीटों की तरह सभी संभव सुविधाएं मिल सकें।

जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार हमेशा सक्षम एथलीटों के साथ-साथ शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों – दोनों को समान महत्व देती है। जो भी नकद पुरस्कार दिया जाता है, वह समान रूप से दिया जाता है। हम सक्षम खिलाड़ियों को जो भी राशि देते हैं, उतनी ही राशि दिव्यांग खिलाड़ियों को भी दी जाती है।

आपकी जानकारी के लिए, जैसा कि मेरे माननीय वरिष्ठ सहयोगी, श्री तोमर जी ने, मुझे अभी बताया है, दक्षिण अफ्रीका में, जब भारत की नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीता था, उस समय हमारे माननीय वरिष्ठ सहयोगी, श्री अनंत कुमार जी, श्री तोमर जी, और मैं, उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पर गए थे, और उसी दिन हमने 17 क्रिकेटरों को नकद पुरस्कार भी दिए हैं। इसी तरह, जब उन्होंने इंचियोन एशियाई खेलों में 33 पदक जीते, तो उन्हें उसी तर्ज पर नकद पुरस्कार भी दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्रीमती सुप्रिया सुले: उस क्रिकेट टीम के नेत्रहीन लड़कों में से एक, जिसका आपने उल्लेख किया है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से था और वह उस टीम का हिस्सा था। मुझे पता है कि उन्हें आपके द्वारा सम्मानित किया गया था।

किसी को लगता है कि 'दिव्यांग' का मतलब है कि सिर्फ एक रैंप ही काफी है। कई अन्य आवश्यकताएँ भी हैं। तो, क्या आप अपने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कुछ विशेष विशेषज्ञों को लाएंगे या कम से कम राज्यों को कुछ दिशानिर्देश देंगे कि आप सही हस्तक्षेप के साथ हर खेल सुविधा कैसे उपलब्ध करा सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक रैंप पर्याप्त नहीं है? हम सभी का मानना है कि सिर्फ एक रैंप जोड़ने का मतलब है कि यह

दिव्यांग लोगों की सभी समस्याओं का समाधान है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वास्तव में इस खेल कार्यक्रम में शामिल महसूस करें।

श्री सर्वानंद सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार देश में दिव्यांगों के लिए विशेष केंद्र भी चला रही है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: 'विकलांग' नहीं, बल्कि 'भिन्न रूप से सक्षम'।

श्री सर्वानंद सोनोवाल: हम दिव्यांग और शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए विशेष केंद्र चला रहे हैं। जैसा कि आपने सुझाव दिया है, निकट भविष्य में, जो भी सर्वोत्तम आधुनिक सुविधाएं हैं, वे दिव्यांग एथलीटों को प्रदान की जाएंगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा और यह एक ऐसा मामला है जिस पर गौर किया जाएगा।
[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद: यह प्रश्न 'ड' भाग से जुड़ा हुआ है कि उन सब को रोकने के लिए आगे सरकार क्या कार्रवाई करेगी? केवल विकलांगों को ही तकलीफ नहीं होती है, बल्कि जो विकलांग नहीं हैं उनको भी तकलीफ होती है। स्पोर्ट्स का कोई भी डिसिप्लिन हो सबके साथ यह होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने पहले भी हमें एश्योरेन्स दिया था, मैं पूर्व के खेल मंत्री अजय माकन जी का धन्यवाद करता हूं कि वह 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल', लेकर आये थे। वह किन कारणों से कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, मुझे वह मालूम नहीं है, लेकिन जो 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल' तैयार किया गया है, अगर उसे लाया जायेगा तो आपको उन समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सबको अपने कार्यक्रमों के बारे में बताना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खेल जिसका न कोई जात होता है और न कोई मजहब होता है, लोग अपने देश और टीम के लिए खेलते हैं, ऐसे 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल' को सरकार कब ले कर आयेगी, जिससे कि हो रही गंदगियां थम सकें?

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह ब्लाइंड प्लेयर्स को लेने गये थे, यह खुशी की बात है। जब मैंने इन्हें आई.पी.एल. के ओपनिंग सेरेमनी में देखा था तो मुझे और प्रसन्नता हुई थी।

[अनुवाद]

श्री सर्वानंद सोनोवाल: अध्यक्ष महोदया, मैं सभा को सूचित करता हूं कि इस विधेयक पर कुछ और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसलिए, इस प्रतिष्ठित सभा को कुछ और समय इंतजार करना होगा क्योंकि यह परामर्श चरण अभी भी जारी है।

डॉ. रत्ना दे (नाग): आयोजन स्थल पर दयनीय बुनियादी ढांचे और आयोजन की पूरी अवधि के दौरान एथलीटों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में मीडिया रिपोर्टें थीं। इससे कई परेशान हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों की मदद के लिए, अतिरिक्त सहायता देने की बात करें तो उन्हें पंखे, पानी, रैंप, दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय और रहने की सुविधा भी नहीं दी गई है। बेशक, पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था। क्या इतना ही काफी है? क्या माननीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों से संबंधित इस तरह की चौंकाने वाली घटना के बाद क्या अभिनव प्रयास किए गए हैं?

श्री सर्वानंद सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विशेष विषय ने हम पर गहरा प्रभाव डाला है और इसलिए हमने तुरंत जांच की है। हमने मौके पर एस.ए.आई. की एक टीम भेजी है। उन्होंने पूरी स्थिति का आकलन किया है और हमें वापस सूचित किया है। उनकी प्रतिवेदन के आधार पर, हमने महासंघ को निलंबित कर दिया है और मान्यता रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

यह एक ऐसी शिक्षा है जिसे उन्हें अपने कुकर्मों से सीखना चाहिए। इस महती सदन में, मैं सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों से अनुरोध करना चाहूंगा कि, वे अपने भीतर की अंदरूनी लड़ाई के बावजूद एकजुट हों। देश में खेलों की बेहतरी के लिए एकजुट होना बेहतर है। उनकी अंदरूनी लड़ाई के बावजूद, हमारी सरकार हमेशा एस.ए.आई. के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भेजने में मदद कर रही है। जो कुछ भी हो रहा है, वह संघों के भीतर की अंदरूनी लड़ाई के कारण हो रहा है। इसलिए, देश की जनता चाहती है कि संघ एकजुट हों। खेल संघ के चार महत्वपूर्ण स्तंभ केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, भारतीय ओलंपिक संघ और महासंघ

हैं। हमें एकजुट होना चाहिए; हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। कल - आपने प्रतिवेदन देखी होगी - अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, श्री थोमस बाक भारत आए थे। हमारे परिचय के दौरान, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्वायत्तता और सुशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्वायत्तता और सुशासन साथ-साथ चलने चाहिए। यही कारण है कि, सरकार और हमारा मंत्रालय हमेशा संघ की स्वायत्तता का सम्मान कर रहा है। लेकिन, साथ ही, दिन-प्रतिदिन के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। यही देश के लोगों की, देश के खेल प्रेमियों की इच्छा है।

(प्रश्न संख्या 485)

[हिन्दी]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि देशभर में जहाँ स्किल सेंटर्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का विषय है, क्या हम उसे ए.डी.आई.पी. जो एड्स और आसिस्टेंस का प्रोग्राम है, उससे जोड़ने का कोई प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि पूर्व में देखा गया कि तकरीबन 43 प्रतिशत डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। अभी वह घटकर 38 प्रतिशत से भी कम हो चुका है क्योंकि 38 प्रतिशत का आंकड़ा भी वर्ष 2001 का है। आज के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। किस प्रकार ऐसा प्रावधान हो कि स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स तक डिफरेंटली एबल्ड लोग पहुंचें और उनके रोजगार में उसे तब्दील किया जाए। क्या उसके लिए मंत्रालय का कोई प्रावधान है?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से इस प्रकार की सुविधा मेरे विभाग की ओर से अशक्त जनों को सिपडा योजना के माध्यम से, दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना के माध्यम से, विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से, हमारे सात राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से और श्रम विभाग की ओर से विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। हमने देशभर में इस प्रकार के कौशल प्रशिक्षण के लिए थोड़ा सक्रिय प्रयास प्रारंभ किया है। कौशल मंत्रालय के माननीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी के साथ 21 तारीख को हमने एक एम.ओ.यू. भी किया है। लक्ष्य तय किया है कि इन तीन वर्षों में 5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेंगे और पांच वर्षों या वर्ष 2020 तक 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। राष्ट्रीय कार्य योजना में 70 प्रतिशत रोजगार लक्ष्य रखा गया है और हम इस रोजगार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े भी हैं कि हमने अभी तक केवल 2014-15 में 52,650 लोगों को लाभान्वित किया है। दिल्ली का आंकड़ा मेरे पास है, राज्यवार आंकड़ा भी मेरे पास है। अगर माननीय सदस्या चाहेंगी तो मैं उसे उपलब्ध करवा दूंगा।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: माननीय अध्यक्षा जी, सरकार स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिवैंप करने की कोशिश कर रही है। नेशनल काउंसिल एंड स्किल ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही रही थी। क्या इस कार्यक्रम के साथ उसे इंटीग्रेट करने का कोई प्रावधान है? आप हर डिस्ट्रिक्ट में आई.आई.टी. बनाना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं आई.आई.टी. के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या अलग से प्रावधान होगा या उनके लिए अलग से आई.आई.टी. की स्थापना होगी? क्या इस पर सरकार ने विचार किया है?

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, हम आवश्यकतानुसार और नित्य नई तकनीकी प्रणाली को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परिवर्तन करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना को जिला स्तर पर संचालित करते हैं। सिपड़ा और फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से इस प्रकार की कार्ययोजना को संचालित किया जा रहा है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, भारत के विभिन्न राज्यों के गांवों में स्किल डेवलपमेंट की मजबूत संभावनाएं हैं। हाथ की कारीगरी में बिहार को महारत हासिल है। मधुबनी की पेंटिंग और भागलपुर में रेशम की कढ़ाई की जाती है। मुंगेर और हवेली खड़गपुर में चांदी की मछली तराशी जाती है। बांका और मुंगेर में जो चांदी की मछली बनती है उसे बिचौलिए गजरे के भाव से उठा लेते हैं। उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम है? बिहार को इस बाबत क्या विशेष सुविधा दी जा रही है?

श्री थावर चंद गहलोत: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य सामान्य प्रकृति का प्रश्न पूछ रहे हैं। जिस कारोबार में वे लोग लगे हैं अगर वे विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो हम उनको विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से सस्ते ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

डॉ. मनोज राजोरिया : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने विशेष योग जनों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं विशेषकर स्किल डेवलपमेंट का विस्तृत विवरण दिया है। जिसमें सिपड़ा, दीनदयाल उपाध्याय रिहैबिलिटेशन स्कीम, एन.एच.एफ.डी.सी. योजनाओं के माध्यम से राज्यों को सहायता

दी जाती है या एन.जी.ओ. के माध्यम से दी जाती है। सरकार की भावना है कि विशेष योग जनों को किसी विशेष कार्य के लिए ट्रेनिंग दी जाए। सरकार का अंतिम उद्देश्य उनको नौकरी देने का है, लेकिन उनकी नौकरी सुनिश्चित करने का कहीं जिक्र नहीं है। विशेष योग जन जो जन्म से ही प्राकृतिक मुसीबत झेलता है, अपमान झेलता है और अपनी मेहनत से ट्रेनिंग करके रोजगार पाने की कोशिश करता है, क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर विशेष योग जनों का राज्यवार विवरण तैयार करके सरकारी और प्राइवेट नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कोई मोनिटरिंग सिस्टम बना रही है जिससे उनकी नौकरी सुनिश्चित की जा सके?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हम निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं और ट्रेनिंग के बाद लाभान्वित व्यक्ति की नौकरी लगी है या नहीं, इसका भी हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसका हमें बहुत कठिनाई से पता लगता है, फिर भी मेरे पास राज्यवार बेनीफिशरीज की संख्या है। अगर आप अनुमति दें, तो उसे मैं पढ़कर भी सुना सकता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उन्हें यह जानकारी उपलब्ध करा दीजिए।

श्री थावर चंद गहलोत : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने इस पर गंभीरता से विचार करके यह निर्णय लिया है कि जिन लोगों को हम आर्थिक सहायता देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वे प्रशिक्षण के बाद कुशल हो जाते हैं। अब कुशल होने के बाद वे कारोबार में लगे हैं या नौकरी में लगे हैं, उनका भी हम पता लगायेंगे। हम भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनका पता लगाकर उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने की कोशिश करें।

(प्रश्न संख्या 486)

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : बहुत-बहुत धन्यवाद।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन पहले से ही न केवल पूरे भारत में बल्कि दुनिया भर के समुदायों को हिंसक रूप से प्रभावित कर रहा है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन प्रदूषक है। यह देश के कुल उत्सर्जन का लगभग छह प्रतिशत है। यह हिस्सा आने वाले दशकों में बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि 2050 तक भारतीय आबादी 1.2 बिलियन से बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाएगी और देश बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए अधिक जीवाश्म ईंधन संचालित बिजली संयंत्र जोड़ रहा है। इसलिए, मेरा पहला सवाल यह है कि, सरकार ने ग्रामीण स्तर पर किफायती बजट में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और अन्य पारंपरिक प्राकृतिक संसाधनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता का दोहन करने के लिए क्या उपाय किए हैं।

श्री प्रकाश जावडेकर: यह सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको बता दें कि सबसे पहले हमें वर्तमान उत्सर्जन में भारत के योगदान के केवल छह प्रतिशत के एक आंकड़े पर विचार नहीं करना चाहिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बहस और ग्लोबल वार्मिंग की बहस में जो मायने रखता है वह यह है कि ऐतिहासिक और संचयी उत्सर्जन क्या रहे हैं; हमारे बहुत कम हैं। हम तीसरे नहीं हैं। हम सौवें अथवा उससे बहुत नीचे भी हो सकते हैं। तो, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत के संचयी उत्सर्जन पर यही स्थिति है।

दूसरा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, प्रत्येक व्यक्ति को कार्बन स्पेस का अधिकार है। यही वह शब्दावली है जिसका हम उपयोग करते हैं क्योंकि हर किसी को विकास का भी अधिकार है और इसलिए उसे उस स्थान पर कब्जा करना चाहिए। इसलिए, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन महत्वपूर्ण है; और हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.79 टन प्रति वर्ष के साथ बहुत कम है। हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अन्य देश हमसे बहुत आगे हैं लेकिन हमारा उत्सर्जन बढ़ रहा है।

जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, कोई दबाव नहीं है लेकिन जलवायु परिवर्तन का दबाव है और आने वाली पीढ़ियों का दबाव है। इसलिए, हमने अपने नवीकरणीय लक्ष्यों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री पहले ही एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा की घोषणा कर चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, 10,000 मेगावाट बायोमास ऊर्जा और 5,000 मेगावाट छोटी पनबिजली ऊर्जा शामिल है; सभी 1,75,000 मेगावाट तक आते हैं। इसका मतलब है कि \$ 150 बिलियन का निवेश और 350 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी। इसलिए, हम सबसे सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। यह सटीक रूप से 2020 से पहले की कार्रवाई है, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनिवार्य नहीं करते हैं लेकिन हम इसे अपनी प्रतिबद्धता के रूप में कर रहे हैं। इसलिए, लक्ष्यों को बढ़ाना और ऊर्जा मिश्रण को बदलना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

अब हम सभी स्ट्रीट लाइटों को एल.ई.डी. में बदल रहे हैं। इस कार्रवाई से भी, हम अपने उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा दक्षता बढ़ा सकते हैं। इसलिए, हम सभी मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ भारत और हरित भारत की दिशा में, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मार्ग पर हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार ने मौजूदा नीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए हैं ताकि इसके शमन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और पर्याप्त वित्त और संस्थागत क्षमता के साथ-साथ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे आठ राष्ट्रीय मिशन हैं। अब हमने चार नई पहल जोड़ी हैं। इन सभी को मिलाकर, इसे राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाना है। इसलिए, इसमें स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्यों का क्षमता निर्माण भी शामिल है। इसलिए, हमने सभी राज्यों को अपनी राज्य कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम अनुकूलन और अन्य

क्षेत्रों में क्षमता निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। साथ ही, सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया जाता है। हमने हाल ही में सभी पर्यावरण मंत्रियों और प्रदूषण, पर्यावरण और वन से संबंधित राज्यों के सभी सचिवों का एक सम्मेलन किया था। राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा क्या किया जाएगा, इसके संबंध में हमने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी अपनाया है।

श्री कीर्ति वर्धन सिंह: धन्यवाद, आदरणीय, अध्यक्ष महोदया। यह मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के भाग (घ) का उल्लेख कर रहा है जहां सरकार ने 2020 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 20 से 25 प्रतिशत तक कम करने का एक बहुत ही यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों को जलाना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है...

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: हम 2020 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 20-25 प्रतिशत तक कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर हैं। आई.पी.सी.सी. उत्सर्जन गैस प्रतिवेदन ने प्रमाणित किया है कि भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

***प्रश्नों के लिखित उत्तर**

(तारांकित प्रश्न संख्या 487 से 500,
अतारांकित प्रश्न संख्या 5521 से 5750)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.02 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

माननीय अध्यक्ष: अब, पटल पर पत्र रखे जाने हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-6 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2366/16/15]

(दो) सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड तथा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुआ समझौता।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2367/16/15]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि.127(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2015 जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि.127(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2368/16/15]

युवा और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2369/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2370/16/15]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर):

महोदया, मैं पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के तहत 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 93 (ई) में कुछ संशोधन करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 606 (ई) (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखना चाहता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2371/16/15]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- 1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- 2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2372/16/15]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

- 2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2373/16/15]

- 3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलोर के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलोर का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

- 4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2374/16/15]

- (5) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 से 2012-13 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2375/16/15]

- (7) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2376/16/15]

- (9) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस.[हिन्दी] ए.एस. नगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2377/16/15]

(11) ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2378/16/15]

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. एम. सिद्धेश्वर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने का अनुरोध करता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के कामकाज की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में वक्तव्य।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षका का टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2379/16/15]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2380/16/15]

(दो) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच

वर्ष 2015-2016 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2381/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने का अनुरोध करता हूँ:-

- (1) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत शत्रु संपत्ति नियम, 2015 जो 19 मार्च 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 205 (ई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2382/16/15]

- (2) वर्ष 2012-2013 के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2383/16/15]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- 1) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- 2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2384/16/15]

- 3) कंपनी अधिनियम, 1957 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- 4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2385/16/15]

- 5) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

- 6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2386/16/15]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) वर्ष 2011-2012 के लिए गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजी, के कामकाज की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजी की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित खातों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2387/16/15]

(ख) (एक) वर्ष 2013-2014 के लिए पश्चिम बंगाल पशुधन विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, के कामकाज की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए, पश्चिम बंगाल पशुधन विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित खातों और उस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2388/16/15]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) विद्यारणा, बंगलौर के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विद्यारणा, बंगलौर के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2389/16/15]

- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2390/16/15]

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2391/16/15]

(4) (एक) अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ढेंकानाल के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ढेंकानाल के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लेखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2392/16/15]

(6) कलाइसेल्वी करुणालय सोशल वेलफेयर सोसायटी, चेन्नई के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2393/16/15]

(8) कलाइसेल्वी करुणालय सोशल वेलफेयर सोसायटी, चेन्नई के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2394/16/15]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी होगी:--

उन्होंने कहा, "मुझे लोकसभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि 27 अप्रैल, 2015 को हुई राज्यसभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया है:

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोकसभा से सिफारिश करे कि लोकसभा कोयला खदानों के आवंटन का प्रावधान करने के लिए विधेयक को वापस लेने और कोयला खनन कार्यों और कोयले के उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सफल बोलीदाताओं और आवंटनकर्ताओं को, खनन पट्टों के साथ-साथ भूमि और खदान के बुनियादी ढांचे में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज निहित करने के लिए राज्यसभा द्वारा दिए गए अवकाश पर सहमत हो जाए और इससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए जिसे लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर, 2014 को पारित किया गया था और 15 दिसंबर, 2014 को राज्यसभा के पटल पर रखा गया था।"

अपराह्न 12.03 ½ बजे**प्राक्कलन समिति****दूसरा से चौथा प्रतिवेदन**

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : मैं प्राक्कलन समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित "ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों का मूल्यांकन" के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
 - (2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" विषय के बारे में पंद्रहवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (2013-14) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
 - (3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" विषय के बारे में पंद्रहवीं लोकसभा की प्राक्कलन समिति (2013-14) के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।
-

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

तीसरे से छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में 26वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
 - (2) कोल इंडिया के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
 - (3) 2011-12 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्यांक 3 के पैरा 2.5 पर आधारित भारत सरकार की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण-मुंबई इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लिमिटेड द्वारा न्यासीय हैसियत में धारित एस्करो खाते से अप्राधिकृत वापसी के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (पंद्रहवीं लोकसभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
 - (4) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में छठा प्रतिवेदन।
-

[अनुवाद]

अपराह्न 12.05 बजे

विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति

पाँचवाँ और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

- (1) वर्ष 2015-16 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पाँचवाँ प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा)।
- (2) वर्ष 2015-16 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठा प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा)।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.05 ½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति

वक्तव्य

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी (अनन्तपुर): मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2014-15) की निम्नलिखित कार्रवाई रिपोर्टों के अध्याय (v) के संबंध में अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले अंतिम कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) के अनुदानों की मांगों (2012-13) और (2013-14) (पंद्रहवीं लोक सभा) के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी चौबीसवें और बत्तीसवें प्रतिवेदन।
 - (2) उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2011-12), (2012-13) और (2013-14) (पंद्रहवीं लोक सभा) के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी बाईसवें, पच्चीसवें और इकत्तीसवें प्रतिवेदन।
-

अपराह्न 12.06 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

11वें से 14वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस (रायपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.06 ½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

117वां और 118वां प्रतिवेदन

श्री सुल्तान अहमद (उल्बेरिया): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 117वीं रिपोर्ट।
- (2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 118वीं रिपोर्ट।

अपराह्न 12.07 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

268वां और 269वां प्रतिवेदन

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2015-16(मांग संख्या 108) के बारे में 268 वीं रिपोर्ट।
- (2) खेलकूद विभाग की अनुदानों की मांगों 2015-16 (मांग संख्या 109) के बारे में 269 वीं रिपोर्ट।

अपराह्न 12.07 ½ बजे**परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति**

218वां से 222वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट) : माननीय अध्यक्षा जी, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 218वां प्रतिवेदन।
- (2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 219वां प्रतिवेदन।
- (3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 220वां प्रतिवेदन।
- (4) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 221वां प्रतिवेदन।
- (5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 222वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.08 बजे**कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति**

75वां और 76वां प्रतिवेदन

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 75वां प्रतिवेदन

(2) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2015-16) के बारे में 76 वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 ½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति* ।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्षा जी, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूँ।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) निःशक्तता कार्य विभाग (अब निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें और 40वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 2395/16/15

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 2396/16/15

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निःशक्तता कार्य विभाग (अब निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें और 40वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूँ।

[अनुवाद]

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित 'उर्वरकों के मूल्य निर्धारण' पर रसायन और उर्वरकों पर स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीया अध्यक्ष जी, मैं उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "उर्वरकों का मूल्य निर्धारण" के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूँ।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 2397/16/15

माननीय अध्यक्ष : मैं दे दूंगी। यह परिपाटी मत बनाओ कि तुरंत दे दूंगी। मुझे मालूम है। बैठिए।

... [अनुवाद] (व्यवधान)

श्री गौतम सिकंदर रेड्डी(नलगोन्डा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कोडाड-मिर्यालागुडा-देवरकोंडा-कल्वकुर्ती सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत करने के मामले में माननीय सड़क और परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह एक लंबे समय से लंबित अनुरोध है जिसे तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रस्तावित किया गया है। यह पिछड़े क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रों को खोलने में मदद करेगा और औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा देने में मदद करेगा और इस तरह अंतर-राज्यीय संपर्क प्रदान करने के अलावा, राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देगा। सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों, प्रमुख बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों को कवर करने के लिए सड़क अवसंरचना का विकास करना आवश्यक है। यह राजधानी शहर से पड़ोसी राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को संपर्क प्रदान करने में मदद करेगा जिससे इस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। दुर्घटनाओं से बचने के लिए भी यह आवश्यक है। बार-बार पत्राचार और माननीय मंत्री को उनकी मंजूरी के लिए अपील किए जाने के बावजूद, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तेलंगाना की नई सरकार ने भी यह प्रस्ताव नए सिरे से भेजा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में आवश्यक आवंटन करके उपरोक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की संभावनाओं का पता लगाएं।

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस मुद्दे को उठाने से पहले मैं अपनी नेता पुरात्वी थलाइवी अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, तमिल एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है। भारतीय राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में इसका आधिकारिक दर्जा है। तमिल श्रीलंका की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा भी है और सिंगापुर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे एक भाषा के रूप में भी वैध बनाया गया है और यह मलेशिया के स्कूलों में शिक्षा का एक माध्यम है। यह मुख्य

रूप से दक्षिण भारत में माध्यमिक भाषाओं में से एक के रूप में बोली जाती है। यह 2004 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित होने वाली पहली भारतीय भाषा थी।

तमिल भाषा को निचली अदालतों और उच्च न्यायालय की भाषा बनाने के लिए तमिलनाडु में जोरदार आवाजें उठ रही हैं। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने अदालतों में तमिल में बहस को खारिज कर दिया और कहा कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा “अंग्रेजी में होगी”।

संविधान स्पष्ट है। अंग्रेजी का उपयोग सभी आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है। यह समझ में आता है। भारत में कानून की भाषा अंग्रेजी है। लेकिन अब तक केवल चार उच्च न्यायालयों – राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में – ने हिंदी भाषा का उपयोग किया है। कुछ उच्च न्यायालयों में हिंदी के लिए अनूठा भत्ता देश के तमिल बोलने वालों के लिए एक नुकसान है, जो लंबे समय से उत्तर से हिंदी अतिक्रमण का विरोध करते रहे हैं।

हमारी माननीय नेता अम्मा ने पहले राष्ट्रीय सांसदों से मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश करने की अनुमति देने का आह्वान किया था। अम्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हमें न्याय के प्रशासन को वास्तव में लोगों के करीब ले जाना है, तो यह बिल्कुल जरूरी है कि स्थानीय भाषा का उपयोग उच्च न्यायालय में किया जाए जैसा कि पहले से ही राज्य सरकार और विधानमंडल द्वारा किया जा रहा है।

महोदया, इसलिए मैं सरकार से मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा को अदालत की भाषा के रूप में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने का आग्रह करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस पर अभी बहस नहीं हो सकती है, अगर आप एसोसिएट करना चाहें, तो कर सकते हैं। श्री केशव प्रसाद मौर्य ।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। जैसा कि सम्पूर्ण सदन जानता है, इलाहाबाद में विश्वप्रसिद्ध, संसार का सबसे बड़ा कुम्भ मेला लगता है, जहां दस करोड़ से अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। प्रत्येक वर्ष वहां माघ मेले का भी आयोजन होता है जिसमें पांच करोड़ से अधिक संख्या में तीर्थयात्री अलग-अलग स्नान पर्वों पर एकत्र होते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था सदैव बहुत खराब रहती है। जब भी कोई बड़ा मेला होता है तो वहां ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं जिनसे तीर्थयात्रियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश सरकार के माध्यम से वहां की व्यवस्था संभलती नहीं है। चूंकि यह बहुत बड़ा मेला क्षेत्र है, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि शहरी विकास मंत्रालय केन्द्र के अधीन वहां व्यवस्था कराए और वहां के लिए संगम मेला प्राधिकरण का गठन किया जाए।

वहां पर एक किला है, जहां अक्षयवट है, जहां बिन्दुमाधव का...(व्यवधान) वह किला सेना के कब्जे में है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि उसे खाली कराया जाए। इसी तरह से प्रयाग में नेहरू पार्क भी सेना के कब्जे में है, उसे भी खाली कराने की मांग करता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात हो गयी है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य: अध्यक्ष महोदया, हेतापट्टी से सलोरी, कुड़ेसर घाट से फतेहपुर घाट, मलाकराड़ से टी.पी. नगर के लिए गंगा जी पर छः लेन के सेतु का निर्माण हो एवं असरावे पूर्व से इलाहाबाद-चित्रकूट मार्ग को जोड़ने के लिए छः लेन के सेतु का निर्माण किया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतनी मांगें एक साथ नहीं रखिए।

श्री केशव प्रसाद मौर्य: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, आप बोलिए - नहीं बोल रहे हैं।

श्री गौरव गोगोई, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नेट तटस्थता पर एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप (जौनपुर): महोदया, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपका नाम दो बार बुलाया है। अभी बैठिए।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई : यह प्रक्रिया एक विवादास्पद प्रस्ताव पर केंद्रित थी जहां दूरसंचार प्रदाताओं को इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा पसंद की जाने वाली सामग्री का चयन करने का अवसर मिलता है। कांग्रेस नेता, श्री राहुल गांधी ने कहा था कि यह प्रस्ताव प्रत्येक भारतीय नागरिक के मुफ्त इंटरनेट के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। उनकी आवाज उन दस लाख लोगों को समर्थन देती है जिन्होंने नेट तटस्थता की मांग करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को लिखा है।

कल, एक गंभीर त्रुटि में, टी.आर.ए.आई. ने इन सभी दस लाख कार्यकर्ताओं के नाम और ई-मेल पते प्रकाशित किए थे। इस अपराध की गंभीरता का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब सभा कल्पना करे कि

अगर कोई बैंक अपने सभी खाताधारकों के नाम और खाते का विवरण लीक कर देता है तो क्या होगा। यही नुकसान इन दस लाख कार्यकर्ताओं को हुआ है। नाम और ई-मेल पते अब हैकर्स, ऑनलाइन अपराधियों, साइबर अपराधों, स्पैमिंग, आदि के संपर्क में हैं। इसलिए, इसने इन दस लाख कार्यकर्ताओं के लिए बोझ बढ़ा दिया है जो नेट तटस्थता के मूल अधिकार की मांग कर रहे थे।

मैं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह निकाय की कड़ी जांच शुरू करें, सुरक्षा प्रक्रियाओं में खामियों की पहचान करें और इन दस लाख नागरिकों के लिए सुरक्षा के अधिकार और ऑनलाइन गोपनीयता से समझौता क्यों किया है। टी.आर.ए.आई. की जांच होनी चाहिए और मंत्रालय को इन दस लाख कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहिए जो नेट निरपेक्षता पर बड़े कॉरपोरेट्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह जनता के साथ खड़ी रहे न कि बड़े कॉरपोरेट्स के साथ। ...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप श्री गौरव गोगोई के साथ जुड़ सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. के. बीजू, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री जोस के. मणि, अधिवक्ता जॉयस जॉर्ज, डॉ. ए. संपत, श्रीमती पी.के. श्रीमती शिक्षक, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और प्रो. सुगाता बोस और श्री मोहम्मद बदरुद्दूजा खान को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कृष्ण प्रताप सिंह।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप: अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री कृष्ण प्रताप सिंह जो कहते हैं, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: आप सभी श्री गोगोई के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे, कृपया अपनी सीट पर बैठें। कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप: अध्यक्ष महोदया, आज किसानों की फसलों का प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बैठिए। मैं आप लोगों की बात समझ गयी हूं। आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रताप: वहां किसानों को सौ- दो सौ रुपये के चेक दिए जा रहे हैं।...(व्यवधान) वे चेक भी बाउंस हो गए हैं।...(व्यवधान) राजस्व विभाग और लेखपालों की मिलीभगत के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश में

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

एक ही क्षेत्रफल पर, एक जैसी भूमि पर कहीं अधिक मुआवजा दिया जा रहा है और कहीं पर कम मुआवजा दिया जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत दुबे जी, आप बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है। आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रताप : मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से इसकी जांच कराने की मांग करता हूं। इसके लिए एक कमेटी गठित करने की मांग करता हूं। भविष्य में किसानों का ऐसा नुकसान न हो, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई कमेटी बनाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, आप कृपया माननीय मंत्री जी को एक बयान देने का निर्देश दें... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। [हिन्दी] मैं जीरो ऑवर में इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। प्लीज, बैठिए। ऐसा होता है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप : भविष्य में किसानों को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए कोई कमेटी केन्द्र सरकार बनाए, जिससे किसानों को मुआवजा सीधे पहुंचाया जा सके, किसानों को सीधे लाभ मिल सके और उत्तर

प्रदेश में जो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी केन्द्र सरकार किसी केन्द्रीय समिति द्वारा जांच कराए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको इश्यू उठाने का मौका दिया था, आपने अपनी बात कह दी है। मैं हर समय सरकार को कम्पेल नहीं कर सकती। आपने अपनी बात कह दी है अब आप बैठ जाएं। [अनुवाद] अगर सरकार जवाब देना चाहती है तो वे खुद जवाब देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप जुड़ सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती के. मरगथम (कांचीपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मुद्दा मेरे निर्वाचन-क्षेत्र का है।

सिरुसेरी पुराने महाबलीपुरम रोड के साथ नवलूर और केलम्बक्कम के बीच स्थित है और कांचीपुरम जिले में चेन्नई का एक दक्षिण-पूर्वी उपनगर है।

तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को विकसित करने के लिए 1971 में तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (एस.आई.पी.सी.ओ.टी.) की स्थापना की गई थी। अब, सिरुसेरी में लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आई.टी. पार्क है। इस पार्क में बिजली आपूर्ति के लिए अलग सब-स्टेशन, अलग टेलीफोन एक्सचेंज, आदि जैसी, सभी बुनियादी बुनियादी सुविधाएं हैं।

विभिन्न बहुराष्ट्रीय आई.टी. कंपनियां, जैसे कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड, 30,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ टी.सी.एस., शैक्षणिक संस्थान, जैसे प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान; शैक्षणिक संस्थान, जैसे चेन्नई गणितीय संस्थान; मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन और चेट्टीनाड अस्पताल और अनुसंधान संस्थान जैसे स्वास्थ्य संस्थान, यहां स्थित हैं। पूरे भारत से लोग सिरुसेरी आते हैं और यहां रह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: बस इतना ही। आपको पूरी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती के. मरगथम: हालांकि सिरुसेरी बस से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, लेकिन रेलवे की कोई सुविधा नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन वेलाचेरी है जो 17 किलोमीटर की दूरी पर है और चेन्नई 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह काफ़ी है। आपने अपनी बात कही है।

श्रीमती के. मरगथम: सिरुसेरी में एक रेलवे आरक्षण केंद्र की स्थापना से रेलवे और इसके राजस्व को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। मैं इस मुद्दे पर माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और जल्द से जल्द सिरुसेरी में रेलवे आरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं समाज के एक बहुत ही दलित और पिछड़े वर्ग की आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोरी जाति संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति में आती है। परन्तु कुछ स्थानों पर उसे अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। इस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में सहारनपुर में कोरी जाति के लोगों को हमारे प्रयासों के बावजूद भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि न तो इन जाति के बच्चों को एडमिशन मिल पा रहा है और न ही उन्हें नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिल पा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे भी इन्हें नहीं मिल रही हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए जाएं और जो आधिकारी उनके हक को छीनने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री देवजी एम. पटेल को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद] श्रीमती एम. वसन्ती। आपको पूरा कागज नहीं पढ़ना चाहिए। आप सभी इस तरह पढ़ रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती एम. वसन्ती (तेनकासी): मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। मकल मुदलवर पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने बीड़ी श्रमिकों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।

बीड़ी रोलिंग मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवार का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हजारों स्कूल जाने वाले बच्चे भी अपने स्कूल के घंटों के बाद इस सामूहिक पारिवारिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। स्कूली बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा छात्रवृत्ति बहुत कम है और इससे केवल कुछ ही बच्चे लाभान्वित होते हैं। इससे श्रमिकों के बीच असमानता पैदा होती है। बीड़ी मजदूरों के ये गरीब बच्चे अब अपर्याप्त छात्रवृत्ति राशि के कारण घोर गरीबी और वंचितता से जूझ रहे हैं। वे अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं क्योंकि यह राशि उनकी रोजमर्रा की रोटी के लिए खर्च की जा रही है।

इसलिए, मैं केंद्रीय श्रम कल्याण मंत्रालय से शैक्षिक छात्रवृत्ति की राशि और बच्चों की संख्या तुरंत बढ़ाने का आग्रह करता हूं। ... (व्यवधान) कृपया मुझे एक मिनट और दें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, एक मिनट भी नहीं। आपको पढ़ना नहीं चाहिए। यह बात मैं आपको हमेशा बताती हूं।

श्रीमती एम. वसन्ती: बीड़ी श्रमिकों के लिए बने अलंगुलम, सुरंदई में डिस्पेंसरी को उन्नत करना भी आवश्यक है क्योंकि यह इन श्रमिकों और परिवार के सदस्यों को अन्य अस्पतालों में संदर्भित किए बिना आसानी से समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से वंचित करता है। इसके अलावा, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बीड़ी श्रमिकों के लिए और अधिक आवासों का निर्माण किया जाए। प्रत्येक आवास इकाई में बिजली, पीने का पानी और स्वच्छता के लिए पानी, जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।

इसलिए, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम कल्याण मंत्रालय से इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, आपने सुरेश जी का अडजर्नमेंट मोशन भी स्वीकार नहीं किया है, फिर कॉलिंग अटेंशन भी नहीं आया है, उनको जीरो ऑवर में बोलने का मौका दे दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं उनको बोलने का मौका दूंगी। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कई सदस्य यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): महोदया, मुझे बोलने के लिए बुलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सरकार द्वारा मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में एन.एच.-183ए नामक एक नया राजमार्ग पहले ही घोषित किया जा चुका है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको 'ना' नहीं कह रही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री एंटो एन्टोनी : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से 110 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र से गुजर रहा है।

माननीय अध्यक्ष: अन्यथा, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी।

... (व्यवधान)

श्री एंटो एन्टोनी : नए राजमार्ग का महत्व यह है कि यह सबरीमाला पवित्र मंदिर के पास से गुजर रहा है। आप जानते हैं कि हर वर्ष चार करोड़ से अधिक तीर्थयात्री सबरीमाला जाते हैं। हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की हाल ही में केरल की यात्रा हुई थी। उस यात्रा के दौरान, उन्होंने केरल सरकार और मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सबरीमाला के पास से गुजरने वाले, इस राजमार्ग का काम इस वर्ष निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा और पूरी राशि इसी साल स्वीकृत कर दी जाएगी। उन्होंने केरल में खुले तौर पर इसकी घोषणा की।

महोदया, मैं आपके माध्यम से, सरकार से, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि नए राजमार्ग एन. एच.-183ए. का निर्माण इसी वर्ष शुरू हो। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में आश्वासन दे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सभी से निवेदन है कि शॉर्ट में बोलें, तभी सभी बोल पाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री जी को भी रिप्लाय देना है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्षा जी, गंगा अनादि काल से मानव जीवन के लिए जीवनदायिनी और प्रेरणा का स्रोत रही है। गंगा जीवन है, लेकिन आज गंगा प्रदूषित हो रही है। गंगा का जल अमृत है और इसकी एक बूंद हजारों-लाखों व्याधियों से लड़ने की क्षमता रखती है। आज गंगा लगभग 46 जिलों से होकर गुजर रही है। 15 लाख शौचालय विहीन घर हैं, ऐसी स्थिति में गंगा के जितने भी तट हैं, वहां पीने के पानी की गुणवत्ता गिर रही है। पीने का सही पानी नहीं है, क्योंकि उसमें सीवरेज गिर रहा है। यह स्वास्थ्य के विरुद्ध भी है, इसलिए स्थानीय निकाय और पंचायतों के साथ मिल कर निजी क्षेत्र की सहायता से शौचालय विहीन क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर शौचालय बनाए जाएं। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र बनाए जाएं, जिससे गंगा का जल स्वच्छ और पवित्र रखा जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्री पी.पी.चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोख सिंह चौधरी।

श्री अधीर रंजन चौधरी।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदया, सभा स्थानीय नगर निगम और निगम चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई भयावह घटना से परिचित है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। आपने तत्काल चुनाव सुधारों की मांग की है। आपको केवल उसी मुद्दे को उठाना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. वीरेन्द्र कुमार। कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: यह सब ठीक है। कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों की कठिनाइयों के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) आज विकास की अंधी और भौतिक दौड़ में ईंट और पत्थर के विशालकाय जंगल खड़े होते चले जा रहे हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है कि विरेन्द्र जी, संतोख जी वहाँ हैं। [हिन्दी] संतोख जी आप नाम बुलाने पर खड़े नहीं हुए थे।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं पंजाब प्रांत से आता हूँ, जहां 70 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं। पिछले महीने बहुत भारी बारिश और ओले पड़े थे, जिसकी वजह से किसानों की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन एक बड़ी चिन्ताजनक स्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि मण्डियों में किसानों ने जब अपनी फसल लानी शुरू की तो पंजाब की मण्डियों में लाखों किसान अपनी फसल को लेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी परचेज नहीं की जा रही है। जो थोड़ी-बहुत परचेज हुई भी है तो लाखों की तादाद में बोरियां लिफ्ट नहीं हो रही हैं। 10.88 परसेंट की कट लगा कर फसल की खरीद हो रही है। एक बड़ा भारी कंप्यूजन प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार में चल रहा है। एफ.सी.आई. के साथ एक टसल चल रही है, जिसके कारण फसल को लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। एक बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गई है और पंजाब का किसान सड़कों पर आ गया है। कल सारे किसानों ने रेल पटरियों पर बैठकर रेल यात्राएं ठप की हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि फौरी तौर पर इस तरफ ध्यान दिया जाए और किसानों की फसल उठाई जाए तथा उसका जायज मूल्य दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ईंट भट्टा मजदूरों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज विकास की भौतिक और अंधी दौड़ में ईंट और पत्थरों के विशालकाय जंगल खड़े होते जा रहे हैं। अवैध रूप से लगने वाले इन ईंट भट्टों के जो कारखाने हैं, इनके कारण न केवल हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में जीव-जंतुओं के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। संगठित क्षेत्र में लगभग आठ प्रतिशत मजदूर हैं और असंगठित क्षेत्र में 92 प्रतिशत मजदूर काम करते हैं। ईंट-भट्टों में काम करने वाले मजदूर भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने चालीस कानून बनाये हैं, लेकिन ईंट भट्टा उद्योग में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए कोई कारगर कानून नहीं बनाया गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ईंट-भट्टा में दसियों तरह के काम किये जाते हैं, जिसमें लगभग 175 श्रमिक काम करते हैं और उसमें लगभग चालीस प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। चार साल से पांच साल का उनका बच्चा भी वहां पर काम करता है, लेकिन ईंट-भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के आशिक्षित होने के कारण उन्हें श्रम कानूनों की जानकारी नहीं होती है, इसके कारण वहां जो काम करने वाले स्थान होते हैं, वहां न तो आंगनबाड़ी होती है, न बालबाड़ी होती है, न स्कूल होता है और न पालनाघर होता है और वहां जो मजदूर काम करते हैं, वे अनेक तरह के चर्म रोगों और टी.बी. के शिकार हो जाते हैं और उनकी चिकित्सा की वहां कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 कहता है कि कोई मजदूर एक स्थान पर यदि छः महीने तक लगातार काम करता है तो उसके अस्वस्थ होने पर उसकी चिकित्सा की व्यवस्थाएं वहां के प्रबंधन को करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रम सुरक्षा कानूनों के पुख्ता प्रबंध किए जाएं और उनकी चिकित्सा की तथा उनके बच्चों की शिक्षा की वहां पर उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री नाना पटोले, श्री देवजी एम.पटेल, डा.किरीट सोलंकी, श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया, श्री निशिकान्त दुबे, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री पी.पी.चौधरी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डा.वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद] मैं आपको एक अवसर दे रही हूँ। कृपया कुछ समय इंतजार करें।

श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): महोदया, वेल्लोर जिले में पेयजल समस्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

वेल्लोर जिला पानी की दीर्घकालिक कमी के संकट का सामना कर रहा है। संकट से निपटने के लिए, हमारी पार्टी की प्रमुख डॉ. पुरात्वी थलाइवी अम्मा ने संयुक्त जलापूर्ति योजना नामक एक योजना की परिकल्पना की जो सलेम जिले के चेक्कनूर बांध से जोलारपेट, तिरुपत्तूर, वाणियाम्बडी, अंबुर, गुडियाट्टम, वेल्लोर, कटपडी, रानीपेट, वालाजापेट और अरकोनम तक 313 किलोमीटर की दूरी पर पानी लाती है जिससे वेल्लोर निगम, 11 नगर पालिकाओं, पांच नगर पंचायतों के साथ-साथ 944 ग्राम बस्तियों में रहने वाले लगभग 20 लाख लोगों की कुल आबादी लाभान्वित होगी। हालांकि यह योजना लगभग पूरी हो चुकी है, फिर भी, राष्ट्रीय राजमार्ग-46, राष्ट्रीय राजमार्ग-4 और राष्ट्रीय राजमार्ग-234, के साथ-साथ कुछ स्थानों पर, पाइप लाइन बिछानी है। टी.डब्ल्यू.ए.डी. बोर्ड, जिसे इस परियोजना के निष्पादन का काम सौंपा गया है, ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से संपर्क किया ताकि कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर सड़क के साथ-साथ पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्राप्त की जा सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विशेष रूप से, कृष्णगिरी में मुख्य अभियंता और परियोजना निदेशक ने इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर

दिया कि जब कांचीपुरम और श्रीपेरंबदूर के बीच इसी तरह की परियोजना का निष्पादन किया गया था, तो 3 करोड़ रुपये के परिव्यय का भुगतान किया जाना था।

अब, वेल्लोर जिले में स्थिति बहुत गंभीर है जिसमें तिरुवन्नामलाई के तीन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र शामिल हैं जो वेल्लोर जिले के साथ-साथ अरकोनम निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। एन.एच.ए.आई. और टी.डब्ल्यू.ए.डी. बोर्ड के बीच कलह के कारण, लोग इस अद्भुत योजना के फल को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो एक चुनौतीपूर्ण थी और जिसे रिकॉर्ड कम समय में लागू किया गया था।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग आवेदन पर यह दावा कर रहा है कि आवेदन के निपटान में श्रम शक्ति की कमी है। इसलिए, मैं संबंधित मंत्रालय से समस्या पर गौर करने और तुरंत समाधान खोजने का अनुरोध करूंगा।

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम): एमू पक्षी 1996 में भारत में आए थे। केंद्र सरकार और संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य ने किसानों को एमू पक्षी पालन के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय प्रचार किया है। भारत सरकार और नाबार्ड ने उत्साही किसानों को आश्वासन दिया है कि एमू की खेती बहुत उत्साहजनक होगी और किसानों को उच्च स्तर का लाभ मिलेगा। सरकार के दुष्प्रचार से आकर्षित होकर, लगभग 20,000 किसान एमू पक्षियों की खेती करने के लिए आगे आए हैं। पक्षियों, मांस, तेल और उसके उत्पादों, आदि को बेचने के लिए कोई बाजार सुविधा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों ने बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी तरह से अनदेखी की है, जिसके कारण किसानों को अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ा है। इस दयनीय स्थिति के कारण, कुछ किसान आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब एमू पक्षियों की खेती और उनके उत्पादों के लिए बाजार सुविधाएं नहीं बनाने के कारण हुआ। इसलिए, मैं, इस प्रतिष्ठित सभा के माध्यम से सरकार से ईमानदारी से अपील करता हूं कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और किसानों को बचाने के लिए एमू पक्षियों के कृषक समुदाय को संबोधित करे।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र बाँका उत्तरायण गंगा, अजगैवीनाथ से भोलेनाथ तक का दूरी तय करता है, उसी बीच में है। विश्व प्रसिद्ध 107 किलोमीटर की लंबी काँवड़ यात्रा के साथ पांव पैदल उत्तरायण गंगा, सुल्तानगंज से झारखण्ड के बैद्यनाथ धाम देवगढ़ तक की आस्थावान श्रद्धालु लोग यात्रा करते हैं। लगातार चार माह की यात्रा 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के नर-नारी, भाई-बहन, बूढ़े एवं बच्चे करते हैं। देश-विदेश से आस्थावान लोग लाखों की संख्या में आते हैं। बगल से नेपाल और भूटान से तथा देश के सभी राज्यों से लोग पांव-पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा सुल्तानगंज, तारापुर, बेलर, सुरिया, कटोरिया, चांदन, देवगढ़ होते हुए की जाती है। यह आस्था यात्रा की है, लेकिन वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय, यातायात सुविधा, सराय और अन्य व्यवस्था वहां बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। मेरी मांग है कि इसे राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। यह मांग बार-बार सदन में उठायी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर के इस विश्व प्रसिद्ध मेला की गरिमा को बढ़ाएं और साथ-साथ इसे राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। यह उत्तरायण गंगा से ले कर के देवगढ़, झारखण्ड तक की यात्रा 107 किलोमीटर तक की है और यह विश्व प्रसिद्ध मेला है, इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन (शिवगंगा): तमिलनाडु के दक्षिण मध्य क्षेत्र में शिवगंगई जिला एक पारंपरिक कृषि क्षेत्र है, जो वर्षा आधारित क्षेत्र है। सिंचाई के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए, जिले भर में चैनल वाले गाँव के तालाबों को बनाए रखने के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण किया गया है। भूजल क्षमता बढ़ाने और वर्षा जल को, प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने नदियों-कावेरी, वैगई, मणि मुट्टर, और कुंदर को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। माननीया *अम्मा*, के मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने, केंद्र को 5,166 करोड़

रुपये की परियोजना लागत प्रदान करने के अनुरोध के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ एक प्रस्ताव भेजा है। इस परियोजना से आठ जिलों – शिवगंगई, मदुरै, विरुदुनगर, तिरुचि, पुदुकोट्टई, तुतीकुडी, तंजावुर और रामनाथपुरम में 79,374 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। यह परियोजना तमिलनाडु की 17 नदियों को जोड़ेगी। इसलिए, मैं केंद्र से आग्रह करता हूँ कि वह अपनी मंजूरी दे और तमिलनाडु में बड़ी संख्या में किसानों को लाभान्वित करने के लिए जल्द से जल्द धन जारी करे।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलिककारा): माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में दलित अत्याचारों से संबंधित तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाने का मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं और गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी सदन में चर्चा की जा रही है। दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सक्रिय कदम गायब हैं।

महोदया, मुझे डर है कि अस्पृश्यता, विभिन्न रूपों में, अब सामने आ रही है। एन.डी.ए. सरकार के सत्ता में आने के बाद, दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया कोई आरोप न लगाएं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, हाल ही में, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक 13 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में भी, ... (व्यवधान) महोदया, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में, कुछ दलित छात्रों का उपयोग स्कूल प्रबंधन द्वारा शौचालयों की सफाई के लिए किया जाता था। ... (व्यवधान) हाल ही में हुई ये दोनों घटनाएं बहुत गंभीर और निंदनीय हैं। ... (व्यवधान) महोदया, मैंने पूरा नहीं किया है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान) हम अपने गणतंत्र की स्वतंत्रता के 67 साल बाद किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ... (व्यवधान) हमारे देश के कई हिस्सों में अस्पृश्यता व्याप्त है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह सामान्य तरीके से कुछ कह रहा है। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? वे मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? ... (व्यवधान)
तमिलनाडु में दलितों पर अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तमिलनाडु में, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ...
(व्यवधान) वे गुस्से में क्यों हैं? ... (व्यवधान) तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार दिन-प्रतिदिन
बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान) ये समाचार पत्रों की खबरें हैं। ... (व्यवधान)

डॉ. एम. थंबीदुरई (करूर) : महोदया, आंध्र प्रदेश में 20 आदिवासी लोगों की हत्या की गई है। वह इस मुद्दे को
क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर वह इतने ईमानदार हैं तो, उन्हें उस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, मैंने इन दो हालिया घटनाओं का उदाहरण के रूप में उल्लेख किया है।
उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास, एक 13 वर्षीय लड़की के साथ कुछ गैंगस्टरों ने बलात्कार किया। इसका भी मैंने
उल्लेख किया है। मैंने केवल तमिलनाडु का उल्लेख नहीं किया है। इस तरह के अत्याचार हर जगह हो रहे हैं।
इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने सामान्य तरीके से कुछ कहा है। समय-समय पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं
है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश, आपने अब पूरा कर लिया है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान सुरेश, कृपया मेरी बात सुनें।

... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, दलित अत्याचार एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह सामान्य तरीके से कहा कि ये चीजें देश में हर जगह हो रही हैं। अब गृह मंत्री गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देने जा रहे हैं। वह जो कहना चाहता है उसे कहने दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश जी, आपने अब पूरा कर लिया है। लेकिन यह राज्य या वह राज्य न कहें। किसी विशेष राज्य का उल्लेख न करें। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे सामान्य तरीके से कह सकते हैं। आप किसी विशेष राज्य की बात क्यों कर रहे हैं? फिर, हर किसी को उठने और यहाँ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, हमारे देश में प्रतिदिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। वे कहाँ जाएँगे? ... (व्यवधान) महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है और मैंने कॉलिंग अटेंशन के लिए नोटिस दिया है। आपने मुझे अनुमति नहीं दी है। लेकिन कम से कम मुझे 'शून्यकाल' में इस मुद्दे को उठाने का मौका दें? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे समझ नहीं आता कि आप सभी क्यों खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य स्थानों पर हुई हैं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, मैं देश के बीस हजार नौजवान छात्रों के भविष्य को लेकर सदन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप भी बोलने लगे। जरा एक सेकेंड रुकिए, पहले इनको शांति से बैठने तो दीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं कुछ नहीं कह रही हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है। तुम यहां आकर बैठ जाओ। आप इतने गुस्से में क्यों हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश जी, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। अब गृह मंत्री, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देंगे। वह इस पर ध्यान दे सकते हैं। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है। आप किसी विशेष राज्य की बात क्यों कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, उन्हें अपना बयान पूरा करने दें क्योंकि आपने सभी को पूरा करने की अनुमति दी है। उन्हें अपना बयान पूरा करने दें; फिर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं उन्हें अनुमति देती हूँ।

... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, यह ज्वलंत मुद्दा है। ... (व्यवधान) तमिलनाडु में हर जगह, अस्पृश्यता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): यह तरीका नहीं है। आप सब कह रहे हैं; श्री खड़गे जी कह रहे हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. एम. थंबीदुरई: वे केवल तमिलनाडु बता रहे हैं। केरल के बारे में क्या? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: इस तरह, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है। ये सब बातें क्या हो रही हैं? क्या आप इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं अथवा नहीं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): यह तरीका नहीं है। [हिन्दी] मैंने कहा किसी भी प्रदेश का नाम लेने की बजाय इन जनरल आप बात करे और कंप्लीट करे। क्यों किसी प्रदेश का नाम ले रहे हैं? [अनुवाद] कृपया ऐसा न करें। [हिन्दी] नहीं तो मैं किसी को अलाऊ नहीं कर सकती।

... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, मैं दो मिनट में पूरा करने जा रहा हूँ। यह एक ज्वलंत मुद्दा है। जहां तक दलित आदिवासी समुदाय का सवाल है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): यह तरीका नहीं है। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, मैं दो मिनट के अंदर पूरा करने जा रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): यह 'शून्य काल' है। दो मिनट नहीं; केवल आधा मिनट आपको लेना है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: आधा मिनट काफी नहीं है, महोदया। मुझे दो मिनट दें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): फिर, आप बैठ जाए। आप पूरा कर चुके हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): श्री आर. ध्रुवनारायण और श्री पी.के. बीजू को श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। केवल श्री प्रहलाद पटेल का बयान दर्ज किया जाएगा।

... (व्यवधान) ... *

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय स्तर पर 20 हजार छात्रों के भविष्य का मामला उठाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग ने जो परीक्षा के लिए एक कट ऑफ डेट 1 जनवरी, 2015 से बढ़ाकर 1 अगस्त, 2015 की है, उसके कारण देश के 20 हजार छात्रों का भविष्य खतरे में है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी चयन आयोग ने एक कंबाईंड ग्रेजुएट लैवल के एक्जामिनेशन की बात कही है जिसमें 1 जनवरी, 2015 के कट ऑफ डेट के बजाय 1 अगस्त, 2015 कर दिया गया है। इससे 20 हजार परीक्षार्थी उस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। वे छात्र मुझसे मिले थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि 1 जनवरी, 2015 ही तारीख रखी जाए। यह परीक्षा 2 मई को है और इसमें

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

समय कम है। इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करे ताकि 20 हजार छात्रों का भविष्य बच सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री पी.पी.चौधरी एवं श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : अध्यक्ष महोदया, मैं स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 में कुछ संशोधन करने का निवेदन करने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। मैं एक ऐसे शहर से आती हूँ जहाँ डेंसिटी के रूप में शहर बहुत बड़ा है लेकिन वह फैल नहीं सकता और हर वक्त ऊँचाई से बड़ा बनता है। वहाँ गत दो महीने से रैजिडेंट्स एसोसियेशंस और हाकर्स एसोसियेशंस में बहुत बड़ा शीत युद्ध चल रहा है। वह इसलिए चल रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट बनाया गया है, वह पापुलेशन डेंसिटी पर आधारित न करते हुए ईक्वली पूरे देश के लिए बनाया है। उससे मुम्बई जैसे शहर में और बहुत से ऐसे शहर जो बढ़ रहे हैं, उनमें दिक्कत है। हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है तो मुम्बई की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। आने वाले सन् 2030 तक मुम्बई की जनसंख्या 3 करोड़ तक बढ़ेगी और वर्ल्डज फोर्थ लाजैस्ट सिटी के रूप में मुम्बई शहर बनेगा। इस एक्ट में संशोधन की जरूरत इसलिए है कि यू.डी.पी.एफ.आई. ने आइडियल स्क्वायर मीटर पर कैपिटा स्पेस रेशियो परसन को 10 स्क्वायर मीटर रखा है। लेकिन मुम्बई में वह 0.99 है, मात्र 1 परसेंट भी वह पर परसन कैपिटा स्क्वायर मीटर जगह नहीं है। जब मुम्बई इस रूप से बढ़ नहीं सकती और लोग मुम्बई में हैं चूँकि आर्थिक राजधानी है और लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन जब मुम्बई में आते हैं तो घर भी छोटे होते हैं, रास्ते भी छोटे होते हैं, बढ़ नहीं सकते। तो स्टेशनों पर, छोटी छोटी गलियों में खुद स्ट्रीट वैंडर्स रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री जी ने स्ट्रीट वैंडर्स को एक प्रकार का मुद्रा बैंक के रूप में स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश की है। लेकिन दोनों का सम्मान हो, रहने वाले रेजिडेंशियल एसोसिएशन का भी हो तो इस संशोधन के लिए मैंने श्री वेंकैया नायडू जी को खत भेजा है। मुम्बई जैसे शहर में उस संशोधन में डेंसिटी के रूप से वे एक्ट बनायें तो ही म्युनिसिपल कारपोरेशन उस एक्ट को आगे बढ़ा सकती है और हॉकर्स जोन को उस रूप से मुम्बई में विस्तारित रूप दे सकती है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रहलाद सिंह पटेल, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्री अरविंद सावंत, श्री राहुल शेवाले और श्री पी.पी.चौधरी को श्रीमती पूनम महाजन के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे तटीय सुरक्षा में कई खामियों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए।

तटीय सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसका ध्यान भारतीय नौसेना द्वारा रखा जाना चाहिए। सी.ए.जी. द्वारा तटीय सुरक्षा में कई खामियां पाई गईं, जिसका खुलासा मार्च, 2014 में अपनी प्रतिवेदन में किया गया था प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों के साथ तटीय रेखा पर पर्याप्त तटीय पुलिस स्टेशन या चेक पोस्ट उपलब्ध नहीं हैं।

सी.ए.जी. ने यह भी देखा है कि समुद्र में नावों के नौवहन चैनल और स्थानों को समझने में चालक दल की मदद करने वाली जी.पी.एस. प्रणाली प्रभावी ढंग से स्थापित नहीं की जा रही है। गश्ती नौकाओं का ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। बहुत पहले 2005 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में 19 सी.पी.एस. को मंजूरी दी थी। सी.ए.जी. ने पाया कि नौ वर्षों के दौरान केवल एक चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है और पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इसका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। महोदया, 26/11 के हमले के बाद न्यूजीलैण्ड से चार उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री नौकाएं खरीदी गईं, जो रखरखाव की समस्या के कारण अप्रयुक्त पड़ी हैं।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को तत्काल देखें और सी.ए.जी. द्वारा बताई गई खामियों पर कार्रवाई करें।

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): श्री अरविंद सावंत, श्री विनायक भाऊराव राउत, श्री राम मोहन किंजरापु नायडू और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद। महोदया, होसुर से बेंगलुरु रोड एन.एच.-7 का हिस्सा है। का हिस्सा है। यह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेंगलुरु-होसुर रोड कृष्णागिरी जिले के होसुर शहर को जोड़ती है। यह चार से छह लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है।

होसुर बस स्टैंड से लगभग आठ किलोमीटर दूर जुजुवादी में बहुत सारे कारखाने स्थित हैं। यह अशोक लेलैंड इकाई-1 के विपरीत है। कारखाने के मजदूर और आम जनता दोनों तरफ से सड़क पार कर रहे हैं। अशोक लेलैंड इकाई-1 में लगभग 200 कारखाने, पाँच गाँव और 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर है। इसके दाहिनी ओर, लगभग 500 उद्योग और छोटे कारखाने और 10 मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।

दोनों तरफ रहने वाले लोग बिना किसी जीवन सुरक्षा के सड़क पार कर रहे हैं। तेज गति वाले वाहन कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए मृत्यु और हताहत होने जैसी कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। डिवाइडर न होने के कारण, पैदल चलने वालों को सड़क पार करने में काफी परेशानी हो रही है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह एन.एच.ए.आई. को इस विशेष बिंदु पर एक फ्लाईओवर या एक अंडरपास बनाने के निर्देश जारी करें।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैं इस सभा के समक्ष ई.पी.एफ. पेंशन भोगियों के संबंध में कुछ बहुत गंभीर मुद्दे रखना चाहूंगा।

हजारों ई.पी.एफ. पेंशनभोगी दिल्ली में आ चुके हैं। वे आंदोलन कर रहे हैं। वे लंबे समय से न्यूनतम पेंशन लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब वे सेवा में थे, तो उनके वेतन का एक हिस्सा उनके पेंशन खाते में जमा किया जाता था। यह विश्वास था कि उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आय मिलेगी। उन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही है। जहां तक कासरगोड और कन्नूर जिलों के बीड़ी मजदूरों का सवाल है, उन्हें 10

रुपये या 12 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। श्रम संबंधी स्थायी समिति ने उस स्थान का दौरा किया था और सरकार की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन स्थायी समिति की प्रतिवेदन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

लंबे आंदोलनों के बाद, पिछली सरकार एक निष्कर्ष पर पहुंची थी और मंत्रियों के एक समूह ने निर्णय लिया था कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। अधिकांश पेंशनभोगियों को यह पेंशन नहीं मिल रही है। लगभग 17 लाख पेंशनभोगियों को यह पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि उन्हें अन्य लाभ मिल रहे हैं। उनका आंदोलन न्यूनतम पेंशन लागू करने के लिए है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। जब वे सेवा में थे तो उन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया था, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में सभी सांसदों ने मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इसे एक गंभीर मुद्दे के रूप में ले क्योंकि यह उनके अस्तित्व का सवाल है।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सुगाता बोस, श्री पी.के. बीजू, डॉ. ए.संपत और श्रीमती पी. के. श्रीमती टीचर को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है। माननीय सदस्यगण, आज मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा।

अपराह्न 12.55 बजे**नियम 377 के अधीन मामले ***

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, नियम 377 के तहत मामलों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा के पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से बीस मिनट के भीतर मामले का पाठ सभा के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल उन मामलों को ही पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) राजस्थान को रावी और ब्यास नदियों को उसके आवंटित हिस्से के जल को जारी किये जाने हेतु उपयुक्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था, लेकिन राजस्थान को अभी तक उक्त समझौते के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने संपूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है, इसके बावजूद भाखड़ा-व्यास प्रबंधन मण्डल राजस्थान को 8.00 एम.ए.एफ जल ही आवंटन कर रहा है। राजस्थान ने अपने हिस्से के शेष 0.6 एम.ए.एफ. जल को देने के लिए केन्द्र, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को कई बार प्रतिवेदन दिए हैं, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान को उनके हिस्से का पूर्ण पानी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब विधान सभा द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 पारित कर रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता व रावी-व्यास जल से

* पटल पर रखा माना गया

संबंधित सभी समझौते शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसीडेन्शियल रेफरेन्स द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता के परीक्षण हेतु भिजवाया है तथा राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उक्त रेफरेन्स की एक विशेष पीठ का गठन किया जावे। मेरी सरकार से मांग है कि भारत सरकार पंजाब सरकार/भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को राजस्थान के शेष 0.6 एम.ए.एफ. पानी दिए जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा साथ ही रावी-व्यास जल पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर शीघ्र निर्णय हेतु एक विशेष पीठ गठित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निवेदन करें।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 को चार लेनों में परिवर्तित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : एनएच-98 बिहार की राजधानी पटना से शुरू होकर दो जिला मुख्यालयों अरवल और औरंगाबाद (बिहार) एवं दो-दो अनुमंडल मुख्यालयों दाऊदनगर एवं छतरपुर (झारखंड) को जोड़ते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ (जिला सरगुजा, आम्बिकापुर) को जाती है अर्थात् यह सड़क तीन-तीन राज्यों तथा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का संपर्क पथ है।

वर्तमान में यह पथ किलोमीटर-15 (नौबतपुर) से लगभग किलोमीटर-33 (पतूत, पटना) तक मात्र 12 फीट चौड़ी है। किलोमीटर-33 से किलोमीटर-50 तक सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। किलोमीटर-70 से किलोमीटर-132 तक सड़क लगभग 16 फीट चौड़ी है, जिसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती और किलोमीटर-132 से किलोमीटर-156 तक यानी बिहार, झारखंड की सीमा से आगे झारखंड राज्य में भी इसकी स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिसके कारण आम लोगों को यात्रा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

यह राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड को जोड़ने वाला मुख्य पथ ही नहीं वरन् उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा मध्य प्रदेश के भोपाल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग होने के कारण पांच राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को सड़क मार्ग से जोड़ती है। इस पथ पर छोटे-बड़े, निजी और व्यावसायिक गाड़ियां काफी संख्या में चलती है, इसलिए आग्रह करना चाहूंगा कि एनएच-98 के महत्व को देखते हुए जनहित में इसे चारपथीय सड़क (फोर लेन) बनाने की महती कृपा की जाए।

अभी दो लेन का काम हो रहा है -

1. निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं कही जा सकती।
2. कार्य की गति भी काफी धीमी है।

(तीन) बीज विधेयक, 2004 को अधिनियमित करने तथा स्वदेशी बीजों के संरक्षण हेतु उपयुक्त कदम

उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : मैं सरकार का ध्यान हाइब्रिड बीजों से भरे पटे बाजारों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ जहाँ देशी परंपरागत बीज विलुप्त होते जा रहे हैं। किसानों को अपने अन्न, सब्जी और फलों के लिए हाइब्रिड विदेशी बीज ही खरीदना पड़ता है और यह बीज किसान स्वयं अपने खेत में पैदा नहीं कर सकता जिस कारण किसान को हर फसल के लिए बीज खरीदने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। यह बीज काफी महंगा होता है जिस कारण किसान को सब्जी या अन्य उत्पादन में लागत मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस स्थिति में भी किसान को सही प्रमाणित बीज भी नहीं मिल पाता है। कभी-कभी बीज खराब या फेल भी हो जाता है और फसल बेकार हो जाती है जिसके कारण किसान की मेहनत, परिश्रम, खेत की जुताई, पानी बेकार चला जाता है और किसान बीज महंगा होने के कारण पुनः बीज खरीदने की स्थिति में नहीं रह पाता। बीज फेल होने के कारण सब्जी कृषि का कार्य और लगातार घाटे का सौदा होता जा रहा है। बाजार में दुकानदार कंपनी का फर्जी पैकिंग कर नकली बीज बिना प्रमाणित सख्त कानून न होने के कारण खुले आम बेच रहे हैं। किसान अपना परंपरागत देशी बीज अपने खेत में स्वयं अगली फसल के लिए पैदा कर लेता था और ज्यादा होने पर उसे बीज के रूप में अन्य को बेच भी देता था जिससे किसानों को हर फसल के लिए बीज खरीदना नहीं पड़ता था और किसानों को अपना बीज होने के कारण, बीज खराब या फेल होने की संभावना नहीं रहती थी। देशी बीज के द्वारा उत्पादित अन्न, सब्जी, फल आदि में स्वाद भी होता है और शरीर को ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है। विदेशी हाइब्रिड के द्वारा उत्पादित अन्न, फल, सब्जी आदि में न तो स्वाद ही होता है और न ही शरीर को उचित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, केवल पेट ही भरता है।

अतः सरकार से प्रार्थना है कि किसानों और स्वास्थ्य की चिंता करते हुए विलुप्त होती जा रही परंपरागत देशी बीज के संरक्षण के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाए और सन् 2004 से लंबित बीज विधेयक को सदन में ऐसा बीज विधेयक लाकर जिसमें सख्त कानून का प्रावधान हो जिससे किसानों को फर्जी, नकली बीज देकर विक्रेता द्वारा ठगा न जा सके, बीज फेल या खराब निकलने पर किसान की मेहनत, जुताई, पानी, खाद आदि की भी भरपाई हो सके।

(चार) राजस्थान में लोहारू-झुंझुनू-सीकर-जयपुर रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के काम में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनू से गुजरने वाली रेल लाइन लोहारू-झुंझुनू-सीकर-जयपुर रेलवे ट्रैक का आमान परिवर्तन का कार्य काफी लंबे समय से लंबित है, जिसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। जिसका कारण क्षेत्रीय लोगों को काफी असुविधा हो रही है। इसके साथ ही साथ निर्माण कार्य की लागत भी बढ़ रही है।

अतः रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर रेलगाड़ियाँ चलवाने की कृपा करें।

(पाँच) रांची और नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस रेल सेवा प्रतिदिन चलाये जाने तथा रांची और दिल्ली/मुंबई के बीच विमान सेवा की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : झारखंड की गिनती आज देश के पिछड़े राज्यों में होती है। इसके अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण यातायात की सुविधा का अभाव भी है। आज देश के आधिकांश राज्यों में सुपरफास्ट ट्रेन तथा राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि चलती है। परंतु झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां से प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस नहीं है। सप्ताह में 4 दिन ही राजधानी एक्सप्रेस रांची से खुलकर नई दिल्ली आती है वह भी दो विभिन्न मार्गों से होकर।

झारखंड राज्य के चक्रधरपुर डिवीजन एवं धनबाद डिवीजन देश में सबसे अधिक रेलवे को रेवेन्यू देने वाले डिवीजन हैं। अनेकों थर्मल पावर स्टेशनों को कोयला की आपूर्ति करने वाला राज्य झारखंड है। बावजूद इसके रांची - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में प्रत्येक दिन नहीं है।

यही स्थिति वायुयानों की है। फ्लाइट्स की संख्या इतनी कम है कि कोई भी व्यक्ति सुबह रांची पहुंचकर दिनभर अपने कार्यों को निपटारा कर रात्रि में वापस दिल्ली/मुंबई नहीं जा सकता है। नतीजा यह है कि एक्स.एल.आर.आई. जमशेदपुर जैसे इंस्टीट्यूट से उत्तीर्ण छात्र बड़ी-बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट से वंचित रह जाते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में प्रतिदिन चलाया जाए एवं वायुयानों की संख्या बढ़ाई जाए एवं ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी व्यक्ति सुबह जाकर अपने कार्यों का निपटारा कर दिल्ली/मुंबई रात्रि में वापस हो सके।

(छः) अहमदाबाद और खेडब्रह्मा के बीच रेल सेवा को राजस्थान में अंबाजी होते हुए आबू तक बढ़ाये जाने तथा इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री डी.एस. राठौड़(साबरकांठा): मेरे साबरकांठा लोक सभा क्षेत्र में अहमदाबाद-खेडब्रह्मा रेलवे चल रही है। यहाँ विस्तार के नजदीक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ अम्बाजी मंदिर है जो समग्र भारत में आस्था का केन्द्र है और अम्बाजी के बिल्कुल नजदीक राजस्थान में माउंट आबू की तलहटी में विश्व प्रसिद्ध शांति केंद्र है जहां पूरे भारत और विश्व के लोग आते हैं। माउंट आबू स्वयं एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गुजरात और दक्षिण भारत के लोग अहमदाबाद से गुजरकर अम्बाजी और आबू जाते हैं। इसलिए अहमदाबाद से खेडब्रह्मा की रेलवे लाइन को अम्बाजी से आगे आबू रोड तक विकसित करने की जरूरत है जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोड़ ट्रैफिक कम करने में लाभदायी रहेगा।

मेरी खेडब्रह्मा से अम्बाजी और आबू तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन शुरू करने की मांग है।

**(सात) निजी अस्पतालों में निम्न आय वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के लिए
डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय/प्रक्रिया 'डायलिसिस' पर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि करोड़ों गरीब मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा है! आज दिल्ली के साथ सम्पूर्ण भारत वर्ष में लोग मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी संख्या दिल्ली देहात के इलाकों में कुछ ज्यादा ही है। मधुमेह की बीमारी से किडनी फेल होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसमें मरीज को जिंदा रखने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। उच्च आय वर्ग वाले मरीज तो अपना इलाज कराने में समर्थ हैं, लेकिन गरीब परिवार डायलिसिस कराने में असमर्थ हैं। सरकारी अस्पतालों में जब निम्न आय वर्ग/बीपीएल कार्ड धारक गरीब मरीज जाते हैं तो उन्हें वहां से डायलिसिस की मशीन खराब है या यह सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है, कहकर टाल दिया जाता है, जिसके कारणवश उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो इलाज में देरी होने से मरीज की मृत्यु तक हो जाती हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में सैंकड़ों लोग मेरे पास ऐसी शिकायतें लेकर रोज आते हैं। यह हाल तो दिल्ली राजधानी का है, तो सम्पूर्ण भारतवर्ष के गरीब वर्ग का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में ऐसे डायलिसिस केन्द्रों की संख्या में विस्तार किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ देश के सभी मेट्रो शहरों के निजी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी करें, जिससे निम्न आय वर्ग/ बीपीएल कार्ड धारक गरीब मरीज को फ्री डायलिसिस कराने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

(आठ) महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सैफन कार्ड धारकों को रियायतों दर पर
अनाज और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किफायती दर से मध्यमवर्गीय गैर लाभार्थी (सेफ्रॉन कार्ड धारक) ग्राहकों को आवंटित किए जाने वाले अनाज की आपूर्ति बंद करके और केरोसिन में 38 फीसदी कटौती करने का नवंबर 2014 से निर्णय लिया है। इससे देश के विशेषकर महाराष्ट्र के मध्यमवर्गीय गैरलाभार्थी 2 करोड़ ग्राहक जनता प्रभावित हुई है और उन्हें इससे असुविधा प्राप्त हो रही है। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा ध्यान देकर गैर लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने हेतु शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(नौ) मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल को राजभाषा के रूप में प्रयोग किये जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): मद्रास उच्च न्यायालय में आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल के उपयोग को अधिकृत करने की आम जनता की लंबे समय से मांग है।

बहुत पहले 2013 में, मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान, माननीय मक्कलिन मुदलवर, इध्या दैवम, पुरात्ची थलाइवी डॉ. अम्मा ने केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे कदम उठाने का आग्रह किया था ताकि तमिल को मद्रास उच्च न्यायालय में आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जा सके। न्याय के प्रशासन को वास्तव में न्याय के करीब ले जाने के लिए, यह बिल्कुल अनिवार्य है कि उच्च न्यायालय में स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाए।

देश का प्रत्येक सही सोच वाला व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यदि न्याय को लोगों के अनुकूल तरीके से प्रशासित किया जाना है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि उच्च न्यायालय में राज्य की स्थानीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

यदि तमिल को मद्रास उच्च न्यायालय में एक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो राज्य के अधिकांश गरीबवादियों को बहुत लाभ होगा क्योंकि वे वास्तव में वास्तविक अदालती कार्यवाही को समझने में सक्षम होंगे और आसानी से निर्णयों को समझने में भी सक्षम होंगे। राज्य की कानूनी बिरादरी भी इस कदम का समर्थन करती है।

इसलिए, मैं, केंद्र से उचित कदम उठाने और उच्चतम न्यायालय को भी शामिल करने का आग्रह करूंगा ताकि तमिल को मद्रास उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जा सके।

(दस) तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मनुष्यों और मवेशियों पर आक्रमण करने वाले आवारा घड़ियालों के लिये अस्थायी बचाव केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री ए. अरुणमणिदेवन (कुड्डालोर): मैं तमिलनाडु के, नेवेली में आवारा मगरमच्छों के लिए अस्थायी बचाव केंद्रों की स्थापना के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

कोल्लीडम नदी, वीरानम झील और इसकी नहरों में आवारा मगरमच्छ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जल निकायों में पाए जाने वाले इन आवारा मगरमच्छों के आक्रामक हमलों के कारण, बहुमूल्य मानव जीवन और जानवरों के नुकसान की कई घटनाएं हुई हैं। 8 अप्रैल की सुबह कुड्डालोर जिले के वेलाकुडी में, सालियांथोप गांव, चिदंबरम तालुक के मूल निवासी पर एक विशाल मगरमच्छ ने हमला किया। अभी तक उसके शव का पता नहीं चल सका है। घटना को देखने वाले लोग अभी भी भय मनोविकृति अधीन हैं। इस मगरमच्छ के खतरे को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। मैंने तुरंत एक अस्थायी बचाव केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। मैंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र लिखा है। कुड्डालोर के जिला, कलेक्टर ने भी संबंधित अधिकारियों के साथ मामला उठाया है। इसलिए, मैं, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे कुड्डालोर निर्वाचन क्षेत्र के नेवेली में आवारा मगरमच्छों के लिए तुरंत एक अस्थायी बचाव केंद्र स्थापित किया जाए ताकि मानव और पशुधन दोनों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा की जा सके।

(ग्यारह) ओडिशा में पर्याप्त संख्या में आई.पी.एस. अधिकारी आवंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): ओडिशा के आई.पी.एस. संवर्ग में कुल 188 पद हैं, जिनमें से 131 पद प्रत्यक्ष भर्ती के लिए हैं और 57 पद राज्य पुलिस सेवा कार्यालयों को आई.पी.एस. संवर्ग में पदोन्नत करने के लिए पदोन्नति कोटे के तहत हैं। प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए प्रदान किए गए 131 पदों में से, 107 अधिकारी अब 24 अधिकारियों की कमी के साथ पद पर हैं। पदोन्नति कोटे के तहत सभी 57 पद आई.पी.एस. कैडर में पदोन्नति के लिए योग्य राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण खाली पड़े हैं और अगले 8 से 10 वर्षों के भीतर इन रिक्तियों के भरने की संभावना भी कम है। 107 अधिकारियों में से, 21 अधिकारी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत हैं और 7 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए, राज्य में 128 वरिष्ठ ड्यूटी पदों के मुकाबले वास्तव में केवल 79 अधिकारी उपलब्ध हैं।

आई.पी.एस. अधिकारियों की भारी कमी के कारण, विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक के स्तर पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर हैं। कई जिलों के पुलिस प्रशासन के प्रबंधन के लिए आई.पी.एस. कैडर के पदों पर एस.पी. (प्रभारी) के रूप में तैनात किए जा रहे हैं।

राज्य में माओवादी हिंसा को ध्यान में रखते हुए, बढ़ती माओवादी गतिविधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अब युवा और ऊर्जावान अधिकारियों को एस.पी. के पद पर तैनात करना अनिवार्य महसूस किया जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सी.एस.ई.-2013 से कम से कम 7 आई.पी.एस. अधिकारियों को आवंटित किया जाए और अगले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष में 7/8 अधिकारियों को आवंटित किया जाए।

**(बारह) घरेलू विमान सेवा के परिचालन हेतु भागलपुर हवाई अड्डे का विकास किये जाने की
आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र भागलपुर हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। भागलपुर के लिए सबसे नजदीक हवाई अड्डा पटना है, जिसकी दूरी 270 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से जाने में लगभग सात घंटे का समय लगता है। भागलपुर एशिया का एक महत्वपूर्ण रेशम उद्योग नगरी है इसलिए भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में भी जाना जाता है। देश के विभिन्न भागों से रेशम के कपड़े के व्यापार के लिए लोगों का आना-जाना लगा रहता है। भागलपुर आने के लिए नजदीक में हवाई अड्डे का कोई अन्य विकल्प नहीं है। रेलगाड़ी से आने में काफी समय लगता है। यहां कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। जैसे विक्रमशिला, मन्दार हिल, तिलका मांझी, श्री चंपापुर दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र आदि सहित कई पर्यटक स्थलों को देखने की दृष्टि से भी लोग आते हैं। लेकिन हवाई मार्ग से जुड़े नहीं होने के कारण व्यापारी वर्ग तथा पर्यटकों को काफी असुविधा होती है। गंभीर रूप से बीमार अथवा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को आपात स्थिति में सड़क मार्ग से पटना ले जाना पड़ता है। इस दौरान समय पर इलाज नहीं होने से रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों के आलोक में भारत सरकार से मेरी मांग है कि भागलपुर स्थित हवाई अड्डे को विकसित कर अंतर्देशीय हवाई यात्रा के लिए विमानों का परिचालन प्रारंभ कराने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को आदेश देने की कृपा करने का कष्ट करें।

(तेरह) बिहार में विशेष रूप से नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनसीसी कैडेटों को उचित वर्दी प्रदान करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : नालंदा सहित पूरे बिहार में नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) छात्र-छात्राओं के लिए विगत 8 वर्षों से पोशाक नहीं मिली है। कभी-कभी 10-20 की संख्या में जूते मिल जाते हैं जबकि हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिहार शरीफ में 38वीं बिहार बटालियन का एन.सी.सी. कैम्प है, जिसमें नालंदा, नवादा, बाढ़ व बख्तियारपुर के लगभग 2 हजार 5 सौ छात्र-छात्राएँ जुड़े हैं।

एन.सी.सी. सेना की लघु इकाई मानी जाती है और सरकार कैडेटों के कैम्प, नाश्ते तथा ट्रेनिंग में भी काफी खर्च करती है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र जांच कराकर उन्हें पोशाक यानी शर्ट, पैंट, पी. टी. जूते, टोपी, मोजा और पी.टी. ड्रेस अतिशीघ्र दिया जाये।

(चौदह) करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही बेमौसम वर्षा के कारण फसल को हुए नुकसान का आकलन करने हेतु एक केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज): पूरी संसद किसानों को क्षतिपूर्ति देने के पक्ष में है। कृषि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, करीमगंज, असम के लोगों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। हाल की बेमौसम बारिश के कारण, सोनबिल में 4000 हेक्टेयर, रतबिल में 1500 हेक्टेयर, तपांग ब्लॉक क्षेत्र में 400 हेक्टेयर, चटला में 300 हेक्टेयर और बकरीहावर, बोरो में 100 हेक्टेयर कृषि भूमि, जलमग्न हो गई और फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय किसान अब आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत दयनीय स्थिति में हैं। भारत के अन्य हिस्सों की तरह, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में उनके पास आय का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, मैं केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उपर्युक्त बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण दल भेजें और हाल ही में सभा में सरकार की घोषणा के अनुसार पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करें।

(पंद्रह) संघर्ष से जूझ रहे देशों से निकाले गए भारतीय पैरामेडिकल के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाये
जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम): मैं भारत सरकार को यमन में लगभग 5000 लोगों को बचाने के लिए उसके त्वरित और कुशल संचालन के लिए बधाई देना चाहता हूं। केरल ऐसी स्थितियों में सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा है, जो अब अपनी निरंतर आवर्ती में बार-बार हो रही है। वर्षों से लीबिया, इराक, यमन आदि में संघर्ष क्षेत्रों से हजारों भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। इस पृष्ठभूमि में, मैं सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही योग्य पैरामेडिक्स की भर्ती की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस कदम का विस्तार बुनियादी ढांचा/निर्माण और ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाने वाले अधिकांश लोग पेशेवर हैं; ज्यादातर पैरामेडिक्स के पास चुकाने के लिए ऋण होता है और वे विदेश में नौकरी पाने के लिए एजेंटों को भुगतान करने वाली दलाली भी करते हैं। श्रमिक समुदाय के लिए भी यही सच है। उनके लिए विदेश जाना और काम करना एक मजबूरी बन जाता है, भले ही उन देशों में स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न बन जाए। केरल में, लोग नोरका के साथ पंजीकृत हैं जो एक सरकारी एजेंसी है। केंद्र सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो राज्य सरकार के साथ मिलकर सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और अन्य प्रासंगिक स्थानों में आरक्षण प्रदान करके या उन्हें अस्थायी पुनर्वास पैकेज देकर राज्य एजेंसियों में पंजीकृत लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करे। यह लोगों को राज्य एजेंसियों के साथ पंजीकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा ताकि आपात स्थिति के मामले में उनका पता लगाया जा सके और उन्हें संदिग्ध एजेंटों का शिकार होने से रोका जा सके।

अपराह 12.56 बजे**अनुदानों की मांग (सामान्य), 2015-16****(एक) गृह मंत्रालय – जारी ..**

माननीय अध्यक्ष: अब, हम मद सं 26 पर चर्चा करेंगे—आगे की चर्चा और गृह मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान की मांगों पर मतदान 2015-16 के लिए।

[हिन्दी]

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** मैं मान्यवर मंत्रीजी का ध्यान आजकल बढ़ रहे साइबर क्राइम की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी का एक कारण यह है कि आम जनता में जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है एवं वित्तीय संस्थान एवं पुलिस विभाग के बीच, एक पुलिस स्टेशन और एक बैंक की ब्रांच के स्तर पर जो तालमेल होना चाहिए उतना तालमेल हमारे देश में अभी तक बैठा नहीं है। मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि पुलिस विभाग में पुलिस स्टेशन के स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी इस विषय की जानकारी देने की योजना बनाई जानी चाहिए। साथ ही साथ, साइबर क्राइम के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कई बार एक ही व्यक्ति से दो या तीन बार चोरी के भी मामले सामने आते हैं। तब एक व्यक्ति पहले बैंक में सूचना देता है और उसके बाद पुलिस स्टेशन में सूचना देने जाता है। तब उसे पता चलता है कि इस पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन में वह ब्रांच नहीं आती। जब वो उस पुलिस स्टेशन में जाता है तब तक आरोपी नौ दो ग्यारह हो चुका होता है। इसलिए यह जरूरी बनता है कि बैंक में सूचना जाने के बाद बैंक की ओर से तुरंत उस विस्तार का जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें फोन द्वारा इस क्राइम की सूचना दी जानी चाहिए। बाद में आम व्यक्ति

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उस दिन में कभी भी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सके। इसलिए बैंकों के साथ तालमेल बढ़ाना और आम जनता में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाना और साइबर क्राइम की डीटेक्शन इन तीन बातों पर विशेष मुहिम चलाई जाए।

[अनुवाद]

***श्री एस. आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय):** मैं इस प्रतिष्ठित सभा में मुझे मध्य चेन्नई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए और वर्ष 2015-16 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए अपने प्रिय नेता माननीय मक्कलिन मुदलवर, इंदिरा देवम, पुरात्वी थलाइवी डॉ. अम्मा को धन्यवाद देता हूँ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर मामलों का विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, राजभाषा विभाग शामिल हैं। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भी इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

गृह मंत्रालय के लिए बजट अनुमान 62,124.52 करोड़ रुपये है, जिसमें से 7,371.90 करोड़ रुपये योजना परियोजना के लिए और 54,752.54 करोड़ रुपये गैर-योजना परियोजना के लिए हैं। इस विभाग के लिए कुल बजट अनुमानों में पिछले वित्त वर्ष 2014-15 के परियोजना की तुलना में 10.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई है। महिला सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। निर्भया कोष कॉर्पस को 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है। महिलाओं की सुरक्षा में किसी भी कदम का हम स्वागत करते हैं क्योंकि डॉ. अम्मा के नेतृत्व वाली ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी ने हमेशा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा का समर्थन किया है। डॉ. अम्मा की क्रेडल बेबी योजना दुर्भाग्यपूर्ण अवांछित परित्यक्त बच्चों की सुरक्षित परिवार सुनिश्चित करने के लिए थी। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भले ही जैविक माता-पिता शिशुओं को अस्वीकार कर दें, सरकार उनकी देखभाल करेगी।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के लिए आवंटन में वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है। चरम नागरिक उपद्रव, आतंकवादी, सांप्रदायिक और नक्सल तत्वों के कारण हिंसा के समय तैनात ये बल एक प्रशंसनीय भूमिका निभाते हैं और परिव्यय में वृद्धि योग्य है।

सी.बी.आई. और लोकपाल के परिव्यय में क्रमशः 10 और 7 प्रतिशत की वृद्धि एक प्रगतिशील कदम है।

इस मंत्रालय के तहत मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और इसे मादक पदार्थों के तस्करों की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह बताने के लिए लिखा है कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) के तहत किसी भी नए प्रस्ताव पर वित्त वर्ष में विचार नहीं किया जाएगा। यह एक दुखद विकास है। पुलिस आधुनिकीकरण के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में, वास्तव में, आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और राज्य सरकारों के पुलिस आधुनिकीकरण कार्य को जारी रखने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का आग्रह करूंगा। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय डॉ. अम्मा के मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार सभी महिला पुलिस थानों की स्थापना जैसे सराहनीय कार्य कर रही है और यह रिकॉर्ड पर है कि तमिलनाडु पुलिस महिला सुरक्षा के बारे में अत्यधिक संवेदनशील है। मैं चाहूंगा कि केंद्र सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सतर्क तमिलनाडु सरकार से प्रेरणा ले।

तटीय सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। लंबी तटरेखा वाले तमिलनाडु को तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिक केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। तमिलनाडु को और अधिक समुद्री पुलिस स्टेशनों, जेटी, समुद्री संचालन केंद्रों, नौकाओं, कठोर हवा वाली नौकाओं, चार पहिया वाहनों और मोटरसाइकिलों आदि की स्थापना के लिए और अधिक धन आवंटित किया जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा उपायों की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** मैं गृह मामलों के लिए अनुदान की मांग पर निम्नलिखित बिंदु रखना चाहता हूँ:-

- (1) बी.ए.डी.पी. की उचित समीक्षा की जानी चाहिए। सीमा 1-10 किमी की सीमा को बढ़ाकर 20 किमी या पूरे ब्लॉक को बी.ए.डी.पी. के तहत पात्र बनाया जाना चाहिए।
- (2) पुलिस सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री विद्युत बरन महतो (जमशेदपुर):** मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे गृह मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। हमारा देश बहुत बड़ा है और भारतवर्ष को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विगत कुछ वर्षों में हमारे देश के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, साम्प्रदायिक दंगे तथा कानून व्यवस्था से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। यह हम सबका दायित्व बनता है। अगर देश में इसी तरह की राजनीति की जाती रहेगी, तो देश की जो राष्ट्रीय समस्या है, जिस समस्या पर किसी सरकार का नहीं, किसी एक दल का नहीं, बल्कि सब लोगों को मिल करके इस समस्या का निदान करना पड़ेगा, वरना देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आज अपराध बढ़े हैं, समस्याएं हमारे सामने हैं।

पूरे झारखंड में नक्सलवाद ने व्यापक ढंग से घर करने का काम किया। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में दुखद घटना घटी। उड़ीसा में भी यह घटना घट रही है। कई ऐसे इलाके हैं, जहां नक्सलवाद की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या का निदान कैसे होगा, क्या इस पर हमने गहन चिन्तन करने का काम किया है? हमारे देश में कई तरह की असमानताएं हैं। गरीबी और अमीरी में इतना अंतर आ गया है, जिसकी वजह से वहां के लोग, किसान, बेरोजगार नौजवान अपनी हालत सुधारने के लिए इन सब गतिविधियों में आने का काम कर रहे हैं। जब तक देश में असमानता रहेगी, तब तक हम नक्सलवाद की गतिविधियां बंद नहीं कर सकते। हमारी असमानता में समानता कैसे आए, गैर-बराबरी कैसे दूर हो, विकास कैसे हो। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, जहां आज भी सड़कों, जल, बिजली एवं शिक्षा का अभाव है। इसलिए यह चिन्ता का विषय है और इस पर निश्चित तौर पर कारगर कदम उठाने चाहिए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):** गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, 2015-16 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि पुलिस अनिवार्यतः एक सार्वजनिक सेवा है और लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यह ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो सरकार की किसी भी अन्य एजेंसी की तुलना में जनसंख्या के बड़े हिस्से को उनके रोजमर्रा के जीवन में व्यापक रूप से प्रभावित करती है। पुलिस, नागरिक के लिए संपर्क का पहला प्रत्यक्ष बंधु है। यह एकमात्र एजेंसी है जिसके पास लोगों के साथ संपर्क का सबसे व्यापक अवसर है। इसलिए सार्वजनिक संस्था के रूप में पुलिस का गठन तथा सशक्तीकरण कानून द्वारा होता है। अतः पुलिस को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

राजस्थान में आम लोगों के बीच पुलिस की छवि को लेकर हुए एक अध्ययन से निम्न तथ्य उजागर हुआ। लोगों का मत था कि 11 प्रतिशत लोग ही कभी पुलिस से मिले जबकि 89 प्रतिशत लोगों का पुलिस से कभी सामना नहीं हुआ। इनमें से 24 प्रतिशत लोग शहरी और 17 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे। केवल 5 प्रतिशत महिलाएं ही पुलिस से कभी मिली थीं। यह जाहिर करता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा पुलिस से मिलने या बात करने से हिचकता है। इसमें 87 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पुलिस से कार्य कराने के बदले उन्होंने पुलिस को घूस दी है। अध्ययन में बताया गया कि लोग जब अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का रवैया बहुत उदासीन रहता है। इस कारण पैसा देकर अपना काम कराने को मजबूर होते हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें 70 प्रतिशत लोगों ने घूस देने के आतिरिक्त पुलिस से अपना काम सीधे नहीं बल्कि ऊपर से दबाव डालकर अथवा दलाल के माध्यम से करवाया। आज भ्रष्टाचार से पुलिस के प्रति जनता का विश्वास घटता है साथ ही कानून के शासन की प्रतिष्ठा गिरती है और कई अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इससे किसी पुलिस कर्मी के साथ पुलिस संगठन की छवि और प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। मेरा मानना है कि जब पुलिस राज्य सरकार के किसी अन्य सार्वजनिक कार्यालय यथा राजस्व नगरपालिका जलविभाग और विद्युत विभाग की तरह ही एक सार्वजनिक सेवा है तब लोग पुलिस थाने जाने और पुलिस से मिलने से डरते क्यों हैं? आज

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पुलिस स्टेशनों को ऐसे जन स्वागत केन्द्र में तब्दील करने की आवश्यकता है जहाँ लोग अपनी जरूरत पड़ने पर जा सके। अब समय की मांग है कि थानों का आधुनिकीकरण किया जाए। जहाँ सभी सुविधा उपलब्ध हो। इसी के अंतर्गत हमारी सरकार ने गृह मंत्रालय को पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक धन दिया है। यह आवंटन महिलाओं की सुरक्षा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया है। जागरूकता के कार्यक्रम को समर्थन देने के प्रयासों के तहत निर्भया फंड के लिए और 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। हमारी सरकार 17 राज्यों के 104 जिले के 367 ब्लॉकों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के अंतर्गत राज्यों को निधि अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से संबंधित विकास के कार्य पर जोर दिया जाता है परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित सांचौर तहसील को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि सांचौर तहसील को दिनांक 12 मार्च 1996 को सांचौर चितलवाना सर्वना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। सांचौर और चितलवाना प्रखंड के नागरिकों को प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से 1.5 किमी की दूरी पर चार गांव हैं, 10-15 किमी पर आठ गांव तथा 15-20 किमी पर 13 गांव स्थित हैं। इन गांवों में मूलभूत सुविधा का नितांत अभाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट वर्ष से सांचौर तहसील को इस फंड से विकास कार्य प्रारम्भ हो जाएंगे।

ठीक इसी प्रकार, देश की सीमाओं की निगरानी व देश के अंदर विभिन्न तरह से सुरक्षा में लगे अर्द्धसैनिक बल राष्ट्र की सेवा में समर्पित सेवा बल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान से लगी सीमा की सुरक्षा पूर्ण रूप में अर्द्धसैनिक बल हर जगह मुस्तैदी से तैनात है। हमारे देश के एक सजग प्रहरी है। देश के अंदर भी आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगा, प्राकृतिक विपदा, तीर्थ स्थलों की सुरक्षा एवं विषम परिस्थितियों में ये जवान राष्ट्र सेवा में डटे हुए हैं। लेकिन इन जवानों को वो सुविधा नहीं मिलती है जो सेना के जवानों को मिलती है। अतः मेरा आग्रह है कि अर्द्धसैनिक बलों को निम्न सुविधा जल्द से जल्द देने के लिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।

10 वर्ष पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट के तहत सेना के डिपो से दैनिक जरूरत का सामान मिलता है, परन्तु आजकल ये सुविधा बंद है जिससे अर्द्ध सैनिक बल के जवानों को काफी असुविधा होती है। यह सुविधा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तालमेल नहीं होने के कारण बहाल होने में देरी हो रही है। अतः कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट से अर्द्धसैनिक बलों के जवानों व उनके परिवार को दैनिक उपयोग के सभी सामान उपलब्ध कराए जाए।

अर्द्धसैनिक बलों के जवान हमेशा परिवार से दूर रहते हैं। अतः इनके बच्चों को नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में कोटा देकर इनका शत प्रतिशत नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के लिए प्रत्येक जिला में अर्द्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए, जिससे रिटायरमेंट के बाद इनके पुनर्वास का पूरा ख्याल रखा जाए। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, जिससे इनको पेंशन स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी मदद हो सके।

[अनुवाद]

***श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर):** गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है जो इस देश के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक प्रमुख मंत्रालय है और यह प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने का सवाल किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, भारत सरकार ने, वर्ष 2015-16, के इस वर्तमान बजट में गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए धन के आवंटन को कम कर दिया है।

सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां गृह मंत्रालय को चीजों को ध्यान में रखना है, वह है देश में पुलिस बल का आधुनिकीकरण, देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के कठिन कार्य से निपटने के लिए पुलिस को दी जाने

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वाली सुविधाओं और उन्हें प्रदान किए जाने वाले हथियारों और गोला-बारूद पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दोबारा, दुर्भाग्य से, इस साल के बजट में, पुलिस बल के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना के लिए ज्यादा धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

अगर हम देश में पुलिसकर्मियों के सामने आने वाली समस्याओं को देखें, तो बहुत कम युवा इस क्षेत्र में प्रवेश करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाएं आकर्षक नहीं हैं। पुलिस बल में युवा और ऊर्जावान लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। पुलिस के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक आवास की समस्या है। आम तौर पर लोग पुलिस कर्मियों के लिए किराए पर घर नहीं देते हैं। सभी स्थानों पर, भारत सरकार पुलिस कर्मियों को आवास की सुविधा प्रदान नहीं कर रही है। पुलिस कर्मियों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें आवास की सुविधा दी जाए।

भारत सरकार ने सीमा प्रबंधन के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए भी पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया है। अच्छे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए इस कार्यक्रम के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए था क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को आम तौर पर बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों की देखभाल करना भारत सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। अतः, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए सीमा प्रबंधन के लिए अधिक से अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय चक्रवात, भूकंप, आदि जैसी प्राकृतिक आपदा से, उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है। अगर हम इस प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए धन के आवंटन को देखें, तो एक बार फिर पूरी तरह से निराशा है। हाल ही में, हमने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आदि में चक्रवात हुड्डुद के दौरान एक कठिन स्थिति का सामना किया है। और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आदि में, हाल ही में आए भूकंपों में भी जान-माल का बहुत नुकसान हुआ, हालांकि संबंधित राज्य सरकारों ने स्थिति को अच्छी तरह से प्रबंधित किया, केंद्र सरकार पर भी बहुत उम्मीदें और जिम्मेदारियां थीं। इसलिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी अधिक धन का आवंटन करना आवश्यक है।

देश के कुछ हिस्सों में नक्सल गतिविधियां भी एक और खतरनाक कारक है जो आम जनता में भय पैदा करती है। भारत सरकार को भी अधिक धन उपलब्ध कराकर और आवंटित करके नक्सल विरोधी बल को मजबूत करने में अधिक रुचि लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** जैसाकि हम सभी जानते हैं कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों में प्रमुख रूप से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निधारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें।

गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्वों में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मानवाधिकारों के सिद्धांतों का संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती रेखा का प्रभावी रूप से प्रबंधन, आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा राहत प्रदान करना, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना, 10 वर्षीय जनगणना करना, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरुपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण करना एवं राजभाषा नीति का कार्यान्वयन के साथ-साथ भारतीय पुलिस सेवा नियमों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का उचित प्रशासन सुनिश्चित करना है।

किसी भी देश में व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एवं मजबूत, स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए शांति एवं सद्भावना आनिवार्य अपेक्षाएं होती हैं। इस उद्देश्य के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित बातों के लिए पूरा प्रयास करेगा।

इसके तहत किए जाने वाले भावी कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना, समाज को अपराध मुक्त वातावरण मुहैया कराना, सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नयन, कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी अपराधिक न्याय प्रणाली उपलब्ध कराना, मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा को बनाए रखना, केंद्र राज्य

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना तथा सुशासन को बनाए रखना, प्राकृतिक तथा मानव जनहित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग अनुकूल बनाना है।

सरकार के लिए वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद एक चुनौती बना हुआ है। इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से समग्र तरीके से निपटने का है जो कि एक प्रशंसनीय कदम है। क्योंकि किसी भी तरह की विध्वंसक गतिविधि से किसी भी राष्ट्र के विकास को आघात पहुंचाना है। दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने में संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श और बातचीत के बाद यह उचित समझा गया है कि इस संबंध में एक ऐसी एकीकृत योजना बनाई जाए जिसके अपेक्षित परिणाम निकले और इस दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता से अपना काम कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने का काम तेजी से कर रही है और सड़कों, सीमा चौकियों का निर्माण एवं तेज रोशनी करने का कार्य भी तीव्रता से कर रही है।

इस बार केन्द्रीय बजट में गृह मंत्रालय को 62124.52 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के आवंटन से 10.2 प्रतिशत ज्यादा है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह आवंटन महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत निर्भया फंड के लिए एक हजार करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के राहत और पुनर्वास के लिए बजट में 580 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वित्त वर्ष में 342.50 करोड़ रुपए का था। विश्व के विशालतम अर्द्ध सैनिक बल सी.आर.पी.एफ. जिन्हें अक्सर नक्सल विरोधी आभियान सहित आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है, को 14089.38 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस बल को 12866.12 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस लिहाज से इस बार के आवंटन में काफी वृद्धि की गई है।

भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करने के लिए तैनात किए जाने वाले बी.एस.एफ. को इस बार 12517.72 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि इस बल के लिए पिछले वित्त वर्ष में आवंटन 11717.46 करोड़ रुपए था। इसी तरह भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात आई.टी.बी.पी. के लिए पिछले वर्ष 3404.93 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 3736.47 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने देश के ज्यादातर हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, दिल्ली मेट्रो के अलावा कई अन्य की सुरक्षा के लिए भी तैनात किए जाने वाले सी.आई.एस.एफ. के लिए पिछले वर्ष के 4937.91 करोड़ रुपए की अपेक्षा इस बार 5196.65 करोड़ रुपए का आवंटन किया है जो कि एक स्वागतयोग्य कदम है।

इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ, मैं गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

***श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर):** गृह मंत्रालय सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। नागरिकों की सुरक्षा, और सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में इसकी सबसे व्यापक जिम्मेदारियां हैं। इसके बजटीय आवंटन में 2014-15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.52% की वृद्धि हुई है। बजट अनुमानों की तुलना में, आवंटन में 4.78 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालांकि, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वामपंथी उग्रवाद का मुद्दा है, जो आज देश के सामने सबसे अधिक दबाव वाला सुरक्षा मुद्दा है। अकेले 2014 में, देश भर से वामपंथी उग्रवाद के 1,091 उदाहरण थे। इनमें से अधिकांश झारखंड (384) और छत्तीसगढ़ (328) में हुए थे। इन घटनाओं में वर्ष दर वर्ष कई लोगों की जान

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

चली गई है। 2014 में, वामपंथी उग्रवाद ने 222 निर्दोष नागरिकों और 87 सुरक्षा बलों को मार डाला। एक बार, फिर 2015, के पहले डेढ़ महीने में 28 नागरिकों और 8 सुरक्षाकर्मियों की जान गई है।

सरकार ने हिंसा से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है, लेकिन विकास पर ध्यान केंद्रित करने में कमी दिखाई देती है। 2008 में, 'चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चुनौतियों' पर योजना आयोग को विशेषज्ञों के समूह की प्रतिवेदन ने बढ़ती माओवादी हिंसा के कारणों और प्रकृति का आकलन किया और सिफारिश की कि वामपंथी उग्रवाद को विकास के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं मंत्री से अन्य मंत्रालयों के साथ भी काम करने का आग्रह करता हूँ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में विकास और शासन को प्राथमिकता दी जाए। जिन क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद प्रचलित है, उनमें से अधिकांश देश से पूरी तरह से कट गए हैं। इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान संतोषजनक नहीं है। एन.एच.ए.आई. के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) प्रभावित क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं के मामले में, 100 में से लगभग 60 परियोजनाओं में देरी हुई। इसने लगभग 2,200 किलोमीटर की दूरी तय की और इसकी लागत 3,418 करोड़ रुपये के करीब आती है।

यू.पी.ए. सरकार ने 10 राज्यों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता लाई थी। हालांकि, सरकार ने इस योजना को आसानी से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया है। यह कदम निंदनीय है और यहां तक कि मंत्रालय के गृह सचिव ने भी स्थायी समिति की प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि, इस तरह का कदम सुरक्षा से समझौता है। मंत्रालय स्वयं इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से सहमत नहीं है। पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण योजना को राज्यों की जिम्मेदारी पर, कैसे छोड़ा जा सकता है?

एक अन्य परेशान करने वाली प्रवृत्ति नागरिकों के विरुद्ध अपराधों और आदिवासियों के शोषण की बढ़ती घटनाओं की स्थिति है। ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड से यौन शोषण, जबरन शादी, छेड़छाड़ और समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों के परिवारों के बच्चों की जबरन भर्ती के कई उदाहरण सामने आए हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है?

वर्ष 2013 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराधों में 2012 की तुलना में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कुल मामलों की संख्या 39,408 दर्ज की गई है। यह वृद्धि डकैती, बलात्कार, चोट, अपहरण और एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम सहित सभी प्रमुख अपराध शीर्षों के तहत हुई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि, आज भी ऐसे अपराध हो रहे हैं और वास्तव में बढ़ रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों की इस प्रवृत्ति के बीच, पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रियाशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस तंत्र और न्याय प्रणाली इन समुदायों के प्रति संवेदनशील हो।

स्थायी समिति की प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रतिवेदन के मामले के अध्ययन के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों की प्रतिवेदन करने में देरी या इस तरह के अपराध को दर्ज करने में विफलता, अपराध स्थल पर जाने में देरी और आरोप पत्र में देरी के उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां सख्त अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज नहीं किए गए हैं और इसके बजाय अन्य धाराओं के तहत मामले भरे गए हैं। इन मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विफलता के कारण अपराधियों को कम सजा के साथ छोड़ दिया गया है और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है कि मंत्रालय इस मुद्दे को नहीं उठाएगा और उपयुक्त कार्रवाई करेगा ताकि विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार को खत्म करने के लिए कार्य करें।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जिसे गृह मंत्रालय अपना रहा है। वास्तव में, यह अतीत में देखा गया है कि राज्यों की बाधाओं और पुलिस बल के लिए उनके कम आवंटन को देखते हुए, गृह मंत्रालय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के मोर्चे पर उनके प्रयासों को मजबूत करने में एक प्रमुख शक्ति रहा है। तथापि, यह बजट इस मोर्चे पर एक बड़ी निराशा के रूप में सामने आया है। स्थायी समिति की प्रतिवेदन में कहा गया है कि हालांकि पुलिस बलों के लिए 2014-15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2015-16 के बजटीय व्यय में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कुल आवंटन का 89.13 प्रतिशत वेतन और राशन के

लिए उपयोग किया जाता है और केवल 10.87 प्रतिशत का उपयोग विभिन्न योजनाओं के लिए किया जा रहा है। ऐसे मामले में मंत्रालय अपनी परिचालन क्षमता को कैसे बनाए रखेगा?

इस वर्ष से, सरकार ने प्राकृतिक आपदा घटक को छोड़कर, पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना को भी राज्यों को हस्तांतरित कर दिया है। इस प्रकार, वर्तमान में गृह मंत्रालय की कोई भी योजना पुलिस बलों के विकास या आधुनिकीकरण पर केंद्रित नहीं है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि राज्य सरकारें इन निधियों के एक हिस्से को पुलिस अथवा सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा की आवश्यकताओं में लगाएंगी। यह लंबे समय में राज्य के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। इस प्रकार, मैं मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ फिर से उठाएं, ताकि केंद्र से बजटीय समर्थन के साथ योजना को फिर से जारी रखा जा सके।

तटीय सुरक्षा कर्नाटक सहित, तट पर सभी राज्यों के लिए चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसकी 320 किलोमीटर की तटरेखा है। मुंबई में 26/11 के हमले के बाद, कर्नाटक सहित अधिकांश राज्यों ने तटीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तथापि, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केंद्र से बहुत अधिक समर्थन की आवश्यकता है।

हाल ही में, तटीय सुरक्षा पर महाराष्ट्र में एक सी.ए.जी. ऑडिट में स्पष्ट खामियां पाई गईं। तटीय पुलिस थानों में तैनात 57% गैर-तकनीकी कर्मचारियों के पास तैराकी का कौशल भी नहीं था। प्रतिवेदन में कहा गया है कि पांच तटीय जिलों में नौका संचालन के लिए तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती में अंतर 51.21% के साथ 40.02% पदों की मानव शक्ति की कमी थी। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि जी.पी.एस. सिस्टम, जो चालक दल को समुद्र में नावों के नौवहन चैनलों और स्थानों को समझने में मदद कर सकते थे, 69 परिचालन में से 34 में स्थापित नहीं थे।

तथ्य यह है कि राज्यों में इसी तरह की स्थितियां मौजूद हैं, विशेष रूप से जेटी और मानव शक्ति की आवश्यकताओं जैसी सुविधाओं के मामले में। इस तरह का एक महत्वपूर्ण मुद्दा, केवल, राज्यों पर नहीं छोड़ा

जाना चाहिए। मैं मंत्री से इस मुद्दे पर ध्यान देने, धन आवंटित करने और देश में तटीय सुरक्षा के विकास की निगरानी करने का आग्रह करता हूँ।

***श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर):** अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने लिखा है कि एक राज्य को चार प्रकार के खतरों से खतरा हो सकता है - आंतरिक, बाहरी, बाहरी सहायता प्राप्त आंतरिक, और आंतरिक सहायता प्राप्त बाहरी। उन्होंने सलाह दी कि इन चार प्रकारों में से, आंतरिक खतरों का तुरंत ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि आंतरिक परेशानियां, जैसे छिपे हुए सांप का डर, बाहरी खतरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन भीतर का दुश्मन है। आंतरिक सुरक्षा पर कौटिल्य की शिक्षाएँ और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बारे में उनकी कुशल अभिव्यक्ति की वैश्वीकृत 21वीं सदी में बहुत प्रासंगिकता है। आंतरिक अशांति के माध्यम से किसी देश को अस्थिर करना अधिक किफायती और कम आपत्तिजनक है, खासकर जब प्रत्यक्ष युद्ध एक विकल्प नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। बाहरी विरोधी, विशेष रूप से कमजोर, आंतरिक अशांति और अस्थिरता का कारण बनने वाली ताकतों को बनाना और उनकी सहायता करना आसान पाते हैं।

भारत का इतिहास ऐसे अनुभवों से भरा हुआ है। आजादी के बाद से, हमने 60 के दशक के मध्य से पूर्वोत्तर में और यहां तक कि, देश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी चीन, पाकिस्तान और अन्य लोगों द्वारा शुरू की गई ऐसी कई स्थितियों का सामना किया है। लेकिन 11 सितंबर 2001, की घटनाओं के बाद ही दुनिया ने इन बाहरी और आंतरिक संबंधों को अधिक गंभीरता से देखना शुरू कर दिया है। वर्तमान में, दक्षिण एशिया के लगभग सभी देश - भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान - विद्रोह आंदोलनों, जातीय संघर्षों, धार्मिक कट्टरपंथ या केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण, आंतरिक सुरक्षा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत विविधता का उदाहरण है - लगभग 3.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक अरब से अधिक लोग फैले हुए हैं। देश के लोग 200 से अधिक बोलियों में 16 प्रमुख भाषाएँ बोलते हैं। लगभग एक दर्जन जातीय समूह, कई संप्रदायों और उप-संप्रदायों के साथ सात प्रमुख धार्मिक समुदाय, और 68 सामाजिक-सांस्कृतिक उप-क्षेत्र हैं। जब ऐसे परिदृश्य में सामाजिक-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संतुलन बना रहता है, तो विविधता में एकता होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी असंतुलन है, तो हमारे पास अधिक विविधता और कम एकता है। यह भारत के इतिहास की पहचान रही है और इसका हमेशा बाहरी तत्वों द्वारा दोहन किया गया है। स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी, हमारी धर्मनिरपेक्ष, आंतरिक परेशानियां, जैसे छिपे हुए सांप का डर, बाहरी खतरों से कहीं अधिक गंभीर हैं। भारत के जटिल आंतरिक सुरक्षा अभियानों से निपटने के लिए तालमेल आवश्यक है। 26/11 के बाद, इन कार्यों में शामिल एजेंसियों की बेहतर नेटवर्किंग सुनिश्चित करने के लिए एक सचेत प्रयास प्रतीत होता है।

रणनीतिक रूप से, भारत आंतरिक सुरक्षा या बाहरी रूप से प्रेरित आतंकवादी दबावों के तहत झुकने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यह विनाशकारी होगा। न ही यह अपनी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं का ध्यान रखने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने का जोखिम उठा सकता है। आंतरिक सुरक्षा गतिविधियों की वर्तमान प्रवृत्ति में विकल्पों के कठोर विश्लेषण के आधार पर, कठोर निर्णय, लेने होंगे। हमें विभिन्न विद्रोहियों और सांप्रदायिक आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक केंद्र-राज्य रणनीति की आवश्यकता है। इसमें त्वरित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, सुरक्षा और मीडिया नीतियों सहित राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के व्यापक-आधारित क्षेत्र शामिल होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, इसे अच्छे प्रशासन, त्वरित और निष्पक्ष न्यायपालिका और एक कानून और व्यवस्था तंत्र के माध्यम से समर्पित और प्रभावी शासन को संबोधित करना चाहिए जो जनता के विश्वास को प्रेरित करता है।

***श्री अर्का केशरी देव (कालाहांडी):** ओडिशा राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहांडी वामपंथी उग्रवादियों के अधीन आ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे का कनेक्शन बहुत खराब है, जिसके परिणामस्वरूप घटना के समय विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच अच्छा समन्वय नहीं है। इसलिए, मैं अनुदान की मांगों को पारित करते समय मंत्री द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करने का सुझाव दे सकता हूँ।

सरकार एल.ई.डब्ल्यू. प्रभावित जिलों के लिए जनजातीय और पिछड़े जिलों के विकास के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) के लिए केंद्रीय सहायक को दोगुना करने पर विचार कर सकती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2 अप्रैल, 2013 को बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के विशेष बलों के उन्नयन और महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए धन को मंजूरी दी है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिला मुख्यालय भवानी पटना में सी.आर.पी.एफ. इकाई की स्थापना की जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्र में अर्धसैनिक बल को बहुत जल्दी कुशलता से तैनात किया जा सके।

सभी विकासात्मक गतिविधियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी अपने क्षेत्रों के विकास में भागीदारी को नजरअंदाज करने से अधिक सफल हो सकती है।

इन प्रभावित वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों के शिक्षित युवाओं को बेरोजगार लाभ दिए जा सकते हैं ताकि इन युवाओं को कभी यह महसूस न हो कि सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। यह बेरोजगार लाभ इन युवाओं को काफी हद तक असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से रोक सकता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में समाज विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस बल का आधुनिकीकरण, और उन्नयन और राज्य पुलिस बल के साथ खुफिया डेटा साझा करना आवश्यक है। इन प्रभावित क्षेत्रों के सभी स्कूलों को मोबाइल टावरों से जोड़ा जा सकता है ताकि लोगों के हताहत होने की संख्या को कम करने के लिए सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करके जानकारी और डेटा स्कूल को भेजा जा सके।

जनजातीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया जा सकता है और हस्तशिल्प केंद्रों को विकसित करने के लिए धन की आसान उपलब्धता हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण इन हस्तशिल्पों का विपणन है, ताकि ये जनजातीय लोग अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

स्कूली बच्चों को कारपेंटर, मिट्टी के बर्तन, लोहार, पत्थर की लालसा और खेती जैसे फूलों की खेती, मछली पकड़ने/मछली पालन, मधुमक्खी पालन और फलों की खेती जैसी कौशल विकास की शिक्षा दी जा सकती है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर और स्व-नियोजित बनाया जा सके। यहां सरकार को सौर ऊर्जा का उपयोग करके छोटे कोल्ड स्टोरेज के बारे में सोचना चाहिए ताकि खराब होने वाली वस्तुओं को लंबे समय तक अतिरिक्त मूल्य के साथ संग्रहीत किया जा सके।

सौर, पवन और जैव-गैस जैसी स्वच्छ और हरित ऊर्जा को पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करके पी.पी.पी. मॉडल के साथ जोरदार तरीके से लिया जा सकता है।

ओडिशा में एक लंबी तट रेखा है, ताकि केंद्र सरकार को तटीय निगरानी को उन्नत करके सुरक्षा और सुरक्षित कोयला लाइन के बारे में सोचना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आतंकवाद का मुकाबला करने और देश के नागरिकों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) शाखा की स्थापना की जाए।

सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे संपर्कों, सिंचाई, बिजली और पीने के पानी की आपूर्ति जिन्हें वर्तमान दुनिया में लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं माना जाता है, को अधिक धन आवंटित करके और लक्ष्यों को प्राप्त

करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ-साथ राज्य मशीनरी को शामिल करके प्रमुख महत्व दिया जा सकता है। मेरी राय में इन क्षेत्रों में कोई भी ईमानदार प्रयास निश्चित रूप से ग्रामीण भारत का चेहरा बदल देगा।

***श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़):** मैं गृह मंत्रालय के तहत अनुदान की मांग का समर्थन करता हूँ। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न एजेंसियों के कामकाज में सुधार के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। महोदया, मैं अपने राज्य असम से संबंधित मुद्दों पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदया, असम के डिब्रूगढ़ जिले के लाहोवाल में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बटालियन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। मेरा सुझाव है कि इसे कबीर सी एस्टेट में स्थापित किया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्रालय से लाहोवाल में आई.टी.बी.पी. बटालियन की स्थापना के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। यदि यह तेजी से किया जाता है, तो आई.टी.बी.पी. सुविधा निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों को व्यापार और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। एक अन्य मुद्दा जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, वह यह है कि 23 दिसंबर, 2014, को एन.डी.एफ.बी. (एस.) के उग्रवादियों द्वारा असम में कई स्थानों पर निर्दोष ग्रामीणों पर की गई गोलीबारी में कई लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। मैं स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए किए गए सभी प्रयासों के लिए माननीय गृह मंत्री की सराहना करता हूँ, साथ ही मैं मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आतंकवादियों के इस कायरतापूर्ण कृत्य में प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए। अध्यक्ष महोदया, असम की पड़ोसी बांग्लादेश के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन सीमा विभिन्न स्थानों पर छिद्रपूर्ण है जिसके माध्यम से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। इसके अलावा, असम के विभिन्न हिस्सों से झरझरा सीमा के माध्यम से मवेशियों की तस्करी भूमि और नदी दोनों मार्गों से बांग्लादेश में की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के पलायन को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने की अपील करता हूँ। साथ ही, सीमा चौकियों (बी.ओ.पी.) का प्रबंधन करने वाले बलों को भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

एक और गंभीर मुद्दा जिसका तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है, वह है असम में उग्रवाद की समस्या। माओवादी, यू.एल.एफ.ए. और एन.डी.एफ.बी. जैसे उग्रवादी संगठनों ने हमारे राज्य के विभिन्न हिस्सों में आतंक का राज छेड़ दिया है। प्रशिक्षित माओवादियों के कैडर चाय बागान क्षेत्रों में हैं। आतंकवादियों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उनकी गतिविधियों की जांच की जा सके।

अंत में, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6,000 युवाओं को विभिन्न अर्धसैनिक बलों में शामिल करने का अनुरोध करना चाहूंगा जैसा कि मंत्रालय द्वारा पहले तय किया गया था।

[हिन्दी]

***श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) :** गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन आदि के लिए जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना स्थिति की निरंतर निगरानी करता है, उचित सलाह देता है, सुरक्षा, शांति तथा सद्भाव को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को मानव शक्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। तथापि भारत के सातवीं अनुसूची में लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं।

यद्यपि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कई घटक विभाग हैं परन्तु मैं अपनी बातों को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ही केन्द्रित करना चाहूंगा।

आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चार थियेटर हैं - जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, नक्सलवाद, आतंकवाद।

जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की समस्या अहम है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, बाड़ का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर तकनीक, हथियार और उपकरण, बेहतर सूचना के प्रवाह की सक्रियशीलता शामिल है। इसी का नतीजा है कि हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव एवं विधान सभा चुनावों में वहां की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ और जिसकी प्रशंसा दुनियाभर ने की। आज जम्मू-कश्मीर की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्ता का द्वार भी खोला है, बशर्ते कि वे हिंसा का परित्याग करें एवं भारत के संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों का समाधान करें। सरकार द्वारा की गई पहल तथा वार्ता नीति के अनुसरण में पूर्ववर्ती राज्यों में शांति वार्ता के लिए अनेक उग्रवादी संगठन अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सामने आए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एवं विकास के जरिए उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 10 महीनों में प्रधानमंत्री की इन राज्यों को दो-दो बार यात्रा एवं उस क्षेत्र के विकास के लिए घोषित योजनाएं इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2014 में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 965 काडर ने 282 आर्म्स के साथ समर्पण किया है।

आज से कुछ वर्ष पूर्व देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उग्रवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। देश के 9 राज्यों में उग्रवाद की समस्या आज भी बनी हुई है। हालांकि गतिविधियों एवं हिंसक घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

1967 में जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो भारत सरकार ने इसे महज एक विधि-व्यवस्था की समस्या माना एवं तत्कालीन गृह मंत्री वाई.बी. चव्हाण ने 13 जुलाई, 1967 में इस लोक सभा में वक्तव्य देते हुए नक्सलवादी घटना को लॉलेसनेस की संज्ञा दी। वर्षों बाद सरकार ने यह महसूस किया कि नक्सलवाद की समस्या एक महज विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है और केवल बल प्रयोग से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर भी गहन चिंतन की आवश्यकता है। इसी सोच के परिणामस्वरूप नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए ट्विन थ्योरी सामने उभरकर आई, जिसके अनुसार सिक्योरिटी के साथ-साथ डेवलपमेंट की भी बात कही गई। यह कहा गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए उस क्षेत्र से नक्सलियों को बाहर करना होगा और साथ ही साथ उस क्षेत्र को विकसित करना होगा। परन्तु हुआ क्या? हुआ ये कि उस क्षेत्र से नक्सलियों को बाहर तो कर दिया गया परन्तु उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और सुरक्षाबलों के हटते ही पुनः नक्सली उस क्षेत्र में आ घुसे। समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। सरकार

ने इस बात को महसूस किया है और नक्सल समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी स्ट्रेटेजी अख्तियार किया है।

सिक्थोरिटी फ्रंट पर भारत सरकार ने सुरक्षा से संबंधित उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 100 से अधिक बटालियनों को राज्य पुलिस की सहायता के लिए नक्सलवाद प्रभावित 9 राज्यों में तैनाती की है। इसके अतिरिक्त काउंटर इनसर्जेंसी एवं जंगल वारफेयर में दक्ष एवं विशेष प्रशिक्षित कोबरा की 10 बटालियन तैनात की है।

सिक्थोरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत 9 राज्यों के 106 जिलों में सुरक्षा संबंधी खर्चों को रिम्बर्स करती है, जिसमें उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों / सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान (एक्सग्रेसिया पेमेंट), पुलिस कर्मियों की बीमा राशि, सुरक्षाबलों के प्रशिक्षण, समर्पण करने वाले उग्रवादियों की मुआवजे की राशि, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, विलेज डिफेंस कमेटी पर होने वाले खर्च की राशि, प्रचार सामग्री से संबंधित खर्च की राशि शामिल है।

पुलिस स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार प्रति पुलिस स्टेशन 2 करोड़ की राशि प्रदान करती है। 45 पुलिस स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। एस.एस.आई. (स्कीम फॉर स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) पुलिस स्टेशनों की गतिशीलता एवं संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गाड़ियों एवं वितंतु सेटों पर होने वाले खर्च, दुर्गम स्थलों पर जाने के लिए सड़कों के निर्माण, सिक्थोर कैम्पिंग ग्राउन्ड करने पर होने वाले खर्च एवं हेलीपेड बनाने तथा हेलीकॉप्टर एवं यू.ए.वी. का वहन भारत सरकार करती है।

इंडिया रिजर्व बटालियन - नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नौजवानों को चयनित कर इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन का भार राज्य सरकारों को दिया गया और इसके लिए 37 इंडिया रिजर्व बटालियन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत अब तक 36 बटालियन का गठन किया जा चुका है।

ये तो सिक्थोरिटी से संबंधित किए गए उपायों का मैंने जिक्र किया। अब विकास से संबंधित किए गए उपायों पर भी एक नज़र डालना आवश्यक है। पी.एम.जी.एस.वाई. , एन.आर.एल.एम. , एम.एन.आर.ई.जी.ए.

, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.), इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आई.सी.डी.एस.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), फॉरेस्ट एक्ट, 2006 इत्यादि योजनाओं के जरिए भारत सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में गरीब एवं आवश्यकता मंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है। इसके पीछे भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि गरीब, पिछड़े क्षेत्रों के गरीब, दलित, शोषित आदिवासी बंधु नक्सलियों के विचारों से प्रभावित होकर या उनके दबाव में आकर उग्रवादी संगठन में शामिल न हो। परन्तु इन सारे उपायों के बावजूद नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलियों के द्वारा उगाही की जाने वाली राशि या उनको की जाने वाली फंडिंग पर प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए। उनको समाप्त किया जाए। बाल दस्ते को प्रतिबंधित किया जाए। फॉरेस्ट एक्ट, 2006 के प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए। वन उत्पादों पर वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों का एकाधिकार हो। फॉरेस्ट एक्ट, 2006 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन हो क्योंकि आज भी अधिनियम के स्थापित हो जाने के बावजूद इन गरीब आदिवासियों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वन क्षेत्रों में काम करने वाली आयरन ओर कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत उनके विकास के लिए कुछ भी लाभकारी कार्य नहीं किया जा रहा है।

सरकार को गरीब आदिवासियों एवं जंगलों में रहने वाले अन्य लोगों में एक विश्वास पैदा करना होगा कि उनकी जिन्दगी सरकार के साथ ज्यादा महफूज होगी, बनिस्पत नक्सलियों का साथ देने में। आदिवासियों के विरुद्ध बल प्रयोग, नक्सली संगठन में सम्मिलित नहीं होने के लिए बैकफायर करेगा। सरकार को इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करनी होगी जो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से की जा सकती है। सी.आर.पी.एफ. के द्वारा इस क्षेत्र में सहायनीय कार्य किया जा रहा है। अतः इसके लिए ज्यादा राशि उपलब्ध करानी होगी। उस क्षेत्र का विकास करके ही संभव है। सरकार नक्सलियों के कुकृत्यों एवं अपनी उपलब्धियों को वृहद पैमाने पर और प्रभावकारी ढंग से प्रचारित / प्रसारित करें एवं विकास से जुड़े पदाधिकारियों खासकर बी.डी.ओ. /सी.ओ.ओ. को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर इन क्षेत्रों में तैनाती की जाए जो जंगल में रहने वाले लोगों खासकर

आदिवासी लोगों के प्रति एवं उनके कार्यों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों उनके कार्यों को अपना कार्य समझकर संपादित करें।

आदिवासी क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की गहन समीक्षा की जाए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसके लिए एक पृथक घटक/विभाग बनाया जाए या सरकार के अधीन एक पृथक मंत्रालय बनाया जाए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के कार्यों को देखें।

राज्यों को नक्सल गतिविधियों में आयी कमी का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि नक्सलियों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। इस अवधि का इस्तेमाल जैसा नक्सली करते हैं पुलिस बल को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अपने जवानों का कमिटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए, उनमें प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मार्क्समैनशीप उन्नत करने के लिए क्योंकि आमने-सामने की लड़ाई में ये तीनों चीजें आति महत्वपूर्ण होती हैं।

सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि आतंकवाद का खतरा न तो समाप्त हुआ है और न ही कम हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कराने के लिए भी कटिबद्ध है कि न केवल बड़े आतंकवादियों बल्कि आतंकवादी कुकृत्यों में संलिप्त उनके मार्गदर्शक एवं षडयंत्रकारियों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। जैसे मास्टरमाइंड के आतिरिक्त मोस्ट वान्टेड आतंकवादी अब्दुल सुभान तथा सईद शेख की गिरफ्तारी आतंकवाद से लड़ाई में एक बड़ी सफलता है तथा देश के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को सजा दिलाने के सरकार के संकल्प को भी दर्शाती है।

बावजूद इसके देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत स्लीपर सेल्स पर कड़ी नज़र रखनी होगी।

अंत में, मैं बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय का 2015-16 का बजट जो 78470.35 करोड़ निधारित किया गया और 2014-15 के बजट (बी.ई.) 74884.29 करोड़ से ज्यादा है परन्तु सी.एस.एस. को राज्यों को हस्तांतरित किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता दिखाई पड़ती है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा

से जुड़े इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाए या उनके कार्यान्वयन की गति धीमी न पड़े।

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2015-16) पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय द्वारा 10 अनुदान मांगों को सदन की स्वीकृति के लिए रखा गया है। 2015-16 के लिए गृह मंत्रालय की दस अनुदान मांगों के लिए कुल आवंटन 78470.35 करोड़ रुपये है। जो 2014-15 के संशोधित प्राक्कलन की राशि 70358.34 करोड़ रुपये के बनस्पित 11.53 प्रतिशत आधिक है। बजट प्राक्कलन 2015-16 में आवंटित 78470.35 करोड़ रुपये में से 14586.98 करोड़ रुपये योजना मद और 63883.37 करोड़ रुपये गैर-योजना मद में निर्दिष्ट है। गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों के विश्लेषण से शीर्षवार वृद्धि इस प्रकार है, गृह मंत्रालय में 24.08%, पुलिस में 10.20%, अन्य व्यय गृह मंत्रालय 25.70%, संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण 3.97%, जबकि मंत्रिमंडल पर 9.06% की कमी हुई है। उसी प्रकार गैर-विधान सभा वाले संघ राज्यों क्रमशः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 15.51%, चंडीगढ़ में 15.79%, दादरा और नगर हवेली में 15.13%, दमन और दीव में 27.87%, लक्षद्वीप में 17.80% सहित कुल मिलाकर 11.80% की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को जहां मजबूत बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया है वहीं मंत्रिमंडल पर किए जाने वाले व्यय में 9.06 प्रतिशत की कमी का अर्थ है स्थापना मद में खर्च को कम करने के प्रति सरकार का संकल्प।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद वाले राज्यों में चल रही विशेष अवसंरचना योजना को अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर एक समग्र योजना बना दिया गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इन योजनाओं का दायित्व अब राज्य सरकारों पर होगा। मेरा आग्रह है कि सरकार ऐसी योजनाओं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, को

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राज्यों को सौंपते समय सावधानी बरतनी चाहिए। किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्यों को अंतरित किया भी जाता है तो केन्द्र सरकार उन योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रगति पर ठोस निगरानी की प्रणाली बनानी चाहिए।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (एल.डब्ल्यू.ई.) में सुरक्षा संबंधी उपायों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस और प्रशासनिक भवन निर्माण, सड़कों के सुधार हेतु सड़क आवश्यकता योजना जैसी विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन, मोबाईल टावरर्स स्थापित करने हेतु परियोजनाएं, रेल संपर्क का सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना इत्यादि पर विशेष ध्यान देते हुए इनके लिए अलग से कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। साथ इन क्षेत्रों में लघु वनोपज (एम.पी.एफ.) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भू-स्वामित्व का अधिकार देना चाहिए। वन आधिनियम, 2006 की समीक्षा करनी चाहिए। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी उपायों, अधिकारों तथा पात्रताओं व भूमिका को सुनिश्चित करने संबंधी उपायों और जन-सहभागितापूर्ण प्रबंधन सहित एक समग्र और एकात्म कार्यनीति का निर्माण कर उसे कार्यरूप दिया जाना चाहिए। आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने से वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सकता है।

झारखंड राज्य का संथाल परगना सहित पूरा राज्य आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या के असंतुलन का संकट झेल रहा है। इससे कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अतः इस पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई सहित दंडात्मक निषेध भी लगाया जाए। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करते समय हिन्दू शरणार्थियों को विशेष राहत पहुंचाते हुए उन्हें भारत की नागरिकता देनी चाहिए।

झारखंड में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर घोटाले की चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा दिया गया था। इसकी किसी समर्थवान एजेंसी द्वारा जांच करवानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि झारखंड में बहुमत की पहली सरकार बनी है। उस सरकार में लोगों का भरोसा है। सरकार वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव को समाप्त करने में सफल होगी। इसके लिए उसे केंद्र से सुरक्षा संबंधी सहित हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री बी. एन. चंद्रप्पा (चित्रदुर्ग):** मैं कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार की असामाजिक गतिविधियों के कारण देश में कानून और व्यवस्था के मुद्दे को महत्व मिला है। एक तरफ अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, झारखंड में, नक्सलवाद परेशान कर रहे हैं और धीरे-धीरे भारत के दक्षिणी हिस्सों में भी अपने पंख फैला रहे हैं। नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर रहा है। यह नक्सलवाद की समस्या न केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है, बल्कि यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है। यह कुछ समुदायों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताएँ हैं जिनसे नक्सल आंदोलन का निर्माण हुआ है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि पहले गांवों का विकास करके जमीनी स्तर से ही इस खतरे से निपटा जाए। एक बार जब लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, तो वे इस तरह की असामाजिक गतिविधियों का सहारा नहीं लेते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वह है महिलाओं पर हमले। ये घटनाएँ हमारे देश के कोने-कोने में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। निर्भया की घटना के बाद सरकार ने कुछ कार्रवाई की। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अब भी, हम महिलाओं पर बढ़ते हमले देख रहे हैं। बंगलुरु में एक बैंक के ए.टी.एम. बूथ में दिन में एक महिला पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया था। हमें इस विषय से दृढ़ता से निपटना होगा। इस मुद्दे से निपटने के लिए पुलिस बल और अन्य अर्धसैनिक संगठनों को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार को इन उपद्रवियों को फंसाने के लिए तकनीकी उपकरणों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। हम अभी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए उसी पुरानी प्रणाली का पालन कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को कर्मियों के कल्याण के पहलू सहित पुलिस बल के आधुनिकीकरण के बारे में सोचना चाहिए। अभी, हम जो पाते हैं वह

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह है कि पूरे देश में पुलिस संगठन अपनी लगभग आधी ताकत पर काम कर रहा है। इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? पदों को भरने के लिए कैपस साक्षात्कार और अन्य तरीकों को क्यों अपनाया जा सकता है? सरकार को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अनुदान की इन महत्वपूर्ण मांगों पर मुझे अपने विचार रखने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

***श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़):** यह मुझे प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी के अथक प्रयासों के कारण गृह मंत्रालय के बारे में बोलने में अत्यंत गर्व की बात है जो हमारे पड़ोसी और उन राज्यों तक पहुंचे हैं जो भयानक भूकंप से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने त्रासदी के इस क्षण में भारत के नेपाल और प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद दी है। इस सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि "कार्य केवल शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं"।

हमारे प्रधानमंत्री ने 2001 भुज भूकंप को बहुत करीब से देखा है। वह समझते हैं कि कैसे एक प्राकृतिक आपदा जीवन को नष्ट कर सकती है, परिवारों को विभाजित कर सकती है और एक व्यक्ति से सब कुछ छीन सकती है। यही कारण है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता प्रशंसा के योग्य है। पिछले साल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आए चक्रवात "हुदहुद" के दौरान, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया उपचारात्मक से अधिक निवारक थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की है। सरकार ने न केवल लोगों को निकाला, बल्कि जानवरों के प्रति सहानुभूति भी दिखाई और कई जानवरों को उनके मालिकों के साथ समय पर और सुरक्षित निकालने में सफल रही। इसके अलावा, आपदा की अग्रिम तैयारियों और त्वरित कार्रवाई के कारण, इस परिणाम के अन्य तूफानों की तुलना में जानमाल का नुकसान बहुत कम था।

अपने प्रयासों के अलावा, सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को 416 करोड़ रुपये भी दिए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तटीय समुदायों की चक्रवात और अन्य जल मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है।

यू.पी.ए. सरकार के, कार्यकाल के दौरान, सीमा पार से संघर्ष विराम के उल्लंघन के लगातार मामले सामने आए हैं। तथापि, सरकार हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान को उतना योग्य जवाब नहीं दे सकी। हम 2013 की उस घटना को कभी नहीं भूल सकते जहां पाकिस्तानी सेना ने हमारे भारतीय सैनिकों का सिर कलम कर

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दिया था। जब से भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार सत्ता में आई है, तब से भारत पाकिस्तानी सेनाओं को करारा जवाब दे रहा है। जब भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, हमारे सैनिक इसका कड़ा जवाब देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।

यह सरकार समझती है कि यह देश शांति से सोता है क्योंकि हमारे जवान जागते हैं और हमें दुश्मनों से बचाते हैं। यही कारण है कि सीमा प्रबंधन के बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। सरकार ने सीमा प्रबंधन बजट को संशोधित बजट 2014-15 के 810.64 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1382 करोड़ रुपये कर दिया है, जो कुल 70.49 प्रतिशत की वृद्धि है।

हम 26/11 की घटना को कभी नहीं भूल सकते। कैसे आतंकवादी हमारी धरती पर घुस आए और हमारे देशवासियों की जान ले ली। तटीय सुरक्षा में चूक के परिणामस्वरूप भारत का सबसे बुरा आतंकवादी हमला हुआ था। यह सरकार राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार है। 2015 के नए साल की पूर्व संध्या पर एक पाकिस्तानी नाव ने हमारे तटरक्षकों की सतर्कता के कारण खुद को उड़ा लिया, जिन्होंने इसे रोक लिया। इसलिए, सरकार तटीय सुरक्षा के महत्व को समझती है और उसने अपना बजट 39.37 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 710 करोड़ रुपये कर दिया है।

केवल सीमा सुरक्षा ही नहीं, सरकार आंतरिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जिन्होंने राष्ट्र के वृद्धि और विकास को प्रभावित किया है। सरकार वामपंथी उग्रवाद से समग्र तरीके से निपट रही है। सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एस.आर.ई.), विशेष अवसंरचना योजना (एस.आई.एस.), उग्रवाद-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सी.आई.ए.टी.) स्कूलों की स्थापना तथा भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में काम करने वाली 92 बटालियन विद्रोहियों का मुकाबला करने और जंगल युद्ध अभियानों के लिए सुसज्जित हैं, जिन्हें कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन (सी.ओ.बी.आर.ए.) के रूप में नामित किया गया है इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद के अभियानों में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बलों के लिए 10 अनअटेंडेड ग्राउंड सिस्टम सेंसर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत ऐसी 184 प्रणालियों

को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 2015-16 में पुलिस के बजट में 42306.76 करोड़ रुपये से 46060.85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पुलिस के लिए भवनों के निर्माण के लिए भी बजट में 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसलिए, महिला सुरक्षा के हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए निर्भया कोष से मोबाइल वैन और नियंत्रण कक्षों के साथ पीड़ितों से संकट संकेत के बैक एंड इंटीग्रेशन पर योजनाएं बनाई गई हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने 1 जनवरी 2015 को हिम्मत (एच.आई.एम.एम.ए.टी.) नामक एक महिला सुरक्षा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए मुफ्त में उपलब्ध है और इसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

इसके अलावा, भारत एक एकल नंबर '112' रखने की योजना बना रहा है जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में '911' के समान पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सहित देश भर में सभी आपातकालीन फोन कॉल के लिए किया जा सकता है। इससे लोगों को मदद मिलेगी क्योंकि पीड़ित अधिक कुशलता और तेजी से आपातकालीन सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जी "सबका साथ, सबका विकास" में विश्वास करते हैं।

गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के लोगों की चिंताओं को देखने के लिए बेजबरौह समिति नामक एक समिति का गठन किया। मंत्रालय ने समिति में प्रस्तावित कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस पूर्वोत्तर राज्यों से पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करेगी और इन राज्यों के साथ पुलिस आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये उपाय देश की एकता को और मजबूत करने वाले हैं और पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं।

जैसा कि हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, "एकता के बिना मानव शक्ति एक ताकत नहीं है, जब तक कि यह सामंजस्यपूर्ण और उचित रूप से एकजुट न हो जाए, तब तक यह एक

आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में वर्तमान गृह मंत्री सरदार पटेल के नक्शेकदम पर चल रहे हैं और इस देश को प्रगतिशील तरीके से आगे ले जा रहे हैं।

[हिन्दी]

***श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम):** नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के बाद समुद्र किनारों से सटे राज्य में नेशनल मरीन पुलिस अकादमी स्थापना करने का निर्णय तत्कालीन केंद्र सरकार ने लिया था। इसके लिए महाराष्ट्र के पालघर में 305 एकड़ भूमि निधारित की थी। राज्य सरकार ने अल्प रेंट से सदर भूमि देने का निर्णय लिया। तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री ने पालघर में जाकर उस भूमि का निरीक्षण भी किया था।

पालघर मध्यवर्ती स्थान रहने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक व केरल राज्यों के समुद्री किनारों की सुरक्षा प्रणाली को ट्रेनिंग के लिए सुविधाजनक स्थान है। इसके बावजूद पालघर महाराष्ट्र राज्य के अलावा पिंडारा (देवभूमि) द्वारका जिले के अत्यंत दुर्गम स्थान में सदन अकादमी को स्थानांतरित करने का केंद्र सरकार का निर्णय अनुचित है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार करें।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप ने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने का हमें अवसर दिया है। मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर लगभग 22 मेंबर्स ने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ, 33 मेंबर्स ने अपनी रिटेन स्पीच सदन के पटल पर रखी है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सभी सम्मानित सदस्यों के भाषण को सुन रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि किसी को अपने नज़रिए से यदि कोई कमी नज़र आई तो उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उन्होंने कोशिश की है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं तो इस विषय पर बोल ही नहीं पाया।...(व्यवधान) कल इस पर चर्चा खत्म हो गयी थी तो हम चले गए।...(व्यवधान) हम इस पर बोल ही नहीं पाए। आज के लिए कह दिया था। यह क्या बात है?...(व्यवधान) क्या हम इस विषय पर नहीं बोलेंगे?

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह गलत बात है। क्या हम इस विषय पर नहीं बोलेंगे?

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : कुछ और भी मेंबर इस पर बोल नहीं पाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। सब के भाषण हो गए थे। अब माननीय मंत्री जी रिप्लाय कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो इनकी रिप्लाय के बाद मैं कुछ पूछने के लिए आपको एक मिनट का समय दे दूंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव: मुझे अभी छः मिनट का समय दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनके रिप्लाय के बाद आप पूछ सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बाद में क्या बोलेंगे? माननीय मंत्री जी उसका जवाब अभी देंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी सभी पार्टियों के लोग बोल चुके हैं। ऐसा नहीं होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आज बोलने के लिए कह दिया था।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है। यहां कुछ भी नोटिंग नहीं है। प्लीज़, आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या इतने महत्वपूर्ण सवाल पर हम नहीं बोलेंगे?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। प्लीज़, आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : स्पीकर साहिबा, यह गलत है।... (व्यवधान) फिर तो मेरा इस सदन में आने का कोई मतलब ही नहीं है।... (व्यवधान) अगर हम इस विषय पर भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मतलब है?... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू) : मुलायम जी, जब बोलने का वक्त था, उस समय आप यहां नहीं थे। इसलिए आप नहीं बोल पाए।

माननीय अध्यक्ष : वेंकैया जी, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम जी, ऐसा नहीं होता है। मैं बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए आपको समय दूंगी। अभी आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूँ कि श्री मुलायम सिंह यादव जी इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और अनुभवी नेता हैं। इसलिए यहां जो भी चर्चा हुई है, उस पर मेरे द्वारा विचार व्यक्त किए जाने के बाद उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा अथवा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका भी मैं उत्तर दूंगा। इतना मैं आपको आश्चस्त करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : उसके लिए तो मैंने बोला ही है।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने अपने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने हमारे गृह मंत्रालय के कामकाज की आलोचना की है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना का भी अपना एक महत्व होता है। आलोचना को भी हमने सकारात्मक तरीके से लिया है। साथ ही साथ, जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें भी हमने सकारात्मक तरीके से लिया है।

जहां तक गृह मंत्रालय का प्रश्न है, गृह मंत्रालय को कई प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। इंटरनल सिक्यूरिटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, जिनका उसे निर्वह करना पड़ता है। वहीं पर बॉर्डर मैनेजमेंट, सेन्टर-स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ ही साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का भी प्रबंधन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय को ही संभालनी पड़ती है।

अपराह्न 01.00 बजे

[हिन्दी]

मैं उन सारी चीजों का यहां बहुत डिटेल में जाकर उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा। इंटेलिजेंस विभाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है। तकनीकी दृष्टि से इसकी ताकत को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हम उसे करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं।

एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को निभानी पड़ती है कि समाज का जो वलनरेबल सेक्शन है, जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, चाहे वे महिलाएं हों, चाहे वे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, आदिवासी हों या चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबको सुरक्षा की गारन्टी देना। इसे मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की भी होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल केवल सेंटर का सबजेक्ट नहीं है, बल्कि यह स्टेट सबजेक्ट है। मैं किसी राज्य की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। सभी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से वे उसकी कोशिश करते हैं।

हमारे सामने बैठे हुए कांग्रेस लोक सभा दल के नेता श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय को लेकर उन्होंने अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं। पहली चिन्ता श्रीमान खड़गे जी की यह रही है कि जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, उस अभिभाषण में गृह मंत्रालय का जितना विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी चिन्ता की कि बजट अलोकेशन पहले की अपेक्षा कम हुआ है। मैं बजट अलोकेशन के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि बजट अलोकेशन पहले से कम नहीं हुआ है, पहले से बजट अलोकेशन बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में बजट अलोकेशन जहाँ 67,978 करोड़ 15 लाख था, वहीं वर्ष 2014-15 में बढ़कर 74,884 करोड़ हो गया और वर्ष 2015-16 में बढ़कर 78,470 करोड़ तक पहुँच गया है। यदि रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो एप्रॉक्सिमेटली 11.52 परसेंट की इसमें वृद्धि हुई है। इसलिए किसी भी प्रकार से गृह मंत्रालय को कहीं से कोई कमजोर कर रहा हो अथवा उसकी उपेक्षा कर रहा हो, यदि यह आशंका खड़गे जी को है, तो उन्हें इसे दूर करना चाहिए। उन्होंने स्वयं ही इस बात को कहा है कि यदि हम किसी देश का विकास करना चाहते हैं, तो जब तक उस देश की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी, तब तक विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यह देश सुरक्षित रहना चाहिए, इस देश के लोग सुरक्षित रहने चाहिए और इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए।

जहाँ तक इस देश की आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, जैसा मैंने पहले कहा कि आंतरिक सुरक्षा को इंशोर करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एवं माओवाद से प्रभावित जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी शांति की बहाली के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। मैं यह कह सकता हूँ कि चाहे वह देश के हिटरलैंड में हो, चाहे जम्मू-कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या माओवाद से प्रभावित राज्य हों, सभी स्थानों पर सिक्योरिटी इंशोर करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

मैं आंकड़ों पर बहुत यकीन नहीं करता हूँ और आंकड़ों के आधार पर मैं आश्वस्त नहीं होना चाहता हूँ। सुरक्षा से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, कभी किसी महीने बढ़ जाते हैं, कभी किसी महीने घट जाते हैं। माओवाद की घटनाएं भी किसी महीने बढ़ जाती हैं, किसी महीने घट जाती हैं। लेकिन फिर भी चूंकि इस बात की चर्चा हुई है, इसलिए उसका उल्लेख करना भी मैं आवश्यक समझता हूँ कि माओवादी क्षेत्रों में टोटल किलिंग्स कितनी हुई हैं, टोटल किलिंग्स ऑफ सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, वर्ष 2013 में 397 किलिंग्स हुई हैं, वर्ष 2014 में 309 किलिंग्स हुई हैं, वर्ष 2015 में अप टू 15.04.2015, 79 किलिंग्स ही हुई हैं। यानी [अनुवाद] वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में 22 प्रतिशत कम हत्याएं हुईं। [हिन्दी] टोटल नम्बर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, उनकी कितनी किलिंग्स हुई हैं, वर्ष 2013 में 115 किलिंग्स हुई हैं, वर्ष 2014 में 87 किलिंग्स हुई हैं, लेकिन वर्ष 2004 में एक बड़ी वारदात छत्तीसगढ़ की हुई है, जो हमारे लिए केवल चिन्ता का ही विषय नहीं है बल्कि उसे हमने एक चुनौती के रूप में भी स्वीकार किया है। वर्ष 2014 में अब तक केवल 34 किलिंग्स हुई हैं। जहां तक सिविलियन्स के मारे जाने का प्रश्न है, वर्ष 2013 में 282 सिविलियन्स मारे गये हैं, वहीं वर्ष 2014 में 222 सिविलियन्स मारे गये हैं।...(व्यवधान) वर्ष 2015 में केवल 45 लोगों की जानें गयीं हैं। जहां तक एल.डब्ल्यू.ई. कैडर की किलिंग्स का सवाल है, उनके भी आंकड़े हैं लेकिन बहुत-सारे आंकड़े देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों से माओवाद का संकट समाप्त हो, यह हमारा लक्ष्य है। मैं जानता हूँ कि केवल लोगों को मौत के घाट ही उतार कर, हम यह कामयाबी कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। मैं यह भी स्पष्ट

कर देना चाहता हूं कि यदि अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग की कोई हत्या करने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी, लेकिन मैं इस हकीकत को भी स्वीकार करता हूं कि आज तक जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रह गये हैं, उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिए। हम लोगों ने पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रभावी तरीके से योजना चलाने की व्यवस्था कर ली है। जहां तक माओवाद का प्रश्न है, यह साल, दो साल, चार साल, दस साल या 15 साल की समस्या नहीं है, यह समस्या वर्ष 1980 के बाद तेजी से इस देश में बढ़ी है और इसके पहले भी कई सरकारें रही हैं। मैं किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहता हूं, किसी को लांक्षित नहीं करना चाहता हूं कि उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है, लेकिन आज मैं इस सदन में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से विनम्रतापूर्वक यह अपील करना चाहता हूं कि माओवाद का यह संकट केवल सरकार के लिए चुनौती नहीं है बल्कि यह देश के लिए चुनौती है, हम सभी के लिए चुनौती है, हम सबको मिल-जुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए, ताकि हम माओवाद के संकट से देश को निजात दिला सकें। यह हमारी कोशिश अपनी तरफ से होनी चाहिए। इस संकट को दूर करने के लिए यहां पर मैंने इस बात की चर्चा की है कि उन क्षेत्रों में हम विकास का कार्य तेजी से चला रहे हैं और वहां पर हमने कम्यूनिकेशन फैसिलिटी को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल मौखिक रूप से ऐसा नहीं कह रहा हूं बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि कम्यूनिकेशन फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए लगभग 2000 टावर्स उन क्षेत्रों में लगाने का काम तेजी से प्रारंभ हो गया है, क्योंकि मैंने 9 फरवरी को एक मीटिंग की थी, उसमें दस राज्यों के कुछ मुख्य मंत्री थे, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेट्रीज और उनके ऑफिसर्स थे। केन्द्रीय मंत्रालय के लगभग सात-आठ मंत्रिगण और उनसे संबंधित अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, मैंने उनके साथ एक बैठक की थी। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों से विकास के लिए किस-किस डिपार्टमेन्ट के सहयोग की आवश्यकता होगी, उसके संबंध में चर्चा हुई है। आज मुझे इस बात का संतोष है और मैं खुशी का भी इजहार करना चाहता हूं कि जिन-जिन मंत्रालयों के ऊपर जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सबने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, उन्हीं में से रोड ट्रांसपोर्ट ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है और टावर्स लगाने का काम प्रारंभ हो गया है। जहां तक सड़कों का सवाल है, आर.आर.पी.

फर्स्ट फेज में 3700 किलोमीटर रोड का निर्माण हो चुका है। आर.आर.पी. सेकेण्ड फेज में भी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया गया है। इसलिए देश को इस संकट से निजात दिलाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है और मुझे सबका सहयोग प्राप्त होगा, यह मुझे विश्वास है।

जहां तक नॉर्थ ईस्ट का प्रश्न है, यह बात सच है कि विगत कुछ वर्षों में एक सेंस ऑफ एलिमेंशन, एक दुराव का भाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों में पैदा होना प्रारंभ हुआ। यदि कोई हमसे पूछे कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सेंस ऑफ एलिमेंशन को दूर करना और नार्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।

उग्रवाद का संकट है। उग्रवाद का संकट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उग्रवाद आज से नहीं है, आजादी हासिल होने के पहले से ही उग्रवाद का सिलसिला वहां प्रारंभ हुआ और आज भी वह सिलसिला निरंतर चल रहा है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हमें काफी हद तक उस उग्रवाद के संकट पर काबू पाने में सफलता हासिल हुई है। इंटरलोकेटर्स वर्षों से, दूसरी सरकारें थीं तब भी लगे हुए थे। वहां के उग्रवादी, इनसर्जेंट ग्रुप्स के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन समाधान संतोषजनक नहीं रहा है। आज भी मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हम जो कर रहे हैं, पूरी तरह से समाधान हो गया। आज भी हमारे इंटरलोकेटर्स बात कर रहे हैं। मैं बातचीत का पक्षधर हूं, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में एन.डी.एफ.बी. (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड) एस ग्रुप ने वहां 62 निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी। मैंने उसी दिन गुवाहाटी की धरती पर जाकर कहा था कि जो समाज के कमजोर वर्गों की हत्या करते हैं, उनके साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में बातचीत नहीं करेगी। आप हत्या करते रहें और बातचीत भी करते रहें, यह दोनों चीजें साथ नहीं चल सकतीं। लेकिन मुझे आज सदन को यह बताते हुए खुशी है कि उनमें से लगभग पौने तीन सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों ने हमारे जवानों के ऊपर इस बीच आक्रमण करने की कोशिश की, उनमें से 10-11 लोगों को अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ी।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : क्या उसके लीडर को गिरफ्तार किया?... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : सौगत राय जी, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम आएंगे। अध्यक्ष महोदया, श्रीमान सौगत राय जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तर्कसम्मत बोलते हैं। उल्फा और एन.एस.सी.एन.-आई.एम. के साथ जो बातचीत चल रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी चाही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि यह साठ साल से ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम है। हमें उम्मीद है कि अब इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। हम इस संबंध में जल्दी ही आपको परिणाम देने वाले हैं।

जहां तक अलफा के परवेज बरुआ की बात है, उसने सरेआम घोषणा की है कि वह अपनी बात पर अड़ा रहेगा, उसे शान्ति वार्ता वगैरह में कोई रूचि नहीं है। कहा है, लेकिन फिर भी आपको परिणाम देंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में एन.एस.सी.एन.-आई.एम. एवं अन्य समूहों के साथ वार्ता की जो स्थिति है, किन-किन ग्रुप के साथ हमारी क्या बातचीत चल रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, यदि मैं उस बारे में बताऊंगा तो बहुत लम्बी चर्चा हो जाएगी। यदि आपकी इजाजत होगी और सदन के सम्मानित सदस्य चाहेंगे तो मैं यहां उसकी विस्तृत जानकारी भी दे सकता हूं...(व्यवधान) आप कहें तो मैं अभी बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट उसी में लग जाएगा।

श्रीमान खड़गे जी ने वहां डोनर मिनिस्ट्री की चर्चा की थी। पहले कभी था। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि खड़गे जी को जानकारी नहीं है। खड़गे जी पूरी जानकारी रखते हैं। डोनर नार्थ ईस्ट के विकास की जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। इसका एक मंत्रालय अलग से है। वह उसके विकास की जिम्मेदारी संभाल रहा है। कई बार नार्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, इसकी मुझे जानकारी है।

मैं यहां आंध्र और तेलंगाना की चर्चा भी इसलिए करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था। लंबे अरसे से वहां विभाजन की मांग हो रही थी, अब अलग राज्य तेलंगाना बन चुका है। रीआर्गनाइजेशन एक्ट, 2014 का इम्प्लीमेंटेशन सबसे अहम सवाल है। उस एक्ट को प्रोपरली एम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार मोनिटरिंग हो रही है कि यह प्रोपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश रीआर्गनाइजेशन एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। दोनों राज्यों के बीच कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जिनको रिजोल्व

करने के लिए मैंने विभाग के संबंधित आधिकारियों को निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी या संबंधित अधिकारी के साथ बैठ कर इसे जल्दी रिजोल्व किया जाए। यह आग्रह मैंने उनसे किया है।

महोदया, मैं गोरखालैंड की भी चर्चा करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि यहां ट्राइपटाइट एग्रीमेंट भारत सरकार, वेस्ट बंगाल और गोरखालैंड टेरिटोरिएल एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य हुआ था। इस एग्रीमेंट का प्रोपरली एम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी मोनिटरिंग विभाग द्वारा की जा रही है। मैं यहां सभी विषयों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल मेजर चैलेंज की चर्चा करना चाहता हूं। साइबर क्राइम केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत दुनिया के बड़े देशों में एक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। सरकार भारत में साइबर क्राइम को चेक करने के लिए बेहद चिंतित है। विडंबना यह है कि सर्वर हमारे पास नहीं है। दुनिया के कई बड़े देशों के पास भी सर्वर नहीं है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इफेक्टिव सिस्टम की कमी है। हमने दो कमेटी बनाई है जिसे सुझाव देने के लिए कहा है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, चाहे वह कदम खर्चीला ही क्यों न हो। साइबर क्राइम को हम चुनौती मानते हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम संस्थागत संरचना को मजबूत करेंगे। इस संबंध में हमने इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर कायम करने का भी फैसला किया है।

महोदया, देश के वलनरेबल सेक्शन में महिलाएं शामिल हैं, लेकिन महिलाओं को कमजोर नहीं मानना चाहिए। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर अगर कोई देखे तो महिलाओं को शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, यह सब किताबों, वेदों और पुराणों में ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली 5000 हजार साल से हम देख रहे हैं, जब ह्यूमन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और सोसियोलॉजी को देखें तो महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको मालूम चल जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं वैसा कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं जिससे कोई हर्ट हो। मैं सभी का रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग चाहता हूं। खड़गे जी, आपकी सरकार ने भी कदम उठाया था। निर्भया

कांड आपके ही समय हुआ था। उस समय भी आप लोगों ने कुछ प्रभावी कदम उठाये थे। हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आपने कुछ गलत किया हुआ है। हमने इन्वेस्टीगेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण काम किया है। वूमैन क्राइम के इन्वेस्टीगेशन में काफी विलंब होता है। हमने पहला फैसला यह किया कि चाहे हमारी स्टेट्स हों, यूनिशन टेरिटरीज हों, उनमें हमने फर्स्ट फेज में लगभग 150 इकाइयों को कायम किये जाने का फैसला किया है। इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स ऑन क्राइम्स अगेन्स्ट वूमैन, यानी आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट देश भर में एस्टेब्लिश किये जाने के संबंध में भी हमने फैसला किया है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कम्प्यूटर ऐडेड डिस्पेच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक इमर्जेंसी रिस्पांस सिस्टम कायम करने के भी कदम उठाये हैं। महिलाओं से जुड़े हुए मामले अदालतों में जाते हैं, लेकिन लम्बे समय तक उन पर फैसला नहीं हो पाता और वे पेंडिंग पड़े रहते हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के संबंध में भी राज्यों को एडवाइजरी दी है। अब जैसे दिल्ली में सभी जनपदों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जा चुके हैं। महिलाओं पर एसिड से जुड़े हुए जो हमले होते हैं, उस संबंध में भी हमने कई प्रभावी कदम उठाये हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी उस खुशी का इजहार कर देना चाहता हूं, जिसमें हमें राज्यों का सहयोग प्राप्त हुआ है। इस देश के सभी राज्यों ने विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम को नोटीफाई कर दिया है। गृह मंत्रालय से जो सुझाव दिया गया था, उसे सभी राज्यों ने नोटीफाई कर दिया है। हमने सी.आर.पी.सी. में भी कुछ परिवर्तन किए हैं। जैसे एसिड अटैक की कोई विक्टिम यदि किसी अस्पताल जाती है, वह चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या गवर्नमेंट अस्पताल हो, उसमें कोई भी डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देता है, तो उसे भी पनिश करने की व्यवस्था उसमें है। उसे भी दंडित किया जायेगा। संभवतः यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद सात साल या दस साल तक की सजा है। हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन संभवतः इतनी है। साथ ही एसिड अटैक की जो पीड़ित महिला होगी, उसका मुफ्त इलाज किया जायेगा। हमने यह भी एक व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदया, एसिड की बिक्री को कंट्रोल करने के संबंध में भी हमने कुछ व्यवस्था की है। इसके लिए हमने कुछ नियम नोटिफाई किये जाने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ हम एक सॉफ्टवेयर भी बना रहे

हैं, ताकि एसिड बिक्री को रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा अन्य बहुत सारे उपाय किये गये हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली की डी.टी.सी. बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स क्रूज के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करना, पार्किंग की जगहों पर, शॉपिंग मॉल्स पर सी.सी.टी.वी. कैमरे, बैक कैमरा लगवाना आदि। हमने एक नया ऐप हिम्मत(एच.आई.एम.एम.ए.टी.) जारी किया है। अगर महिला से कोई किसी भी प्रकार से छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो वह तुरंत बटन दबाये, लेकिन सभी प्रकार के मोबाइल्स पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैंने यहां के पुलिस विभाग और पुलिस कमिश्नर को यही निर्देश दिया है कि अब यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर प्रकार के मोबाइल्स में इस प्रकार का बटन होना चाहिए, जिसे दबाने पर पी.सी.आर. वैन अधिकतम से अधिकतम पांच से लेकर सात मिनट तक उस पीड़िता की रक्षा के लिए वहां पर पहुंच सके। इसके आतिरिक्त बहुत सारी बातें कही गयीं। निर्भया फंड के यूटीलाइजेशन के संबंध में भी कहा गया। निर्भया फंड का यूटीलाइजेशन नहीं हुआ था। उसके यूटीलाइजेशन का सिलसिला भी हमने यहां पर प्रारंभ कर दिया है। अब होम मिनिस्ट्री ने अब तक क्या तैयारी की है, उस संबंध में मैं यहां संक्षेप में बताना चाहूंगा।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के तहत वित्त पोषण के लिए तीन और प्रस्ताव तैयार किए हैं-बलात्कार, तेजाब हमले आदि जैसे जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये के कोष के साथ केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष स्थापित करने का प्रस्ताव; देश के 564 जिलों में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जांच इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव; वर्तमान पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए 88 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव। [हिन्दी] हमने ऐसे कई प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया है।

जहां तक जेलों के सुधार का प्रश्न है, वैसे यह पूरी तरह से स्टेट सब्जेक्ट है। जेलों के अंदर अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स का क्राउड बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हमने एक एडवाइजरी जारी की है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, मैंने उस समय लॉ मिनिस्टर को भी कहा था कि आपकी तरफ से एडवाइजरी जानी चाहिए

कि ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जिस धारा के अंतर्गत बंद हैं, यदि 50 परसेंट से अधिक समय तक वे जेल में रह चुके हैं तो उनकी रिहाई कैसे हो सकती है, इसे एश्योर करें। मैंने इस संबंध में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी तरफ से पत्र लिखा है।

ह्यूमेन ट्रेफिकिंग के बारे में चर्चा आई थी। मैं यहां ह्यूमेन ट्रेफिकिंग की चर्चा करना चाहता हूं, हमने इस संकट से निजात दिलाने के लिए कई एजेंसियों की मदद ली है। सरकार का प्रस्ताव है कि एंटी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डैवलप किया जाए और यह काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। हमने ह्यूमेन ट्रेफिकिंग को रोकने के लिए बेजबरुआ कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया है।

अब प्रश्न धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का सवाल आता है। मैं देखता हूं कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के सवाल पर हम लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आंकड़ें देना नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत होंगी। यदि कहेंगे तो दे दूंगा। ... (व्यवधान) इसी समय धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हुए हैं, ऐसा नहीं है। मंदिरों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, आक्रमण की नहीं हैं, हमलों की नहीं हैं, चोरी की भी हो जाती है, कुछ वैंडेलिज्म की भी हो जाती है। कुछ इस प्रकार की छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं, इसे जरूरत से ज्यादा तूल दिया जाता है। मैं समाज के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे सेंसिटिव इश्यू आए तो हम उसे पोलिटिसाइज करने की कोशिश न करें। बल्कि हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि यदि कहीं किसी धार्मिक स्थल पर... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): गृह मंत्री के रूप में आपने क्या कार्रवाई की है? ... (व्यवधान) आपने सदन को आश्वासन दिया था। ... (व्यवधान) गृह मंत्री ने स्वयं सभा में आश्वासन दिया। ... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): आप इस देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के नेता नहीं। ... (व्यवधान) देश में अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ, लेकिन आपने अल्पसंख्यक हमले का उल्लेख नहीं किया। ... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : एक अल्पसंख्यक दूसरे अल्पसंख्यक पर हमला कर रहा है। ... (व्यवधान) क्या करना है?... (व्यवधान) आगरा में क्या हुआ? ... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: इसलिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। केवल मंत्री जी का बयान ही रिकॉर्ड में जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, आगरा में हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए, आंध्र प्रदेश में हो जाए, तेलंगाना में हो जाए, केरल में हो जाए, कहीं भी हो जाए, क्या सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, हम स्टेट के मामलों में इंटरवीन करें? क्या संसद हमें इस बात की इजाजत देगा? क्या संसद को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है?... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: दिल्ली के बारे में क्या? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अब दिल्ली पर आइए। अब मैं दिल्ली की बात कहता हूँ। मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: संघ परिवार ऐसा कर रहा है। ... (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री राजीव प्रताप रूडी: वह ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? ... (व्यवधान) आपका क्या मतलब है कि संघ परिवार ऐसा कर रहा है? ... (व्यवधान) वह यह वाक्य कैसे बना सकते हैं? वह इसके माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल मंत्री जी का बयान ही रिकॉर्ड में जाएगा।

... (व्यवधान)... *

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : अगर ऐसा नहीं है तो आप आंखें क्यों बंद कर रहे हैं?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): हाँ, माननीय मंत्री जी। केवल आपका बयान रिकॉर्ड में चल रहा है और कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, 2012, 2013 और 2014 में और इससे पहले, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सभी स्थानों पर कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं। मैंने कहा कि हमें यदि पोलिटिकल बेनिफिट लेना होता तो सचमुच मैं इन आंकड़ों को यहां रख देता। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल: अब, आप गृह मंत्री हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया, यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: आप भाजपा के नेता नहीं हैं। ... (व्यवधान) आप अब इस देश के गृह मंत्री हैं। ... (व्यवधान)

श्री एम. आई. शनवास (वायनाड): आपने क्या कार्रवाई की है? हमारा प्रश्न है कि आपने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह: अगर माननीय सदस्यों को आंकड़े चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैं आंकड़ों का उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अनावश्यक इसके कारण बवाल खड़ा होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं बार-बार सदन में कह चुका हूँ और सदन के बाहर भी कह चुका हूँ कि हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने और चलाने के लिए नहीं करते बल्कि हम राजनीति समाज बनाने के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता।

मैं विशेषकर माइनोरिटीज़ को इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह भी भारत के नागरिक हैं, माइनोरिटी के लोग भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं। हम उनको अपने से अलग नहीं मानते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद अगर डी.एन.ए. टेस्ट कराया जाए तो काफी हद तक मिलेगा भी। अब क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, मैं यह नहीं कह रहा हूँ मिलेगा ही, मैं कह रहा हूँ कि मिल सकता है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैं कहना चाहूंगा कि, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी को, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करे। ... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदया, माननीय मंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उनका भाषण पूरा होने के बाद उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, यदि कहीं पर कोई कम्युनल टेंशन होती है या कहीं पर कम्युनल वायलेंस होता है, हमने उस संकट से निपटने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित किए हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूं, भारत का जहां तक सवाल है। भारत दुनिया का इकलौता देश है, ऐसा मैं क्यों कहता हूं क्योंकि यहां हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों और यहां तक यहूदियों तक के साथ पहले भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मैं समझता हूं आज भी हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाए। क्यों? आप सब शांतिपूर्वक मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद जो बोलना होगा बोलिएगा। यहां मोहम्मद सलीम साहब बैठे हैं, ई. अहमद साहब बैठे हैं। अहमद साहब बहुत सीनियर पोलिटीशियन हैं। ओवैसी साहब यहां अभी नहीं हैं। आपको मालूम होगा कि इस्लाम के 72 फिरके होते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इस्लाम के 72 के 72 फिरके पाए जाते हैं। यह दुनिया के किसी और देश में नहीं पाए जाते हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: यह आपका योगदान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : दुनिया का सबसे पुराना चर्च केरल में है। दूसरी या तीसरी सदी में यहां सेंट थॉमस चर्च की

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

स्थापना हुई थी। एक-दूसरे के प्रति सम्मान, एक-दूसरे के प्रति उनकी आस्था, एक-दूसरे के प्रति उनके विश्वास को सम्मान देने की भावना हमारे यहां पहले से ही रही है।

जहां तक इजरायल का सवाल है, सैकड़ों वर्षों तक दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में यहूदी लोग रहे। लेकिन जब यहूदियों का देश इजरायल बना तो इजरायल ने जो इतिहास लिखा है, उस इतिहास के पन्नों को कोई पलटकर देखें तो उस समय यहूदी ने कहा था कि दुनिया के सभी देशों में हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए थे। दुनिया का इकलौता देश यदि कोई था तो भारत था जहां पर यहूदियों के ऊपर कोई अत्याचार और जुल्म नहीं हुआ...(व्यवधान)

यह ऑन रिकॉर्ड है। मैं पारसी धर्म की बात करना चाहता हूं। उनकी जन्मभूमि ईरान है। लेकिन आज सचमुच केवल सम्मानजनक तरीके से ही पारसी यहां नहीं रह रहे हैं बल्कि यहां तक कि सेना प्रमुख के रूप में भी पारसी समुदाय के लोग जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह भारत की विशेषता है...(व्यवधान) इसलिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हर इश्यू पर राजनीति न करें, उनको राजनीति करनी है तो करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कृपया इस मुद्दे पर राजनीति न करें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, घर-वापसी और धर्मांतरण का जहां तक संबंध है, इन सब पर सारी कार्रवाई की अपेक्षा हमेशा केन्द्र सरकार से ही की जाती है कि दिल्ली में बैठी हुई केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों में भी जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर केन्द्रीय सरकार कार्रवाई करे। अध्यक्ष महोदया, आप इस हकीकत को जानती हैं कि यह संभव नहीं है...(व्यवधान)

राज्य सरकारें कम्युनल हार्मनी को मजबूत करने के लिए जो कार्रवाई करना चाहती हैं, वे कार्रवाई करें। हम उनके साथ हैं। घर-वापसी और धर्मांतरण के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन दुनिया का भारत ही इकलौता देश है जो कभी कन्वर्जन के भी सवाल को लेकर अपनी डेमोक्रेसी प्रोफाइल बदल देगा, इसकी भी

चिंता कभी अगर जिस देश ने नहीं की है तो वह भारत ने नहीं की है।...(व्यवधान) दुनिया का कोई भी देश अपनी डेमोक्रेसी प्रोफाइल को बदलने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देगा। आज यह हो रहा है।...(व्यवधान)

दुनिया का इकलौता देश भारत ही है कि ...(व्यवधान) सब नहीं हैं। बाकी थ्योरिटिकल कंट्रीज हैं। सेकुलर कंट्री भारत है।...(व्यवधान) दुनिया के हर देश में धर्मांतरण रोकने की मांग, एंटी-कन्वर्जन बिल लाने की मांग यदि होती है तो माइनॉरिटीज के द्वारा होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में माइनॉरिटीज यह मांग नहीं करती हैं कि एंटी-कन्वर्जन बिल लाया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि घर-वापसी हो। धर्मांतरण को लेकर, कम्युनल हार्मनी को लेकर जो प्रश्न-चिन्ह समय समय पर लगता रहता है और यदि उसको दूर करना चाहते हैं, यदि यह समस्त सदन सहमत हो और यदि एक बार फैसला कर दे कि हम यहां एंटी-कन्वर्जन बिल सर्वसम्मति से सदन में पारित करेंगे तो मैं समझता हूं कि फैसला हो गया।...(व्यवधान) इस संकट से निजात मिल गया।...(व्यवधान)

हमारे चंदमाजरा जी ने ...(व्यवधान) अहमद साहब, मैं आपका जवाब दूंगा। यदि अध्यक्ष महोदया की इजाजत होगी तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा।...(व्यवधान) वर्ष 1984 में सिख विरोधी जो दंगा हुआ था, उसमें पीड़ितों की सहायता के लिए हम लोगों ने भी कुछ प्रभावी कदम उठाये हैं और हमने कहा है कि पांच पांच लाख रुपये ऐसे सभी परिवारों को एडीशनल मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। मैं सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि तुरंत ही 1984 के सिख दंगों के जो भी पीड़ित हों, उनको तत्काल 5-5 लाख रुपये का एडीशनल कमपनसेशन मुहैया कराएं और उसका रीइम्बर्समेंट केन्द्रीय सरकार के द्वारा शीघ्र कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया जी, 1984 के कई दंगा पीड़ितों की यह शिकायत थी कि उस पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। जब से मैं गृह मंत्री बना हूं, मेरे सामने आ कर महिलाएं आंसू बहाती रही हैं। हम लोगों ने तुरंत फैसला किया कि उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए जस्टिस पी.पी. माथुर की अध्यक्षता में 23/12/2014 को हमने एक कमेटी बना दी। जस्टिस माथुर की इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उन उपर्युक्त रूप से गंभीर आपराधिक मामलों की छानबीन करने और फिर से

छानबीन करने के लिए श्री प्रमोद अस्थाना, आई.पी.एस. की अध्यक्षता में 12/02/15 को एक विशेष एस.आई.टी. का गठन कर दिया गया है जो कि 1984 के दंगों के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दायर किए गए थे और अब बंद कर दिए गए हैं।

महोदया, प्राकृतिक आपदा का विषय भी हमारे मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदा को बहुत ही गंभीरता से लिया है और भारत तथा नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, उसके पहले भी प्राकृतिक आपदाएं चाहे वह जम्मू-कश्मीर में आई हो, चाहे उड़ीसा में आई हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी भूमिका निभाई है। उस पर पुनः चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन वर्ष 2013-14 वित्तीय वर्ष के ई.एफ.पी.आर.एफ. आवंटन में पांच परसेंट का हम लोगों ने इजाफा किया है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में पांच परसेंट का इजाफा हुआ है लेकिन वर्ष 2015-16 में वार्षिक इजाफा 50 परसेंट का हुआ है। ... (व्यवधान) पहले इस चैलेंज से निपटने के लिए जितना धन रहता था, उसे बढ़ाकर हम लोगों ने डेढ़ गुना कर दिया है। यह काम हमारी सरकार ने अभी किया है। सभी राज्यों को जो धनराशि आवंटित हुई है उसकी डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सहायता प्रदान के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें भी काफी परिवर्तन कर दिया है। जिनकी जिंदगी चली जाती है उनके परिवार वालों को चार लाख रुपये देने का फैसला किया है। इसमें 75 परसेंट कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्यों के लिए रहता था और 25 परसेंट राज्यों का रहता था लेकिन सम्भवतः वह 90/10 परसेंट हो गया है। यूटीज़ के लिए पहले से ही 90/10 परसेंट रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी को भी हम लोगों ने री-ओरिएंटेशन और री-ऑरगेनाइजेशन किया है। उसको काफी इफैक्टिव बनाया है जिसके कारण कामयाबी हासिल हुई है। इस बार हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी एक बैठक में कहा कि इस बार की जो घटना हुई है, इसमें लोगों को संकट से उबारने में तो हम मदद करें ही लेकिन साथ ही साथ हम इस घटना से सीख लें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति यदि होती है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, वैसा सिस्टम भी हम अपने यहां डवलप करने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदया, बॉर्डर मैनेजमेंट और कोस्टल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम भी गृह मंत्रालय के पास है। इसमें हम लोगों ने इसे प्राथमिकता दी है। पिछले वर्ष के रिवाइज्ड एस्टीमेट 1785 करोड़ रुपये की तुलना

में इस वर्ष बजट एस्टीमेट में 3340.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यहाँ मैं इस बात से भी अवगत कराना उचित समझता हूँ कि रिवाइज्ड एस्टीमेट के 1785 करोड़ रुपये की तुलना में ऐक्चुअल एक्सपेंडीचर 1645 करोड़ रुपये हो गया है।

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) : उसमें सैलरी का कितना है?

श्री राजनाथ सिंह : कृपया उस विषय पर मत जाइए। [हिन्दी] मो. सलीम साहब ने कुछ प्रश्न उठाये थे। मैं उनके संज्ञान में कुछ नये फैक्ट्स लाना चाहता हूँ। भारत-बांग्लादेश सीमा की स्वीकृत 3326 किलोमीटर की फेंसिंग का 88 प्रतिशत काम पूरा कर दिया गया है। 293 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि भूमि अधिग्रहण में डिले हो रहा है, दूसरा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस और एनवायरमेंट क्लीयरेंस का मुद्दा है। लेकिन अब एनवायरमेंट क्लीयरेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं रह गयी है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आपकी वजह से यह पूरा नहीं हो सका है। लेकिन उसे भी मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर अतिरिक्त स्वीकृति 383 कंपोजिट बॉर्डर आउट पोस्ट में 74 पूरी तरह से पूरे हो गये हैं और 86 पर तेजी से काम चल रहा है और भूमि अधिग्रहण में डिले होने की वजह से ऐसा हुआ है।

बी.एस.एफ. के जवानों के संबंध में यह बात आयी कि बॉर्डर पर कैटल स्मग्लिंग हो रही है। मैं विनम्रतापूर्वक सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें संसद में भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, जिससे हमारी आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हों, जो किसी भी सूरत में डिमोर्लाइज हों। कहीं पर कोई घटना हो सकती है, कहीं किसी ने कुछ किया हो, लेकिन यदि सार्वजनिक रूप से हम किसी भी फोर्स को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो उसके मोराल पर क्या असर होगा? इसका सहज रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। फोर्स के मोराल को बनाकर रखना, मैं समझता हूँ कि इस देश की सुरक्षा के लिए भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है, जिसकी हमें चिन्ता करनी चाहिए। कैटल स्मग्लिंग हमारे लिए भी एक चुनौती है। मैं कैटल

स्मग्लिंग के संबंध में यह बतलाना चाहता हूँ कि जब हमने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, तो उसके पाँच-छः महीने के बाद ही जो प्रोग्रेस हुई है, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पहले जितनी कैटल स्मग्लिंग होती थी, उसमें अब 33 प्रतिशत की कमी आयी है। ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी इस हकीकत को स्वीकार कर रहा है। सीमाओं की सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए भी हमने बहुत सारे कदम उठाये हैं। मैं अब बहुत डिटेल् में नहीं जाऊँगा।

अब मैं कोस्टल सिक्योरिटी के विषय पर आ जाता हूँ। कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमने जो कार्य किये हैं, उसकी मैं चर्चा कर दूँ। एक तो जो फिशिंग वेसल्स हैं, जिन पर नावों से मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनकी संख्या इस समय 1.19 लाख है। हम लोगों ने प्रोविज़न किया है कि जिस फिशिंग वेसल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वह फिशिंग के काम के लिए नहीं जा सकता है। 155 मरीन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, 97 चेक पोस्ट बनाये गये हैं, 58 आऊट पोस्ट बनाये गये हैं, बैरक्स, बोट्स बनाये गये हैं। 204 लोगों को बोट्स प्रोवाइड किये गये हैं। फोर व्हिलर्स और टू व्हिलर्स की व्यवस्था भी की गयी है। साथ ही एक मुकम्मल व्यवस्था भी की गयी है, जो एक फिशर मैन के लिए भी आवश्यक है और देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। फिशर मैन की बोट, जो 20 मीटर से कम होती है, उसकी ट्रैकिंग की व्यवस्था, वह कहाँ गयी, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, इसकी ट्रैकिंग करने के लिए ट्रांसपोंडर्स लगाने का फैसला किया है और पूरी कोस्टल मैपिंग भी करा रहे हैं। सभी फिशर मैन के लिए हम लोगों ने बायोमीट्रिक कार्ड तैयार करने का काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उसे कभी कोई पड़ोसी देश अपने साथ ले गया, तो यह जानकारी हो सके कि वह कौन है, कहाँ का है, कैसे है और उसके परिवार के सदस्यों से भी उसका कांटैक्ट हो सके।

अध्यक्ष महोदया, पैरा-मिलिट्री फोर्स के बारे में जैसा सौगत रॉय जी ने कहा, हमारे पास छः-सात ऐसी पैरा-मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं। किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि असम राइफल्स को भी इनमें शामिल करना चाहिए। इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए गृह मंत्रालय पूरी तरह से काम कर रहा है। एक्सट्रीम कोल्ड में भी सी.ए.पी.एफ. के हमारे जवानों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले वर्ष कपड़े और उपकरण के लिए

143 करोड़ रुपये दिए। आर्म्स एंड एम्पूनिशन प्रोक्योर करने के लिए भी हमने धनराशि बढ़ाई है। पहले आर्म्स फोर्सेज के डी.जी. के पास पांच करोड़ रुपये तक की खरीद का अधिकार था कि आवश्यकता पड़ने पर वे आर्म्स एंड एम्पूनिशन्स खरीद सकते हैं। आते ही मैंने उसे पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया। उनका अधिकार बढ़ा दिया है। सी.ए.पी.एफ. के लिए एल.डब्ल्यू.ई. एवं जम्मू-कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा ए.के-47 एसाल्ट राइफल्स अब स्वीकृत की गयी हैं, क्योंकि राइफल्स पुरानी होने के कारण उनको प्रॉब्लम होती थी। सी.ए.पी.एफ. की ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। वर्ष 2015-16 में एक लाख 34 हजार 599 कर्मियों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग हमने की है। इसके आतिरिक्त कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिनसे पैरा-मिलिटरी फोर्सेज के हमारे जवानों का मोराल बना रहे। जो जवान हताहत होते हैं, उनके परिवारों को कंपनसेशन पहले 15 लाख रुपये मिलते थे, अब उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। हम अपने जवानों को अन्य क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, वह भी विचाराधीन है, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे चिन्ता है, जैसे भी हो, हमारे देश के जवानों का मोराल कभी डाउन नहीं होना चाहिए।

यहां पर पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात आई। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए गृह मंत्रालय के पास फंड रहता था, समय-समय पर हम उसे राज्यों को देते थे। 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जिसे अब ए.सी.ए. कहते हैं, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। सी.सी.टी.एन.एस. को भी समाप्त कर दिया है, लेकिन इस संबंध में प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से मेरी बात हुई है। हम लोग यह सोच रहे हैं कि इसका विकल्प कैसे तैयार किया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। वैसे पहले टोटल रेवेन्यू का 32 प्रतिशत राज्यों को मिलता था, उसे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे राज्यों को पहले की तुलना में ज्यादा धनराशि स्वतः प्राप्त हो गयी है, इसलिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से भी उसे राज्य खर्च कर सकते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, वीजा की प्रक्रिया को भी हमने काफी हद तक सिम्पलीफाई कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है। सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी होगी की ई-टूरिस्ट वीजा स्कीम हम लोगों ने प्रारम्भ कर दी है। यह स्कीम फिलहाल 45 देशों से आने वाले लोगों पर लागू होती है, लेकिन इसको बढ़ाकर 150 देशों तक हम ले जाना चाहते हैं। अब तक इस ई-टूरिस्ट वीजा स्कीम का लाभ लगभग एक लाख पन्द्रह हजार यात्री उठा चुके हैं। यह एक नई योजना है। साथ ही साथ, पी.आई.ओ. और ओ.सी.आई., दोनों का विलय कर दिया गया है क्योंकि एन.आर.आई. की यह बराबर शिकायत रहती थी कि इसके कारण उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया है, अब लोगों के पास केवल ओ.सी.आई. कार्ड होगा।

पाकिस्तान से मछुआरों की नौकाओं की वापसी की संबंध में एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था। मैं बताना चाहता हूँ कि मार्च, 2015 में 1.27 करोड़ रुपये के व्यय के साथ चार वर्षों में पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गयी, 57 भारतीय मछुआरा नौकाएं वापस लाई गयी हैं। यह कार्य लगभग 11 वर्षों के अंतराल पर हुआ है। इससे पहले वर्ष 2003-04 में पाकिस्तान द्वारा 53 भारतीय मछुआरा नौकाएं छोड़ी गयी थीं। सरकार की पहल से प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसके तहत भारत दोनों देशों द्वारा पकड़ी गई नौकाओं को छोड़े जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ निरंतर बातचीत का माध्यम अपना सकता है।

जहां तक आगामी योजनाओं की बात है, तो योजनाएं बहुत सारी हैं, सबके बारे में बताने में काफी समय लगेगा। सीमाओं के प्रबंधन में भी हमारी आगे की योजनाएं हैं...(व्यवधान) जैसे पंजाब सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा 983.01 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 711 किलोमीटर की लैट्रल और एक्सीएल सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है। गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और चौकसी बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुजरात के सरक्रीक में 30 और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में छः फ्लोटिंग सीमा चौकियों की स्थापना सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के लिए 523 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर निरीक्षण चौकियां यानि आउटपोस्ट्स हैं और ए.सी.पी.ज़. जैसे आश्रय स्थलों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी फेंसिंग को जहां फ्लड लाइटिंग होती है, उसकी संख्या काफी बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाने की कोशिश

कर रहे हैं। भारत-चीन सीमा पर 34 लगभग 800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को जिम्मा सौंपा गया है। वैसे ही मरीन पुलिस ट्रेनिंग के सम्बन्ध में हम लोगों ने एक प्रपोजल तैयार किया है और उसका अनुमोदन भी हमने दे दिया है। ऐसे कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने यूनियन टैरिटरीज के बारे में कहा था। लक्षद्वीप के माननीय सदस्य ने वहां पर विधान सभा के गठन की बात कही थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे प्रशासनिक कारण हैं, जिनकी वजह से वहां विधान सभा गठित करना सम्भव नहीं है। लेकिन जो भी माननीय सदस्य हैं मैं उन्हें आश्वासित करना चाहता हूं कि वहां की जो समस्याएं हैं, उन्हें लेकर हमसे मिलते रहिए, हमारे राज्य मंत्री किरन रिजीजू या हरि भाई चौधरी दोनों मौजूद हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। यूनियन टैरिटरीज से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने की हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जितनी भी यूनियन टैरिटरीज हैं, उनके विकास के लिए कई ऐसे प्रस्ताव जो अब तक विचाराधीन पड़े थे, कुछ नए प्रस्ताव भी हमने तैयार किए हैं और उन सब पर अंतिम निर्णय ले लिया है।

माननीय अध्यक्ष: उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है।

श्री राजनाथ सिंह : उसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भी है, दादर नगर हवेली है, पुडुचेरी भी है और चंडीगढ़ भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कुछ कहा, कमोबेश सबका जवाब मैंने देने की कोशिश की है। सेंसस में कटौती के बारे में इन्होंने कहा है कि कुछ की गई है। रिवाइज एस्टीमेट में कुछ हुआ होगा, उसे मैं देख लूंगा कि क्या हुआ है, क्योंकि यह छूट गया है और देख नहीं पाया हूं।

अलगाववादियों के खिलाफ सरकार का नरम रुख है, ऐसा यहां पर कहा गया। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी से कि ऐसा नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, वहां कुछ लोग बराबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं। कुछ अलगाववादी हरकतें वहां चलती रहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हरकतें बंद होनी चाहिए। आपने देखा कि एक घटना हुई, उस पर तुरंत हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की और उन्हें बिहाइंड बार किया गया है।

हुकुम सिंह जी ने आई.एस.आई.एस. के कारण जो संकट सारे विश्व में पैदा हुआ है, उसकी चर्चा की है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है। दुनिया में भले ही दूसरे देशों में आई.एस.आई.एस. की गतिविधियों से लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत के मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे डिस्क्रेज करने का काम किया है।

अपराह्न 02.00 बजे

[हिन्दी]

अपने परिवार के सदस्यों ने, उनके माता-पिता ने उनको बराबर डिस्क्रेज किया है। मैं उनका सदन के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ई.अहमद साहब और सलीम साहब यह बहुत बड़ा काम हुआ है।...(व्यवधान) हुकुम सिंह जी ने नारी सुरक्षा और पुलिस जवानों के लिए बैटर इक्वीपमेंट्स के बारे में कहा, जिस पर मैं बोल चुका हूँ। प्रेमचंद्रन जी ने प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि के बारे में बोला है, इसके लिए पर्याप्त धनराशि दी गयी है, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूँ। मछुआरों की समस्या के बारे में आपने कहा, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूँ। सौगत राय जी ने कानून-व्यवस्था की चर्चा की, जो कि राज्य का विषय है। जहां तक माओवाद की समस्या का सवाल है, आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा की है। हमारा इसमें दो मत नहीं है कि राज्य सरकार ने माओवाद से निजाद के लिए कार्रवाई की है और मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं इसके लिए वहां की सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी देश के लिए काम कर रहे हैं और हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम भारत को विश्व की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। गोरखालैंड की चर्चा मैं कर चुका हूँ। मोहम्मद सलीम साहब की बात का जवाब भी आ चुका है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : वर्ष 2014-15 के रिवाइज़ बजट में कटौती हुई थी, उसके बारे में मैंने पूछा था।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हो सकता है कि पहले जितना खर्च करना चाहिए था, उतना नहीं किया गया। निधाररित समय में जितना खर्च करना चाहिए था, उतना नहीं किया गया हो, इसलिए रिवाइज़ एस्टीमेट में कम हो गया था। यह तो आप जानते ही हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप हर बात का जवाब नहीं देते।

श्री राजनाथ सिंह: मैं पहले ही अपने उत्तर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण का उल्लेख कर चुका हूँ... (व्यवधान) लक्षद्वीप के बारे में मैं जवाब दे चुका हूँ। [हिन्दी] लक्षद्वीप में महिला विधानसभा के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूँ और गुजरात के समुद्री रास्ते से जो आते हैं। श्री विजय पांडा जी ने भी कुछ सवाल किए थे कि आवंटन में कमी आ रही है, एलोकेशन की बात भी कही है, लेकिन उन्होंने अच्छी बात कही है कि माओवादी क्षेत्रों में डेवलपमेंट होना चाहिए। बजट के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। सुरक्षा बलों के परिवार वालों की अधिकतम मदद करनी चाहिए और एन.डी.आर.एफ. की चर्चा की है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बारे में भी कहा है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो कश्मीरी पंडित जम्मू-कश्मीर की धरती से किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, उनका पुनर्वास करना हमारी प्रतिबद्धता है...(व्यवधान) वहां के मुख्यमंत्री आए थे। उनसे हमारी बात हो गई है और पहली किश्त में उन्होंने पचास एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया है...(व्यवधान) शैलेश कुमार जी, जयप्रकाश जी, आर.के. सिंह जी, चंदूमाजरा जी और एम.आई. शाहनवाज साहब आदि सदस्यों ने भी जो समस्याएं उठाई थीं कमोबेश मैंने सबका जवाब दे दिया है। ई. अहमद साहब का भाषण मैं उस समय सुन नहीं पाया था लेकिन बाद में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने अपनी तरफ से सभी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है...(व्यवधान)

अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पहले केवल असम की सीमा तक ही सीमित था लेकिन कभी-कभी कुछ उग्रवादी तत्व जो अरुणाचल में चले जाते थे शायद उसके कारण बीस किलोमीटर तक लग गया है। लेकिन समय पर उसे हम रिव्यू भी कर सकते हैं। सौगत राय जी आपने

एल.डब्ल्यू.ई. एरियाज में सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एक सरेंडर पॉलिसी बनी है और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पहले टुकड़ों में एल.डब्ल्यू.ई. का पॉलिसी थी, पहली बार हमने एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव और इंटिग्रेटिड एल.डब्ल्यू.ई. की पॉलिसी तैयार की है और सभी स्टेट्स को भी उसे भेजा है, यदि आपको इस पर अपना कोई ओपिनियन देना हो तो आप दे सकते हैं। हम उसे और परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री विनायक राउत जी ने कश्मीरी पंडितों की बात कही थी, टी.नरसिम्हन जी ने भी सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया को डबल एज सोर्ड, दुधारी तलवार कहा, डिसेप्टिव कंट्रोल की बात कही है, साइबर क्राइम से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। मो.सलीम साहब के द्वारा भी उठाए गए लगभग सारे सवालों का जवाब आ गया है। श्री वाई.एस. आविनाश रेड्डी, श्री शैलेश कुमार, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा के सवालों के जवाब भी आ गये हैं। श्री ओवैसी साहब ने भी यहां कुछ सवाल खड़े किये हैं, उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट के संबंध में ...*(व्यवधान)* अब वह यहां हैं नहीं, इसलिए रहने देते हैं। लेकिन संदेश पहुंच जायेगा। हमने कोई काम गैरकानूनी नहीं किया है, अटार्नी जनरल और लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेकर ही कोई काम हुआ है, हमने उसके बियांड जाने की कोशिश नहीं की है। श्री एम. शाहनवाज, श्री आर.राधाकृष्णन ने भी पांडिचेरी को स्टेटहुड देने की बात कही है, लेकिन फिलहाल अभी हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे भविष्य में देखेंगे।

ई. अहमद साहब चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी रहे, यह सारा देश चाहता है और हम भी चाहते हैं। श्री जॉयस साहब केरल के सांसद हैं, उन्होंने नेशनल इंटिग्रिटी एवं कम्युनल हार्मनी पर चर्चा की है। सत्यपाल सिंह जी संभल से हैं, उन्होंने पुलिस की सैलरी और एलोकेशन की बात की है, पुलिस रिफार्म्स की बात की है। मैं इन सारी बातों के कमोबेश उत्तर दे चुका हूं और हो सकता है कि किसी का नाम यदि छूट गया हो तो यदि उसकी भी कोई आशंका होगी तो मैं उसका समाधान देने के लिए तैयार हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मुझे भाषण नहीं देना है। मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी ने विस्तार से बहुत सारी बातें कह दी हैं, इसलिए अब मुझे उन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि आपने भाषण में कहा है, लेकिन देश भर में खास

तौर से मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक हैं, इनके मन में जो एक भय धर्म परिवर्तन के नाम पर पैदा हो गया है, इस पर आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : अध्यक्ष महोदया ने श्री मुलायम सिंह जी को बोलने का समय दिया है, आप लोग बीच में ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने गृह मंत्री जी को कितने ध्यान से सुना। खास तौर से इन दोनों के धर्म परिवर्तन के बारे में आपने जिक्र तो किया है, लेकिन आपको इस पर खुद पहल करने की जरूरत है और यह सवाल न उठे, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता पर असर पड़ेगा।

दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि चर्चों में तोड़फोड़ के बारे में आपने कहा है। अब मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन अब जब आपकी जानकारी में आ ही गया है तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी धर्म पर या किसी के धर्म स्थल पर किसी को किसी तरह का हमला करने का अधिकार नहीं है और न उसको बर्बाद करना चाहिए। वह देश की एकता के लिए हैं। जहां तक कहीं माओवाद और कहीं नक्सलवाद के नाम पर जो हो रहा है, उस पर गृह मंत्री जी मैं एक राय दे रहा हूं कि निर्दोष आदिवासियों को न मारा जाए, यह आप ध्यान रखिये। चूंकि अभी निर्दोष आदिवासी मारे गये हैं, इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में बीस लोगों को चंदन के तस्कर बताकर मार दिया गया। यह बिल्कुल गलत किया गया है। वे लोग तस्कर नहीं थे। आपने जांच कराई होगी, आपकी जानकारी में आ गया होगा, हमारी जानकारी में है, यहां तमिलनाडु के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तस्करों के नाम पर इतनी बड़ी तादात में निर्दोष लोगों की हत्या करना देश के लिए शर्म की बात है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने जो वायदे किए हैं, उसमें एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन वायदों को पूरा आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह विश्व हिंदू परिषद् क्या बोल रही है? इसको बंद कीजिए। अखबारों में छपा है कि विश्व हिंदू परिषद् क्या बोल रही है, इस पर आपको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद् के प्रमुख कह रहे हैं कि पृथ्वी राज चौहान के बाद हिंदू राष्ट्र भारत में बनेगा। इस पर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जब सब जगहों पर यह बात आई है, उस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप सबका हैड इस

तरह की बात कहेगा तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ, मैंने लंबा भाषण नहीं दिया है, आपने सारे वालों के उत्तर भी दे दिए हैं, लेकिन इन दो-तीन बातों पर मैंने जो कहा है, उनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसका असर अच्छा नहीं जाएगा, न आपके लिए, न देश के लिए और न आपकी सरकार के लिए अच्छा होगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, मैं मुलायम सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

डॉ. एम. थंबीदुरई (करूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, गृह मंत्री जी ने, अपने भाषण में राज्य सरकारों द्वारा, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का उल्लेख किया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए सहायता अब बजट से छीन ली गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चूंकि 14^{वें} वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को सहायता के रूप में 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की है, इसलिए हस्तांतरण किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से, इसे हटा लिया गया था।

मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस हस्तांतरण के कारण, राज्य सरकारों को 1,42,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, बजट में, 1,33,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इसलिए, राज्य सरकारों को केवल लगभग 8000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध होने जा रहे हैं।

वे कह रहे हैं कि कानून और व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण है और यह राज्य का विषय है। हालांकि यह राज्य का विषय है, यदि वह भारत में अच्छी आंतरिक सुरक्षा चाहते हैं, तो राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सीमा सुरक्षा का भी उल्लेख किया है।

अधिकांश राज्य सरकारें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता नहीं देती, तब तक उनके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने अभी-अभी सभा को आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, वे प्रधानमंत्री से परामर्श

करेंगे और इसके बारे में कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अच्छी राशि देंगे।

दूसरा, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य, श्री मुलायम सिंह यादव ने एक मुद्दा उठाया है जिसे हमने आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के 20 आदिवासी मजदूरों की हत्या के संबंध में सभा में भी अक्सर उठाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मुद्दे को पहले ही उठा चुका है। लेकिन केंद्र सरकार का क्या रुख है? पिछली बार जब उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि, वह तथ्यों को प्राप्त करेंगे, सभा के सामने आएंगे और जानकारी देंगे। यह एक अंतरराज्यीय मुद्दा है जहां आदिवासियों की हत्या की गई है। क्या वह उस जानकारी को सदन के साथ साझा कर सकते हैं जो उन्हें मिली है? वह सुस्त नहीं हो सकता। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मुद्दे को उठाया है, तो केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा इस नरसंहार में शामिल आदिवासियों के रूप में की गई कार्रवाई के बारे में क्या?

मुझे उम्मीद है कि वह उन 20 आदिवासियों के बारे में कुछ जानकारी देंगे, जो तमिलनाडु के मजदूर हैं, जिनकी आंध्र प्रदेश में हत्या कर दी गई है। मैं इस मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री से जवाब प्राप्त करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे जी, कृपया केवल एक स्पष्टीकरण पूछें। [हिन्दी] लंबे भाषण दोबारा नहीं होंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ और गृह मंत्री जी ने यहां पर उत्तर में यह कहा है कि बजट में कट नहीं हुआ है। लेकिन बजट का टेबल आइटम फेसिंग बजट कट्स अगर आप देखेंगे तो एक्स्पेंडिचर के जो आइटम हैं, उनमें 25 आइटम्स के ऊपर आपने कट किया है। अगर यह असत्य है तो आप जो भी शिक्षा देंगे, उसे मैं मानूँगा, लेकिन अगर यह सत्य है तो महोदया आप गृह मंत्री को क्या शिक्षा देंगी।

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी को सजा नहीं दे सकती हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यहाँ असत्य चीजें नहीं रखनी हैं। इन 25 आइटम्स में उन्होंने जो कुछ कमियाँ कीं, माडर्नाइजेशन से लेकर सभी चीजों पर की हैं, यह आपके सामने है, मैं आपके माध्यम से उनको यह देना चाहता

हूँ...(व्यवधान) यह हँसने की बात नहीं है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यह आपका डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप क्लेरिफिकेशन पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दूसरी चीज, जो अभी माइनोरिटीज के बारे में खासकर चर्च हो या माइनोरिटी मुस्लिम्स के विषय में हो, विशेषकर दलितों के विषय में हो, ये सारी चीजें हैं। आपको एक स्ट्रांग मैसेज अपने लोगों को भी देना चाहिए और देश में जो भी ऐसे विषय पर हमेशा बात करते हैं या लोगों को उकसाते हैं, उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए। वह मैसेज आपने यहाँ पर कभी नहीं दिया है। सिर्फ आपने इतना ही कहा कि यह कहना ठीक नहीं है।

महोदया, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर बार-बार कहा। इनके नवरत्न, मैं फोटो के साथ देता हूँ, आपके नवरत्न ने क्या-क्या बातें बोली हैं, खासकर समाज तोड़ने की बात हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन आप हमेशा यह कहते रहे हैं, उनको हमने वार्न किया है, हमने उनको बोला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, भाषण मत करिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह क्या संदेश देने जा रहे हैं? इसका मतलब है कि उनके निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। [हिन्दी] यह बात अगर कोई बाहर करते हैं तो मैं मान लूँगा कि इनके कंट्रोल में वह नहीं है, लेकिन आपके लोग जब बार-बार बोलते हैं और फिर भी वे हमेशा वही बात करते हैं तो क्या वे आपके कंट्रोल में नहीं हैं, क्या वे आपकी बात सुनते नहीं हैं? ऐसे लोगों को या तो पार्टी से निकाले या ऐसे लोगों को बर्खास्त करें।...([अनुवाद] व्यवधान) आप उनका खंडन कर रहे हैं। ... [हिन्दी] (व्यवधान) ये चीजें आपके सामने हैं। ... (व्यवधान) सभी हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं जानना चाहता हूँ कि इनके बारे में आपने क्या एक्शन लिया है? ...(व्यवधान)
इसके बारे में जो एक्शन लिया है, वह बताना चाहिए। ...(व्यवधान)

तीसरी चीज, जो जम्मू-कश्मीर का मामला है, मशरत आलम के बारे में, उनके ऊपर जो एक्शन लिया है, वह भी आपको स्पष्ट करना चाहिए।...(व्यवधान) उसको जो रिलीज किया है, उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया, वह भी आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, यदि कोई हो।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आखिर में मैं यह कहूँगा कि वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक आप ही थे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? आपकी बात हो गई है। ऐसा नहीं होता है। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक तो आप ही थे। उस वक्त सिखों के बारे में कम्पैशनिएट ग्राउंड पर जो-जो करना था, आप वह कर सकते थे, लेकिन बार-बार यह मुद्दा पॉलिटिकली आप उठाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन पॉलिटिक्स में उसे लाने की कोशिश करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, फिर से नहीं, यह दोबारा भाषण नहीं हो रहा है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह मीठी गोली है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको क्लेरिफिकेशन पूछना है, फिर से दोबारा भाषण नहीं करना है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, उन्होंने तो कहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा...(व्यवधान)

इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो चार मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, सिर्फ मीठी गोली देने से काम नहीं चलता है। आपको सख्त इसके बारे में कहना पड़ेगा ताकि ऐसी चीजें सारे देश में बन्द हों और शान्ति रहे...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गई।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: शान्ति बनाए रखना आपका कर्तव्य है। आखिरी में एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ...(व्यवधान) मैं कविता कहूँगा और उनको बताऊँगा...(व्यवधान)

"उदित प्रभात हुआ,

फिर भी छाई चारों ओर उदासी, अंधेरा।

ऊपर मेघ भरे बैठे हैं, किन्तु धरा प्यासी की प्यासी।

जब तक सुख के स्वप्न अधूरे,

पूरा अपना काम न समझो।

विजय मिली, विश्राम न समझो।"

आपको विजय मिली है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विश्राम से मत सोओ। इतनी समस्याएँ आपके सामने हैं। सत्य से दूर मत जाओ, सत्य से कहो। इसलिए जो चीज़ आपके सामने है, देश के हित में, आप यह सब क्लैरिफिकेशन हमारे सामने रखियो।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी: महोदया, माननीय गृह मंत्री जी से मेरा एक बहुत छोटा अनुरोध है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: केवल एक स्पष्टीकरण की अनुमति है।

श्री कल्याण बनर्जी : मेरा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि किसी भी महिला के संबंध में किए गए किसी भी अपराध के संबंध में कानून के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना पर विचार किया जाए, जिसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जो अपने ससुराल में पीड़ित हैं। वर्तमान में कोई विशेष न्यायालय नहीं है। महोदय, कृपया इसके बारे में सोचें।

मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि पूरे देश में केवल एक ही मोबाइल नंबर देने के बारे में सोचें ताकि मोबाइल नंबर देश की महिलाओं के कानों में जा सके। यदि, किसी भी समय, कोई अपराध किया जाता है, जिसमें उसकी सास के घर में रहने वाली महिला भी शामिल है, रात के 11 या 12 बजे भी, यदि वह फोन करती है तो उपयुक्त पुलिस अधिकारी को उसके संबंध में कदम उठाने चाहिए। यदि पुलिस अधिकारी की ओर से कोई विफलता है, तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक दंडात्मक खंड होना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह ऊपर आ रहा है।

आधुनिक समय में, कृपया एक महिला को उसके ससुराल में हुई मानसिक चोट के बारे में सोचें। हमें एक महिला की मानसिक चोट की परिभाषा पर पुनर्विचार करना होगा, यहां तक कि उसके ससुराल में भी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मरीन एकेडमी के निर्माण का उल्लेख किया। 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो रिवीजन लिया, कोस्ट गार्ड को अपटुडेट ट्रेनिंग देने के लिए मरीन गार्ड के निर्माण के काम का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के पालघर में 308 एकड़ ज़मीन उसके लिए दी गई। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने वहाँ जाकर, विजिट करके सब फाइनल किया लेकिन अभी समझ में आता है कि यह मरीन गार्ड की एकेडमी द्वारका में एस्टेब्लिश करने का सरकार प्रयास कर रही है। मैं उस पर ऑब्जेक्शन लेता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर से इस एकेडमी को उधर ले जाना उचित नहीं है। क्योंकि पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के बीच में पालघर है और इस मरीन एकेडमी में नेशनल कोस्ट गार्ड का भी हक रखा जाएगा, ऐसा उस समय आतंकवादी हमले के बाद डिक्लेयर किया था। माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हो गया। बार बार वही बात नहीं बोलें। उन तक बात पहुंच गई है।

... *(व्यवधान)*

श्री गजानन कीर्तिकर: यह जो बदलाव किया है, उसको रद्द करके पालघर में यह मरीन एकेडमी एस्टेब्लिश करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी(ढेंकनाल): मैं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि, महोदया, ओडिशा में 400 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है। दुर्भाग्य से, तट रेखा की कोई उचित सुरक्षा नहीं है। कोई तटरक्षक स्टेशन नहीं है जिसके कारण कुछ पड़ोसी देशों से बहुत घुसपैठ कर रहे हैं जिनका मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ओडिशा में एक उचित तटरक्षक बल की स्थापना पर विचार करें, जिसका मुख्यालय अधिमानतः गोपालपुर या पारादीप में हो, जो ओडिशा के तटीय क्षेत्रों का संचालन और सुरक्षा कर रहा हो।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, बिहार नक्सल प्रभावित उग्रवादी क्षेत्र है और बिहार के कई जिले इससे प्रभावित हैं। जिस बांका क्षेत्र से हम आते हैं, वह और भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय इत्यादि उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि उनके एक्शन प्लान के तहत बांका को लेकर उसके चतुर्दिक विकास के कामों को अंजाम देने का काम किया जाये। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : विधूड़ी जी, आप क्या पूछ रहे थे? अब हो गया, आपके ही गृह मंत्री हैं। वे बात करेंगे, बैठिये।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली पुलिस के बारे में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ब्रॉट डैडबॉडी मिलती है तो पुलिस वाले सिपाही उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उनको सरकार कोई खर्चा नहीं देती, उसे सिपाही अपनी जेब से देते हैं। अगर वे जेब से देते हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, इसलिए सरकार की तरफ से यह व्यवस्था हो और ए.सी.पी. के स्तर का कोई अधिकारी उसके बिल को सिपाही को, कांस्टेबल को दे, जिससे वह आराम से स्कूटर में डालकर पेशेंट को ले जाये, कई एक्सीडेंट के मामले होते हैं तो वे देखते रहते हैं, किसकी गाड़ी पकड़ें, किसकी न पकड़ें, क्योंकि, कांस्टेबल या हवलदार अपनी जेब से कहां से पैसा देगा, यह मेरा निवेदन है। ऐसा एक्सपेंडीचर दिल्ली पुलिस के बारे में बढ़ाना चाहिए, इस बात को लेकर मेरा निवेदन है।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह जी यादव ने एक तो आन्ध्र प्रदेश की जो घटना हुई है, जिसमें 20 लोग मारे गये हैं, उसकी चर्चा की है। पिछली बार जब यह विषय सदन में उठा था तो मैंने आपको आश्चस्त किया था कि जब कभी आपका निर्देश होगा तो इस सम्बन्ध में आकर मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, जो भी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त होगी, वह मैं सदन को दे दूंगा। यदि आप कहेंगी तो मैंने इसकी रिपोर्ट मंगवा ली है, उसको भी मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)* उन्होंने एस.आई.टी. बना दी है और एक पी.आई.एल. भी वहां की कोर्ट में फाइल हुआ है, लेकिन इसमें और मुझे क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो यह

जानना चाहता हूं कि जो भी कांस्टीट्यूशनल प्रोवीज़ंस हैं, आप मुझे बताइये कि मुझे क्या करना चाहिए जो आप बताएंगे, वह मैं कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप सी.बी.आई. इन्क्वायरी बिठा दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह: कैसे सी.बी.आई. इन्क्वायरी, कैसे कर दें, नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना करिये।

श्री राजनाथ सिंह: खड़गे जी, आप जानते हैं कि कैसे हो सकता है। स्टेट के मामले में विदाउट स्टेट रिकमेंडेशन हम उठाकर किसी की सी.बी.आई. इन्क्वायरी कर दें तो क्या हालत होगी। कहां जाकर इण्टर स्टेट रिलेशन खड़ा होगा? आप जानते हैं, मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, आदिवासियों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, किसी निर्दोष आदिवासी की यदि हत्या होती है, यदि जानकारी मिल जायेगी तो उस सम्बन्ध में मैं सभी राज्य सरकारों से भी अपील करना चाहता हूं कि सख्त कार्रवाई की जाये और यदि मेरे संज्ञान में कोई मामला आएगा तो मैं सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आर्गेनाइजेशन क्यों न हो, यदि आदिवासियों की हत्या करेगा तो मैं किसी भी सूरत में उसे माफ नहीं करूंगा। यही हुआ है और हम यही करेंगे।

उन्होंने कहा है कि चर्चे के ऊपर अटक हो रहे हैं तो हमारी सभी राज्य सरकारों से अपील है कि इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो, कहीं पर भी ऐसे जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहां पर यदि किसी प्रकार का कोई अटक होता है अथवा उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह हम करेंगे। अगर मैं ही जो घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई है, उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई है, अध्यक्ष महोदया, लेकिन उस राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उसके सम्बन्ध में मैं फिलहाल नहीं कह सकता हूं।...*(व्यवधान)*

थम्बी दुरई जी ने पुलिस आधुनिकीकरण की बात कही है, मैंने कहा है कि 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के कारण यह प्रोवीज़न अब नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है

और वित्त मंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई है। हम देखेंगे कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। हम चाहते हैं कि पुलिस आधुनिकीकरण हो, यह आवश्यक है, होना चाहिए। खड़गे जी ने एक्सपेंडीचर कट की बात कही है। इस समय बजट के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन मैंने टोटल आपको बताया कि बजट एलोकेशन में कोई कमी नहीं हुई है, क्योंकि, पहले 74 हजार करोड़ था, वह बढ़कर 78 हजार करोड़ हो गया। किस मद में कितना रुपया कम हुआ, कितना अधिक हुआ, मैं समझता हूं कि इस डिटेल में जब कभी कोई केवल इसके बजट पर ही चर्चा होने लगेगी तो मैं वह करने को तैयार हूं...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसी के ऊपर तो हमने बोला है।

श्री राजनाथ सिंह : नहीं। खड़गे जी, अगर आप उसे प्वायंट-आउट कर दीजिएगा तो मैं आपको पत्र लिखकर उसका जवाब भेज दूंगा।

दूसरी चीज, यहां पर कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द का सवाल खड़ा हुआ। खड़गे साहब ने अपेक्षा की है कि इस संबंध में सरकार की तरफ से स्ट्रॉंग मैसेज दिया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्री के नाते, सरकार की ओर से कहता हूं और सभी राज्य सरकारों से अपील करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि कहीं भी कोई अगर कम्युनल हार्मोनी को तोड़ने की कोशिश करता है तो राज्य सरकारों को उस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकारें प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? अगर दिल्ली में कोई करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि और कहीं कोई इसे करता है तो आप कार्रवाई कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : चर्च के ऊपर हमले यहीं हुए हैं।

श्री राजनाथ सिंह : उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। लेकिन, देश के किसी भी राज्य में अगर किसी के द्वारा कम्युनल हार्मोनी को तोड़ने का प्रयत्न होता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी अगर सीधे केन्द्र सरकार के ऊपर फिक्स की जाती है तो मैं समझता हूं कि केन्द्र की सरकार के साथ यह इंसाफ नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर देते जाइए। अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। इस तरह तो बहुत समय लगेगा।

श्री राजनाथ सिंह : नहीं, हम कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

कल्याण बनर्जी जी ने एक इश्यू उठाया था...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब वे चले गए हैं। [अनुवाद] वह इसके बारे में चिंतित नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : वे कोई भी नवरत्न हों, यह पता नहीं कि वे नवरत्न किसके हैं, क्या हैं, इसे भगवान जानें।...(व्यवधान) लेकिन, इसे रोकने के लिए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। मैं बस इतना ही कहूंगा।

कीर्तिकर जी ने मरीन गार्ड एकेडमी की बात कही है कि वह महाराष्ट्र में था और अभी दूसरे स्थान पर चला गया है। कीर्तिकर जी, मैं इसे दिखाऊंगा कि यह क्या है? इस समय मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

तथागत सत्पथी जी ने कोस्ट गार्ड के सिस्टम को और स्ट्रेंथेन करने की बात कही है। हम उसे देखेंगे।

जय प्रकाश नारायण यादव जी ने सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (एस.आर.ई.) के अंतर्गत बांका के विकास की बात कही है। हम इसे देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदया, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लिया है, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय से संबंधित डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को वे पारित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, सदस्यों द्वारा गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के लिए कई कटौती प्रस्ताव पेश किए गए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन के वोट के लिए एक साथ रखूंगी?

श्री भर्तृहरि महताब(कटक): महोदया, हम चाहते हैं कि हमारे कटौती प्रस्तावों को अलग से रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा सदन के मतदान के लिए पेश किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 4 और 28 से 30 को रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा सदन के मतदान के लिए पेश किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 5 से 11 रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जयप्रकाश नारायण यादव द्वारा सदन के मतदान के लिए पेश किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 12 से 19 और 24 रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कोई बोलना नहीं होता है, सब क्लेरिफिकेशंस हो चुके हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप अपने कटौती प्रस्तावों के लिए दबाव डाल रहे हैं?

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं दबाव डाल रहा हूं और मैं एक मिनट के लिए एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, तो मैं खुश रहूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 25 और 26 को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मूव हो चुका है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव के लिए दबाव डाल रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, गृह मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: इसलिए, वह दबाव नहीं डाल रहे हैं।

अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 31 को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत किया गया।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं सदन के मतदान के लिए श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 32 और 33 रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

“आदेश पत्र के चौथे कॉलम में दर्शाई गई राजस्व खाते और पूंजी खाते की राशि से अधिक नहीं संबंधित राशि भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से प्रदान की जाए, ताकि मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 53 से 57 और 99 से 103 के विरुद्ध दूसरे कॉलम में दर्ज मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के क्रम में आने वाले प्रभारों का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि पूरी की जा सके।

गृह मंत्रालय के संबंध में अनुदान माँग 2015-16 लोक सभा द्वारा मतदान किया गया

मांग की संख्या.	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
53	गृह मंत्रालय	253,68,00,000	26, 40,00,000
54	कैबिनेट	69,50,00,000	-
55	पुलिस	9179,75,00,000	2297,59,00,000
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	480,17,00,000	66,43,00,000

57	केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को हस्तांतरण	282,67,00,000	12,00,00,000
99	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	547,79,00,000	95,61,00,000
100	चंडीगढ़	538,88,00,000	95,16,00,000
101	दादरा और नागर हवेली	99,75,00,000	51,49,00,000
102	दमन और दीव	229,59,00,000	67,32,00,000
103	लक्षद्वीप	162,47,00,000	30,00,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को पारित किया जाता है।

अपराह्न 02.38 बजे**(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

माननीय अध्यक्ष: सभा में अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32 पर चर्चा और मतदान होगा।

प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि आदेश पत्र के चौथे कॉलम में दर्शाई गई राजस्व खाते और पूंजी खाते की राशियों से अधिक न होने वाली संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32 के विरुद्ध उसके दूसरे कॉलम में दर्ज मांग के शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के क्रम में आने वाले प्रभारों को चुकाने के लिए आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाए।"

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंध में अनुदान मांग (2015-16) लोक सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत की गई

मांग की संख्या	मांग का नाम	लोक सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
32	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	314,80,00,000	8,13,00,000

माननीय अध्यक्ष: सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके वर्ष 2015-2016 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंध में अनुदान की मांग के प्रस्तावों में कटौती की गई है, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर तालिका में पर्ची भेज सकते हैं जिसमें वे कटौती प्रस्तावों के क्रम संख्या का संकेत देते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो जाएंगी, ही प्रस्तुत माने जाएंगे।

प्रस्तुत किए गए रूप में माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची उसके तुरंत बाद सूचना पट्ट पर डाल दी जाएगी। यदि सदस्यों को सूची में कोई विसंगति मिलती है, तो वे कृपया इसे तुरंत पटल पर मौजूद अधिकारी के संज्ञान में ला सकते हैं।

अब, श्री निनोंग इरिंग

[हिन्दी]

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

अपराह्न 02.39 बजे

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

[हिन्दी] उपाध्यक्ष जी, आज वन और पर्यावरण मंत्रालय के विषय में हमारी पार्टी की ओर से बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी की लीडर, अध्यक्ष महोदया सोनिया गांधी जी और संसदीय दल के नेता श्री खड़गे जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का एक मौका दिया। मैं अरुणाचल प्रदेश से चुन कर आया हूँ, वहां लगभग 83 प्रतिशत वन क्षेत्र है। जब हम दिल्ली या अन्य राज्यों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, वनों का सर्वनाश हो रहा है,

हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट पेश करते समय कम से कम 26 बार इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है और 22 बार ग्रोथ के बारे में बोला है। हम भी चाहते हैं कि देश में विकास होना चाहिए और हम विकास की बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर सारी दुनिया चिंतित है, उन्होंने एक भी शब्द क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट या डिग्रेडेशन के बारे में नहीं कहा है। शायद, इस पर भी बहुत बहस होगी। मेरे बाद शायद बी.जे.पी. के सदस्य इस विषय पर बोलेंगे, वे हमारी खामियों के बारे में बोलेंगे। बहुत ही वरिष्ठ नेता जावेदेकर साहब, हमारे वन मंत्री हैं। हमारे एनवायरनमेंटलिस्ट्स और वह भी इसकी बहुत चिंता करते हैं। इसमें रियासत वाली बात नहीं है, लेकिन सात महीने में आंकड़े के हिसाब से उन्होंने 650 प्रोडक्ट्स एक साथ अप्रूव कर दिये हैं। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इससे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इसके लिए बहुत ही चिन्तित हैं। वर्ष 2013-14 का जो बजट था, उसमें हमारी एक उपलब्धि थी कि आंकड़े में 5.65 परसेन्ट की बढ़ोतरी हुयी थी लेकिन वर्ष 2014-15 में उसमें 15 प्रतिशत की कटौती हुयी है और वर्ष 2015-16 का जो बजट है, उसमें कम से कम 23.8 प्रतिशत की कटौती हुयी है जिससे हमें यह पता चलता है कि इसको हम गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। हमारा और हमारी स्टैंडिंग कमेटी की यह निवेदन है कि पूरे वर्ल्ड में इस पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है लेकिन हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं जिससे एक गलत मैसेज जायेगा।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से विनती करता हूं कि विकास का कार्यक्रम होना चाहिए लेकिन हमारे वन और पर्यावरण विभाग में जो कटौती हुई है, वह उसको पूरा करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोजल दिया है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्लान आउटले में 4,440.20 करोड़ रुपये की मांग थी और आपने असल में क्या दिया, उसके लिए आपने 1,406 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2,993 करोड़ रुपये की कमी है। आप इसको कैसे मेक-अप करेंगे? आदरणीय मंत्री जी को इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि आर्थिक स्थिति को देखना पड़ता है, किस मंत्रालय को विशेषता दी जानी चाहिए, यह देखना पड़ता है। बजटरी एलोकेशन्स में अन्य विभागों में जो हो रहा है, वन विभाग को भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी। डिग्रेडेशन है, आपने मेजर फैक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर

में दिया है। इससे किसान, जनजातीय लोग प्रभावित होते हैं। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद पूरे देश का नुकसान होगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारी पार्टी से दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। चौदहवीं फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में कहा गया है कि राज्यों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और एलोकेशन स्पेशियली 25 प्रतिशत के एमाउंट को देखते हुए 1098 करोड़ रुपये यानी आठ राज्यों - गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओड़िसा और जम्मू कश्मीर में किया है। जब आप कहते हैं कि राज्यों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि कहां से कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे क्योंकि [अनुवाद] यह राजस्व अर्जित करने वाला राज्य नहीं है। अगर ऐसा प्रावधान रखेंगे तो हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में वहां का कारोबार बंद करवा दिया। वहां के टिम्बर के ऑपरेशन को बंद करवा दिया। हमारा रिवैन्यू अर्निंग सोर्स वही है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 83 प्रतिशत एरिया में वन हैं। देश के 23 प्रतिशत वन नॉर्थ ईस्ट में हैं, 60 प्रतिशत फॉरेस्ट कवरेज में है और अरुणाचल प्रदेश में 83 प्रतिशत का कवरेज है। हम वहां के जनजातीय लोगों, दूरदराज के लोगों के विकास या प्रगति की बात किस प्रकार करेंगे।

जब कोयले की बात आती है तो गृह मंत्रालय से रुकावट आ गई, पर्यावरण विभाग से भी आ गई। हमारे स्टेट को आमदनी कहां से होगी। यहां तक भी बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 9 टन की एक गाड़ी जा सकती है, उससे ऊपर लाद नहीं सकते। ये सब बातें सोचने वाली हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपने रुकावट डाल दी। जब आप टूरिज्म की बात करते हैं,...(व्यवधान) यहां वन मंत्री जी बैठे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1,100 करोड़ रुपये का कैम्पा का प्रोविजन है जिसमें 10 प्रतिशत की बात की जाती है। हमें 110 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। वह पूरा नहीं हो रहा है। आप कैसे बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश या उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान देना चाहते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अफस्पा जैसी चीज लागू करेंगे, इको टूरिज्म को बंद करेंगे तो किस प्रकार वहां के लोगों के विकास के बारे में सोचेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान दीजिए, खास तौर पर कैम्पा के विषय में निवेदन करूंगा।

कि उच्चतम न्यायालय का उसमें कंट्रोल क्यों होता है। अगर कंट्रोल है तो क्या इंटरस्ट को दूसरे काम में नहीं लगाते। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। दुनिया भारत को देख रही है। इस बार दिसंबर में पेरिस में जो समिट होगा, उसमें विश्व के सब देश भारत को देखेंगे। हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाना होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो पर्यावरण की देख-रेख कर सकता है। 1.62 टन कार्बन डाइऑक्साइड भारत में उत्सर्जन होता है जबकि चीन में यह 6 टन है और अमेरिका में 18 टन उत्सर्जन होता है। अगर हम अमेरिका का मॉडल अपनाते हैं तो हमें 7 पृथ्वी की जरूरत होगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों, हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि 6 बजे, हम गिलोटिन लेने जा रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि, वे अपने भाषण देने में बहुत संक्षिप्त रहें। वे सदस्य, जो सभा पटल पर अपने लिखित भाषण देने के इच्छुक हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति है।

अब, श्री भगत सिंह कोश्यारी। कृपया 10 मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल-यू.एस.एन.): महोदय, जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, तो आप हमेशा कहते हैं: 'अपना भाषण 10 मिनट अथवा दो मिनट अथवा तीन मिनट के भीतर समाप्त करें'... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : मुझे देखने दीजिए। यह पर्यावरण के बारे में है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे(गुलबर्गा): वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गृह मंत्री सभी को घर ले गए हैं। वहां कोई नहीं है। इसलिए वह 10 मिनट के भीतर समाप्त करने के लिए कह रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी: लेकिन आप जंगल में नहीं हैं; आप घर में भी हैं, खड़गे साहब!... (व्यवधान)

कटौती प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पर्यावरण और वन आज चिंता का विषय हो गया है। अगर इस पर कम समय मिलेगा तो यह पर्यावरण के साथ अन्याय होगा। मैं वन और पर्यावरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। मैं आदरणीय वन और पर्यावरण मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि लीमा में जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं आशा करता हूँ कि आगामी पेरिस सम्मेलन में भी वह भारत का पक्ष सबलता से रखेंगे। मैं कल हिन्दु में पढ़ रहा था, गार्डियन के संपादक का इतना बड़ा इंटरव्यू आया है जिसमें कहा गया है फॉसिल फ्यूल का उपयोग को कम करने की बात कही गई है, आखिर फॉसिल फ्यूल के उपयोग कम क्यों होना चाहिए, हमें कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगानी चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि चीन में 9.8864 मिलियन टन, अमेरिका में 5.1944 मिलियन टन और भारत में 1.9674 मिलियन टन का प्रदूषण इमिशन होता है। भारत में पर-कैपिटा इमिशन एक परसेंट या डेढ़ परसेंट ही है। पिछले बीस और तीस सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे संगठन तथा तथाकथित इन्टलेक्चुअल इतना अधिक छाप देते हैं जिससे लगता है कि भारत में पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इमिशन ज्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। मंत्री जी इसे देखें। कहीं साजिश के तहत हिन्दुस्तान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है।

हमारे यहां जब ग्रीन हाउसेज का एमिशन पर कैपिटा इतना कम है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बारे में हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। हमारे देश में विकास न हो, ऐसा नहीं चल सकता। मैंने पिछले कई वर्षों से देखा है कि जो भी पर्यावरण मंत्री बनता है, वह केवल पर्यावरण के बारे में ही सोचता है। आपने कम समय दिया, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा जी की दो लड़कियां थीं। एक लड़की कुम्हार को

ब्याही गयी और दूसरी लड़की माली को ब्याही गयी। जब दोनों से वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो माली वाली लड़की ने कहा कि मुझे हमेशा बरसात दीजिए और कुम्हार वाली लड़की ने कहा कि मुझे हमेशा धूप चाहिए। अब ये दो प्रकार के जो एक्स्ट्रीम हैं, भारत में भी लगभग ऐसे ही एक्स्ट्रीम चल रहे हैं। यहां अतिवाद चल रहा है, यानी इतना अतिवाद चल रहा है कि मैं उसका गवाह हूं। मेरे यहां पहले उत्तराखंड में सरकार द्वारा पेड़ों का बहुत नुकसान किया गया। उसके खिलाफ जो चिपको आंदोलन चला, उस आंदोलन ने दुनिया में एक नयी जागृति पैदा की। उस वन एक्स्ट्रीम से हम दूसरे एक्स्ट्रीम में चले गये। हमने कहा कि सड़क भी नहीं बननी चाहिए, पानी भी नहीं आना चाहिए, बिजली भी नहीं आनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि एक एक्स्ट्रीम से दूसरी एक्स्ट्रीम में आना उचित नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर हमें पर्यावरण बचाना है, तो यह पर्यावरण किसके लिए है? एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यह पर्यावरण किसके लिए है? यहां पर मेनका गांधी जी नहीं हैं। उन्होंने हमारे यहां जो बहुत सी पशु बलि होती थी, उसे बंद किया है। उनका पशु प्रेम बहुत है। बहुत से लोग पशु प्रेमी हैं। यहां भी कुछ पशु प्रेमी होंगे, जिनमें से कुछ खाने के लिए होंगे और कुछ बचाने के लिए होंगे। ऐसे बहुत से पशु प्रेमी हैं। मैं देखता हूं कि आज क्या स्थिति है? आप ताज्जुब करेंगे कि एक एक्स्ट्रीम से दूसरी एक्स्ट्रीम कितनी होती है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अरुणाचल में वह समस्या नहीं है जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। इन दोनों प्रदेशों में केवल 33 प्रतिशत क्षेत्र में ही खेती होती है, जबकि 67 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध जंगल है। वहां बंदर और सुअरों का राज हो गया है, जिसके कारण वहां कोई भी आदमी खेती नहीं कर सकता। इस कारण उत्तराखंड और हिमाचल के लोग मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, एक्सोडस हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं न कहीं संतुलन होना चाहिए। इसके लिए तुरंत कोई उपाय करना चाहिए। अगर सारे लोग भागकर आ जायेंगे, तो पता लगेगा कि ऊपर से, चीन से वहां लोग आ रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उन्हें मार दीजिए, लेकिन हमारा वन विभाग, हमारे पर्यावरणविद् जब पर्यावरण की बात करते हैं तो मनुष्य की बात करनी चाहिए। जब कभी-कभी हमारे जंगल के अधिकारी बैठते हैं तो मैं उनसे इस बारे में कहता हूं। बंगाल के सब साथी चले गये हैं। एक बार बंगाल से विद्यापति जी गये थे। वे कहते थे कि 'सबार ऊपर मानुस भाई,

तहार ऊपर किछु नाहीं।' सबसे ऊपर मनुष्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जंगल भी है, तो मनुष्य के लिए है, पशु भी है, तो मनुष्य के लिए है और जमीन भी है, तो वह भी मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही सबकी रक्षा कर सकता है। प्रकृति की रक्षा भी मनुष्य ही कर सकता है। इस प्रकार से हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आगे सब ठीक रहे।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमें जहां संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए, वहां हमें समन्वय भी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूं कि डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन न होने से विकास के सारे कार्य लंबे समय तक रुके रहते हैं। जब से माननीय जावेडकर जी मंत्री बने हैं, हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी आये हैं, तब से काफी छूट दी गयी है। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि जल्दी से जल्दी सारे मामलों का निपटारा होना चाहिए, ताकि विकास की गति रुकने न पाये। अभी वहां के सदस्य बॉर्डर की बात कर रहे थे, तो बॉर्डर के बारे में मंत्री जी ने कहा कि रक्षा के लिए सौ किलोमीटर तक की जरूरत नहीं होगी। मैं सोचता हूं कि आपका यह बहुत प्रशंसनीय कदम है। आप चाहें तो इसे सौ की जगह डेढ़ सौ किलोमीटर कर लीजिए, तब भी अच्छा रहेगा। यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हमारे ऊपर जो ड्रैगन बैठा है, उसकी हम सब कल्पना कर सकते हैं। इसलिए उस संबंध में सावधानी रहनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो प्राइवेट वन हैं, वन पंचायत हैं, शायद वह ग्रामीण लोगों की वन पंचायत हैं। यहां पर वन अधिकारी बैठे हुए हैं, वे समझ सकते हैं कि मेरे प्रदेश में वन पंचायत, जो जनता द्वारा रक्षित होते हैं, जनता लगाती है, जनता द्वारा उन्हें हक मिलते हैं, वे रिजर्व फॉरेस्ट से कहीं अधिक अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारा वन है, हम इसमें से अधिकार प्राप्त करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, उसे संशोधित करते हुए आप प्राइवेट वनों को प्रमोट कीजिए। प्राइवेट वनों में आप लोगों को अधिकार दीजिए, ताकि वे उन वनों की लकड़ी ला सकें।

अपराह्न 03.00 बजे

[हिन्दी] वहां से घास ला सकें, पत्तियां ला सकें। इस प्रकार का प्रबंध करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सहभागिता, कोऑपरेशन होना चाहिए। जनता की सहभागिता अधिकतम कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए।

मैं आपसे एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। आज ओज़ोन में कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल जैसे हिमालय प्रदेश ऑक्सीजन की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इन राज्यों को कार्बन क्रेडिट कैसे दिया जाए, यह देखा जाए क्योंकि यहां कार्बन कम पैदा होता है। इन राज्यों को कार्बन क्रेडिट, ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए ताकि यहां के लोग जंगलों और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, नदियों को साफ रख सकें। मेरा निवेदन है कि आपको इन सब के बारे में विचार करना चाहिए।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने 2014 के अभिभाषण में हिमालय मिशन की बात कही थी। उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही थी। मैं पिछले बजट में देख रहा था कि हिमालय मिशन के लिए मात्र दस करोड़ रुपया अलॉट किया गया था लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हुआ है। हिमालय मिशन की अभी तक कोई रूपरेखा भी नहीं रखी गई है। इस बार बजट में 100 करोड़ का इंतजाम है लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा? आप हिमालय को कैसे बचाएंगे? अभी काठमांडू, नेपाल, केदारनाथ में क्या हुआ है? अभी मुझे कोई कह रहा था कि केदारनाथ में कुछ लोग जाते हैं तो भूकंप आ जाता है। वे मजाक कर रहे थे, लेकिन यह मजाक की बात नहीं है। हिमालय की स्थिति के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है।

मेरा निवेदन है कि हिमालय की परिस्थितियों को देखते हुए हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी चाहिए।

आई.सी.मोड एक संस्था है, मैं देख रहा था कि विदेशों की इस प्रकार की संस्थाओं को आपने क्या क्या प्रकार की सहायता दी है। आई.सी.मोड की संस्था आपने कम कर दी है। मैं आई.सी. मोड की हिस्ट्री को

जानता हूँ। ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए मैं सोचता हूँ कि हमें इन सब चीजों में सहयोग करना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में जहां देश में लगातार फॉरेस्ट का क्षेत्र हमारा कम हो रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर इसका क्षेत्र बढ़ा है। ये आपके आंकड़े बताते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्योंकि आज हिमाचल और अरुणाचल, उनका 80 प्रतिशत से ज्यादा अरुणाचल में है। हमारे यहां 60 प्रतिशत से ज्यादा है। सारे देश में केवल 24 प्रतिशत है।

इसलिए कहीं न कहीं इसका भी उपयोग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि कैम्पा के अंदर जो एन.पी.वी है, उसका बहुत सारा पैसा है। मैंने जयराम रमेश जी से भी निवेदन किया था कि इस कैम्पा का उपयोग राज्यों में करना चाहिए। वहां वृक्षारोपण में, नदियों की सफाई में या जो भी कारण हो, जिस कारण से भी हमारा पर्यावरण बढ़ सकता है, उसमें उस कैम्पा का उपयोग होना चाहिए और जिस राज्य का पैसा है, उस राज्य को पैसा देकर तथा न केवल पैसा ही देकर बल्कि उस पैसे की मॉनीटरिंग भी होनी चाहिए कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ताकि आगे दिया जाए या कितना दिया जाए क्योंकि अगर वहां पैसा देंगे तो हिमालय राज्यों में जो गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका भी हल हो सकेगा।

अंत में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब आप वन की बात करें या पर्यावरण की बात करें तो कम से कम हम एक बार अपने भारत की ओर देखें। जिस भारत ने कहा था: “विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे” अर्थात् हे मां भगवती, हे मां पृथ्वी, तू मुझे क्षमा करा। मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूँ। यह जो हमारे यहां तुलसी जी की और पीपल के पेड़ की पूजा जो हमारे प्राचीन लोग करते थे, आखिर क्या कारण था कि उस संस्कृति ने आज तक पर्वत बचाये रखे, हमारी नदियां बचाए रखीं और हमारे पेड़ और जंगल बचाये रखें अन्यथा क्या कारण है कि आज जो सभ्यता और संस्कृति आ गई है, जो सभ्यता हम लोग पश्चिम से ला रहे हैं, उस भोगवादी सभ्यता के कारण हम लोग ये सारी चीजें खोते जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अगर हम फिर से उन चीजों में जाएंगे यानी यदि हम प्राचीन संस्कृति जिसमें हमारे पेड़-पौधों की भी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है, गंगा,

नर्मदा को भी मां के रूप में माना गया है, यदि हम उसी अपनी प्राचीन सभ्यता में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य सफल होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री शिवकुमार उदासी (हावेरी):** 2015-16 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान की मांगों पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। अब हम एक ऐसे चरण में हैं जब हमें आर्थिक विकास और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी के संदर्भ में सतत विकास की अनिवार्यताओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को विकास के विपरीत उद्देश्यों के रूप में नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आखिरकार हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार सतत और न्यायसंगत विकास के केंद्र में है।

11वीं योजना के लिए केंद्रीय क्षेत्र का कुल परिव्यय 10,96,860 करोड़ रुपये (स्थिर मूल्य) है, जिसमें से 8,841 करोड़ रुपये और 10,000 करोड़ रुपये (क्रमशः स्थिर और वर्तमान मूल्य) पर्यावरण, वन और वन्यजीव क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए वर्तमान आवंटन कुल केंद्रीय क्षेत्र के परिव्यय का 0.70 प्रतिशत (0.91 प्रतिशत) है और राज्यों में यह पर्यावरण के लिए राज्य के परिव्यय का 0.021 प्रतिशत से 1.78 प्रतिशत और वानिकी और वन्यजीव के लिए 1.25 प्रतिशत के बीच है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा पर्यावरण, और वानिकी क्षेत्रों के लिए वार्षिक, राज्य, और केंद्रीय क्षेत्र के परिव्यय का कम से कम 5 प्रतिशत का आवंटन अलग से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

ई-कचरा सभी अपशिष्ट पदार्थों में सबसे अधिक विषाक्त है और इससे गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी खतरे जुड़े हुए हैं। यह खतरनाक दर से बढ़ रहा है और इस तरह इसका प्रबंधन और संचालन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर, वर्ष 2005 में देश में लगभग 1,46,800 टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था और यह अनुमान लगाया गया था कि 2012 तक

* भाषण सभा पटल पर रखा गया

ई-कचरे की मात्रा बढ़कर 8,00,000 टन हो जाएगी। भारत में उत्पन्न होने वाले ई-कचरे और इससे निपटने की इसकी क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर है। विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी (ई.पी.आर.) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ई-कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011, की मुख्य विशेषता है, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा उन्हें त्यागने के बाद उत्पादक अपने उत्पाद के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अब तक, 11 राज्यों में 123 उत्पादकों और 15 राज्यों में 111 संग्रह केंद्रों को अधिकृत किया गया है। 12 राज्यों में 126 पंजीकृत ई-कचरा रीसाइक्लर/डिसमेंटलर्स हैं। ई-कचरे के पुनर्चक्रण में विफलता से भविष्य की पीढ़ियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की कमी भी हो रही है।

ई-कचरा प्रबंधन के एक बड़ी वैश्विक समस्या होने को देखते हुए (दुनिया भर में 50 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न किया गया था या ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 7 किलोग्राम), ऐसी कई प्रतिवेदन हैं जो दर्शाती हैं कि ई-कचरे से जुड़े खतरों को दूर करने और वैध पुनर्चक्रण से जुड़ी लागतों से बचने के लिए "प्रयुक्त वस्तुओं" के आयात की आड़ में विकसित देशों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में ई-कचरा भेजा जा रहा है। सरकार को हमारे देश को विकसित देशों के लिए ई-कचरे के डंपिंग ग्राउंड में से एक बनने से रोकने के लिए आवश्यक विधायी और प्रवर्तन तंत्र के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए।

अवैध रेत खनन का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह पूरे देश में व्याप्त है। स्थायी समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अवैध रेत खनन की मात्रा और रूपों का आकलन करना चाहिए ताकि समस्या की व्यापकता का आकलन किया जा सके और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके। इसके बाद, इस पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

सेल टावरों से ई-विकिरण एक और मुद्दा है जिस पर मंत्रालय ने अपनी उदासीनता बनाए रखी है और यह इस तथ्य को नकारता है कि यह मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों और मधुमक्खियों के, स्वास्थ्य पर इसके कथित प्रभाव के कारण बहुत चिंता का विषय बन गया है। सरकार से किसी भी विश्वसनीय जानकारी के अभाव में, लोग उत्तेजित और चिंतित महसूस करते हैं। दूरसंचार विभाग ने समिति के समक्ष अपने बयान में सूचित किया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र के लिए एक्सपोजर सीमा के मानदंडों को गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण पर

अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई.सी.एन.आई.आर.पी.) द्वारा निर्धारित मौजूदा सीमाओं के 1/10^{वें} हिस्से तक कम कर दिया गया है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर सेल टावरों से विकिरण के प्रभाव पर मतभेद था। तथापि, सेल टावरों आदि से विकिरण के प्रभाव की प्रभावी ढंग से निगरानी करने की आवश्यकता है। और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध निरीक्षकों की संख्या को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

यह बताया गया है कि लगभग 38,000 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) के पास है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय को लगभग 23,800 रुपये की मूल राशि के केवल दस प्रतिशत की सीमा तक और वह भी अर्जित ब्याज से धनराशि जारी करनी चाहिए। इस वर्ष हालांकि मंत्रालय को लगभग 2,400 करोड़ रुपये जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन यह केवल 1,100 करोड़ रुपये जारी कर सका क्योंकि सभी राज्यों से कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई थी। राज्य को अपनी संबंधित कार्य योजनाओं की सिफारिश करने के लिए सलाह दी जानी चाहिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी मिल सके और सी.ए.एम.ओ.ए. निधि का खर्च नियमों और विनियमों के तहत होना चाहिए ताकि उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके जिसके लिए धन एकत्र किया गया है। मंत्रालय को इस संबंध में जल्द से जल्द कुछ रचनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

मंत्रालय को लोगों में इस विषय पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। इस मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए और हितधारकों के साथ सार्वजनिक सुनवाई मामले में आगे की कार्रवाई का आधार होना चाहिए। इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण संरक्षण और हमारी पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान की रोकथाम की चुनौती को समग्र परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। चुनौती वास्तव में गंभीर है और इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के मामले के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है जैसे कि कल आज था। कार्रवाई का एजेंडा पक्षपातपूर्ण राजनीति की मजबूरियों या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का बंधक नहीं हो सकता है। न ही नौकरशाही का लालफीताशाही

और गलत रवैया निष्क्रियता का बहाना हो सकता है। गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में उच्च आर्थिक विकास के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य का पीछा करते हुए हमें अपने कार्यों में पर्यावरणीय चिंताओं की प्रधानता को दोहराने की आवश्यकता है।

पारिस्थितिकीय असंतुलन, हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के उग्र और अस्थिर दोहन और त्रुटिपूर्ण प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन ने हाशिए पर रहने वाले हमारे लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदाय और शहरी गरीबों के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

हमारी कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव और जल संसाधनों के प्रबंधन की चुनौती ने लाखों भारतीयों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, जिससे गरीबी और आर्थिक स्थिरता के अभाव के साथ होने वाली दुर्दशा और बढ़ गई है। वायु प्रदूषण और देश के कई हिस्सों में पीने योग्य पानी, स्वच्छता और आवास सुविधाओं की कमी के कारण लाखों भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु की चुनौती ने प्रभावित लोगों को गरिमा के साथ जीवन के उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है।

हमें लोगों के सतत विकास और जीवन स्तर के बीच प्रदर्शित सह-संबंध को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमें ऐसी नीतियां तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास की अनिवार्यताओं को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ एकीकृत कर सकें।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास हमारे पर्यावरण की रक्षा करने का केंद्रीय अधिदेश है जो हमारी साझा विरासत है। त्रुटिपूर्ण विनियामक, शासन, संसाधनों का खराब प्रबंधन, प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त उपयोग, पर्यावरण संरक्षण के लिए हतोत्साहित करना, एक विश्वसनीय, प्रभावी और जवाबदेह तंत्र का अभाव जो अंततः पर्यावरण मानदंडों और कानूनों के प्रवर्तन की कमी की ओर ले जाता है, ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें बिना किसी देरी के संबोधित करने की आवश्यकता है।

मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि, पंचवर्षीय योजना के रूप में दीर्घकालिक योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक परियोजनाओं को तैयार करना और उन्हें समय पर लागू करना है, जिसके लिए धन का अपर्याप्त

आवंटन एक बाधा नहीं होना चाहिए। साथ ही मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि धन का विवेकपूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

[हिन्दी]

***श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :** मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के बदलते पर्यावरण परिवेश में हिमालय स्टडी हेतु गठित नेशनल मिशन हेतु 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है मेरे कुछ सुझाव हैं जो निम्न हैं:

1. वन क्षेत्र सघनीकरण हेतु कार्यरत कार्यबल अगर आपके मंत्रालय द्वारा स्थापित मानक को पूर्ण करते हैं तो उनको पुरस्कृत करने हेतु बजट में पुरस्कार राशि प्रस्तावित करना चाहिए।
2. सघन क्षेत्रों को और सघनीकरण हेतु वन क्षेत्र के कार्यबल के आतिरिक्त वन मित्रों को जोड़ना चाहिए इस हेतु वन मित्रों को ट्रेनिंग देने हेतु एकेडमी का गठन करने का प्रावधान बजट में करना चाहिए।
3. गांधी सागर (चम्बल) मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 37000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र सघनीकरण के आतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है इस क्षेत्र में रेंजर कालेज या वन शिक्षा एकेडमी की स्थापना का बजटीय प्रावधान हो तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण उपलब्धि होगी।
4. वन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पशु विशेषकर नीलगाय कृषि क्षेत्रों में आकर कृषकों की फसलें बर्बाद करती है उन्हें रोकने हेतु नीलगाय की पूर्ति हेतु आवश्यक वनस्पति उत्पादन हेतु निदेश देने व बजटीय व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

***श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):** पर्यावरण, और वन में जीव विज्ञान, भू विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, इंजीनियरिंग, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और पृथ्वी के पर्यावरण संसाधन, शामिल हैं। इस प्रकार अधिकांश संधियाँ जो पारंपरिक समाजों की रक्षा करने में मदद करती हैं और जब हम उस क्षेत्र को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा परिवेश मूल रूप से एक प्राकृतिक परिदृश्य था जैसे कि जंगल, नदी, पहाड़, रेगिस्तान, या इन तत्वों का एक संयोजन। हममें से अधिकांश ऐसे परिदृश्यों में रहते हैं जो गांवों, कस्बों, अथवा शहरों में मनुष्यों द्वारा भारी रूप से संशोधित किए गए हैं। लेकिन हममें से जो लोग शहरों में रहते हैं, उन्हें भी आसपास के गांवों से भोजन मिलता है और ये लोग कृषि के लिए पानी, ईंधन लकड़ी, चारा और मछली जैसे संसाधनों के लिए जंगलों, घास के मैदानों, नदियों, समुद्र तटों, जैसे प्राकृतिक परिदृश्यों पर निर्भर हैं। इस प्रकार हमारा दैनिक जीवन हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ है और अनिवार्य रूप से उन्हें प्रभावित करता है। हम पानी का उपयोग पीने और अन्य दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए करते हैं। हम हवा में सांस लेते हैं, हम उन संसाधनों का उपयोग करते हैं जिनसे भोजन बनाया जाता है और हम जीवित पौधों और जानवरों के समुदाय पर निर्भर करते हैं जो जीवन का एक जाल बनाते हैं, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। हमारे आस-पास की हर चीज हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है और हमारा जीवन इसकी महत्वपूर्ण प्रणालियों को अक्षुण्ण रखने पर निर्भर करता है क्योंकि प्रकृति पर हमारी निर्भरता इतनी अधिक है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं। हम पर्यावरण अध्ययन की बहु-विषयक प्रकृति की रक्षा किए बिना जीना जारी नहीं रख सकते जीवन के तीन रूप हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझे विश्वास होने लगा कि घरेलू जानवरों और फसलों के उपभेदों के लिए यह आसान जवाब है। औद्योगिक विकास और गहन कृषि जो पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की हमारी बढ़ी हुई मात्रा के लिए सामान प्रदान करती है, वे हैं जो भविष्य के संसाधनों, जैसे लकड़ी और पानी में समाप्त हो जाएंगे, जिनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन प्राकृतिक

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रक्रियाओं जैसे पुनः विकास या वर्षा द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन ये भी समाप्त हो जाएंगे यदि हम उनका उपयोग प्रकृति की जगह लेने की तुलना में तेजी से करते रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि जंगल से लकड़ी और जलाऊ लकड़ी को हटाना पेड़ों के पुनः विकास और पुनर्जनन की तुलना में तेज है, तो यह आपूर्ति को फिर से नहीं भर सकता है। और वन क्षेत्र का नुकसान न केवल लकड़ी और अन्य गैर-लकड़ी उत्पादों, जैसे वन संसाधनों को कम करता है, बल्कि हमारे जल संसाधनों को प्रभावित करता है क्योंकि एक अक्षुण्ण प्राकृतिक वन स्पंज की तरह काम करता है जो पानी को पकड़ता है और इसे धीरे-धीरे छोड़ता है। वनों की कटाई से मानसून में बाढ़ आती है और नदियां सूख जाती हैं। नियमित मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर इस तरह के कई प्रभावों की हम में से प्रत्येक को सराहना करनी चाहिए, अगर यह हमें दीर्घकालिक रूप से आवश्यक संसाधन प्रदान करना है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों की तुलना बैंक में मौजूद धन से की जा सकती है। यदि हम इसका तेजी से उपयोग करते हैं, तो पूंजी शून्य हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि हम केवल ब्याज का उपयोग करते हैं, तो यह हमें लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसे सतत उपयोग या विकास कहा जाता है। अस्थिर उपयोग वास्तव में हमारी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। उनके पर्यावरणीय रूप से सकारात्मक होने के बारे में सोचे बिना, हमें संसाधनों का उपयोग करने के तरीके को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

हम जिस भी संसाधन का उपयोग करते हैं, उसके लिए हमें खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास एक व्यापक योजना है जिसमें संरक्षण, निवास स्थान में सुधार, अधिकारों का निपटान, पर्यावरण विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण, पर्यावरण पर्यटन, शिक्षा और जागरूकता, आदि के घटक शामिल हैं। उच्च विविधता और उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। एस.पी.सी.बी. द्वारा परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी में कभी-कभी लंबा समय लगता है। मानक प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। इससे प्राप्तियां संयंत्र की कुल परिचालन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने की उम्मीद नहीं है। इस स्थिति में,

नगर पालिकाओं को बड़े हुए सीवेज कर के माध्यम से लागत का एक हिस्सा वहन करना पड़ता है ताकि किया गया निवेश बर्बाद न हो जाए।

2,600 वर्ग किलोमीटर की राजमहल पहाड़ियों में आप जो भी चट्टान उठाते हैं वह लाखों वर्षों से पृथ्वी द्वारा संरक्षित एक खजाना है लेकिन अब धूल में बदल रहा है। कुछ वर्षों में, बेलगाम उत्खनन के कारण, जुरासिक युग के जीवाश्मों की यह विस्मयकारी संपत्ति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी।

सैकड़ों ट्रक, क्रेन और बुलडोजर एक ऐसे क्षेत्र में धूल उड़ाते हैं जहाँ कभी डायनासोर का शासन था। प्रागैतिहासिक पेड़ों और पौधों की छापों को संरक्षित करने वाली चट्टानों को पड़ोस में सड़कों का निर्माण करने के लिए टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जगह-जगह, पहाड़ियों को लगभग 10 मंजिला ऊँचा काट दिया गया है, जिससे ग्रह पर कहीं भी पाए जाने वाले अनगिनत बेहतरीन जीवाश्म नष्ट हो गए हैं।

राजमहल पहाड़ियाँ उन बेहतरीन शोध क्षेत्रों में से हैं जिनकी भूवैज्ञानिक और प्लायोबोटनिस्ट उम्मीद कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि, वह दिन दूर नहीं जब आपको यहां एक भी जीवाश्म नहीं मिलेगा। यहाँ के पौधों के जीवाश्म 68 मिलियन वर्ष और 150 मिलियन वर्ष के बीच के हैं। राजमहल जाल में मेसोजोइक युग के जीवाश्म हैं, जो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस युग में फैले हुए हैं। उत्खनन संभावित डायनासोर जीवाश्मों को भी नष्ट कर रहा है। इस क्षेत्र में जुरासिक और ट्रायसिक युग के सरीसृपों के अस्तित्व के स्पष्ट संकेत हैं। यदि उचित खुदाई और अध्ययन किया जाए, तो इन जीवाश्मों को पाया जा सकता है। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें एक दिन यहाँ डायनासोर का जीवाश्म मिल सकता है।

राजमहल पहाड़ियों के पौधों के जीवाश्म बेहद अच्छी तरह से संरक्षित हैं - उस युग के अवशेषों के लिए एक दुर्लभता - और वे मानव के पौधे पर चलने से बहुत पहले, जीवाश्म-पर्यावरण का एक सटीक रिकॉर्ड देते हैं। ऐसे अधिकांश पौधे और पेड़ कोयले में बदल गए होंगे। राजमहल ज्वालामुखी विस्फोट, जो सिलहट (अब बांग्लादेश में) तक चला गया था, में शांति की अवधि थी जिसके दौरान पौधों की शानदार वृद्धि हुई थी। जब

ज्वालामुखी फिर से फूट पड़े, तो 'कोयलिफिकेशन' को रोकने के लिए पेड़ों को सही तापमान और दबाव पर दफन कर दिया गया।

प्रागैतिहासिक अवशेष इतनी अच्छी तरह से संरक्षित हैं कि एक आम आदमी भी पत्थरों से जीवाश्मों को देख सकता है। एक पेड़ के वार्षिक छल्ले या पत्तियों के उत्तम पैटर्न को आसानी से पहचाना जा सकता है। यहाँ के जीवाश्मों को दुनिया भर के संग्रहालयों और प्रयोगशालाओं में गौरवपूर्ण स्थान मिलता है। लेकिन इस अद्वितीय खजाने पर उन लोगों का हमला हो रहा है जिन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए।

पूरे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, झारखंड सरकार ने खनन पट्टों को अंधाधुंध रूप से निजी कंपनियों को दे दिया है, जो पहाड़ियों को उड़ा रही हैं और सुरंगें खोद रही हैं। सभी के लिए इस मुफ्त में, यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि किसके पास खनन पट्टा है और किसके पास नहीं है।

कुछ कंपनियां जिनके पास पट्टा नहीं है, वे पहाड़ियों को लूटने के लिए स्थानीय प्रशासन की हथेली पर तेल लगाती हैं। यदि पहाड़ियों का खनन और उड़ाने वाली 500 एजेंसियां हैं, तो आपके पास 2000 पत्थर - कुचलने वाली इकाइयां हैं जो कीमती जीवाश्मों को नष्ट कर रही हैं-शायद दुनिया में सबसे 'महंगी' सड़क - निर्माण सामग्री।

कुछ सबसे पुराने जीवाश्म जुरासिक और लोअर क्रेटेशियस काल से संबंधित हैं, जो 150-200 मिलियन वर्ष पहले के हैं, पार्क में संरक्षित किए जाएंगे।

समृद्ध जीवाश्म स्थल के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। प्राचीन परिस्थितियों में पौधों के जीवाश्मों को संरक्षित करना आवश्यक है। यह उद्यान भारत में पांचवां लेकिन पूर्व में पहला होगा। यह देश में पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्मों का घर होगा। जीवाश्म जुरासिक और लोअर क्रेटेशियस युग के हैं। "यह पौधों के जीवाश्मों का एक नया परिवार है जो हमें भारत में मिला है। बाद में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पौधों की इसी तरह की प्रजातियों की खोज की गई।

इस उद्यान में अन्य चीजों के अलावा, एक सभागार प्रयोगशाला और एक भूगर्भीय गैलरी के साथ एक संग्रहालय शामिल होगा, जिसमें भारत और झारखंड के जीवाश्मों, वनस्पतियों और जीवों के जैविक विकास का विवरण देने वाले वैज्ञानिक चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। जीवाश्मों का अधिकतम घनत्व साहिबगंज से 32 किमी दूर, मंडरो सी.डी. ब्लॉक में स्थित है।

पूरे क्षेत्र से जुड़ी विरासत और सांस्कृतिक इतिहास के साथ और देवघर धार्मिक महत्व का केंद्र है, जहां सालाना 5 करोड़ लोग आते हैं, साथ ही प्राचीन शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला, मंदार पहाड़ियाँ इसके आस-पास अपार सांस्कृतिक महत्व रखती हैं।

तदनुसार मैं संबंधित अधिकारियों को राजमहल क्षेत्र में किए जा रहे अंधाधुंध खनन पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध करूंगा।

दिवंगत बीरबल साहनी प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस महत्वपूर्ण अभ्यास में शामिल थे।

इसमें कोईरीडीह के वन आरक्षित क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित करने का संदर्भ है। इस क्षेत्र में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है जो अंततः आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रति पूंजी आय बढ़ाने में मदद करेगी।

आपका अच्छा कार्यालय इस बात से अवगत है कि पास के शहर कोईरीडीह, देवघर को प्रमुख शहरों की सूची में शामिल किया गया है और इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से, मेगा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। देवघर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक और द्वारका ज्योतिर्लिंग का भी अनूठा और अत्यंत संशोधित स्थल है। यह पूर्वी भारत की एक धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है जिसने इस पवित्र स्थान को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई और हर साल 5 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री यहां आते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री का एक पत्र संलग्न किया गया है जिसमें तीन जिलों-देवघर, दुमका और पाकुड़ को एस.आर.ई. जिलों के रूप में शामिल किया जाना है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरी चिंता को बरकरार रखते हैं क्योंकि नक्सलवाद इस क्षेत्र में गहराई तक फैलने के कगार पर है।

कोईरीडीह वन आरक्षित क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित करने से देवघर के आगंतुक भी कोईरीडीह की यात्रा करने के लिए आकर्षित होंगे।

प्रसिद्ध त्रिकूट पर्वत भी पास में ही है। कहा जाता है कि भगवान रावण यहां भगवान शिव की पूजा करने आते थे। इस पहाड़ के बारे में रामायण में व्यापक रूप से बात की जाती है। पार्क में अन्य चीजों के अलावा, एक सभागार, प्रयोगशाला, और एक संग्रहालय शामिल होगा।

झारखंड में जंगल लंबे समय से खनन और ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए दबाव में रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इसके वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पहल की गई है। बेहतर प्रबंधन और योजना के लिए जिला स्तर पर वन संसाधन सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं। राज्य ने वन आधारित आजीविका विकास, वन्यजीव प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और अपशिष्ट निपटान योजनाओं के अलावा संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) समितियों का भी गठन किया है। खनन के प्रभावों से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में कानून लाने का भी प्रस्ताव किया है ताकि खनन क्षेत्रों से उत्पन्न संसाधनों को स्थानीय विकास गतिविधियों के लिए वापस पंप किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के वनों के लिए स्थायी वन प्रबंधन योजनाओं का विकास विभिन्न जलवायु और जैव विविधता मॉडल का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के वनों में वन उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए विस्तृत अध्ययन की सिफारिश की जाती है। इससे जलवायु अनुकूल वन प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। संरक्षण भूखंडों, नमूना भूखंडों और उपज भूखंडों के पुनरुद्धार की भी सिफारिश की गई है। सामान्य परिदृश्य की तरह व्यवसाय से आगे बढ़ने के लिए, झारखंड के प्रत्येक वन प्रकार के लिए उनके जैव भौतिकी के अनुसार अनुकूलन योजनाओं को विकसित और बनाए रखा जाए।

वन पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना- वन विभाग को जलवायु मॉडल का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरों के विश्लेषण के लिए

क्षेत्रीय विश्लेषण करने के लिए 'उत्कृष्टता केंद्र' विकसित करने पर संसाधनों का निवेश करना चाहिए। वन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की घटना के संभावित प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने, भेद्यता, कार्बन पृथक्करण क्षमता और स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता का आकलन करने के लिए अनुसंधान उच्च प्राथमिकता पर किए जाने चाहिए।

राज्य के किलों में कार्बन पृथक्करण की आधारभूत पद्धति का विकास-राज्य को आर.ई.डी.डी. + और अन्य वानिकी कार्बन पहलों का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध कार्बन स्टॉक के आविष्कार के लिए कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए।

झारखंड के वनों की भेद्यता मानचित्रण - जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वन पारिस्थितिकी तंत्र और वन आश्रित समुदाय की आजीविका का विस्तृत भेद्यता मानचित्रण किया जाना चाहिए और तदनुसार राज्य में अनुकूलन योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

जल बांधों (जैसे पुनासी), उद्योग और बुनियादी ढांचे के लिए वन निकासी समय की आवश्यकता है।

***श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर):** हम वर्तमान में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के संबंध में विश्व राजनयिक संबंधों के एक ऐसे मोड़ पर हैं, जहां देश-चाहे वे विकसित हों (और इसलिए अधिक औद्योगिक और इस तरह अधिक प्रदूषणकारी) या विकासशील-सभी पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन की घटना को रोकने के लिए अपना समर्थन देने का संकल्प ले रहे हैं। और फिर भी, यह दुखद है कि भारत, जो अभी भी एक विकासशील राष्ट्र के रूप में समूहीकृत है, पहले से ही ग्रीनहाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

आज की चर्चा के सीधे संबंध में बजटीय संसाधनों के उपयोग के संबंध में, और भी परेशान करने वाला तथ्य है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान मांगों की स्थायी समिति की प्रतिवेदन के लिए मंत्रालय ने लगभग हर एक खंड में अधिक धन की मांग की है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संसाधनों का औसत से कम उपयोग किया गया है।

भारत का उच्च वायु प्रदूषण, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा दुनिया में सबसे खराब स्थान दिया गया है, अपने नागरिकों के जीवन काल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिससे अधिकांश भारतीय जीवन तीन साल से अधिक कम हो गया है, एक नए अध्ययन में कहा गया है।

भारत की आधी से अधिक आबादी - 660 मिलियन लोग - उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सूक्ष्म कण पदार्थ प्रदूषण भारत के मानकों से ऊपर है जिसे सुरक्षित माना जाता है। हार्वर्ड और येल के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर भारत अपने वायु मानकों को पूरा करने के लिए इस प्रवृत्ति को उलट देता है, तो उन 660 मिलियन लोगों को अपने जीवन में लगभग 3.2 साल का लाभ होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि, वह यहां प्रस्तुत आंकड़ों की चुनौती का सामना करे, और इस दिशा में बेहतर नीतियों का मसौदा तैयार करे। हालांकि, स्थायी समिति ने देश में किए गए अधिकांश प्रतिष्ठित गैर-सरकारी सर्वेक्षणों को वैधता देने से मंत्रालय की ओर से इनकार करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति की सूचना दी

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति हाल ही में अक्सर चर्चा में रही है, और प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार ने स्वीकार किया था कि अभी तक स्थिति से निपटने के लिए कोई अंतिम कार्य योजना नहीं है। यह गंभीर चिंता का विषय है, और यह भारत के अन्य शहरों से भी संबंधित है।

सरकारी बोर्डों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भी, वायु प्रदूषण के कुछ सबसे खराब रूप भारतीय शहरों में पाए जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) हवा को 'स्वच्छ' मानता है यदि प्रदूषकों के लिए निर्धारित मानकों का स्तर 50 प्रतिशत से कम है। 2007 के दौरान पी.एम.10 के आधार पर केवल 2 प्रतिशत शहरों में वायु प्रदूषण कम था। लगभग 80 प्रतिशत शहरों में (एन.ए.एम.पी. के तहत निगरानी किए गए कुल 127 शहरों/कस्बों में से), कम से कम एक मानदंड में, प्रदूषक वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक थे। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बहुत कम शहर हैं, जिन्हें पी.एम. 10 के स्तर (श्वसन योग्य कण) को मानदंड के रूप में रखते हुए स्वच्छ कहा जा सकता है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई शहरों में एस.ओ.₂ के स्तर में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन कई शहरों में एन.ओ.₂ का स्तर बढ़ रहा है।

भारतीय शहर भारी कण प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जिसमें 52 प्रतिशत शहर (63 शहर) गंभीर स्तर (मानक से 1.5 गुना से अधिक) तक पहुंच गए हैं, उच्च स्तर वाले 36 शहर (वार्षिक मानक से 1- 1.5 गुना) और केवल 19 शहर मध्यम स्तर पर हैं, जो मानक से 50 प्रतिशत नीचे है।

यह सरकार से भारतीय शहरों के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए कहता है, न केवल इसलिए कि यह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस देश का संविधान, अनुच्छेद 21 में, प्रत्येक नागरिक को जीवन की बेहतर गुणवत्ता की गारंटी देता है, और वे स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वयं अपने धन का गंभीर रूप से कम उपयोग करते देखा गया है। वर्ष 2014-15 में, सी.पी.सी.बी. को बजट अनुमान में 57.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो संशोधित अनुमान में घटकर 40 करोड़ रुपये रह गए, और फिर भी दिसंबर 2014 तक, केवल 26.53 करोड़ रुपये का

उपयोग किया गया। 700 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य था, जिनमें से केवल 244 स्थापित किए गए हैं।

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में इसे रोकने के लिए कानून/गति है। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर में सुरक्षित शोर स्तर के रूप में 45 डेसिबल तय किया है, जबकि भारतीय शहरों में औसतन 90 डेसिबल दर्ज किया जाता है, जो डब्ल्यू.एच.ओ. मानकों का दोगुना है। समिति की प्रतिवेदन में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 का पूरे देश में घोर उल्लंघन किया जा रहा है। सी.पी.सी.बी. द्वारा, 35 ध्वनि निगरानी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य था, लेकिन यह परियोजना 2013, से प्रगति पर है और अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है।

सरकार को इस पर एक स्टैंड लेने की जरूरत है, और न केवल एक कार्य योजना तैयार करने की बल्कि इस दिशा में जागरूकता अभियान भी शुरू करने की जरूरत है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि, सी.पी.सी.बी. की प्रतिवेदनों के अनुसार, देश में वर्ग-I और वर्ग-II शहरों से अनुमानित सीवेज उत्पादन 2009-10 में लगभग 38255 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) था, जबकि सीवेज उपचार क्षमता 11787 एम.एल.डी. या सीवेज उत्पादन का केवल 30% थी। यह दुखद है कि पांच वर्षों के बाद भी, 2014-15 में, शहरी क्षेत्रों से 21479 एम.एल.डी. की उपचार क्षमता के मुकाबले सीवेज उत्पादन 57233 एम.एल.डी. है-अभी भी उत्पादन का केवल 37% है।

इस प्रकार, दुर्भाग्य से यह कहना सुरक्षित है कि भारत में सीवेज उपचार और निपटान की अत्यंत अपर्याप्त प्रणाली है। इस संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि इसे ठीक नहीं किया गया तो, भारत का स्वच्छ भारत मिशन भी विफल होना तय है। इस मामले में मंत्रालयों के बीच समन्वय का पूर्ण महत्व है-चाहे वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो, या ग्रामीण विकास, शहरी विकास या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय हो। सरकार को तत्काल आवश्यकता के रूप में, भारत के शहरों और कस्बों में और अधिक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने चाहिए, और इस समस्या का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। हमें जैव-

पचाने योग्य शौचालयों के लिए एक कार्य योजना, ठोस कचरे के पृथक्करण और उनके संग्रह और निपटान के नगरपालिका स्तरों पर मानदंडों के बेहतर प्रवर्तन की आवश्यकता है।

वर्तमान में देश में 275 नदियों के 302 अत्यंत प्रदूषित हिस्से हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में नदी संरक्षण उद्देश्यों के लिए मंत्रालय को 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसमें से, 2012 से मार्च 2015, तक मंत्रालय को केवल 388.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2015-16, के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए शून्य आवंटन किया गया है। कुल 295 करोड़ रुपये, के प्रावधान में से 2015-16 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष को केवल 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं और यहां तक कि स्थायी समिति को भी नहीं लगता कि यह राशि नदी संरक्षण के लिए पर्याप्त है।

एक और चिंता जो इस सरकार ने पर्याप्त नहीं उठाई है, वह है ई-कचरा। भारत में उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा और इसके निपटान या उससे निपटने की क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर है। सी.पी.सी.बी. की 2005 की प्रतिवेदन में अनुमान लगाया गया था कि भारत द्वारा उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा 2012 तक सात गुना बढ़ जाएगी। यह अब बहुत अधिक है, और एक बड़ी वैश्विक समस्या का हिस्सा है। हमें इसे इस तथ्य के साथ ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। हम केवल विकास और तकनीकी क्रांति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं और इसके पर्यावरणीय परिणामों के मुद्दे को ध्यान में नहीं रख सकते हैं।

वास्तव में, यहां तक कि सी.एफ.एल. बल्ब, जिन्हें व्यापक रूप से ऊर्जा बचत उपाय के रूप में प्रचारित किया जाता है, पर्यावरण के लिए विषाक्त हो सकते हैं। समिति की प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि केवल एक वर्ष, 2014-15 में, केवल दिल्ली में, 74.65 किलोग्राम पारा जारी करने वाले 14.93 मिलियन सी.एफ.एल. का असुरक्षित निपटान किया गया था।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सेल टावरों से विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रभाव और यह नागरिकों को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह जानकर खुशी हो रही है कि सरकार इस समस्या के वास्तविक प्रभाव का

पता लगाने के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है और अंतर-मंत्रालयी स्तर पर सहयोग कर रही है। स्थायी समिति की प्रतिवेदन में भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया गया है, और मैं भी इससे सहमत हूँ कि, इस समस्या से निपटने के लिए, एक निश्चित कार्य योजना होनी चाहिए और एक समय सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर वित्त पोषित किए जा रहे शोध का वास्तविक उपयोग किया जाएगा।

वैश्विक जलवायु पर बढ़ते तापमान के विनाशकारी प्रभावों के बारे में हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) की प्रतिवेदन की साहसिक चेतावनी के बावजूद, सरकार मौजूदा पर्यावरण को कमजोर करने के लिए परिवर्तनों को लागू करने की इच्छुक है। नई सरकार ने "वन मंजूरी को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी से अलग कर दिया है और वन भंडार के आसपास एन.बी.डब्ल्यू.एल. मंजूरी की आवश्यकता को 10 किमी से घटाकर 5 किमी कर दिया है, इसके अलावा प्रख्यात विशेषज्ञों और संबंधित गैर सरकारी संगठनों को रबर स्टॉप से हटाकर बोर्ड को कमजोर कर दिया है। सरकार ने उन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम (एफ.सी.ए.) को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं में ढील दी है जहां एफ.सी.ए. की सबसे अधिक आवश्यकता है: नक्सल प्रभावित क्षेत्र; वन क्षेत्रों में रैखिक परियोजनाएं; और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र।

इस संदर्भ में, यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम को भारी रूप से कमजोर करने की धमकी दी है, जिसके लिए उन्होंने खुद एक साल पहले मतदान किया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जल और वायु प्रदूषण अधिनियम के दायरे में पर्यावरण संरक्षण कानून के बेड़े पर पूरी तरह से कमजोर करने की दृष्टि से संशोधन किया है, जबकि अत्यधिक भेदभावपूर्ण औपनिवेशिक कानून को संरक्षित करते हुए जो अपने वर्तमान रूप में सभी वन अधिनियमों की जनक है - भारतीय वन अधिनियम, 1927

फिर, 28 अक्टूबर, 2014 को जारी एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. आदेश, 2006 के, वन अधिकार अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान को खारिज करता है, जो वन भूमि का अधिग्रहण करने और औद्योगिक या किसी अन्य गैर-

वन गतिविधि के लिए वनों को साफ करने से पहले ग्राम सभाओं (ग्राम परिषद निकाय) की "पूर्व सूचित सहमति" चाहता है।

हाल ही में, सरकार ने खनन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों के साथ सार्वजनिक परामर्श के लिए खंडों को कमजोर कर दिया है, और आदिवासी (स्वदेशी) समुदायों की "मुफ्त, पूर्व और सूचित सहमति" को अनिवार्य करने वाले प्रावधानों को कमजोर करने की मांग की है।

अपने मूल रूप में वन भूमि पर स्वदेशी आदिवासी समुदायों और गैर-आदिवासी वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देते हुए, एफआरए समुदायों को यह प्रमाणित करने का अधिकार देता है कि आगामी परियोजना द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। सरकार को प्राथमिकता के रूप में प्रभावित पक्षों से परामर्श करके इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए।

1980 से, कुल 1.21 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों-मुख्य रूप से खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 23,784 प्रस्तावों के लिए डायवर्ट किया गया है। अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 400,000 हेक्टेयर क्षेत्र को डायवर्ट किया गया है, इसके बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 100,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को डायवर्ट किया गया है। वर्तमान में, भारत का 22% भाग वनों से आच्छादित है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, पर्यावरण नीतियों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के संदर्भ में, यह लक्ष्य पूरा होने के करीब भी नहीं है।

विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि दशक के अंत तक भारत में कुल औद्योगिक गोल लकड़ी की खपत प्रति वर्ष 70 लाख वर्ग मीटर (350,000 बड़े शिपिंग कंटेनर) से अधिक हो सकती है, जबकि घरेलू आपूर्ति इस आंकड़े से अनुमानित 14 करोड़ वर्ग मीटर कम हो जाएगी।

एक बार फिर, भारत खाद्य तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। वास्तव में, यह यूरोपीय संघ और चीन के साथ दुनिया में पाम तेल के तीन सबसे बड़े आयातकों में से एक है। इन आयातों में से, 95% इंडोनेशिया और मलेशिया से आते हैं, जिससे इन निर्यातक देशों में नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं।

हैरान करने वाली बात यह है कि, सी.ए.जी. की ऑडिट प्रतिवेदन से पता चलता है कि 2012 में, देश में हरित ऊर्जा के लिए एकत्र किए गए उपकर का उपयोग भारत के राजकोषीय घाटे को संतुलित करने के लिए किया गया था, न कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के कारण। सरकारी ऑडिटर ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि, जहां 3,646.01 करोड़ रुपये (2010-11 में 1066.46 करोड़ रुपये और 2012-13 में, 2,579.55 करोड़ रुपये) स्वच्छ ऊर्जा उपकर के माध्यम से एकत्र किए गए थे, वहीं एन.सी.ई.एफ. को केवल 1,066.46 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। यह इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण पर अन्य चिंताओं को प्राथमिकता दी है।

मंत्रालय ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं - भारत का सौर ऊर्जा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य 2020 तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करना है, और पवन ऊर्जा पर अन्य पहल, जल संरक्षण, और तटरेखाओं और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तथापि, ये कदम तभी फायदेमंद हैं जब इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

2011 से, भारत ने मुश्किल से 20 मेगावाट से 2013 के अंत तक 1,686 मेगावाट तक सौर क्षमता स्थापित की है। सरकार हर साल, नवीकरणीय क्षेत्र में 10,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है - जो देश की वर्तमान कुल स्थापित क्षमता का लगभग आधा है। हालांकि भारत अभी भी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू ऊर्जा स्रोतों का विकास कर रहा है, लेकिन इसने पिछले वर्ष की तुलना में जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मात्रा का आयात किया है। अपने बिजली उत्पादन को 44% तक, बढ़ाने के उद्देश्य से, देश के लिए कोयले का आयात 2014 में असाधारण रूप से अधिक था और अगले पांच वर्षों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसलिए, भारत का 2022 तक, 100 गीगावाट सौर और 175 गीगावाट ऊर्जा के कुल नवीकरणीय स्रोतों का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी कार्य की तरह लगता है।

अंत में, वन्यजीव संरक्षण के संबंध में, अवैध शिकार अभी भी जारी है और भारत के पास अभी भी अपना स्वतंत्र संरक्षण अधिनियम नहीं है। भारत अभी भी 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पर निर्भर है। राज्यसभा में 2013 के विधेयक में बेहतर संरक्षण तकनीकों के लिए कानून में बदलाव का प्रस्ताव किया गया

था। तथापि, इस साल की शुरुआत में विधेयक को वापस ले लिया गया था, और सरकार ने कहा था कि वे बेहतर विधेयक पर काम कर रहे हैं। तथापि, इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है। सरकार को इस तरह के काम में देरी नहीं करनी चाहिए और विधेयक को तुरंत पेश करना चाहिए क्योंकि यह देश में पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

अंत में, मैं यह बताना चाहूंगा कि आज विकास एक बड़ी कीमत पर आता है - दुनिया के विकसित देश इसका प्रमाण हैं। हमने भी कश्मीर और उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़, और देश के विभिन्न हिस्सों में तटीय कटाव के अलग-अलग स्तर देखे हैं। ओडिशा में 484 किलोमीटर की विशाल तटरेखा है और मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, बालासोर में, 80 किलोमीटर की तटरेखा है। जहां केंद्र में हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के परिणामों को संख्या में मापते हैं, वहीं देश के आम लोग अपने दैनिक जीवन में इसके परिणामों का सामना कर रहे हैं। इस बीच, भारत 'मेक इन इंडिया' और अन्य प्रयासों के माध्यम से एक औद्योगिक क्रांति लाता है, लेकिन एक परिणाम के रूप में, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले से ही ग्रीन हाउस गैसों के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए, इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए, जो अब आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।

***श्री जी. हरी (अराकोन्नम):** पर्यावरण का मुद्दा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा बन गया है। यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दे रही है चाहे वह वन भूमि का रूपांतरण हो, नदी का प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण, हो आदि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आया है और आजकल काफी सक्रिय है। मुझे एक खबर मिली है कि सरकार राज्य सरकार के परामर्श से कई मौजूदा पर्यावरण कानूनों को बनाने या संशोधित करने पर विचार कर रही है। यह एक अच्छा विचार है क्योंकि पर्यावरण के मुद्दों को राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ समग्र पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। मुझे यह पता चला है कि कई राज्य सरकारें धन की कमी के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सभी निर्देशों को लागू करने में सक्षम नहीं थीं। सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित करने के निर्देश एक मुद्दा है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में धन लगता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि, सरकार एस.टी.पी. की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करे।

एक अन्य मुद्दा जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि, आदिवासी लोग जो वन क्षेत्र में रह रहे थे, जिसमें वे अज्ञात अवधि से रह रहे थे, कठोर पर्यावरण कानूनों के कारण, ये लोग सड़क बनाने जैसी, विकासात्मक गतिविधियों से वंचित हैं। इसलिए, जनजातीय लोगों के हित में, मैं सरकार से पर्यावरण कानूनों के कुछ प्रावधानों में ढील देने का आग्रह करता हूं, ताकि वन भूमि में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए वे भी कुछ लाभ उठा सकें जो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद):** आजकल क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा सवाल है। पूरे विश्व में पर्यावरण की जो स्थिति पैदा हुई है, वह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। आजकल पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, जंगल को जिस तरह समाप्त किया जाता है उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही विकसित देशों की वजह से हुई है। पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य विकसित देशों ने किया है। उसके लिए भारत जैसे देशों की जवाबदेही बहुत कम है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए।

पर्यावरण क्लीयरेंस देने के बारे में हमारी सरकार ने जो लचीलापन अपनाया है इसकी वजह से पर्यावरण एवं विकास का संतुलन बना है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

जहां तक बायो-मेडिकल वेस्ट कानून का सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में कॉमन बायोमेडिकल फसेलीटियों का सवाल है गुजरात में दो कंपनियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मगर अच्छे कार्य करने वाली सी.बी.एम.डब्ल्यू.टी.एफ. को अलग-अलग प्रकार के नए प्रावधानों के लिए मजबूर किया जाता है। उन सी.बी.एम.डब्ल्यू.टी.एफ. को आदर्श गाइड लाइंस के लिए सख्ताई किया जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनमें लचीलापन लाना चाहिए तथा अच्छे कार्य करने वाली सी.बी.एम.डब्ल्यू.टी.एफ. की सराहना चाहिए।

भारत की संस्कृति पर्यावरण का हमेशा सम्मान करती है। मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति ही पर्यावरण को बचाने का उपाय है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री नलीन कुमार कटील (दक्षिण कन्नड़):** पश्चिमी घाटों पर कस्तूरीरंगन प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को समिति की प्रतिवेदन के सुझाव के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन करने से पहले स्थानीय लोगों के विचार लेने चाहिए।

एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण बनाने के संबंध में, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए कि सभी शहरों और कस्बों को अपने कचरे, तरल और ठोस कचरे को संभालने के लिए सख्ती से पालन करना चाहिए। हालांकि, एजेंसियों द्वारा उचित योजना नहीं बनाई गई है और अधिकारियों ने दिशा-निर्देश तैयार करते समय वास्तविक जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखने में गहरी रुचि नहीं दिखाई है। यह हमारे शहरों को आलीशान इमारतों और मॉल के मामले में स्मार्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि टिकाऊ जीवन के बारे में है। यह बेहतर योजना और इसके सख्त कार्यान्वयन से संभव हो सकता है।

जहां तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है, स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर प्रोफेसर, एक आम आदमी से लेकर एक नेता तक, हर कोई जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अवगत है। देश को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने और अपनाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को हर साल कम से कम एक जलवायु परिवर्तन योजना शुरू करने का निर्देश देना चाहिए।

बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए समाधान खोजने के संबंध में, सरकार को वैज्ञानिक तरीके से औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु प्रदूषक, अपशिष्ट और अपशिष्ट की प्रकृति-खतरनाक या अन्यथा-एक औद्योगिक इकाई के संचालन का हिस्सा हैं, औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा उत्पादित प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार को प्रदूषण के मानक मानदंडों के अनुपालन की आवश्यक समीक्षा करने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित करना चाहिए।

ताजे पानी को बचाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को शोधित पानी का उपयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए और उद्योगों में शून्य तरल निर्वहन प्रणाली शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

मैं 2015-16 में कम से कम एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने पर विचार करने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। यह विशेष क्षेत्रों के जैविक संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को सभी राज्यों और क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए। विभिन्न प्रजातियों की पशु आबादी का आकलन करने के लिए कदम उठाने की भी आवश्यकता है ताकि उनकी जनसंख्या प्रबंधन के विकल्प पर विचार किया जा सके।

मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में पर्यावरण शासन संस्थान पर्यावरण और वन संसाधनों के संरक्षित और संरक्षण के लिए प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और वन्यजीव न्यासों के कामकाज की शैली से स्पष्ट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) के साथ अपर्याप्त समन्वय है। नागरिक प्रशासनिक प्राधिकरण की कमी, अप्रभावी जवाबदेही, हितधारक जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार के उच्च स्तर और अपर्याप्त निगरानी कौशल जैसी अन्य बाधाएं इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों के कार्यान्वयन में प्रचलित हैं।

इसके परिणामस्वरूप, देश में वनों का विनाश बड़े पैमाने पर हो रहा है। लकड़ी की अवैध कटाई और बिक्री, जलाऊ लकड़ी की कमी और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी का क्षरण भारतीय कृषि भूमि की उत्पादकता को कम कर रहा है। फसल भूमि का विस्तार सीमांत भूमि तक हो गया है और चराई भूमि कम हो गई है। बेरोजगारी और भूमिहीनता बढ़ने के साथ, वन समर्थक आदिवासी समूह भी वानिकी संसाधनों का मुद्राकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वन कानूनों में इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को

वनवासियों सहित सभी हितधारकों की सुरक्षा के लिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक प्रभावी और आधुनिक कानून लाना चाहिए।

श्री टी. राधाकृष्णन (विरुधुनगर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, पर्यावरण को सभी प्रकार के प्रदूषण से संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी में पर्यावरण की रक्षा करने की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हमारी वायु, जल और आकाश को प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है। यह हमारे नियमित वर्षा प्राप्त करने के रास्ते में आता है। यह पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

मानव अपशिष्ट के साथ-साथ औद्योगिक अपशिष्ट के प्रवाह की अनुमति देने से, हमारी नदी प्रणाली में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। पिछले कुछ वर्षों में सभी सरकारों द्वारा कई कानून और नियम बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी बढ़ती आबादी के साथ प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। यही कारण है कि हमारे पास पर्यावरण के लिए समर्पित एक मंत्रालय है, जो वनों के संरक्षण की भी देखभाल करता है। यह मंत्रालय विश्व मंचों पर सरकार के मुखपत्र के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है जहां जलवायु परिवर्तन एक बहुत चर्चित मामला है।

ओजोन परत में कमी के बारे में किए गए उपायों के संबंध में विकासशील देशों के बीच उठाए गए कदमों के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। दुनिया आज दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है। विकसित देश, जो इन सभी वर्षों में विषाक्त गैसों की मात्रा का उत्सर्जन कर रहे थे, उन्होंने भारत जैसे विकासशील देशों के लिए शर्तें निर्धारित करना शुरू कर दिया है। हम जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए मजबूर हैं। यह स्वाभाविक रूप से हमारी औद्योगिक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।

कार्बन की दरों में कमी के नाम पर, यानी कोयला, पेट्रोल, और प्राकृतिक गैस के, उपयोग से होने वाले गैस उत्सर्जन के नाम पर हम पर कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। चूंकि इससे हमारी आर्थिक प्रगति धीमी हो जाएगी, इसलिए हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रहे हैं।

जब पर्यावरण की बात आती है, तो यह हमारे जीवन चक्र का एक हिस्सा है – एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, वनों की कटाई और वन क्षेत्र में कमी ने वर्षा के स्वरूप को प्रभावित किया है। यह जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले दुःख को भी बढ़ाता है। वन तभी जीवित रह सकते हैं जब हम वहां के जंगली जानवरों को जीवित रहने दें। जब हरित आवरण की रक्षा की जाती है, तभी मानव जाति का अस्तित्व और मानव जीवन की स्थिरता संभव है।

इस मंत्रालय को सौंपी गई तीन जिम्मेदारियों के भीतर अंतर-संबंध को इंगित करने के बाद, मैं अब इस मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में जाने का प्रयास कर सकता हूँ। 2013-14 में इस मंत्रालय के लिए वास्तविक आवंटन 2,256 करोड़ रुपये था, जबकि संशोधित अनुमान 1,764 करोड़ रुपये था। जब मूल्य वृद्धि के कारण मौजूदा खर्च कई गुना बढ़ गया है, तो इस साल का आवंटन सिर्फ 1,681 करोड़ रुपये है।

मुझे समझ नहीं आता कि मंत्रालय हमारे वन क्षेत्र या वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपनी मानव शक्ति को कैसे प्रशिक्षित कर पाएगा। अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे जैसे विशाल देश के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवंटन में कमी को भी मैं समझने में विफल रहा हूँ।

हमारे जैसे उष्णकटिबंधीय देश में प्राणी उद्यानों में पशु प्रजातियों की सावधानीपूर्वक रक्षा करने और उन्हें पोषित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए आवंटन 26.5 करोड़ रुपये से घटाकर 5.88 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यहां, मैं तमिलनाडु में सभी मंदिर के हाथियों के लिए वार्षिक शिविर आयोजित करने में हमारी मार्गदर्शक भावना पुरात्ची थलाइवी अम्मा के दयालु भाव की ओर इशारा करना चाहूंगा। मुदुमलाई अभयारण्य में आयोजित यह वार्षिक शिविर उन जानवरों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य शिविर की तरह है जो साल भर मानव आबादी के बीच मंदिरों में रहते हैं। माननीय पर्यावरण और वन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर हाल ही में जंगली जानवरों, विशेष रूप से हाथियों की देखभाल करने में हमारे नेता के इस तरह के निरंतर भाव की अत्यधिक सराहना कर रहे थे। मैं कर्नाटक के बांदीपुर वनों में

आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में हमारी प्रिय नेता अम्मा को दिए गए उनके शानदार उपहार को याद करता हूँ।

जब पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार की बात आती है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि के मद्देनजर बढ़े हुए आवंटन के साथ ऐसे कार्यक्रम जारी रहने चाहिए। 2013-14 में जो 47 करोड़ रुपये था, वह वास्तव में 2014-15 में इस सरकार द्वारा घटाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। भारी कीमत पर उल्लंघन और क्षति नियंत्रण के लिए दंडात्मक उपायों से अधिक, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना आवश्यक है।

मैं पर्यावरण मंत्रालय जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए निधि आवंटन को कम करने के लिए केंद्र सरकार की समग्र प्रवृत्ति को समझने में विफल रहा, जिसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों से निपटना पड़ता है। मुझे डर है कि उद्योगों से बहुत अधिक उम्मीद की जा सकती है।

पर्याप्त मानव शक्ति की भर्ती, आवश्यक उपकरणों के साथ आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना और विशेष रूप से अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में वन संपदा की रक्षा के लिए, समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। केंद्र द्वारा इस क्षेत्र में कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप हाल ही में तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम वन में एक दुखद घटना हुई है। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान में जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मंत्री यह कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे कि वे वन राज्य सरकार के दायरे में आते हैं।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं केंद्र सरकार का ध्यान कागज और कार्डबोर्ड निर्माण में लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की ओर आकर्षित करता हूँ। इन इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट आसपास की हवा और पानी दोनों को प्रदूषित कर रहा है। प्रस्तावित नई जी.एस.टी. व्यवस्था में विनिर्माता राज्यों को कम राजस्व मिलेगा। वास्तव

में, इसका अर्थ यह होगा कि, राज्य सरकार पर पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक दबाव डाला जाएगा। हमारे विरुधुनगर निर्वाचन-क्षेत्र में, कागज और बोर्ड इकाइयों से औद्योगिक अपशिष्ट बहुत तबाही मचाता है। मैं केंद्र सरकार से समस्या का अध्ययन करने और एक केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार संयंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यवहार्य विधि विकसित करने का आग्रह करूंगा। पर्यावरण मंत्रालय की जरूरतों को नजरअंदाज करना राष्ट्रीय आपदा में समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि यह हमारी आंखों के सामने ऐसा न लगे, लेकिन विनाश अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय होगा। सावधानी के इस शब्द को देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

***श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** वन एवं पर्यावरण किसी भी देश के विकास एवं भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। हमारे देश में सदियों पुरानी वन एवं प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा एवं संरक्षण पद्धति अपनायी गयी है। व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के चलते वन एवं पर्यावरण पर इसका न सिर्फ हमारे देश में अपितु पूरे विश्व में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आधुनिकता एवं जनसंख्या विस्फोट ने तो वन एवं पर्यावरण को बुरी तरह से क्षति पहुंचाया है। आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं प्रदूषण के चलते विश्व में करोड़ों लोग तकलीफ झेल रहे हैं। मनुष्य क्या जानवर एवं पेड़-पौधे तक इस विनाश लीला से प्रभावित हुए है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश की अदालतें वन एवं पर्यावरण मुद्दे पर शुरू से गंभीर रही है। भिन्न-भिन्न न्यायालयों के सैकड़ों फैसलों ने सरकारों को मजबूर किया कि वे वन एवं पर्यावरण की समुचित रक्षा करें।

इसके बावजूद आज वन क्षेत्र हमारे देश में घटना ही जा रहा है। पशु-पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। वनों में मिलने वाले कई प्रकार के पौधे अब दिखाई नहीं देते। लालचवश हमारे देश के लोगों ने वन एवं पर्यावरण का दोहन किया है। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने देश की वन सम्पदा, खदानों एवं नदियों को भी नहीं बखशा। जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की स्थिति वन एवं पर्यावरण के मामले में अन्य देशों की तुलना में अच्छी नहीं है।

वर्ष 2014 में एन.डी.ए. सरकार के आने के बाद वन एवं पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाने लगा है। जलवायु परिवर्तन एवं स्थायी विकास पर विश्व द्वारा किए जाने वाले नए करारों के आलोक में वर्ष 2015 के एक अभिप्रेरणा वर्ष होने की संभावना है। यह अगले 15 वर्षों के लिए वैश्विक समुदाय हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास और पर्यावरणीय नीति संबंधी कार्य सूची के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा। केन्द्र सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में वित्त जुटाने हेतु भारत की संस्थागत संस्था को बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में कुछ प्रमुख पहलों में सोलर मिशन को जोर-शोर से बढ़ाया जा रहा है। इसके आतिरिक्त बजट 2014-15 की उद्घोषणाओं की अनुवर्ती

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कार्वाई के रूप में 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से अनुकूल कार्यों की सहायता के लिए एवं कृषि, पानी, वानिकी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय अनुकूल निधि की स्थापना की गई है।

कार्बन बाजार में भारत की भागीदारी एक सफलता की कहानी है। भारत क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित स्वच्छ विकास तंत्र (सी.डी.एम.) की कुल सात हजार पांच सौ नवासी परियोजनाओं में से 1541 परियोजनाएं भारत के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। अभी तक जारी कुल प्रमाणित उत्सर्जन हास (सी.ई.आर.) 1.52 बिलियन यूनिट है। जिसमें भारत का हिस्सा 191 मिलियन यूनिट का है। इसके आतिरिक्त जो 2941 परियोजनाएं अनुमोदित हुई हैं उससे हमारे देश में लगभग 580000 करोड़ रुपए के निवेश में सहायता मिलेगी।

केन्द्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत में जीव जन्तु सर्वेक्षण एवं अणवेशन में सतत् प्रयासरत है। वन प्रबंधन योजना में भी तेजी लायी जा रही है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, हाथी एवं बाघ परियोजनाओं के द्वारा वन एवं पर्यावरण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन, ई-कचरा प्रबंधन, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र में आशातीत सफलता पाने की कोशिश की जा रही है। ओजोन सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण मंजूरी के लिए राज्यों को ऑनलाइन मंजूरी देने को कहा जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर की श्रेणियों में रखने का फैसला किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आयात में कटौती पर ध्यान दे रहे हैं। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स को पब्लिक सेक्टर बैंक पौने दो लाख करोड़ रुपए का लोन देने जा रहे हैं। यानि, बिजली, संकट को दूर करने में ग्रीन एनर्जी का बड़ा रोल होने वाला है। सरकार का टारगेट 2022 तक 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी, 60 लाख मेगावाट विंड एनर्जी पैदा करने का है। सबसे खुशी की बात है कि 40 साल बाद हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हमारे केन्द्र सरकार का संकल्प है हरियाली की हिफाजत। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि देशभर में फारेस्ट एरिया बढ़ाने और करीब 30 लाख

परिवारों को रोजगार देने के मकसद से जो ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है उसे मनरेगा से जोड़ा जाएगा। सरकार ने उद्योगपतियों से कहा है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और अधिक हरियाली को केन्द्र में रखकर ही उन्हें औद्योगिक उत्पाद बनाने या बेचने चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार देश हित एवं जनहित में वन एवं पर्यावरण संबंधी मामलों को हल करेगी और अब हमारे देश से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे नकारात्मक तत्व दूर होंगे और आदमी का जीवन खुशहाल होगा। इसमें सभी भारतीयों का साथ मिलेगा और सबका विकास होगा।

[अनुवाद]

डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय आकाश, वायु, जल, भूमि और जीवित निवासी हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और वे सभी इस दुनिया में रहने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। संसार के निर्माण के बाद, धीरे-धीरे पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल हो गया और फिर केवल एक कोशिका से विभिन्न पौधे और जानवर और आगे की विकास प्रक्रिया से मनुष्य अस्तित्व में आए। उन्हें अपनी आजीविका और रहने के लिए स्वच्छ पानी, हवा और विभिन्न उत्पादक जानवरों और पौधों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ विज्ञान और शहरीकरण और आधुनिक जीवन की प्रगति जैसे विभिन्न कारणों से अपार समस्याएं हैं, जिन्होंने इस दुनिया में प्रदूषण पैदा किया है।

अपराह्न 03.17 बजे

(श्री कोनाकल्ला नारायण राव पीठासीन हुए)

अब, पूरी दुनिया में, एक ही समस्या है जो वास्तव में हर किसी को चिंतित कर रही है, वह है, ग्लोबल वार्मिंग, जो विभिन्न कारणों से है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। उनमें से, एक महत्वपूर्ण बिंदु हवा में कार्बन उत्सर्जन है। हर कोई सोच रहा है कि कार्बन उत्सर्जन की समस्या को कैसे खत्म किया जाए।

ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है? यह हमारे स्वास्थ्य को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है, और मुख्य बात यह है कि हवा और पानी गर्म हो रहे हैं। इसलिए, अप्राकृतिक जलवायु, असामयिक वर्षा और असामयिक मौसम परिवर्तन होते हैं जो विभिन्न असामान्यताओं और जीवन के नुकसान की ओर ले जाते हैं।

इसमें शामिल एक अन्य मुद्दा मेरे द्वारा पहले बताए गए कारणों के कारण दुनिया भर में वन क्षेत्र में कमी है। वन भूमि में कमी के कारण पशु जगत में कमी आई है, जो उनका निवास स्थान है, इसके परिणामस्वरूप, जानवरों और पक्षियों की संख्या या तो कम हो रही है या कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में क्या

होता है? उदाहरण के लिए, फूल बनाने के लिए पक्षियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह, विभिन्न अन्य चीजों के लिए अन्य जानवरों की आवश्यकता होती है।

वन भूमि का आवरण कम हो रहा है। विभिन्न वस्तुओं के नुकसान के कारण समुद्र और नदियों में कटाव होता है। सबसे दुखद बात यह है कि जब हम विश्व पर्यावरण को मानव जीवन के अनुकूल बनाने के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस साल कुछ चीजों में मंत्रालय के बजट में भारी कमी आई है। बेशक, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजना, गंगा कार्य योजना के लिए, आवंटन बढ़ाया गया है, और करों के मामले में भी 100 प्रतिशत कमी की गई है। मंत्री महोदय जी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि, गंगा कार्य योजना के साथ-साथ अन्य नदियों को भी प्रदूषण से बचाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून होना चाहिए कि औद्योगिक अपशिष्ट जो अब नदियों में बहता है, उसका उपचार किया जाए और औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में नहीं फेंके जाएं बल्कि इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उपचार किया जाए।

यह दुखद है कि वन संरक्षण के लिए आवंटित धन में कटौती की गई है। पहले जो आवंटन 5,045 करोड़ रुपये था, वह अब घटकर, लगभग आधा, यानी 2,099 करोड़ रुपये रह गया है। 650 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए यह काफी अपर्याप्त है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आवंटित धन में भी 15 प्रतिशत की कमी आई है, यानी, इसे 161 करोड़ रुपये से घटाकर 136 करोड़ रुपये कर दिया गया है, खासकर जब पिछले साल से भारत में बाघों की आबादी मूल रूप से 30 प्रतिशत बढ़ रही है।

मैं बंगाल से हूँ। मुझे कहना होगा कि सुंदरबन क्षेत्रों के साथ-साथ अंडमान में मौजूद अद्वितीय मैंग्रोव बंगाल के बाघों के निवास के लिए अनुकूल हैं। हम उन क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण भी कमी देख रहे हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक, विभिन्न कारकों के कारण मिट्टी के कटाव और लॉन्च से तेल के रिसाव, आदि के कारण। इसलिए, विशेष रूप से बंगाल और अंडमान क्षेत्रों में मैंग्रोव की सुरक्षा के लिए, अधिक धन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

हमारे हिंद महासागर का एक और बहुत महत्वपूर्ण खजाना अंडमान और लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ हैं। पारिस्थितिक रूप से, वे मछलियों के साथ-साथ मनुष्यों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि, सुनामी और अन्य कारकों के कारण, इन प्रवाल भित्तियों का आवरण कम हो गया है। इन प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

जैसा कि आप जानते हैं, बंगाल बाघ विश्व प्रसिद्ध है और यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। तथापि, उनकी आबादी बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने के बजाय, हम बजट आवंटन को कम कर रहे हैं। श्री सत्पथी जी कह रहे हैं कि आप इसे 'शेर' में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो गिर के जंगलों में है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पूरे भारत में, कई स्थानों पर बाघ मिलेंगे। आठ आरक्षित वन हैं जिनमें बाघों की संख्या अधिक है और, इसलिए, यह हमारा राष्ट्रीय पशु बना रहना चाहिए।

इसके अलावा, स्थायी समिति ने अपनी प्रतिवेदन में कहा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए बजट अपर्याप्त था। बंगाल में, वन क्षेत्र में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर, आदि में भी इसमें वृद्धि हुई है। वन उपज आदिवासियों और उन क्षेत्रों में और उनके आसपास रहने वाले गरीब लोगों जैसे वंचित व्यक्तियों की आजीविका है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। वन संरक्षण होना चाहिए क्योंकि वन उपज लोगों की आजीविका है। इसे और अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए और इस संबंध में अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में, उन्होंने बजट बढ़ाया है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। इस मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कृपया उन पक्षियों के बारे में सोचें जो हमारे देश में विलुप्त हो रहे हैं। धन्यवाद।

***श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण और वन्य जीवों की ओर से वकालत करनी चाहिए। इसके बजाय मंत्रालय केवल बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने में रुचि रखता है। लगभग 450 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। फिर भी मंत्रालय ने अवैध शिकार, वायु प्रदूषण, जल क्षरण और घटती जैव विविधता जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई ठोस परिणाम नहीं दिखाया है। इन मुद्दों पर, मंत्रालय ने केवल आश्वासन दिया है। गैंडों के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए कोई परियोजना नहीं है। पेंगलोसियन जैसे छोटे जानवरों का अवैध शिकार बेरोकटोक जारी है। दिल्ली में प्रदूषित हवा बच्चों में अस्थमा के मामलों की संख्या बढ़ा रही है। इतनी सारी गंभीर चुनौतियों के साथ बजट में कटौती ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ही पंगु बना दिया है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली):** पर्यावरणीय मुद्दा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा बन गया है। यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दे रही है चाहे वह वन भूमि का रूपांतरण हो, नदी का प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, आदि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आया है और आजकल काफी सक्रिय है। मुझे एक खबर मिली है कि सरकार राज्य सरकार के परामर्श से कई मौजूदा पर्यावरण कानूनों को बनाने या संशोधित करने पर विचार कर रही है। यह एक अच्छा विचार है क्योंकि पर्यावरण के मुद्दों को राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ समग्र पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। मुझे यह पता चला है कि कई राज्य सरकारें धन की कमी के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सभी निर्देशों को लागू नहीं कर पा रही थीं। सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित करने के निर्देश एक मुद्दा है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में धन लगता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि, सरकार एस.टी.पी. की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करे।

एक अन्य मुद्दा जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि आदिवासी लोग जो वन क्षेत्र में रह रहे थे, जिसमें वे अज्ञात अवधि से रह रहे थे। कठोर पर्यावरण कानूनों के कारण, ये लोग कई विकासात्मक गतिविधियों से वंचित हैं, जैसे कि सड़कें बिछाना, आदि। इसलिए, जनजातीय लोगों के हित में, मैं सरकार से पर्यावरण कानूनों के कुछ प्रावधानों में ढील देने का आग्रह करता हूं, ताकि वन भूमि में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए, वे भी कुछ ऐसे लाभों का आनंद ले सकें जो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरण एवं वन नीति को लागू करने तथा झीलों, नदियों, इसकी जैव विविधता, वन एवं वन्य जीवों सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा प्रदूषण रोकथाम और प्रदूषण कम करने के रोकथाम की देखभाल करने के लिए एक प्रमुख मंत्रालय है। मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सतत विकास के सिद्धांत से निर्देशित होता है। मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया पर्यावरण सहयोग कार्यक्रम, एकीकृत पर्वत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की भी प्रमुख एजेंसी है।

भारत वन्य जीव संरक्षण से संबंधित 5 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, वन्य जीव जंतु, वनस्पतियों के संकटापन्न समूहों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन विश्व विरासत समझौता तथा वन्य पशु प्रवासी समूह संरक्षण समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसके तहत मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य वनस्पति जीव जंतु, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना है तथा साथ ही प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, विकृत क्षेत्रों में वनरोपण और पुर्न उत्पत्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना है।

सरकार ने राज्यों को ऑनलाइन पर्यावरण मंजूरी देने के लिए पहल की है। इसके तहत केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह पर्यावरण संबंधित प्रक्रियाओं की ऑनलाइन मंजूरी शुरू करें। इसके लिए परियोजनाओं को राज्यों में स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी तथा स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट से मंजूरी हासिल करनी होती है। अभी तक इसके लिए देश में पुरानी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। इस पहल के लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ।

इसी तरह से सरकार ने देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रस्ताव किया है, इसके लिए सरकार ने भरोसा दिया है कि इसके माध्यम

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से सोलर और विंड एनर्जी जैसे गैर-पारम्परिक स्रोतों से 34 हजार मेगावाट विद्युत पैदा की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 75 हजार करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ अग्रणी रहा है। इससे 15 हजार मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा की जा सकेगी। इसके बाद 14700 करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ आई.डी.बी.आई. बैंक दूसरे नम्बर पर है। इससे 2940 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो सकेगा। यह भी ग्रीन एनर्जी उत्पादन की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल कदम उठाने का ही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत द्वारा वैश्विक ताप वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस कार्बनडाई ऑक्साईड के उत्सर्जन में दुनियाभर में हो रही बढ़ोत्तरी के बावजूद भारत में इसमें कमी आयी है। सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहल करते हुए जलवायु परियोजनाएं लागू करने के लिए देश में एजेंसियों को आमंत्रित किया है जिसके तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और उसके अनुकूल परियोजनाओं को लागू करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जलवायु कोष से संसाधनों को पाने के लिए आवेदकों को निश्चित तौर पर विश्वासी और मानक प्रबंधन वाला बनाने की दिशा में सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

आज जब दुनियाभर के तमाम जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का आकलन है कि अगर बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को नहीं थामा गया तो जल्दी ही दुनिया गरीबी और भूखमरी की चपेट में आ जाएगी। एक अरब से भी ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर होगा, और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। विश्व बैंक ने ग्लोबल वार्मिंग के असर पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि तापमान बढ़ने से दुनिया के कई इलाकों में फसलों की उत्पादकता में कमी आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक दोषी वे देश हैं जो सबसे ज्यादा इसका शोर मचा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है कि सरकार समावेशी तरीके से सभी का विकास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि गरीबों के लिए समुचित स्वच्छता, पेयजल, मातृत्व और शिशु देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार दें।

वैश्विक विकास में भारत की दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है और वैश्विक स्तर पर सहस्राब्दि लक्ष्य जब तक सफल नहीं हो सकते तब तक उन्हें भारत में हासिल नहीं किया जाता।

अंत में, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए वर्ष 2015-16 की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल की वर्ष 2014 में प्रकाशित आकलन रिपोर्ट की सिंथेसिस रिपोर्ट में बताया गया है कि सूखे और बाढ़ इत्यादि जैसी जलवायु संबंधी विषमताओं से होने वाले प्रभावों में वर्तमान जलवायु से कुछ प्रणालियों और मानव की महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने का पता चला है। फिर भी, भारत में जलवायु प्रभाव संबंधी कोई विशिष्ट अध्ययन उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक आंकलन के आधार पर अनुकूल और उपशमन कार्यों को बढ़ावा दें। सरकार ने 30 जून 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जारी की थी, जिसमें जलवायु से होने वाली बड़ी घटनाओं की रोकथाम और पूर्व तैयारी के लिए किए जाने वाले उपायों में वृद्धि से जलवायु से होने वाली बड़ी घटना के लिए सभी पहलों को रेखांकित किया जा सके और वर्तमान में सभी राज्य सरकारें भी इसी संबंध में कार्य योजना तैयार कर रही हैं।

जलवायु परिवर्तन, वन और पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय है, और पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही हैं। लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसी के चलते, पर्यावरण कानून में बदलाव करने से पहले केन्द्र सरकार राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रही है और वर्तमान में पर्यावरण मंजूरी लेना एक बेहद कठिन काम बन गया है। मंजूरी लेने के लिए लम्बे समय का इंतजार करना पड़ता है, अतः इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण से मंजूरी संबंधी परियोजनाओं को राज्यों में स्टेट एनवायरनमेंट अथॉरिटी और स्टेट एनवायरनमेंट असेसमेंट कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ती है और अभी तक इसके लिए भी पुरानी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अतः इस प्रक्रिया को बदलकर ऑनलाइन किए जाने की जरूरत है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सभी राज्य नगर पालिकाओं द्वारा उत्पन्न सीवेज को 100 प्रतिशत ट्रीटमेंट करने संबंधी योजना बनायी जानी चाहिए और उद्योग को ट्रीटमेंट के लिए पानी को फिर से इस्तेमाल में लाए जाने पर जोर देना होगा।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पेड़ों के आस-पास कंक्रीट डाले जाने से हरे भरे पेड़ों के सूख जाने का मामला बेहद गंभीर है, और शहरों में इस तरह से हजारों पेड़ सूख गए हैं क्योंकि इन पेड़ों को कंक्रीट से पाट दिया गया है और सरकार द्वारा हरियाली बढ़ाए जाने के खूब दावे किए जाते हैं। इन मामलों में उन मनको का पालन नहीं किया जा रहा है जिनके तहत यह कहा गया है कि पेड़ों की जड़ों के आस-पास एक निधाररित दूरी तक कंक्रीट नहीं डाला जाना चाहिए, इस तरह से अक्सर देखने को मिलता है कि जैसी ही हवा थोड़ी तेज गति से चलती है या तेज बारिश होती है तो पेड़ गिरने लगते हैं ज्यादातर मामलों में ये पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं और इस घटना से बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान होता है। इससे जाहिर होता है कि संबंधित एजेंसी को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार द्वारा वन्य संसाधनों की रक्षा के लिए हरित कानून को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है, हमारे पास कानून तो बने हैं लेकिन हम उन्हें सख्ती से क्रियान्वित नहीं करते हैं। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। देश में धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है लेकिन हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

दुनिया के तमाम देश इस बात से चिंतित हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को यहीं नहीं थामा गया तो जल्द ही दुनिया गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ जाएगी और एक अरब से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया में पड़ेगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसके प्रति चिंता व्यक्त की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक दोषी वो देश हैं जो आज सबसे ज्यादा इसका शोर मचा रहे हैं। यूरोप के विकसित देशों और स्वयं अमेरिका ने पिछली सदी में जबरदस्त औद्योगीकरण करके दुनिया को इस हाल में पहुंचाया है, लेकिन आज ये सब देश मिलकर भारत और चीन को अपनी औद्योगिक नीति बदलने को कह रहे हैं और मोदी जी ने इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में जलवायु का न केवल जिक्र किया था बल्कि यह भी कहा था कि हम इसकी संवेदनशीलता को भी जानते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया के कई इलाकों में फसल उत्पादन में कमी हो रही है। यह भविष्य में इस संकट के और गहराने की आशंका है और इसके लिए अगर कोई मजबूत और त्वरित कार्यवाही नहीं की गई तो यह संकट पूरे विश्व में फैल जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के अनुसार पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने पर सहमति बनी थी लेकिन यह कैसे होगा इस पर पिछले दो दशकों से बिना किसी नतीजे में माथापच्ची जारी है। इस काम में सबसे बड़ी बाधा धन की कमी है जिसे पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी के विकास पर खर्च किया जाना है। इस पर 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया जाना है, इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

महाराष्ट्र में बैल गाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का खेल पुराने समय से चलता आ रहा है यह दौड़ महाराष्ट्र के हर गाँव में होती है। इस प्रतियोगिता पर किसानों को कोई आपत्ति नहीं थी जबकि इसमें भाग लेने वाले बैलों को किसान अच्छी तरह से पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं यह प्रतियोगिता एक पारंपरिक खेल था पर एन.जी.ओ. ने जानवरों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर खेल पर रोक लगाने की मांग की और इस बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता पर रोक लगा दी गयी। जहां एक ओर बैलगाड़ी प्रतियोगिता पर रोक लगा दी वहीं दूसरी तरफ घोड़दौड़ अभी भी देश के कई हिस्सों में रेसकोर्स मैदानों में चालू है, मेरा कहना है कि यदि इस बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता से जानवरों पर अत्याचार हो रहा है तो इसमें घोड़दौड़ प्रतियोगिता पर रोक क्यों नहीं लगी? [अनुवाद] अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र में पारम्परिक रूप से चली आ रही बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता पर रोक को यथापूर्व हटाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाए।

इको सेंसेटिव जोन देश के कई भागों में हैं जो कि निश्चित रूप से पर्यावरण के रख-रखाव के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन इको सेंसेटिव जोन से इन क्षेत्रों में जाने वाले नागरिकों एवं पर्यटकों को बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र माथेरान है। यह क्षेत्र ब्रिटिश काल से ही इको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है और इको सेंसेटिव जोन घोषित होने की वजह से यहां पर डीजल गाड़ियों एवं अन्य वाहनों के चलने पर रोक लगी हुई है। माथेरान 25 हजार का आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ इन सब वाहनों के नहीं होने से स्थानीय लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेंसेटिव जोन होने के कारण यहां के लोग

अपने मकानों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं। यहां आवागमन के लिए कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण यहां पर्यटकों को ले जाने के लिए हाथगाड़ी का उपयोग होता है। जो नौजवानों रोजी रोटी के लिए हाथ गाड़ी खींचने का काम करते हैं वह अपनी थकान को दूर करने के लिए नशा करते हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि माथेरान जैसे हिल स्टेशन में बैटरी से चलाए जाने वाले रिक्शा शुरू करने की अनुमति दी जाए और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वहां रोप वे की सुविधा दी जाए जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और केंद्र और राज्य सरकार से मैं इसके लिए आर्थिक मदद की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री राम प्रसाद शर्मा (तेजपुर):** मैं असम के तेजपुर निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ। मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय को अनुदान की मांग का पूरा समर्थन करता हूँ।

असम, जिसे कभी वनों और वन्य जीवन और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और चिकित्सा पौधों के सबसे समृद्ध उपहार के साथ “वन राज्य” के रूप में जाना जाता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासन के दौरान व्यवस्थित रूप से वनों की कटाई और वन्य जीवों की हत्या की गई है। विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे को शिकारियों से गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है, केवल पिछले तीन वर्षों में 79 गैंडे मारे गए हैं। रेत खनन और मूल्यवान वन खदानों और खनिजों का अवैध उत्खनन बेरोक टोक चल रहा है और राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। असम, काजीरंगा, मानस, पोबितारा और ओरंग में गैंडे के सींग, बाघ की खाल, केको सरीसृप और अन्य वन्यजीव अंगों की तस्करी अंधाधुंध रूप से चल रही है जो अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने के कारण एक सींग वाले गैंडे के गंभीर खतरे के लिए जाना जाता है।

वन क्षेत्रों में वन गांवों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को राज्य सरकार द्वारा अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जैसा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक है।

इसलिए, मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह वन सीमांकन, गैंडों की हत्या और पशु अंगों की तस्करी को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाए और राज्य में रेत और अन्य मूल्यवान खनिजों के अवैध खनन और तस्करी को भी रोके। मैं माननीय मंत्री जी से उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू करने का भी अनुरोध करता हूँ जहां पेड़ों की अवैध कटाई के कारण वन क्षेत्र कम हो गया है।

एन.एच.ए.आई. ने अभी तक असम में 4 लेन की सड़कों के दौरान भरे हुए पेड़ नहीं लगाए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय को एन.एच.ए.आई. को 4 लेन वाली सड़क के हिस्से पर सड़क पर पेड़ लगाने का निर्देश देना चाहिए। मैं यह भी बता सकता हूँ कि लेन परिवर्तन के दौरान एन.एच.ए.आई. द्वारा लगभग 3 लाख मूल्यवान और पूरी तरह से उगाए गए पेड़ों को काट दिया गया था।

***श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल):** हम, एक राष्ट्र के रूप में, लंबे समय से जलवायु परिवर्तन और 'विकास' के नाम पर हमारे पर्यावरण पर इसके प्रभावों की अनदेखी कर चुके हैं, लेकिन यह हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने का समय है ताकि वे हमारी जैव विविधता के साथ तालमेल बिठा सकें। नई सरकार के 100 दिनों के बाद, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन पांच कानूनों की जांच के लिए किया गया था; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981। आदेश में कहा गया है कि समिति 'उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए इनमें से प्रत्येक अधिनियम में आवश्यक विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी।' यह बहुत उत्साहजनक नहीं लगता है। एकल खिड़की पर्यावरण और वन निकासी प्रणाली के शुभारंभ के कारण, यह अत्यधिक संदिग्ध है कि क्या सरकार पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के पक्ष में झुकेगी।

मैं अपने भाषण को मोटे तौर पर दो चीजों पर केंद्रित करूंगा; गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री (अर्थात् प्लास्टिक) का बढ़े पैमाने पर उपयोग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव।

औद्योगिक क्रांति के दौरान 1856, में पहली बार प्लास्टिक का उत्पादन किया गया था। इसे विश्व उद्योग में एक बड़ी प्रगति के रूप में सराहा गया था। आज, हम हर जगह प्लास्टिक पाते हैं, पालतू जानवरों की बोतलें जिनमें पेय पदार्थ, पॉलिएस्टर, रसोई के बर्तन, पैकेजिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ होता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्तमान में, भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आई.बी.ई.एफ.) के एक उद्योग सारांश के अनुसार, भारतीय प्लास्टिक उद्योग देश भर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4 करोड़ लोग और 2,000 से अधिक निर्यातक कार्यरत हैं। यह 30,000 से अधिक प्रसंस्करण इकाइयों का संचालन करती है, जिनमें से 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत छोटे और मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) हैं।

ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए.आई.पी.एम.ए) के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 9.7 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 27 किलोग्राम है। हम अभी भी वैश्विक औसत से बहुत दूर हैं लेकिन खपत लगातार बढ़ रही है। जैसे-जैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, वे अधिक एफ.एम.सी.जी. उत्पादों का उपभोग करना शुरू कर देते हैं जो अपने उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं।

यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है क्योंकि एक बार प्लास्टिक बन जाने के बाद, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। 'रीसायकल प्लास्टिक' प्लास्टिक उद्योग का नया आदर्श वाक्य है। 8 फरवरी 2015 को ए.आई.पी.एम.ए. द्वारा जारी एक बयान में उद्योग जगत के नेताओं ने यहां तक कहा है कि प्लास्टिक के थैले 'पर्यावरण के अनुकूल' हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या अप्रयुक्त प्लास्टिक को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नष्ट करने का कोई तरीका है?

मुझे एक चिंताजनक परिदृश्य सामने रखने दें जो अभी प्रशांत महासागर में सामने आ रहा है। नेशनल ज्योग्राफिक ने हाल ही में 'द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच' के बारे में एक कहानी प्रतिवेदन की जो काफी आंख खोलने वाली साबित होती है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जिसे पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से जापान तक फैला हुआ है। यह गैर-जैव अपघटनीय कचरे से भरा हुआ है जो समुद्र के बीच में एक भंवर, में फंस गया है। अनुमान है कि कचरा पैच टेक्सास राज्य जितना बड़ा है।

प्रतिवेदन में कहा गया है, 'कैलिफोर्निया के तट पर फेंकी गई एक प्लास्टिक की पानी की बोतल कैलिफोर्निया धारा को दक्षिण की ओर मेक्सिको की ओर ले जाती है। वहाँ, यह उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा को

पकड़ सकती है, जो विशाल प्रशांत के पार है। जापान के तट के पास, बोतल शक्तिशाली कुरोशियो धारा पर उत्तर की ओर यात्रा कर सकती है। अंत में, बोतल उत्तरी प्रशांत धारा पर पश्चिम की ओर यात्रा करती है। पूर्वी और पश्चिमी कचरा पैच के धीरे-धीरे लुढ़कने वाले भंवर धीरे-धीरे बोतल में आते हैं।

ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में मलबे की मात्रा जमा हो जाती है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कई प्लास्टिक खराब नहीं होते हैं; वे बस छोटे और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये 'माइक्रोप्लास्टिक' फिर समुद्री जीवों द्वारा निगले जाते हैं और समुद्र के नीचे पौधों में फंस जाते हैं। यह मोड़ खाद्य-श्रृंखला को आगे बढ़ाता है और उन रेस्तरां में समाप्त होता है जो समुद्री भोजन परोसते हैं। चूंकि ये सूक्ष्म प्लास्टिक हैं, इसलिए इन्हें नग्न आंखों से देखना मुश्किल है। इन्हें मनुष्य भी खा रहे हैं।

किसी को नहीं पता कि उस विशाल भंवर में कितना प्लास्टिक फंसा हुआ है, क्योंकि इसकी मात्रा का अनुमान लगाना वास्तव में मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के एक वर्ग किलोमीटर में माइक्रोप्लास्टिक के 750,000 बिट्स तक एकत्र किए हैं-जो लगभग 1.9 मिलियन बिट्स प्रति वर्ग मील है। इनमें से अधिकांश मलबा प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों की टोपियों, प्लास्टिक की पानी की बोतलों, और स्टायरोफोम कपों से आता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में लगभग 80% मलबा उत्तरी अमेरिका और एशिया में भूमि-आधारित गतिविधियों से आता है। उत्तरी अमेरिका के तट से कचरे को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच तक पहुंचने में लगभग छह साल लगते हैं, जबकि जापान और अन्य एशियाई देशों से कचरे में लगभग एक साल लगता है।

इस तरह के उदाहरणों को तुरंत कुछ खतरे की घंटी बजानी चाहिए। हाल ही में आई कश्मीर और उत्तराखंड की बाढ़ इस बात का उदाहरण है कि अगर हम अपने पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करने में लापरवाही बरतते हैं तो क्या होता है। उन बाढ़ों के बाद भी, ऐसा लगता है कि हम पर पट्टिका खो गई है। वहाँ की राज्य सरकार ने 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बनेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बताते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास, वन मंजूरी की आवश्यकता को हटाने के लिए हरी झंडी दे दी है।

जलवायु परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। यह तुरंत पहचानने योग्य नहीं है लेकिन प्रभाव हमारे चारों ओर हैं। मानसून के व्यवहार में परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली फसल की क्षति उनमें से सबसे बड़ी है। अप्रैल 22 को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था। उस दिन, अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जीवाश्म ईंधन का एक चौथाई हिस्सा पृथ्वी के अंदर रहने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन हमारे नियंत्रण से परे हो जाएगा, जिससे हमारे अस्तित्व और हम जो कुछ भी प्यार करते हैं उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हमें कार्बन प्रदूषण को शून्य तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के, अस्वीकार्य खतरनाक स्तर के नीचे रखने के लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, हमें 2050 तक अपने समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को, 100% स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से स्थानांतरित करने के लिए तत्काल यथार्थवादी वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय समझौते करने चाहिए।

पिछले साल असम में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था: 'जलवायु परिवर्तन? क्या यह शब्दावली सही है? वास्तविकता यह है कि हमारे परिवार में कुछ लोग बूढ़े हैं। उनका कहना है कि इस बार मौसम ठंडा है। और, लोगों की सर्दी सहने की क्षमता कम हो जाती है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या यह जलवायु परिवर्तन है अथवा हम बदल गए हैं। हमने प्रकृति के खिलाफ संघर्ष किया है। इसलिए हमें प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ रहना चाहिए। 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, यह टिप्पणी करने के कुछ ही दिनों बाद, श्री मोदी' नो शो 'थे। विचार कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर दामोदरदास सरकार इन असत्यों को देश भर के पाठ्यक्रम में शामिल करती है तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। यह एक बहुत ही वास्तविक डर है।

आप हर समय समाचारों में मूसलाधार बाढ़ और अन्य चरम मौसम के बारे में प्रतिवेदन देखते हैं-कुछ लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानव गतिविधि के कारण जलवायु परिवर्तन वास्तव में एक वास्तविक बात है। ध्रुवीय हिमखंड तेजी से खतरनाक दर से पिघलने से भविष्य में समुद्र का स्तर बढ़ेगा। सिक्के

के दूसरी तरफ, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के गर्म, सूखे क्षेत्रों में आग का मौसम एक दशक पहले की तुलना में लगभग 75 दिन अधिक रहता है।

जलवायु शासन की दुनिया एक उतार-चढ़ाव में है। भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस तक चरम मौसम की घटनाओं की एक श्रृंखला समय-समय पर जलवायु परिवर्तन पर खतरे की घंटी बजाती रहती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की पांचवीं मूल्यांकन प्रतिवेदन का जारी होना कार्रवाई की आवश्यकता के लिए और अधिक गंभीर आह्वान प्रदान करता है।

फिर भी, अधिकांश देशों में, और वैश्विक संवाद में, जलवायु परिवर्तन पर राजनीतिक ध्यान का स्तर कम हो रहा है, जो वित्तीय संकट और अन्य अल्पकालिक संकटों से भरा हुआ है। एक ही समय में, पहले से कहीं अधिक देशों - वैश्विक उत्सर्जन के अनुमानित 67% को कवर करते हुए-जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय विधान या रणनीति है। अनौपचारिक स्थानीय पहलों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी प्रसार हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सी.ओ.पी.21 या सी.एम.पी.11 नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया के सबसे बड़े जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में से एक होने की उम्मीद है, जहां 196 देश कार्बन उत्सर्जन में कमी के संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मिलेंगे। यह भारत के लिए यह दिखाने का एक ऐतिहासिक अवसर है कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीर हैं और एक स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। हमें तेजी से एक उद्योग समर्थक और पर्यावरण विरोधी राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से जब से इस सरकार ने एक तरफ पर्यावरण मंजूरी देने और दूसरी तरफ ग्रीनपीस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, हमें ऐसे स्वागत योग्य संकेत नहीं दिख रहे हैं जो अन्यथा कहते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस सम्मेलन में जाने से पहले एक उचित योजना बनाए और इसे सदन के साथ साझा करें। इस विषय के संबंध में उचित परामर्श की आवश्यकता है और हमें जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एकजुट रुख अपनाना चाहिए।

***कुमारी शोभा करंदलाजे (उडुपी चिकमंगलूर):** पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ई.एस.ए.) की अवधारणा शुरू से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की प्रतिवेदन में, पश्चिमी घाट के 59,940 वर्ग किलोमीटर (37%) को ई.एस.ए. के रूप में निर्धारित किया गया है। एम.ओ.ई.एफ. ने मार्च 10, 2014, को इस प्रतिवेदन के आधार पर एक मसौदा अधिसूचना की रूपरेखा तैयार की है जिसमें पश्चिमी घाटों पर फैले छह राज्यों में कुल 56,825 वर्ग किलोमीटर की पहचान की गई है। कर्नाटक ई.एस.ए. के सबसे बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के 20,668 वर्ग किलोमीटर को ई.एस.ए. घोषित करने के प्रस्ताव ने स्थानीय समुदायों के बीच स्थानांतरण की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, हालांकि प्रतिवेदन में केवल इन क्षेत्रों में खनन और ताप संयंत्रों जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।

कस्तूरीरंगन समिति की प्रतिवेदन को पर्यावरणविदों और पश्चिमी घाट क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले लोगों सहित विभिन्न वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ा है। आसपास रहने वाले लोगों को डर था कि प्रतिवेदन के कार्यान्वयन से उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से गांवों में बस्तियों, बागानों और कृषि क्षेत्रों को ई.एस.ए. के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया था। कर्नाटक के 1,91,791 वर्ग किलोमीटर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से पश्चिमी घाट तालुका 44,448 वर्ग किलोमीटर तक हैं, जिसमें ई.एस.ए. के रूप में पहचाने गए 1,576 गांव शामिल हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिए अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण पर के. कस्तूरीरंगन प्रतिवेदन पर केंद्र को अपनी टिप्पणी देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। अब तक, केवल केरल ने केंद्र को अपनी आपत्तियां सौंपी हैं।

प्रदूषण की उदारता धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर अनुपात प्राप्त कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण को उचित प्राथमिकता नहीं दी गई है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उनके समर्थन और सहयोग के बिना, अकेले सरकार के लिए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा। अकेले सरकार के लिए देश भर में हवा, पानी, भूमि, शोर आदि, में प्रदूषण में तेजी से वृद्धि के खतरे से लड़ना और उससे निपटना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। इस संबंध में राज्य सरकारों से आवश्यक सहयोग और समर्थन निश्चित रूप से आवश्यक है। जिस तीव्र गति से पर्यावरण की स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, उसे नियंत्रित करना सरकार के लिए हमेशा मुश्किल होगा, जब तक कि राज्य सरकारों को पर्यावरण की सुरक्षा में प्रभावी भागीदार नहीं बनाया जाता।

मीडिया में दिखाई देने वाली एक परेशान करने वाली खबर यह है कि वायु प्रदूषण भारत में 5वां सबसे बड़ा हत्यारा था, अन्य प्रतिवेदन अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीय शहरों में खतरनाक धुंध जैसी स्थिति से संबंधित थीं। मीडिया में प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार, लगभग आधे शहर गंभीर विशेष प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और वायु विषाक्त पदार्थ जैसे नए प्रदूषक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को खराब कर रहे हैं।

मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 के अनुसार, 131 शहर पी.एम. 10 की अनुमेय सीमा से अधिक हैं, जो 62 प्रतिशत तक अधिक है और 19 शहर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर से अधिक हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन की निरंतर वृद्धि भी पर्यावरण के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक के रूप में उभरी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार देश के 60 प्रमुख शहरों में कुल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन 50,592 टन उत्पन्न होता है, जबकि देश भर में उत्पादन प्रतिदिन 1,50,000 टन होने का अनुमान है। उपरोक्त में से केवल एक छोटे हिस्से को संसाधित किया जा रहा है और शेष कचरे को खुली हवा में फेंक दिया जाता है जिससे शहरों और कस्बों में पर्यावरण और स्वास्थ्य को खतरा होता है। सी.पी.सी.बी. के आकलन के अनुसार, भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। देश में कुल प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में से केवल लगभग 60% एकत्र किया जाता है और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जबकि बाकी असंकलित और बिखरे हुए रहते हैं।

मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को प्रमुख भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु दर पर अपना अध्ययन करना चाहिए, और यदि अध्ययन विज्ञान और शिक्षा केंद्र (सी.एस.ई.), द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के निष्कर्षों की पुष्टि करता है तो नागरिकों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

मैं सभी प्रकार के प्रदूषण में तेजी से वृद्धि पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं और महसूस करता हूं कि जब तक सी.पी.सी.बी. द्वारा कुछ गंभीर और प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक स्थिति बद से बदतर होती जाएगी; आने वाले दिनों में खतरनाक अनुपात मानते हुए और पूरे देश के लिए हानिकारक साबित होगी। निगरानी और प्रवर्तन एजेंसियों का पर्याप्त विस्तार और सुदृढ़ीकरण समय की आवश्यकता है ताकि स्थिति और न बिगड़े। सी.पी.सी.बी. के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या को और बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि परियोजनाओं/प्रदूषणकारी इकाइयों की प्रभावी और सफल निगरानी की जा सके।

मैं पर्यावरण और वानिकी मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों की सराहना करता हूं जो बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन की सुविधा प्रदान करेंगे। कुछ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर सड़कों, अस्पतालों के निर्माण के लिए वानिकी मंजूरी की आवश्यकता वाली छोटी परियोजनाएं लंबे समय से लटकी हुई हैं। मुझे लगता है कि विकास के लिए बुरी तरह से आवश्यक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

कुछ परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी के अनुसार की योजनाओं में सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य कर दी गई है, विशेष रूप से वे जो स्थानीय निवासियों को प्रभावित करते हैं तथ्य यह है कि सार्वजनिक सुनवाई वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष तरीके से नहीं की जाती है। अक्सर सार्वजनिक सुनवाई एक राज्य प्रबंधित हो जाती है और परियोजना प्रस्तावकों की उपस्थिति में एक आंख धोने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां उनके प्रतिनिधि इसका उपयोग प्रभावित जनता को उनके हित और कल्याण के नुकसान के लिए परियोजना के लिए अपनी मंजूरी देने के लिए मनाने, मनाने और मनाने के लिए एक मंच के रूप में करते हैं। इस तरह की घटनाओं से जनता में असंतोष पैदा होता है और कभी-कभी विरोध भी होता है जिससे पूरी परियोजना

खतरे में पड़ जाती है। सरकार को सार्वजनिक सुनवाई में इस तरह के कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए ताकि सार्वजनिक सुनवाई उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए ये अभिप्रेत हैं। लोगों की वास्तविक चिंताओं को पर्यावरण प्रबंधन योजना में जगह मिलनी चाहिए और परियोजना के समर्थक जनता की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक निवारक और उपचारात्मक उपाय करते हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को ई.आई.ए. अधिसूचना में सार्वजनिक सुनवाई के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों के वास्तविक कार्यान्वयन के कुछ नमूने मामलों में निगरानी करनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ई.आई.ए. अधिसूचनाओं के प्रावधानों का वास्तविक व्यवहार में किस हद तक पालन किया जा रहा है।

विलुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाने और महत्वपूर्ण रूप से कम करने की तत्काल आवश्यकता है, यदि मानव-पशु संघर्ष, रेल या सड़क दुर्घटनाओं आदि जैसी, जानवरों को मारने वाली घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है, तो मंत्रालय को सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए, स्थानीय निवासियों को, शामिल किया जाना चाहिए। मानव-पशु संघर्ष, रेल दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मौत, आदि जैसी घटनाएं बेरोकटोक जारी हैं, मंत्रालय को एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किए गए उपायों ने जानवरों की हत्या को कम करने में किस हद तक मदद की है।

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान(संबलपुर) : महोदय, अनुदान की इन मांगों के तीन भाग हैं – पहला वनों से संबंधित है, दूसरा पर्यावरण से संबंधित है और तीसरा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।

मैं पर्यावरण से शुरुआत करता हूँ। अब, भारत में विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं, उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़, कश्मीर में एक के बाद एक आई बाढ़, फैलिन और हुदहुद जैसे गंभीर चक्रवाती तूफानों के रूप में कुछ अनुमानों के संकेत प्रकट होने लगे हैं। ये हाल के कुछ उदाहरण हैं। मानसून का चक्र अनियमित हो गया है जिससे देश के बड़े हिस्सों में धान की खेती प्रभावित हुई है। ओडिशा में गंगा, यमुना, महानदी, ब्राह्मणी सहित प्रमुख नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में गिरावट का रुझान दिख रहा है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। देश में और विशेष रूप से दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी अर्जित करने वाली सुर्खियां बना रही है, इसलिए कुछ देशों ने कथित तौर पर दिल्ली में अपने राजनयिकों का कार्यकाल कम कर दिया है और कई दूतावासों ने अपने कार्यालयों और अपने राजनयिकों के आवासों में एयर प्यूरीफायर लगाए हैं।

21 फरवरी 2015 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित एक अध्ययन 'लोअर पॉल्यूशन, लॉन्गर लाइव्स' में अनुमान लगाया गया है कि अगर पी.एम. 2.5 प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता से अधिक क्षेत्रों में रहने वाले 660 मिलियन लोग हवा में सांस ले सकते हैं जो वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है तो भारत दो अरब जीवन वर्ष और प्रति व्यक्ति लगभग 3.2 वर्ष बचा सकता है। बहुत देर होने से पहले समयबद्ध तरीके से सक्रिय और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए यह एक स्पष्ट आह्वान होना चाहिए क्योंकि एक निश्चित स्तर से परे पर्यावरणीय क्षति अपूरणीय और अपरिवर्तनीय हो जाती है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक हालिया प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा है कि, राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए अभी तक कोई कार्य योजना नहीं है। इसलिए, मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। न केवल महानगरीय शहर बल्कि टियर-II, छोटे शहर भी सभी पर्यावरणीय मापदंडों पर प्रदूषण के गंभीर प्रभाव से जूझ रहे हैं।

राज्य को संवैधानिक रूप से पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और हमारे वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है। संविधान वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य को मान्यता देता है। सतत विकास के सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अभिन्न घटक के रूप में शामिल किया गया है। इन सबके बावजूद, पर्यावरण क्षरण की चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया है।

पर्यावरणीय क्षरण जिसे कृषि उत्पादकता के नुकसान में एक प्रमुख योगदान कारक माना जाता है, क्योंकि पारिस्थितिक क्षरण मिट्टी की उर्वरता, पानी की मात्रा और गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, वनों, वन्यजीवों और मत्स्य पालन आदि को प्रभावित करता है। वन क्षरण के सबसे अधिक पीड़ित गरीब आदिवासी समाज हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर रहते हैं। पर्यावरणीय संसाधन आधार के नुकसान के परिणामस्वरूप अक्सर इन समूहों को बेसहारा बना दिया जाता है जो हमारी आबादी के बड़े हिस्से के अलगाव और थकावट की ओर ले जाता है।

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र दुनिया में बिजली उत्पादन के सबसे अधिक प्रदूषणकारी तरीकों में से एक हैं। भारत में, लगभग 70 प्रतिशत बिजली कोयले द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि, कोयले पर उच्च निर्भरता, पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण लागत पर आती है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के परिणामस्वरूप न केवल बड़े पैमाने पर कण पदार्थ और एस.ओ. 2, एन.ओ. 2 और पारा जैसे अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है बल्कि वे 170 मिलियन विषम टन खराब प्रबंधित फ्लाई ऐश का उत्पादन भी करते हैं और अपने संचालन के दौरान भारी मात्रा में पानी का उपभोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या वे अक्षय ऊर्जा आदि जैसे किसी विकल्प के बारे में सोच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वह इस बारे में कुछ जानकारी दें।

अब मैं दूसरे भाग, यानी, वानिकी पर आता हूँ। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों या वृक्ष आच्छादन के तहत देश के कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम 33 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। भारत-वन स्थिति प्रतिवेदन, 2013 के अनुसार वन और वृक्ष आच्छादन का विभाजन दर्शाता है कि 24.01 प्रतिशत के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में बहुत घने वन का 2.54 प्रतिशत, मध्यम घने वन का 9.70 प्रतिशत, खुले वन

का 8.99 प्रतिशत और वृक्ष आच्छादन का 2.78 प्रतिशत शामिल है। वर्ष 2007 से अब तक बहुत घने वनों का प्रतिशत 2.54 है। इस प्रकार, 2013 की प्रतिवेदन के अनुसार सही मायने में वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 12.2 प्रतिशत है।

वर्ष 2002-03 में वन क्षेत्र और वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका में सुधार के लिए राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई थी। इसमें से 663.45 करोड़ रुपये की राशि, कुल स्वीकृत परिव्यय का लगभग 1/4 वां हिस्सा, पिछले तीन वर्षों के दौरान, खर्च किया गया था। इस वर्ष आवंटन वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान स्तर पर 243.8 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के लिए निर्धारित पूरे परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के वित्तपोषण पद्धति में मौजूदा 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से के बजाय 2015-16 से केंद्र और राज्यों के 50:50 के हिस्से के साथ बदलाव होने की संभावना है। वित्त पोषण पद्धति में यह परिवर्तन निश्चित रूप से कार्यक्रम की प्रगति को प्रभावित करेगा क्योंकि, राज्य अपनी प्राथमिकताओं के कारण, मंत्रालय की अपेक्षा के अनुसार इस कार्यक्रम में योगदान नहीं करना चाहेंगे। इसलिए, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण की पहले की शर्त बनी रहे।

वर्ष 2014-15 के लिए 80 करोड़ रुपये के, कुल बजट आवंटन में से केवल 3 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा सका। फिर भी, इस वर्ष इस योजना के लिए परिव्यय 64 करोड़ रुपये रखा गया है। माननीय मंत्री को अपने उत्तर के दौरान यह बताना चाहिए कि यह पैसा कैसे खर्च किया जाएगा।

क्या यह सच है कि 38,000 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) के पास पड़ी है? उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय को लगभग 23,800 रुपये की मूल राशि के केवल दस प्रतिशत की सीमा तक और वह भी अर्जित ब्याज से धनराशि जारी

करनी चाहिए। इस साल हालांकि मंत्रालय को लगभग 2,400 करोड़ रुपये जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन यह केवल 1,100 करोड़ रुपये जारी कर सका। इस संबंध में, इस सी.ए.एम.पी.ए. फंड की क्या स्थिति है?

एक प्रश्न के उत्तर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक लाख हेक्टेयर वन भूमि को खनन परियोजनाओं के लिए मोड़ दिया गया है। अन्य राज्यों को इस तरह से काम करना चाहिए। धन्यवाद।

***श्री के. परशुरामन (तंजावुर):** हमारे देश में पर्यावरणीय क्षरण से निपटने की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री को पर्यावरण क्षरण से निपटने के उनके प्रयास के लिए, बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने विद्युत वाहनों के लिए आवंटित स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया है और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को सेवा कर का भुगतान करने से छूट दी है। लेकिन साथ ही यह भी चिंता की बात है कि, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए आवंटित धन को मंत्रालय के संशोधित अनुमान 2014-2015 के 1764.60 करोड़ रुपये से घटाकर 1681.60 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत में पर्यावरणविदों ने आवंटन में इस कटौती पर अपनी पीड़ा और चिंता व्यक्त की है और उन्हें डर है कि इससे देश में और अधिक पर्यावरण कार्यक्रम प्रभावित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बिगड़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की भेद्यता को दूर करने में विफलता होगी। इसलिए, मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि, वे ग्रामीण उपयोग के लिए प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, और सौर पर अधिक शोध कार्यक्रमों के लिए पश्चिमी देशों की तरह अधिक धन आवंटित करें।

बजट में एक और चिंताजनक और चौंका देने वाली बात यह है कि सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन की फंडिंग इस साल 80 प्रतिशत कम कर दी गई है, जो 15 अरब रुपये से घटकर 3 अरब रुपये हो गई है। धान की खेती के कारण भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत कृषि है, जो विस्तारित बाढ़ वाले खेतों के माध्यम से मीथेन का उत्पादन करती है और भूमि के छोटे भूखंडों में खेती करने के लिए गायों का उपयोग करती है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेष रूप से वर्षा के बदलते स्वरूप, बाढ़, सूखा और तूफानों से खेती को भी अत्यधिक खतरा है। मैं कावेरी डेल्टा क्षेत्र से आता हूं जहां कृषि 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के जीवन का मुख्य स्रोत है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे पर्यावरण मंत्रालय को और अधिक धन आवंटित करें और राज्यों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण उपयोग के लिए सौर आदि पर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करें।

मैं अपने माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जैव विविधता उन महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि विश्व स्तर पर मौजूद 25 हॉटस्पॉट में से भारत विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंगा के मैदान, मन्नार की खाड़ी, मैंग्रोव वन और पश्चिमी घाट भारत में विविध पारिस्थितिकी तंत्र हैं। साइबेरिया से हमारे देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण, अवैध शिकार, निवास स्थान का विनाश जैव-विविधता के नुकसान का कारण हैं।

वडुवुर पक्षी अभयारण्य मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत है। विभिन्न स्थानों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को बनाए रखने के लिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि पर्यावरण और वन मंत्रालय पहल करता है, तो वडुवुर पक्षी अभयारण्य भविष्य में तमिलनाडु में कोडियाक्कराजी, वेदाथंगल और उधयामर्थडपुरम जैसे महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक स्थानों में से एक बन जाएगा।

इसलिए, मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वडुवुर पक्षी अभयारण्य को डॉ. सलीम अली के पक्षी विज्ञान अनुसंधान केंद्र की तरह महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र में से एक बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। यह पक्षियों की जैव विविधता के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और हमारे देश में अधिक संख्या में युवा वैज्ञानिकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

वडुवुर पक्षी अभयारण्य के तट पर स्थित सुंदर रामर मूर्ति वाला कोदंडरामर मंदिर हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यदि पर्यटन मंत्रालय वडुवुर झील में बोट क्लब स्थापित करता है तो यह स्कूली बच्चों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, पर्यावरणविदों और आम जनता को भी सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।

अंत में, मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि, वे पर्यावरण मंत्रालय को और अधिक धन आवंटित करें, तमिलनाडु के वडुवुर में अनुसंधान केंद्र को लागू करने और वडुवुर पक्षी अभयारण्य को विकसित करने के लिए राज्यों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करें।

***श्री आधलराव पाटिल शिवजीराव (शिरूर):** मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि, सरकार द्वारा, प्रस्तुत संतुलित बजट की सहायता से पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिक कुशलता और सुचारू रूप से कार्य करेगा। मैं लोकशासन आंदोलन की मदद से वन अधिनियम, 2006 के उल्लंघन और महाराष्ट्र राज्य में अनुष्ठान समारोहों में भाग लेने के लिए बैलों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित दो महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

वन पर्यावरण प्रणाली का एक अनूठा प्राकृतिक घटक है। वनों के संवर्धन के लिए वनरोपण आवश्यक है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मौजूदा वनों का संरक्षण है। वनों को पेड़ों की अवैध कटाई, अतिक्रमण, चराई, शिकार और आग से बचाना होगा। मौजूदा वन क्षेत्र को पहले अतिक्रमण से संरक्षित किया जाना है और फिर पौधे लगाकर वन क्षेत्र को समृद्ध किया जाना है। यहाँ तक कि स्थानों पर केवल सुरक्षा प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रोत्साहित करती है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और वन उत्पादन में कमी वन क्षरण के प्रमुख कारण हैं। वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को प्रोत्साहित या नियमित नहीं किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से, यह वन अपराधों का समर्थन करता है और वन विभाग का मनोबल गिराता है। वन को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आरक्षित वन घोषित किया गया था जिसमें वन में लोगों के अधिकारों, विशेषाधिकारों की जांच की गई और उनका निपटारा किया गया।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और नियम 2008 वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को उन वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए मान्यता देने के लिए एक अधिनियम है, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकार दर्ज नहीं किए जा सके हैं, वन भूमि के संबंध में निहित होने की ऐसी मान्यता के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति के निहित वन अधिकारों को दर्ज करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए। इस अधिनियम में 'वन निवास अनुसूचित जनजातियों' का अर्थ है अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के सदस्य

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जो मुख्य रूप से रहते हैं और जो वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए वन भूमि पर निर्भर हैं और इसमें अनुसूचित जनजाति के चरवाहे समुदाय शामिल हैं।

इसी प्रकार, 'अन्य पारंपरिक वनवासी' से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से मुख्य रूप से निवास कर रहा है और जो वास्तविक आजीविका की आवश्यकताओं के लिए वन अथवा वन भूमि पर निर्भर है।

यह अधिनियम केवल अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि पर अधिकार देता है। उन्हें ये अधिकार देने के लिए अनुसूचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से ग्राम स्तर, उपखंड स्तर और जिला स्तर की समितियों का गठन शामिल है और इस अधिनियम के तहत दावों का निपटारा और निर्णय इन समितियों के स्तर पर ही किया जाएगा। कानूनी पात्रता देने की समय सीमा 13 दिसंबर, 2005 थी।

हालांकि, पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से पुणे जिले के आसपास, लोकशासन आंदोलन का नेतृत्व श्री बी.जी. कोलसे पाटिल और लोकशासन आंदोलन के प्रमुख श्री पी.बी. सावंत कर रहे हैं। इस आंदोलन में, तथाकथित कार्यकर्ता वन भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं और अपने अधिकारों का दावा कर रहे हैं जो अवैध है। ये कार्यकर्ता महिलाओं, छोटे बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों सहित भीड़ में आकर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं ताकि वन विभाग भी भीड़ को बेदखल करने की स्थिति में न हो और ये भीड़ कीमती वन भूमि का अतिक्रमण कर ले। यहां तक कि स्थानीय नेता और लोग भी वन अधिकारियों के साथ मिलकर उनका समर्थन करते हैं। अधिनियम की भावना को लागू करते समय नीति पर पुनर्विचार करने और कानून की गलत व्याख्या करके अनधिकृत वन अधिकारियों के साथ मिलकर वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अनधिकृत कार्यकर्ताओं/लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने का यह सही समय है। मैं सभी राज्य सरकारों को इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने और कानून को सख्ती से लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह करता हूं ताकि केवल वही लोग लाभान्वित हो सकें जो पात्र हैं।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी भारत का राजपत्र में प्रकाशित 11 जुलाई, 2011 की अधिसूचना में जंगली पशु के रूप में बैलों को शामिल करना। राजपत्र के प्रभाव से, बैल का प्रशिक्षण और प्रदर्शन निषिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पैतृक दिनों से साल में एक बार धार्मिक कार्यक्रम करने की एक लंबी प्रथा है जिसमें महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू भी शामिल है। हालांकि, इस अवसर पर विशेष ध्यान रखा गया है कि इस तरह से आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान बैलों को नुकसान न पहुंचे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे थे। हालांकि, भारत के राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, बैलों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया है और बैलों को स्थानीय प्रशासन द्वारा समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इससे स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

हमारे पैतृक दिनों से पिछले सैकड़ों वर्षों से बुल्स मेलों से जुड़े धार्मिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धार्मिक समारोह के दौरान बैल को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 22 में आवश्यक संशोधन करके बैल का नाम जानवरों की सूची से बाहर रखा जा सकता है और तदनुसार 11 जुलाई, 2011 की अधिसूचना में उस हद तक संशोधन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

***श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):** मैं बजट में पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में 5871 वर्ग किलोमीटर एरिया वनों की दृष्टि से बढ़ा है। यह बात अलग है कि कई राज्यों में यह बढ़ा है और कई राज्यों में घटा है जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में वनों का एरिया जो पहले 75 प्रतिशत से भी अधिक होता था वह 627 वर्ग किलोमीटर घटा है। भारत सरकार वनों के अन्धा-धुंध कटाव को लेकर आति गम्भीर है। इसी प्रकार से, भारत सरकार पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी गंभीर है।

हाल ही में जेनेवा में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने जोरदार ढंग से यह आवाज उठाई थी कि विकसित देशों को पर्यावरण से हो रही हानि की भरपाई करनी चाहिए और इसके लिए विकसित देशों ने यह संकल्प भी लिया था कि वे ग्रीन क्लाइमेट फंड में 10 बिलियन राशि प्रदान करेंगे। इनमें यू.एस., जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस व स्वीडन जैसे देश शामिल थे परन्तु बड़े दुख की बात है कि इन देशों ने केवल मात्र 1.03 प्रतिशत ही ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए अपना वायदा पूरा किया। भारत ने इस बात को भी बड़े जोरदार ढंग से उठाया है। अभी 2015 में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस में विश्व सम्मेलन होने जा रहा है, भारत उसमें भी जोरदार ढंग से अपनी बात रखेगा। भारत ने प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से अपने देश की सभी नदियों को पर्यावरण से बचाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं जैसा कि- गंगा की सफाई के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया है, जिसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। परन्तु इस दिशा में अभी और ठोस कदम उठाने होंगे। क्योंकि आज भी बड़े-बड़े शहरों का 90 से 95 प्रतिशत तक सिवरेज का गंदा पानी इन नदियों में गिर रहा है। यू.एन.ओ. की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े-बड़े 20 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं जिनमें आज जीना दूभर हो गया है। आज हमारे देश की राजधानी को ही ले लो, आज यहां पर इतना कार्बन या इतना प्रदूषण है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अगर हमने इस दिशा में कोई ठोस

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कदम न उठाए तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज प्रदूषण हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अगर हमने डीजल वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर रोक न लगाई और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी रिफाइनरीज में सुधार नहीं किया, तो हम क्लीन एनर्जी लेने में विफल रहेंगे। इसी प्रकार से, हमारे देश में कचरा मैनेजमेंट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है और अब तो इस सोलिड वेस्ट के साथ-साथ हमारा देश ई-वेस्ट दुनिया के 5वें नम्बर पर पैदा करने लगा है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने कोयले पर यू.टी. 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत प्रतिटन की है। परन्तु इससे मिलने वाली राशि को हमें अपने प्रदूषण को कम करने पर ही खर्च करना होगा।

अभी-अभी यू.एन.ओ. की एक रिपोर्ट आई है कि भारत को अपने देश में आने वाली आपदाओं से दस बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ रही है। भारत में भूकम्प से 19 मिलियन डॉलर, साइक्लोन से 447 मिलियन डॉलर, तूफानों से 727 मिलियन डॉलर, सूनामी से 1160 , बाढ़ से 4772 मिलियन डॉलर यानि की कुल मिलाकर 10 बिलियन डॉलर के लगभग प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ रही है। मोदी सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया है और भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रहे विश्व सम्मेलनों में भारत की इस प्रतिबद्धता को जताया है कि वह आने वाले 5 वर्षों में 9 बिलियन डॉलर अपने आपदा प्रबंधन पर खर्च करेगा। यू.एन.ओ. रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि अगर हम आपदा प्रबंधन पर 6 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं तो हम आपदाओं के मामले में 360 बिलियन का फायदा उठा सकते हैं। इससे हमारी आपदाओं में 20 प्रतिशत की कमी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के 4.8 मिलियन भारतीय पर्यावरण के कारण होने वाली आपदाओं से पीड़ित हैं। अगर हमने युद्धस्तर पर इस दिशा में कदम न उठाए तो 2030 तक भारत के 19 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं।

आज नेपाल में क्लाइमेट चेंज के कारण एक भयंकर आपदा आई है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने फ्रंट पर आकर इस मामले में लीड किया है और नेपाल के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाई है। उन्होंने आज भी अपने कई केन्द्रीय मंत्रियों को बिहार, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के साथ लगे इलाकों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने में पहल की है।

हमारे देश की 50 करोड़ जनता हिमालय रीजन के क्षेत्र में रहती है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज की ओर युद्धस्तर पर ध्यान नहीं दिया तो जिस प्रकार से, हमालय की तलहटी में परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप हमारी नदियों में उफान आ रहा है। अगर हम समय पर नहीं चेते तो तटों पर रहने वाले हमारे शहरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि 21वीं सदी के अन्त तक दुनिया के ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना पिघल सकते हैं कि समुद्र तल का स्तर 85 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए जिसके कारण दुनिया के समुद्र के किनारे पर रहने वाले बड़े-बड़े नगरों को भी खतरा पैदा हो सकता है। हमारे देश में भी जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर कई बार सूनामी आई है। यह सब हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, यह एक मुख्य कारण है। आज हमें अपने देश में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए संस्थागत ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि जो वाहन ज्यादा प्रदूषण पैदा करते हैं उनके प्रदूषण कंट्रोल के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और यहां तक कि ऐसे वाहनों पर टैक्स भी लगाया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान कराने की दिशा में भी कदम उठाए ताकि बड़े-बड़े शहरों में सांस लेना आसान हो सके।

मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार वनों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है क्योंकि अन्धा-धुंध वनों के कटान से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। हालात यहाँ तक पहुंच गए -

"अब तो थक गए पंख भी उड़ती चिड़िया के,

क्योंकि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी इतनी तो बढ़ गई "

हमने अपनी प्रकृति का विनाश इस ढंग से किया है कि अब घरों में न कहीं चिड़िया चहकती हुई नजर आती है और न ही कहीं बर्ड्स के धौंसलें नजर आते हैं।

अन्त में, मैं उन सभी मदों का समर्थन करता हूँ जिन मदों के अंतर्गत पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालयों के लिए अनुदानों का प्रावधान किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार भारत की 125 करोड़ की जनता को प्रदूषणमुक्त करने एवं खुली हवा में सांस दिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय सभापति, महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के संबंध में अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए मुझे समय देने के लिए धन्यवाद।

सबसे पहले, मैं देश में वन्यजीव अभयारण्यों के समग्र विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर इस प्रतिष्ठित सभा को प्रबुद्ध करना चाहूंगा। पिछले कई वर्षों से लापरवाही और खराब योजना के कारण वन्यजीवों की कई कीमती प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। अन्य वन्य जीव प्रजातियों के बीच, मैं देश में गिद्धों की निवासी जिप्सी प्रजातियों के विलुप्त होने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था। उनके संरक्षण में लापरवाही के कारण जिप्सी प्रजातियों के गिद्धों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम हो रही है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बी.एन.एच.एस.) जैसे कुछ गैर सरकारी संगठन राज्य सरकारों के सहयोग से देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बी.एन.एच.एस. द्वारा गिद्धों के प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव में, प्रजनन केंद्रों के रखरखाव और विकास कार्य ठीक से नहीं चल रहे हैं। बी.एन.एच.एस. ने देश में अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को गिद्धों के संरक्षण के लिए अपना विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है जो लंबे समय से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि डिक्लोफेनाक जैसी कुछ दवाओं के पशु चिकित्सा उपयोग की बहु-खुराक भी इस कीमती जिप्सी गिद्ध के विलुप्त होने के कारणों में से एक है। मेरा सुझाव है कि डिक्लोफेनाक

दवा की बहु-खुराक वाली शीशियों की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, जो देश में पशु उपचार में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए लगाया जा सकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले को गंभीरता से देखें और उन राज्यों और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें जो देश में जंगली प्रजातियों, विशेष रूप से गिद्धों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुंबई दक्षिण-मध्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबे समय से लंबित हैं। मैं उनमें से कुछ का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

पहला मुंबई में एक तटीय सड़क का निर्माण है। देश के विभिन्न शहरों में अधिकांश तटीय रेखाओं पर तटीय सड़कें हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शहर मुंबई में अभी तक ऐसी सड़कें नहीं हैं। मुंबई में एक सुंदर तटरेखा है। समुद्र तट पर 36 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की सख्त जरूरत है। यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लंबे समय से मंजूरी न दिए जाने के कारण लंबित है। इसमें तत्काल तेजी लाई जानी चाहिए।

एक अन्य मुद्दा सी.आर.जेड.-II क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश में संशोधन का है। मुंबई में स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए गैर-सी.आर.जेड. क्षेत्रों के समान सी.आर.जेड.-II क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास योजनाओं में अनुमेय एफ.एस.आई. में वृद्धि की अनुमति देने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से ग्रेटर मुंबई में सी.आर.जेड.-II क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने और नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन को अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूँ।

कोलीवाड़ा और गौठान क्षेत्रों के वर्गीकरण और पुनर्विकास जैसे कुछ मुद्दों से संबंधित सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2011 में असमानताओं में संशोधन और संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है; मुंबई में जीर्ण-शीर्ण, सेस्ड और असुरक्षित इमारतों का पुनर्विकास; मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों से संबंधित

पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य; मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2, चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द के लिए सी.आर.जेड. मंजूरी; ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी की सीमाओं का युक्तिकरण; और माहीम, कॉजवे, धारावी, वैतरणा, और तानसा में मीठी नदी पर पुलों का निर्माण।

मुंबई शहर और महाराष्ट्र राज्य के कई मुद्दे हैं जो पर्यावरण मंजूरी और वित्तीय सहायता देने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास लंबित हैं।

पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 2015 को दुनिया भर में मनाया गया है। यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा बनाने के लिए पारिस्थितिक संतुलन के बारे में जागरूकता फैलाएं। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि पर्यावरण जागरूकता अभियान को ठीक से लागू करने के लिए राज्यों को केंद्रीय निधि में वृद्धि करें। मैं समग्र विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के अंत में राज्य सरकार के प्रस्तावों के त्वरित निपटान का भी अनुरोध करता हूं।

धन्यवाद।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके ध्यान में हमारे देश में होने वाले पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तनों को लाना चाहूंगा।

वर्ष 2015 जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर नई चुनौतियों का सामना करने जा रहा है। हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शुरू किए गए ऐतिहासिक पर्यावरणीय उपायों को वर्तमान जरूरतों के आलोक में नीतियों द्वारा पूरक किया जा रहा है।

भारत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना के शुरुआती कार्यान्वयन कर्ताओं में से एक रहा है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कम करने और अनुकूलित करने के लिए नीतियां बनाती है।

घरेलू मोर्चे पर, भारत तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य से समझौता किए बिना पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में काम कर रहा है। नदियों के संरक्षण, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार, वनीकरण में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ गंगा योजना जैसी पहलों ने सकारात्मक सतत जलवायु विकास और विकास में मदद की है।

महोदय, मैंग्रोव ऐसे पौधे हैं जो लवणता ज्वारीय शासन से बचते हैं और वे हवा के वेग को नियंत्रित करते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 4662.56 किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है। वे मुख्य रूप से कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र काकीनाडा और कृष्णा जिलों के पास पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2011 के आकलन वर्ष के अनुसार, यह आंध्र प्रदेश राज्य में 352 किलोमीटर में फैला हुआ है। जीवमंडल भंडार स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो जैविक और सांस्कृतिक विविधता में समृद्ध हैं। पूर्वी घाट में सेसाचलम पहाड़ी श्रृंखलाएँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिलों का हिस्सा हैं जहां नामित जीवमंडल भंडार विशाल हैं। हमारा लक्ष्य इन प्रतिनिधि परिदृश्यों और उनकी अपार जैविक विविधता के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना, तेजी से आर्थिक और मानव विकास प्राप्त करना और अनुसंधान शिक्षा और सूचना आदान-प्रदान कार्यक्रमों की निगरानी के लिए समर्थन प्रदान करना

होना चाहिए। राज्य जैव विविधता बोर्ड जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार अधिसूचित विशिष्ट राज्य नियमों के अनुसार काम करता है।

सभापति, महोदय, हमारे पास आंध्र प्रदेश में 27 संरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण भंडार और सामुदायिक भंडार शामिल हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह नियंत्रण सहायता देकर संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करे। मैं केंद्र सरकार से कोल्लेरू और कोरिंगा जैसे वन्यजीव अभयारण्यों की रक्षा करने का भी अनुरोध करूंगा, जो आंध्र प्रदेश में आते हैं।

केंद्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हैबिटेट स्कीम के तहत, 2012-13 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए 109.50 लाख रुपये जारी किए गए थे। आगे के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाया जाना चाहिए।

केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय मामलों के मंत्री, श्री वेंकैया नायडू गारू की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना अप्रैल, 2015 तक पूरी होने वाली है। स्वच्छ गंगा परियोजना पहले से ही निरंतर प्रगति कर रही है। हरित निर्माण ऊर्जा कुशल भवनों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो अपशिष्ट प्रबंधन योजना को शामिल करके जल संसाधनों का संरक्षण करने में सक्षम हैं।

महोदय, एक अन्य मुद्दा जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है वह है ग्लोबल वार्मिंग पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने और कम करने की आवश्यकता। सकारात्मक प्रभाव बनाए रखने के लिए कार्बन को एक अच्छा तरीका हो सकता है।

मेरा निर्वाचन-क्षेत्र काकीनाडा, एक औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते, पर्यावरण के मुद्दों से अछूता नहीं है। अधिकांश औद्योगिक निर्वहन अनुपचारित हैं और नदी और समुद्री तट को प्रदूषित कर रहे हैं। यह प्रदूषण का मुख्य कारण है। हमें सीवेज और पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह उचित कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के साथ-साथ इसके लिए पहल करे।

सभापति महोदय, मैं सरकार से राज्य वन सेवा, और रेंजर्स कॉलेज जैसे संस्थानों को मजबूत करने का अनुरोध करना चाहूंगा और मेरे निर्वाचन क्षेत्र काकीनाडा में उनमें से एक की स्थापना करने का भी अनुरोध करना चाहूंगा। मैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने का अनुरोध करूंगा। वनों की रक्षा और संरक्षण और वनीकरण बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अधिक पर्यावरण नियोजन और समन्वय कार्यक्रम होने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर अंकुश लगाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका और सुरक्षा सुनिश्चित करने और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम को उचित रूप से लागू किया जाए।

धन्यवाद, महोदय।

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी(चेवेल्ला): माननीय, सभापति महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर बोलने का यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, मंत्रालय का बजटीय आवंटन मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं की चिंता और उद्देश्यों को नकारता है। कुल 2256 करोड़ रुपये हैं और राज्यों को हस्तांतरण के बाद, यह केवल 1681 करोड़ रुपये है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह अधिक महत्व का हकदार है। यह कमोबेश पिछले वर्ष की तरह ही है। मेरा मानना है कि मंत्रालय को अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। चूंकि यह पिछले वर्ष की तरह ही है, इसलिए मैं केवल पिछले बजटों से महत्वपूर्ण बदलावों की ओर इशारा कर रहा हूं।

वन्यजीव संरक्षण पर कुल खर्च 83 करोड़ रुपये से घटकर 47 करोड़ रुपये रह गया है। इसकी पृष्ठभूमि में भारत में वन्यजीव अपराध बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें वास्तव में समीक्षा करने की आवश्यकता है। पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं।

रोकथाम नियंत्रण और प्रदूषण प्रबंधन को 135 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 240 करोड़ रुपये करना वास्तव में स्वागत योग्य है। मैं प्रदूषण प्रबंधन के लिए बजट में इस वृद्धि के लिए मंत्रालय को बधाई देता हूं। तथापि, प्रदूषण का अक्षय ऊर्जा से बहुत कुछ लेना-देना है। हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में नगरपालिका कचरा है। हमारे पास प्लास्टिक कचरा है। हमारे पास गोबर गैस संयंत्र हुआ करते थे। अब हम गोबर गैस और बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने से ज्यादा सब्सिडी एल.पी.जी. को दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में कुल बायोमास भारत में सभी वाहनों को चलाने के लिए गैस का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलती है। हम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इस मंत्रालय दोनों को पर्याप्त पदोन्नति नहीं दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे।

दूसरी बात यह है कि बायोगैस आमतौर पर मीथेन गैस होती है। लेकिन एक चीज है जिसे उत्पादक गैस कहा जाता है जो कृषि अपशिष्ट से भी बनती है। हम जानते हैं कि दिल्ली में, हरियाणा और अन्य राज्यों में फसल कटाई के बाद जलाने से बहुत प्रदूषण होता है। तो बायोमास गैसीफायर एक गैस का उत्पादन कर सकते

हैं जिसका फिर से ईंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। मेरा मानना है कि मंत्रालय को प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसे बढ़ावा देना चाहिए।

मंत्रालय के कार्यक्रमों और व्यय का एक बड़ा हिस्सा मिशन गंगा और जल संबंधी मंत्रालयों के लिए समर्पित है। जल निकायों के कायाकल्प और सफाई पर सरकार के ध्यान के साथ, पर्यावरण मंत्रालय को जैव विविधता प्रबंधन, संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो बजटीय आवंटन को 10 गुना से अधिक बढ़ावा देता है। जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के लिए कुल आवंटन 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 27 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आर्द्र भूमि की बचत पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि महोदय ने भी इसका उल्लेख किया था। हम वास्तव में 2-3 प्रतिशत की वार्षिक दर से गीली भूमि को कम कर रहे हैं।

महोदय, सभी खबरें बुरी खबरें नहीं हैं। बदलाव के लिए कुछ वास्तव में अच्छी और अच्छी खबर है। तेलंगाना में केकड़े मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई। यह केकड़े की तरह व्यवहार करता है लेकिन वास्तव में यह बिना जाल के एक मकड़ी है। यह लगभग एक महीने पहले की बात है। वैज्ञानिक समुदाय ने इसे 'थॉमिसस टेलेनगनेंसिस' नाम दिया। यह इस केकड़े मकड़ी का नाम है। इतना ही नहीं, कलबर बोलानथी जैसी कई अन्य प्रजातियां भी हैं जिनकी खोज हाल ही में की गई थी। यह लगभग विलुप्त हो चुका था। फिर एलाचिस्टोडॉन वेस्टरमानी है। यह एक अंडा खाने वाला सांप है जिसे लंबे समय से विलुप्त माना जाता था। तेलंगाना के आसपास गोलकोंडा किले के चारों ओर भी इसकी फिर से खोज की गई है। वास्तव में, इसका बहुत कुछ हैदराबाद में है।

विश्वविद्यालय परिसरों में, हर तिमाही में हमें कई मकड़ियों सहित नई प्रजातियां मिलती हैं। एक छिपकली है जिसकी खोज की गई थी। यह कोई आश्चर्य और संयोग नहीं है कि मर्सर के क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वेक्षण ने हैदराबाद को रहने के लिए भारत के नंबर एक शहर के रूप में दर्जा दिया है। इसने दुनिया भर के सभी शहरों का मूल्यांकन किया लेकिन भारत में यह नंबर एक है। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण कारकों में से एक प्रदूषण और पर्यावरण नियंत्रण है। हम जीवन यापन की लागत, यातायात, आदि जैसे अन्य कारकों में अच्छा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मंत्रालय को पर्यावरण के प्रति जागरूक शहरों और राज्यों को पुरस्कृत करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मंत्रालय इसे ध्यान में रखेगा।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को 28 करोड़ रुपये से घटाकर 12.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे लगता है कि यह फिर से पर्यावरण में सुधार की अपनी योजना के विरुद्ध है। इसकी पृष्ठभूमि में, मैं आपको एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में कुछ बताता हूँ जिसने दुनिया भर के पर्यावरणविदों का ध्यान आकर्षित किया और हमारे राज्य में स्कूली बच्चों की कल्पना। इसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया हरिता हरम कार्यक्रम कहा जाता है जिन्हें प्यार से के. सी. आर. के नाम से जाना जाता है। यह अगले तीन वर्षों में लगभग 230 करोड़ वृक्षारोपण है और प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये हमारा बजटीय आवंटन है। इन 230 करोड़ पौधों में से 100 करोड़ जंगल में, 130 करोड़ गैर-वन क्षेत्रों में और 10 करोड़ हैदराबाद शहर में हैं। हम 800 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। लगभग 3300 नर्सरी पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम है। पर्यावरण न केवल हमारे राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित करता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो इससे पड़ोसी राज्यों और हमारे देश को भी मदद मिलती है। एक बार फिर मैं केंद्र सरकार से इस परियोजना में हमारी मदद करने का अनुरोध करना चाहूंगा। हम तेलंगाना सरकार के अपने हरिता हरम कार्यक्रम में केंद्र सरकार से समर्थन चाहते हैं।

महोदय, कानून मंत्री यहां थे और दूसरा मुद्दा एक बहुत ही दुरुपयोग किए गए कानून के बारे में है और यह 2006 के कानून के बारे में है जहां एक आदिवासी वास्तव में वन भूमि पर अधिकार का दावा कर सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों का भूमि पर दावा हो, लेकिन दुर्भाग्य से इसका उपयोग किए जाने से अधिक दुरुपयोग किया जाता है। इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। एक कट ऑफ सीमा है। यदि कोई आदिवासी तीन पीढ़ियों से भूमि का उपयोग कर रहा है, तो वह उसका बन जाता है, लेकिन कोई निर्धारित तारीख नहीं है। आज भी एक आदिवासी औद्योगिक समर्थन के साथ जा सकता है और अपनी जमीन पर दावा कर सकता है। इसलिए, मुझे लगता है कि, एक निर्धारित तिथि होनी चाहिए और अगर कोई निर्धारित तिथि नहीं है तो इस पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कानून को कड़ा करना होगा ताकि इस कानून से केवल आदिवासियों को ही लाभ हो।

महोदय, हुसैन सागर झील देश की सबसे प्रदूषित झील है और यह हैदराबाद के बीचोंबीच स्थित है। पिछली सरकार ने इसे साफ करने का फैसला किया था। हम सचमुच इसे खाली कर रहे हैं और इसे साफ कर रहे हैं। यह अगले बारह महीनों में होगा। एक बार फिर हमें इसमें केंद्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि, मंत्रालय काम करेगा और यह पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं है। इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी विभागों, उद्योग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, रेलवे, स्वास्थ्य और पर्यटन, मंत्रालयों के साथ काम करना होगा। पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विकास हो सकता है। भूमि विधेयक आ रहा है और मुझे लगता है कि दोनों सह-अस्तित्व में हो सकते हैं-विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी। मुझे लगता है कि, सरकार को नवोन्मेषी होने की आवश्यकता है और इसे व्यावहारिक भी होना चाहिए क्योंकि अगर सरकार संयुक्त राष्ट्र का अनुसरण करती है, तो वे कहते हैं कि भारत को पर्यावरण संरक्षण के लिए 500 बिलियन डॉलर खर्च करने हैं और ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें अपने दृष्टिकोण में बहुत नवीन और व्यावहारिक होना चाहिए। नीतियों को बदलने की जरूरत है।

महोदय, अंत में मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य देना चाहूंगा। भारतीय काला हिरण जो राजस्थान में प्रसिद्ध है जहाँ इसे सम्मानित किया जाता है। यह गुजरात राज्य में भी पाया जाता है। भारत के दोनों राज्यों और पूरे भारत की तुलना में टेक्सास राज्य में अधिक भारतीय काले हिरण हैं। कई अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि वहाँ भारतीय चंदन है, लेकिन हमारे राज्य से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास ओंगोल बैल का एक जीन पूल है। ओंगोल पड़ोसी राज्य का एक जिला है। लेकिन पूरे भारत की तुलना में दक्षिण अमेरिका में अधिक ओंगोल बैल हैं। मुझे लगता है, ये कुछ चीजें हैं जिनकी हमें रक्षा करने की आवश्यकता है।

धन्यवाद

***श्री लाडू किशोर स्वैन (अस्का):** केंद्रीय बजट 2015-16 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए कुल बजट के रूप में 1682 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष 2256 करोड़ रुपये था। यह इस वर्ष के बजट में 25 प्रतिशत की कटौती का संकेत देता है। इस कम बजट के भीतर, अब सरकार स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के बारे में सोच रही है जिसमें पानी, हवा, मिट्टी, आदि शामिल हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) संश्लेषण प्रतिवेदन विकासशील देशों में विकास योजना में जलवायु संबंधी विचारों को तेजी से आंतरिक बनाने का सुझाव देती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव निचले द्वीपों और तटीय भूमि के डूबने से लेकर भारतीय हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने तक भिन्न होते हैं, जिससे भारत और दक्षिण एशिया की कई सबसे महत्वपूर्ण नदियों की आयतन प्रवाह दर को खतरा होता है। भारत में, इस तरह के प्रभावों से लाखों लोगों के जीवन पर असर पड़ने का अनुमान है (जैसा कि हाल ही में भारत के उत्तरी भाग में आए भूकंप में देखा गया है)।

इस संबंध में, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बजट 2014-15 में 100 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एन.ए.एफ.) बनाया गया था। इस कोष के संचालन के लिए दिशा-निर्देशों का अभी भी इंतजार है। इस बीच, भारत ने वैश्विक अनुकूलन कोष से धन प्राप्त करना शुरू कर दिया है और हरित जलवायु कोष (जी.सी.एफ.) के संचालन के लिए तैयार है।

इसी संदर्भ में मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे बजटीय प्रावधानों में निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विचार करें।

विभिन्न मंत्रालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एन.सी.ई.एफ.) हस्तांतरण में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) का हिस्सा केंद्रीय बजट 2013-14 के संशोधित अनुमानों में 80 प्रतिशत था। 2014-15 के आम बजट में इसे घटाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। यह गिरावट काफी हद तक जल संसाधन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय गंगा योजना का समर्थन करने के लिए एन.सी.ई.एफ. से 1500 करोड़ रुपये

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के हस्तांतरण के कारण है। इससे यह चिंता पैदा होती है कि क्या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के कारण एन.सी.ई.एफ. से एम.एन.आर.ई. के लिए आवंटन में और गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के लिए, 2015-16 के लिए केंद्रीय बजट आवंटन 2014-15 में 235 करोड़ रुपये से घटकर 75 करोड़ रुपये रह गया। अतीत में इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यह एक बड़ी चिंता का विषय रहा है।

यह पहली बार है जब भारत सरकार ने अनुकूलन के लिए घरेलू निधियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी., 2008) में कहा गया है कि भारत ने पांच क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यक्रमों पर 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.63 प्रतिशत खर्च किया लेकिन बाद के वर्षों के लिए कोई आंकड़े नहीं दिए गए। वर्ष 2006-07 के लिए जिन पांच क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था, वे थे: (क) फसल सुधार और अनुसंधान (5.93 प्रतिशत); (ख) सूखा रोकथाम और बाढ़ नियंत्रण (3.04 प्रतिशत); (ग) वन संरक्षण (0.49 प्रतिशत); (घ) गरीबी उन्मूलन और आजीविका संरक्षण (44.65 प्रतिशत); (ण) ग्रामीण शिक्षा और बुनियादी ढांचा (26.85 प्रतिशत); (च) स्वास्थ्य (10.75 प्रतिशत); (छ) जोखिम वित्तपोषण (4.83 प्रतिशत); और (ज) आपदा प्रबंधन। (3.46 प्रतिशत)। किस अनुकूलन पहल को वित्त पोषित किया गया था या उन्होंने जलवायु परिवर्तनशीलता की कमजोरियों को किस हद तक कम किया और लोगों के लचीलेपन का निर्माण किया, यह समझने के लिए इन बजटीय अनुपातों का निर्माण करना संभव नहीं है। संभवतः ये बजट चल रहे कार्यक्रमों के तहत सामान्य गतिविधियों के लिए थे, जिनका उद्देश्य एक ऐसे देश की रक्षा करना है जो वैसे भी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और एक कृषि प्रधान समाज के रूप में, अपने अस्तित्व के लिए तापमान और वर्षा के पैटर्न पर अत्यधिक निर्भर है।

एन.ए.पी.सी.सी. के जारी होने के बाद, न तो अनुकूलन-केंद्रित राष्ट्रीय मिशन (कृषि, जल संसाधन, वन और वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित), और न ही जलवायु परिवर्तन पर राज्य-स्तरीय कार्य योजनाएं (एस.ए.पी.सी.सी.) जो अनुकूलन को प्राथमिकता देती हैं, सभी क्षेत्रों में अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए स्पष्ट बजट के साथ आई हैं,

कोष को बढ़ाना और राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एन.ए.एफ.) के दायरे को व्यापक बनाना ताकि यह स्वतंत्र रूप से अनुकूलन परियोजनाओं को निधि देने के बजाय, पारदर्शी और मापने योग्य तरीके से चल रहे 'सामान्य रूप से व्यवसाय' विकास कार्यक्रमों और/या गतिविधियों में मूल्य जोड़ सके।

सभी जलवायु-संवेदनशील मंत्रालयों/राज्य विभागों द्वारा अपने कार्यक्रमों में लचीले घटकों के निर्माण के लिए अपने खर्च का एक स्पष्ट और मापने योग्य अनुपात निर्धारित करने के साथ विकास के लिए भारत की वित्तीय योजना के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मुख्य बनाएं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2014 को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन से संबंधित आदेश जारी किया, जिसमें अब राज्य सरकार को उन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं से पूर्व सहमति लेने से छूट दी गई थी जहां वन भूमि के उपयोग का ऐतिहासिक डायवर्जन शामिल है। इसके अलावा, ऐसे वृक्षारोपण के मामले में, जिन्हें 13 दिसंबर 2005 से 75 वर्ष से कम समय पहले वन के रूप में अधिसूचित किया गया था और जो उन गांवों में स्थित हैं जहां 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कोई दर्ज आबादी नहीं है वन अधिकारों को मान्यता दिए जाने की संभावना नहीं है और ग्राम सभाओं की सहमति के बिना संबंधित जिला कलेक्टर से केवल एक प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इस तरह का आदेश सतत विकास के लिए प्रतिकूल होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया की सहभागी प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए, हम सरकार से ऐसे आदेशों को वापस लेने की मांग करते हैं जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 में विशिष्ट प्रावधानों को खारिज करते हैं जो गैर-वन गतिविधि के लिए वन भूमि की सफाई का अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभाओं की 'पूर्व सूचित सहमति' की मांग करता है।

यह आदेश जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सहमति लेने के बाद जारी किया गया है, जो इस चिंता को बढ़ाता है कि क्या जनजातीय मामलों के नोडल मंत्रालय ने इस तरह की सहमति देने से पहले उचित परिश्रम किया क्योंकि ऐसा लगता है कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों के बारे में अनभिज्ञता है।

आदेश राजमार्गों, पाइपलाइनों, रेल पटरियों आदि जैसी वन भूमि के रैखिक मोड़ के लिए वन मंजूरी की भी अनुमति देता है। जो वनों के पारिस्थितिक संतुलन में उल्लंघन का कारण बनेगा और भविष्य में इन रैखिक परियोजनाओं के साथ अन्य संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के संभावित प्रारंभ के कारण भारत के वन क्षेत्र में तेजी से कमी आ सकती है। एक सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करने के साथ-साथ भविष्य के परिदृश्यों को देखते हुए, प्रस्तावित परियोजना की संचयी प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल करने के साथ इस आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

एक ऐसे देश में जहां अर्थव्यवस्था कई स्तरों पर जलवायु-संवेदनशील संसाधनों से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय अनुकूलन बजट के रूप में 100 करोड़ रुपये केवल काल्पनिक है। यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के तहत और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से प्रदान किए गए अनुकूलन के लिए बाहरी निधियों के साथ इसे बढ़ाने और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

जलवायु कमजोरियों के बेहतर मूल्यांकन और सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों-स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और आपदा शमन और पुनर्वास में अनुकूलन हस्तक्षेपों के वितरण पर क्षमता और कौशल निर्माण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, इसमें, जलवायु डेटा के संग्रह में कौशल (उदाहरण के लिए, पंचायत और ग्राम-स्तरीय वर्षा मापकों से), जोखिमों का आकलन करना, और अनुकूलन आउटपुट और परिणामों की निगरानी करना शामिल होगा।

केंद्रीय बजट 2015-16 में कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के विकास बजट में भारी गिरावट देखी गई। ये जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर क्षेत्र हैं और अतिरिक्त अनुकूलन वित्तपोषण के साथ मजबूत विकासात्मक बजट की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के निर्माण के साथ, सामान्य डेटाबेस के आधार पर और जी.आई.एस तकनीकों द्वारा सुगम वित्तीय परिव्यय की क्षेत्रीय निगरानी शुरू करने का समय आ गया है।

***श्री एस. आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय):** मैं इस प्रतिष्ठित सभा में मुझे मध्य चेन्नई लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए और वर्ष 2015-16 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी प्रिय नेता माननीया मक्कलिन मुदलवर इदया दैवम पुरात्ची थलाइवी डॉ. अम्मा को धन्यवाद देता हूँ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 1,681 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,446.00 करोड़ रुपये योजना परियोजना के लिए और 235.00 करोड़ रुपये गैर-योजना परियोजना के लिए हैं। पिछले वित्त वर्ष 2014-15 का परियोजना 2,256.00 करोड़ रुपये था, जिसमें से 2,043.00 करोड़ रुपये योजना परियोजना के लिए और 213.00 करोड़ रुपये गैर-योजना परियोजना के लिए थे।

इस मंत्रालय के लिए कुल बजट अनुमानों में पिछले वित्त वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना में कमी देखी गई है।

जबकि समय की मांग है कि हमारे वनों के क्षेत्र को बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए मंत्रालय को आवंटन बढ़ाया जाए। पर्यावरण और वन्य जीव मुद्दों के लिए वैश्विक चिंता के अनुरूप, हमें इस योग्य सीमावर्ती क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि हम पर्यावरण के संरक्षण में अन्य देशों से पीछे न रहें।

जलवायु परिवर्तन ने हमारे देश को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रभावित किया है। वर्षा की विफलता या अपर्याप्तता, असामयिक वर्षा, असामयिक बाढ़, गंभीर सूखा आदि केवल वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को समझने और उनसे निपटने के लिए हमें अधिक विकसित नीति की आवश्यकता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विकास क्षेत्रों पर निर्णय लेने के लिए ग्राम सभाओं की शक्तियों को सीमित करके वन निकासी प्रक्रिया के मुद्दे पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधित दिशानिर्देश एक स्वागत योग्य कदम नहीं हैं। यहाँ तक कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भी इन संशोधित दिशानिर्देशों पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार को इस मुद्दे पर फिर से विचार करना चाहिए और हमारे वनों की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

हमने खबरें सुनी हैं कि राष्ट्रीय पशु को बदलने का प्रस्ताव है। बाघ भारत के लिए हमारा विशेष पशु है और यह हमारा राष्ट्रीय पशु बना रहना चाहिए। इसे बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

माननीया डॉ. अम्मा के कुशल मार्गदर्शन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने पशु कल्याण में विशेष रुचि दिखाई है और मंदिर के हाथियों के कायाकल्प के लिए मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में मंदिर के हाथियों के लिए वार्षिक शिविर आयोजित करने का विशेष ध्यान रखा गया है। इस तरह की अच्छी योजनाओं का अध्ययन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं, सरकार से सभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर पुनर्विचार करने और वर्तमान आवंटन को उचित स्तर तक बढ़ाने का आग्रह करता हूँ।

***श्री वी. एलुमलाई (अरणि):** पर्यावरण मुद्दा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है। यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दे रही है, चाहे वह वन भूमि का रूपांतरण हो, नदी का प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो आदि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आया है और आजकल काफी सक्रिय है। मुझे एक खबर मिली है कि सरकार राज्य सरकार के परामर्श से कई मौजूदा पर्यावरण कानूनों को बनाने या संशोधित करने पर विचार कर रही है। यह एक अच्छा विचार है क्योंकि पर्यावरण के मुद्दों को राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ समग्र पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। मुझे यह पता चला है कि कई राज्य सरकारें धन की कमी के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सभी निर्देशों को लागू नहीं कर पा रही थीं। सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित करने के निर्देश एक मुद्दा है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में धन लगता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि, सरकार एस.टी.पी. की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करे।

एक अन्य मुद्दा जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि आदिवासी लोग जो वन क्षेत्र में रह रहे थे, जिसमें वे कठोर पर्यावरण कानूनों के कारण अज्ञात अवधि से रह रहे थे, ये लोग कई विकासात्मक गतिविधियों से वंचित हैं, जैसे कि सड़कें बिछाना आदि। इसलिए, जनजातीय लोगों के हित में, मैं सरकार से पर्यावरण कानूनों के कुछ प्रावधानों में ढील देने का आग्रह करता हूं, ताकि वन भूमि में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए भी कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हो सकें जो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि नदी का पानी पीने से लोगों के जान गंवाने की खबरें थीं। नदियों में जल प्रदूषण का स्तर ऐसा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और नदियों को साफ-सुथरा बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए।

श्री एम. बी. राजेश (पालक्काड): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसलिए इस चर्चा का बहुत महत्व है। हालांकि वित्त मंत्रालय और समग्र रूप से सरकार इसे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मानती है, जैसा कि इस मंत्रालय के लिए बजट में किए गए अपर्याप्त आवंटन से स्पष्ट है फिर भी मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है।

महोदय, जब मैं इस विषय पर बोलने के लिए उठता हूं, तो मुझे एक प्रसिद्ध कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, श्री ओ.एम.वी. कुरुप द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मलयालम कविता याद आती है और कविता का शीर्षक 'पृथ्वी के लिए एक श्रद्धांजलि' है। कविता इन पंक्तियों से शुरू होती है, *एनियम वारे मारिक्यथा भूमि थिन्नू असंमरथियुल थिनकु आठमशांति*। एक अनुमानित अनुवाद इस प्रकार है-- 'हे पृथ्वी, मुझे आपकी आसन्न मृत्यु में आपकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने दें'। यह उस महान कवि द्वारा व्यक्त की गई आशंका और निराशावाद था और यह कविता लगभग 25 साल पहले लिखी गई थी।

उसके बाद, से स्थिति और खराब ही हुई है। पर्यावरण और प्रकृति के लिए खतरे केवल बढ़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और पर्यावरण और प्रकृति के लिए वास्तविक खतरा क्या है?

वास्तविक खतरा अंतहीन मानवीय लालच से उत्पन्न होता है, लाभ के लिए लालच और यह लालच कॉर्पोरेट्स द्वारा संचालित होता है। इसलिए, सुपर प्रॉफिट के लिए कॉर्पोरेट लालच हमारे पर्यावरण के लिए वास्तविक खतरा है।

अपराह्न 04.00 बजे

(श्री प्रह्लाद जोशी पीठासीन हुए)

महोदय, इस कॉर्पोरेट लालच को नवउदारवादी नीतियों द्वारा आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और यह आर्थिक विकास के नाम पर किया जा रहा है। इस सरकार ने, नवउदारवादी प्रक्षेपवक्र के अपने पालन के माध्यम से कॉर्पोरेट्स को प्रकृति को लूटने और अत्यधिक लाभ कमाने की अनुमति दी है।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी मेरी बात सुनेंगे क्योंकि ये कुछ आलोचनाएँ हैं जो मैं करना चाहूंगा जिनका उन्हें जवाब देना होगा।

पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति इस सरकार की घोर उपेक्षा निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। सबसे पहले, माननीय मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के, नेतृत्व में इसी मंत्रालय ने एक साल से भी कम समय में 6.31 लाख करोड़ रुपये की 190 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस मंत्रालय को मंजूरी मंत्रालय तक सीमित कर दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मंत्रालय को मंजूरी मंत्रालय में नहीं घटाया जाए, बल्कि यह पर्यावरण कानूनों को लागू करने वाला मंत्रालय होना चाहिए।

दुर्भाग्य से, मौजूदा कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के बजाय, मंत्रालय कॉर्पोरेट्स के पक्ष में मौजूदा पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने, समाप्त करने और ध्वस्त करने के लिए बहुत उत्सुक है।

मुझे इस सरकार की नीतियों की आलोचना करनी है, विशेष रूप से श्री प्रकाश जावड़ेकर के, नेतृत्व में इस मंत्रालय की। बेशक, वह मुस्कराते हुए चेहरे वाले एक अच्छे मंत्री हैं। इन सबके बावजूद, मुझे उनकी नीतियों की आलोचना करनी पड़ेगी। उनके नेतृत्व में इसी मंत्रालय ने, एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की, जिसका एकमात्र उद्देश्य कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए सभी मौजूदा पर्यावरण कानूनों को कमजोर करना था।

महोदय, समय की अल्पता के कारण, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता। यह मंत्रालय ही था जो बड़े पैमाने पर वन भूमि को मोड़ने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि वे हमें बताएं और सभा को सूचित करें कि पिछले एक साल में आपने कितनी वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी है। बड़े पैमाने पर वन भूमि का डायवर्सन हो रहा है और यह कॉर्पोरेट्स के लाभ के लिए भी है।

महोदय, जहां तक पर्यावरण संरक्षण का संबंध है इस सरकार की दोहरी बात आपके काल्पनिक रुख से स्पष्ट है जो आपने अरनमुला हवाई अड्डा परियोजना में लिया है।

मैं केरल राज्य से आ रहा हूँ। अरनमुला और केरल के अधिकांश लोग इस हवाई अड्डा परियोजना के खिलाफ हैं। इससे पहले एक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उस पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन को रद्द कर दिया था। हाल ही में, आपने फिर से नए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की अनुमति दी है। अरनमुला हवाई अड्डा परियोजना के खिलाफ आंदोलन में न केवल वामपंथी बल्कि आपकी पार्टी भी भाग ले रही है।

इसलिए, कृपया अपना रुख स्पष्ट और स्पष्ट करें कि अरनमुला हवाई अड्डा परियोजना के संबंध में आपकी क्या स्थिति है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री एम. बी. राजेश: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति: आप कृपया एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम. बी. राजेश: मैं जलवायु संबंधी वार्ताओं और मुद्दों पर भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर बोलूंगा। यह सरकार अमेरिका और अन्य विकसित देशों के दबाव के आगे झुक रही है। जहां तक उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन का संबंध है, यह सरकार भारत की 'समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' की स्थिति का त्याग करने जा रही है।

द बिजनेस स्टैंडर्ड में एक प्रतिवेदन था कि यह सरकार 2015 के अंत तक पेरिस में हस्ताक्षर किए जाने वाले वैश्विक समझौते के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपने लक्ष्य तैयार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन को कम करने में दुनिया को सही मायने में रास्ता दिखा सकता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ एक अलग रुख अपना रहे हैं, तो भारत एकतरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है और एकतरफा रूप से उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश क्यों

कर रहा है? मुझे समझ नहीं आता कि हम इस तरह की स्थिति क्यों ले रहे हैं... (व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे।

इतना ही नहीं, सरकार उत्सर्जन में कटौती के लिए क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य तय करने के बारे में सोच रही है। मुझे आश्चर्य है कि बहुप्रचारित 'मेक इन इंडिया' अभियान का क्या होगा। अगर हम विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य तय करने जा रहे हैं तो 'मेक इन इंडिया' अभियान का क्या होगा? विनिर्माण क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके बहुप्रचारित 'मेक इन इंडिया' अभियान का क्या होगा? तो, ऐसी एकतरफा कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता है?

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री एम. बी. राजेश: यह मेरा अंतिम बिंदु है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति से विचलित न हों और कृपया यह स्पष्ट करें कि 2015 के अंत में पेरिस में होने वाले आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन में हमारी स्थिति क्या होगी? सभी आवंटन में भारी कमी की गई है। मैं इस पर अपनी चिंता व्यक्त करता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

***श्री पी. पी. चौधरी (पाली):** मैं सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य की सबसे प्रदूषित नदी की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की बांड़ी नदी व नेहडा बांध लगातार भयानक रूप से प्रदूषित होते जा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति बद् से बद्तर हो रही है। पीने के लिए भू-जल का पानी खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु-पक्षी भी नगण्य के बराबर दिखते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं, इस पानी को पीने के बाद उनकी मृत्यु तय है।

इस संबंध में राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व केन्द्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा उठाए गए कदम व दिए गए निर्देश नाकाफी रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है और यदि उस जमीन पर कुछ उग भी आता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निचली किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता। राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाली पशुओं में बांझपन, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गई है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण करने के अनेक उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो काफी नहीं रहे।

इस गंभीर समस्या का निदान किया जा सकता है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है राज्य सरकार और औद्योगिक इकाइयां इसे वहन करने में असक्षम है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक बजट जारी करने के बाद ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

अतः मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों की टीम को राजस्थान के पाली जिले में भेजा जाए ताकि पाली जिले की इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा सके।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं अरावली पर्वत श्रृंखला के उस भाग की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर आदि जिले आते हैं। पहले से ही राजस्थान में पेड़ों की भारी कमी है और अरावली पर्वत श्रृंखला पर पेड़ों की रक्षा के लिए कोई उपाय ना होने से दिन-प्रतिदिन पेड़ नहीं के बराबर दिखाई देने लगे हैं। जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसकी मार राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान झेल रहा है। मानसून की अनियमित और अनिश्चितता इसका एक उदाहरण है। यदि सरकार ने इस संबंध में कोई गंभीर उपाय नहीं किए तो इसका दुष्परिणाम जल्द ही भुगतान होगा।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अरावली पर्वत श्रृंखला पर, विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए विशेष कदम उठाए तथा पर्वतों पर वृक्षों की हो रही अवैध कटाई को रोकने के लिए भी उपाय करें।

इसी के साथ, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर):** आज के युग में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के महत्व को कम करके नहीं बताया जा सकता है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए जो हमारी आबादी के 60% से अधिक को प्रभावित करता है और हाल के वर्षों में हुई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए, यह जरूरी है कि हम इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसी दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था, जिसमें भारी आवंटन की सिफारिश की गई थी लेकिन यह बजट में परिलक्षित नहीं होता है। 2013-14 तक, मंत्रालय के लिए आवंटन हर वर्ष बढ़ रहा था, तथापि 2014 के बाद से इस प्रवृत्ति में पूरी तरह से बदलाव आया है। 2014-15 में, सरकार ने आवंटन में 13% की कमी की। अब, इस वर्ष सरकार ने आवंटन में फिर से 19% की कमी की है। यह हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के सामने बिल्कुल चिंताजनक है।

सरकार ने बाघ परियोजनाओं के लिए 137.06 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष 161.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15% कम है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। फिर भी 2014 तक, देश में बाघों की आबादी केवल 2,226 है। हालांकि, हाल के वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह 30% वृद्धि आंशिक रूप से पिछले वर्षों में गिनती की त्रुटियों के कारण है। भारत के वन्य जीव संरक्षण समाज के आंकड़ों के अनुसार, 2011-14 में कम से कम 110 बाघ मारे गए थे, 2007-10 में 118 बाघों का शिकार किया गया था। हमारे पास दुनिया के 70% जंगली बाघ हैं जो दुनिया के 25% से भी कम बाघों के निवास स्थान पर हैं। यह स्वयं सुझाव देता है कि हमें इस निवास स्थान की रक्षा और संरक्षण के लिए अपने प्रयास को बनाए रखना चाहिए।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, चामराजनगर में सरकार द्वारा दो बाघ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं-बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य, और इन दोनों बाघ परियोजनाओं में बी.आर.टी. परियोजना। बाघों की बढ़ती

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आबादी को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। विभिन्न विशेषज्ञों ने भी सरकार से इस मोर्चे पर आगे आने का आह्वान किया है।

देश भर में मानव पशु संघर्ष के कारण होने वाले हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है। इस तरह के आंकड़ों को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, लेकिन मंत्रालय ने समस्या को स्वीकार कर लिया है। ऐसे उदाहरणों में, जो लोग अभयारण्यों के सबसे करीब रहते हैं, यानी आदिवासी आबादी सबसे अधिक प्रभावित होती है। सरकार के प्रयासों में दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा उन मामलों में सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे मुआवजे का है जहां लोग मानव पशु संघर्ष में मारे जाते हैं। वर्तमान में, सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये प्रदान कर रही है। तथापि, यह पर्याप्त नहीं है। मैं मंत्री जी से इस क्षतिपूर्ति को बढ़ाने का आग्रह करता हूं। दूसरा, वर्तमान में, मानव-पशु संघर्ष पर सरकार का दृष्टिकोण निवारक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। इस मुद्दे पर ऐसी घटनाओं की रोकथाम पर केंद्र सरकार के प्रयास की आवश्यकता है। सौर बाड़ और जागरूकता की दिशा में अधिक आवंटन की आवश्यकता है, ताकि मानव-पशु संघर्ष के जोखिम को कम किया जा सके। मैं मंत्री से इस मुद्दे पर उचित कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 को 2008 से, लागू किया गया है और यह वनवासियों को वन क्षेत्र के स्वामित्व, पहुंच और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। एफ.आर.ए. के तहत ग्राम सभा वन संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करती है और किसी भी गतिविधि को रोक सकती है, जो वन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

सरकार ने हाल ही में यह निर्धारित किया है कि जनजातीय ग्राम परिषदों को यह प्रमाणित करने के बजाय कि उनके अधिकारों का निपटारा किया गया है और उन्होंने परियोजनाओं के लिए सहमति दी है, जिला प्रशासन को परियोजनाओं से प्रभावित गांवों की संख्या की परवाह किए बिना 60 दिनों में, ऐसा करने का अधिकार दिया जाएगा। 28 अक्टूबर 2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजकर जिला प्रशासन को वन क्षेत्र को अन्य उद्देश्यों के लिए बदलने का अधिकार दिया था।

यहां तक कि जनजातीय मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को बार-बार लिखा है। प्रतिवेदनों के अनुसार, जनजातीय मामलों के सचिव ने लिखा है कि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वन अधिकार अधिनियम परियोजनाओं में देरी कर रहा था। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय सहमति की कानूनी प्रक्रिया को शॉर्ट-सर्किट कर रहा है।

देश भर के, आदिवासियों के लिए, वन अधिकार अधिनियम सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये वे समुदाय हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं। यह शिथिलता एक संदेश देती है कि, सरकार वन क्षेत्रों की शांति और शासन के बारे में चिंतित नहीं है। मैं मंत्री जी से अधिनियम को कमजोर करने वाली ऐसी किसी भी अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह करता हूं। पर्यावरण और वन के लिए मंजूरी जनजातीय अधिकारों के साथ समझौता करके नहीं दी जानी चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के एक प्रतिवेदन के अनुसार, दिल्ली का वायु प्रदूषण दुनिया में सबसे अधिक है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण के मामले में 13 भारतीय शहर शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। दुनिया भर के प्रतिवेदनों के अनुसार, उच्च वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच का संबंध स्पष्ट है। अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि उच्च वायु प्रदूषण के कारण भारतीय अपने जीवनकाल के औसतन 3 वर्ष खो रहे हैं। इसी के आलोक में, राष्ट्रपति ओबामा ने, हाल ही में दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान एयर प्यूरीफायर खरीदे, जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में स्थापित किया गया था। मंत्रालय स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर इन प्रतिवेदनों को खारिज करता रहा है। क्या इस मामले में मंत्रालय, इस मामले पर एक स्वतंत्र अध्ययन करेगा ताकि स्वास्थ्य जोखिमों और वायु प्रदूषण के बीच संबंध का पता लगाया जा सके?

वहीं, मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि, अभी तक, दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि, वह न केवल दिल्ली के लिए बल्कि वायु प्रदूषण के संकट का सामना कर रहे शहरों के लिए भी एक कार्य योजना बनाए। इसमें बेंगलोर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, फरीदाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद शामिल हैं।

सरकार ने हाल ही में 10 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एन.ए.क्यू.आई.) शुरू किया है। तथापि, तीन शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए डेटा अपर्याप्त पाया गया है। इन शहरों में, निगरानी के बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई है। कुछ शहरों में केवल एक निगरानी केंद्र मौजूद है जबकि विभिन्न निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री से इन मुद्दों पर गौर करने का आग्रह करता हूं ताकि निगरानी पहल सफल हो और यह केवल कागज पर मौजूद न हो।

***श्री सी.आर. चौधरी(नागौर):** “पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन” मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं विभाग को मजबूत करने और पिछले ग्यारह महीनों में नवीन योजनाओं को लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

यह आवश्यक है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को परेशान किए बिना जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और जल संसाधनों से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सरकार की सराहना करना चाहूंगा। वन विभाग से मंजूरी के अभाव में कई परियोजनाएं लंबित थीं। सरकार ने ऐसे मामलों को निपटाने की शक्ति को विकेंद्रीकृत कर दिया है।

इस समय, मैं माननीय मंत्री जी से गैर-धातु खनिजों के खनन पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का अनुरोध करना चाहूंगा जो पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबित हैं। जो लोग चूना पत्थर, चीनी मिट्टी या जिप्सम के खनन का पट्टा चाहते हैं उन्हें पर्यावरण मंजूरी के लिए जाना होगा। उन्हें इधर-उधर घूमना पड़ता है और खनन गतिविधियों में बाधा डालनी पड़ती है।

पर्यावरण मंत्रालय प्लास्टिक के पतले थैलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करना चाहूंगा।

अन्य देशों की तुलना में भारत में वनों का प्रतिशत कम है। वह सारी भूमि जिसे खेती के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है, उसका उपयोग वनों के लिए किया जाना चाहिए। रेगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राजस्थान को सामाजिक वानिकी के तहत वनरोपण के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से “ग्लोबल वार्मिंग” की ओर उचित ध्यान देने का आग्रह करना चाहूंगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए योजनाएं लाई जानी चाहिए। वायु प्रदूषण और वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण हैं और नीतियों को तैयार करते समय दोनों तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित विषयों को रखा जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण की आदत विकसित की जा सके।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को वन विभाग के उन रिक्त पदों को भरना चाहिए जो आरक्षित वन, अभयारण्यों और वन्यजीवों की देखभाल करते हैं।

अंत में, मैं देश में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मंत्रालय के निर्णयों और व्यावहारिक दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और कामना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में यह मंत्रालय वनरोपण, वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण को बनाए रखते हुए इस देश के लोगों के लिए एक अद्भुत काम करेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी(राजमपेट): श्री सभापति महोदय, धन्यवाद। प्रत्येक सभ्य समाज की जिम्मेदारी है कि वह अपने पर्यावरण और वन की देखभाल करे। भारत जैसे विकासशील देश में हमने देखा है कि मानव के लालच ने हमारे वन क्षेत्र और हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। हालांकि वर्ष 2000 से अब तक हमारा वन क्षेत्र 0.46 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और हमें अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि सामाजिक जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक प्रभाव बहुत कम है। 14^{वें} वित्त आयोग ने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 7.5 प्रतिशत आवंटित किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह 7.5 प्रतिशत राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण के माध्यम से है। हमें नकारात्मक प्रोत्साहनों की आवश्यकता है ताकि राज्यों पर अपना वन क्षेत्र बढ़ाने का दबाव हो।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, राजमपेट में, जो आंध्र प्रदेश में है, हमारे पास दुनिया का 80 प्रतिशत लाल चंदन का पेड़ है। यह शेषाचलम वन क्षेत्र में है। लाल चंदन हमारी केंद्र सरकार की लुप्तप्राय सूची में है। एक टन लाल चंदन की कीमत 24 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक होती है। यही कारण है कि बहुत सारी तस्करी हो रही है। इन पेड़ों को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है। सरकार इन लाल चंदन की तस्करी को नियंत्रित करने में असमर्थ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जब्त किए गए लाल चंदन की नीलामी और बिक्री की अनुमति दी है।

हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वह हस्तक्षेप करे और लाल चंदन की तस्करी को नियंत्रित करे। इस नीलामी से प्राप्त आय का उपयोग पूरे राज्य में लाल चंदन के विकास, वन क्षेत्र की रक्षा और लाल चंदन की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। इसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि रेत खनन पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। रेत का व्यापक खनन जल संसाधनों को कम कर रहा है और हमारी पारिस्थितिकी और पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रहा है, विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र में, जल स्तर में भारी कमी आई है। सरकार को संसाधनों के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए जो रेत की जगह ले सकें। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन होना चाहिए। तीव्र आर्थिक विकास गरीबी में कमी के सीधे आनुपातिक है। इसके लिए, आने वाले वर्षों में हमारे देश को 10 प्रतिशत की दर से विकास करना होगा। इस 10 प्रतिशत की वृद्धि को, बनाए रखने के लिए हमें बुनियादी ढांचे और विभिन्न अन्य

विनिर्माण उद्योगों में भारी निवेश की आवश्यकता है। हमारे पास आने वाले पाँच वर्षों में अपनी बिजली क्षमता को लगभग दो लाख मेगावाट तक बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गैर सरकारी संगठनों और निहित स्वार्थ वाले लोगों के दबाव में, कई बड़ी एल्यूमीनियम, इस्पात, सीमेंट और थर्मल परियोजनाएं, जिनके लिए प्रारंभिक मंजूरी दी गई थी, रुकी हुई हैं। वैश्विक परिदृश्य में यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की अनिश्चितता लोगों को भारत आने से हतोत्साहित करेगी।

अब, हमारे पास “मेक इन इंडिया” जैसे नारे हैं, लेकिन अगर हम समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं और इन सभी अनिश्चितताओं को दूर नहीं करते हैं तो यह एक दूर की हकीकत होगी। यहां तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी अपने एक बयान में कहा था कि विदेशी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन कुडनकुलम बिजली परियोजना को रोकने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अन्य परियोजनाएं भी निहित स्वार्थों के कारण रुकी हुई होंगी। ऐसे समय में जब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम पाते हैं कि भारी निवेश वाली परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए अटकी हुई हैं... (व्यवधान)

दुर्भाग्य से, यह राष्ट्रीयकृत बैंक और छोटे निवेशक हैं जो इन कंपनियों में अपने जीवन बचत लगाते हैं जो दांव पर हैं। कोई भी व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा के लिए वास्तविक कदमों का विरोध नहीं करेगा, विशेष रूप से आदिवासी लोग जो जंगलों पर आश्रित हैं। लेकिन अगर हमारे पास जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक और रणनीतिक खदानें हैं, तो हमें निश्चित रूप से इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और लाभ का उपयोग जनजातीय लोगों के विकास के लिए करना चाहिए।

वनों की बात करें तो कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित बीके चतुर्वेदी समिति ने कहा कि देश के सभी कोयला ब्लॉकों को मंजूरी देने के लिए कुल वन क्षेत्र का केवल 0.75 प्रतिशत आवश्यक है। समिति ने यह भी पाया कि यह हमारे देश में दो लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है। इसने सुझाव दिया कि खनन को रोकने के बजाय, सरकार इन खदानों पर कर लगा सकती है और हमारे देश में कम से कम 100 और अवक्रमित वनों पर वन लगा सकती है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमारी पार्टी ने अतीत में आगाह किया है और हम यह फिर से कह रहे हैं कि जब तक पी.एम.ओ., जहां सभी केंद्रीय मंत्रालय मिलते हैं, के पास दैनिक आधार पर सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी करने का तंत्र नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अंतर-मंत्रालयी मंजूरी समय पर दी जाए, हम पहले चरण में वापस आ जाएंगे। हमारे सभी अच्छे इरादे और आकांक्षाएं सिर्फ कागज पर ही रहेंगी और अच्छे दिन बहुत दूर होंगे।

[हिन्दी]

***श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):** जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है और यह परिवर्तन विश्व वातावरण की संरचना को बदल देता है। पृथ्वी की जलवायु हमेशा बदलती और विकसित होती रही है। इस प्रकार के कुछेक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होते हैं लेकिन अन्य के लिए मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार होते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, उद्योगों तथा परिवहन से वायुमंडलीय उत्सर्जन, जिसके कारण वायुमंडल में गैस तथा ऐरोसॉल्स एकत्रित हो जाते हैं। इन गैसों को ग्रीनहाउस गैस कहते हैं क्योंकि ये गर्मी को रोक लेती है और धरातल के निकट वायु के तापमान को बढ़ा देती है और पृथ्वी की सतह पर ग्रीनहाउस की भूमिका अदा करती है।

ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री स्तर, बर्फ की चादर तथा वर्षा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हवा के तापमान में बढ़ोतरी द्वारा जलवायु के क्षेत्रीय पैटर्न में होने वाले परिवर्तन ने विश्व के कई भागों में जल संभरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करना पहले ही शुरू कर दिया है। यह बढ़ता हुआ तापमान और बढ़ता हुआ समुद्र स्तर मीठे पानी की उपलब्धता, समुद्री खारेपन, खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। यह तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है और जलजनित विकारों का प्रकोप बढ़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन विकास के समक्ष एक बड़ा खतरा है, जो गरीबी मिटाने और समृद्धि को जनता में बांटने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। अगर कोई मजबूत और त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो धरती के तापमान में डेढ़ से दो डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसकी वहज बीते समय और वर्तमान समय में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है। इस तापमान बढ़ोतरी के चलते समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और चक्रवातों के जल्दी-जल्दी आने का खतरा बढ़ रहा है। मात्र दो डिग्री की वृद्धि से ब्राजील की सोयाबीन फसल का उत्पादन 70 फीसदी तक कम हो सकती है। दो डिग्री की वृद्धि से दुनिया में मक्का, गेहूं और अंगूर की फसलों के उत्पादन में 50

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

फीसदी की कमी आ सकती है। उत्तरी रूस में इसके कारण बर्फ के ढके क्षेत्र में लगातार बर्फ पिघलेगी जिसके चलते नुकसानदायक मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होगी।

वैश्विक तापवृद्धि से निपटने हेतु संभावित उपायों में शामिल हैं: रसोई गैस सब्सिडी को केवल जरूरतमंद लोगों तक सीमित रखा जाना जिससे कच्चे तेल के आयात में कटौती सम्भव है। एल.ई.डी. के इस्तेमाल करने पर देश में कई अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। सरकारी बैंक देश में ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एवं विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सस्ता एवं सुविधाजनक लोन उपलब्ध कराए। हरित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हमारे देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम की सम्भावनाओं को तलाशने की जरूरत है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अपनाए जाने से भी प्रदूषण का स्तर कम करके उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। भारत में मनरेगा जैसी राष्ट्रीय स्तर की योजना को ग्रीन इंडिया मिशन से जोड़े जाने से जलवायु परिवर्तन द्वारा वैश्विक तापवृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है।

अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले वैश्विक ताप वृद्धि से मुकाबला करने के लिए पर्यावरण हितैषी और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले शहर विकसित करने पर जोर दिया जाए तथा संभाव्य जलवायु सम्बंधी खतरों से सुरक्षित रहने के लिए समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

***श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर):** पर्यावरण और वन वह विषय है जो देश की भावी पीढ़ी से सीधे जुड़ा हुआ है। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार दोनों राज्यों और केंद्र सरकार की प्राथमिकता और सर्वोपरि विचार है। वर्ष 2015-16 के लिए, निधि आवंटन के आंकड़ों को देखने पर लगता है कि केंद्र सरकार ने इस प्रमुख कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया है। किसी भी सरकार को हमेशा इस देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण पर्याप्त नहीं है। उक्त प्राकृतिक संपदा में सुधार किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि घने जंगल दिन-ब-दिन पतले होते जा रहे हैं। जंगलों में बहुत सारे अच्छी तरह से उगाए गए पेड़ों को बेरहमी से काटा और हटाया जाता है। देश भर में अवैध वनों की कटाई की गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। अवैध गतिविधियों के कारण घने जंगलों का आकार धीरे-धीरे कम हो रहा है।

वनों को सुधारने और कम से कम वनों के आकार और मोटाई की स्थिति को बनाए रखने के लिए पौधे लगाना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं बन रहा है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को हर साल के बरसात के मौसम को युद्ध स्तर पर पौधे लगाने के लिए लेना चाहिए। इसके अलावा, स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। बच्चों को पौधरोपण कार्यक्रम के महत्व के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

राज्यों और केंद्र सरकार दोनों को वनों, झीलों और नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण, संरक्षण और सुधार के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता कार्यक्रम बनाने के लिए कुछ तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए। इस जागरूकता से लोगों को इस देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का हिस्सा बनने के लिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में पता चलना चाहिए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रकृति को संतुलित करने के लिए वन्य जीवन का संरक्षण और सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह राज्यों और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरल निर्णय बहुत से जंगली जानवरों की रक्षा और संरक्षण कर सकते हैं। सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

वन्यजीवों की रक्षा के लिए मौजूदा कानून न तो कड़े हैं और न ही उन्हें ठीक से लागू किया गया है। अतः केंद्र सरकार को इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए।

जंगलों में अवैध खनन गतिविधियां और रेत का खनन भी पूरे देश में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस अधिनियम का पर्यावरण की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अतः जंगलों में इस अवैध खनन गतिविधियों और रेत खनन को भी बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। अवैध रेत खनन न केवल पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहा है, बल्कि भूमिगत जल की कमी का एक बड़ा कारण भी है।

देश में प्रदूषण नियंत्रण भी एक गंभीर मामला है। राज्यों और केंद्र दोनों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दांत रहित हो गए हैं। वे वस्तुतः कानूनी आपत्तियों को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के केंद्र बन गए हैं। इन बोर्डों की स्थापना का उद्देश्य ही विफल हो जाता है क्योंकि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री बी.एन. चन्द्रप्पा (चित्रदुर्ग):** मुझे लगता है कि यह सरकार इस मंत्रालय पर बहुत कम ध्यान दे रही है, जो सतत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस मंत्रालय पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो, पूरी सरकार का माहौल प्रभावित होगा।

मुझे लगता है कि हमारा देश पारिस्थितिक संकट का सामना कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर दिन हमारे वाहन, हमारे कारखाने और हमारे बिजली संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में उगल रहे हैं। हमारे एयर-कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वातावरण में कार्बन उगल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे पास पृथ्वी पर वायुमंडल पर एक ढाल है जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यदि इसकी जांच नहीं की जाती है, तो यह अंततः कई निचले इलाकों को समुद्र के नीचे डुबो देगा। पहले से ही ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है।

दूसरी समस्या यह है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को पेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की बड़ी क्षमता होती है।

हम अपने जंगलों को, काटकर अपनी हवा को शुद्ध करने के उन साधनों को नष्ट कर रहे हैं। केवल इतना ही कि, वर्षों से, पर्यावरण और विकास के बीच हमेशा बहस होती रही है। अब जो हो रहा है वह यह है कि पश्चिम के औद्योगिक रूप से विकसित देश हमारे देश पर पर्यावरणीय मानदंडों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, मुख्य प्रश्न संतुलन बनाने का है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण के इन सभी पहलुओं और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या को देखने के लिए नोडल एजेंसी है। बस हमारे शहरों को देखो। हम सीवेज को बहने वाली नदियों में छोड़ रहे हैं। हमारे कारखाने हमारी नदियों में सीवेज छोड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि, भारत सरकार

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल और वायु प्रदूषण और वनीकरण के प्रश्न पर समग्र दृष्टिकोण अपनाए। दुर्भाग्य से, इसकी कमी है।

ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के पास एक बड़ी सूची है। इसे वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण मिला है; इसे वन अनुसंधान संस्थान मिला है। इसे एक विशाल नौकरशाही ढांचा मिला है लेकिन अंततः पर्यावरण के मामले को लोगों के पूर्ण सहयोग से, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर ही हासिल किया जा सकता है। आज, शहरों के अच्छे स्कूलों में, वे पढ़ाने का माहौल बना रहे हैं। लेकिन बड़ी आबादी अभी तक पर्यावरणीय क्षरण की समस्या के प्रति सचेत नहीं है।

मंत्री ने उल्लेख किया कि पर्यावरण मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। हमें सतत विकास के मॉडल का पालन करने की आवश्यकता है। अगर हम 8 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हासिल करना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कम कार्बन वाली वृद्धि हो। जैसा कि है, अभी भी हम जिस दर से जा रहे हैं, 2030 में, भी भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन किसी भी विकसित देश की तुलना में कम होगा। इसलिए, हमें समय पर इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हम विकास की राह पर चलें।

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर) : महोदय, सबसे पहले, मैं कहना चाहूंगी कि मैंने स्थायी समिति की प्रतिवेदन पेश की क्योंकि मैं स्थायी समिति की सदस्य हूँ। लेकिन, प्रतिवेदन को पूरी तरह से पढ़ने पर, मैं कहूंगी कि जो सामने आया वह सौम्य उपेक्षा की गाथा है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है और इस मंत्रालय ने आवंटन में जिस तरह की कटौती की है, उसे देखकर मुझे दुख हो रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस प्रतिवेदन का विषय है। मैं प्रतिवेदन से उद्धृत करती हूँ:

“धरती माता के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

आज, यह प्रतिवेदन सरकार से नीति और विधायी सुधारों के क्षेत्रों की पहचान करने का आग्रह कर रही है जो एक हरित रोडमैप तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में पर्यावरण गहरे संकट के दौर में प्रवेश कर रहा है। आज, जब हम बजट का अवलोकन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? आज, हम देख रहे हैं कि इस सरकार ने जानबूझकर इस विभाग को कम वित्त पोषित किया है, हमारे पर्यावरण को कम वित्त पोषित किया है। आज, इस सभा में सदस्यों ने बार-बार कहा है कि 4,440.20 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 1,446.60 करोड़ रुपये का मामूली आवंटन किया गया है। आज, हमने देखा है कि मंत्रालय ने 11^{वीं} योजना की आठ योजनाओं को 12^{वीं} योजना में पांच योजनाओं में तर्कसंगत बनाया है। परिणामस्वरूप, विषयगत योजनाओं को 22 से घटाकर 18 कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, जलवायु परिवर्तन पर योजना एक स्टैंड अलोन विषयगत योजना बन गई है। लेकिन आज प्रोजेक्ट टाइगर में भी 15 प्रतिशत की कटौती हुई है। आज, भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित एकमात्र योजनाएं प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट हैं।

इस आवंटन के आलोक में, इस समिति ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि आर.ई. के स्तर पर, उचित आवंटन किया जाना चाहिए। चिंता क्यों हो रही है? आज, जब स्थायी समिति ने इस विभाग के अधिकारियों से पूछा कि इस कटौती का क्या प्रभाव होने वाला है, तो उन्होंने उन सभी क्षेत्रों की सूची दी जो इस कटौती से प्रभावित होने वाले हैं।

उसमें से, यह पैराग्राफ 16.14 से है – प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। [हिन्दी] आज देश के प्रधान मंत्री देश और विदेश में जाकर स्वच्छ भारत की बात करते हैं। आज जहां हमें भारत को स्वच्छता की ओर ले जाना है, इस मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा – [अनुवाद] हवा और पानी की स्थिति क्या है? आज, तेजी से हो रहे शहरीकरण के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से पूछती हूं – क्या सीवेज उत्पादन की मात्रा हमारी उपचार क्षमता से मेल खाती है? ऐसा नहीं हुआ है। अगर भारत में 36,000 एम.एल.डी. सीवेज का उत्पादन होने की उम्मीद है, तो हमें इस देश को पर्याप्त सीवेज प्रणाली देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है। मामलों को बदतर बनाने के लिए, [हिन्दी] जब जावड़ेकर जी मंत्री बने तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया - [अनुवाद] कि मैं इस मंत्रालय की संस्कृति को बदल दूंगा। उसका क्या मतलब था? मैं नहीं जानती। [हिन्दी] लेकिन मैंने जो देखा है [अनुवाद] यह सरकार जल्दबाजी में है। जल्दी करो किस बात के लिए! कि भारत को विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में ऊपर चढ़ना चाहिए। इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? यह 'मेक इन इंडिया' है। मैं सिलचर के नाम से जाने जाने वाले निर्वाचन-क्षेत्र से आती हूं। सिलचर से सौराष्ट्र [हिन्दी] जो महासड़क है, आज इनवायरमेंट क्लीयरेंस [अनुवाद] विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण है [हिन्दी] यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता - [अनुवाद] क्योंकि बराक घाटी के लोग आज तक पर्यावरण मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं और [हिन्दी] मैं जीतने के बाद ही जावड़ेकर साहब से मिली थी। [अनुवाद] इसलिए, राज्य ने अब आपको सब कुछ भेज दिया है। गेंद आपके पाले में है, महोदय। [हिन्दी] जरूर कीजिए। मैं यह उदाहरण के हिसाब से क्यों कह रही हूं [अनुवाद] कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस उद्योग विरोधी पार्टी है, कि कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। आज हम चाहते हैं कि व्यापार आसान हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी आसानी से सांस ले सकें। [हिन्दी] आज सुब्रहमणियम कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। लोग कह रहे हैं कि यह इनवायरमेंट फ्रेंडली है या इन्वैस्टर फ्रेंडली है। आज देश में यह सवाल उठ रहा है। मैंने कहा आप सुब्रहमणियम कमेटी की प्रतिवेदन पढ़ेंगे तो देखेंगे [अनुवाद] आप सुब्रहमण्यम प्रतिवेदन पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि वे आपराधिक दायित्व को हटा रहे हैं और नागरिक दायित्व ला रहे हैं। क्या यह कॉर्पोरेट्स की मदद करने के लिए है? आज हम कह रहे हैं-वेतन और प्रदूषण?

आज, मैं अनुरोध करती हूँ कि इस मंत्रालय को स्थायी समिति की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए और टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

आज, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड - [हिन्दी] आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सारे अप्रूवल हो गए हैं। सुना है 789 अप्रूवल हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि 140 अप्रूवल को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे कर दिया। [अनुवाद] क्या आपने उस शरीर को ठीक से बनाया है? क्या आपने 10 वैयक्तिक विशेषज्ञों का एक समूह दिया है? क्या आपने पांच गैर-सरकारी संस्थाओं को शामिल किया है? आज कोयला खनन क्षेत्र में, जहां क्षमता प्रति वर्ष 16 एम.टी. से कम है, क्या आपने सार्वजनिक सुनवाई न करने के प्रावधान को हटा दिया है? आज, क्या आपने प्रभाव कर मूल्य) निर्धारण, ई. आई. ए. नियमों को कम कर दिया है? आज, क्या आप पांच किलोमीटर के भीतर परियोजनाओं को अनुमति देंगे। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बिना आगे बढ़ने के लिए संरक्षित क्षेत्र का? क्या यह सरकार ग्राम सभा की पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता को छोड़ते हुए वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करेगी? [हिन्दी] फिर जो लैंड बिल में इस सरकार की हालत हुई है फॉरेस्ट राइट्स में भी वही होगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

कुमारी सुष्मिता देव : महोदय, अंतिम लेकिन कम से कम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इस राष्ट्र का एकमात्र पर्यावरण न्यायालय है। इसकी स्थापना रियो सम्मेलन में किए गए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए की गई थी। इसलिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियों को भविष्य में कम नहीं किया जाना चाहिए। यह मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है। [हिन्दी] आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मेरा अनुरोध है कि [अनुवाद] पर्यावरण की रक्षा करें। भारत के युवाओं को आराम से सांस लेने दें [हिन्दी] ब्रिथ इजी करेंगे तभी मेक इन इंडिया से नौकरी मिलेगी, इम्प्लायमेंट मिलेगी।

[अनुवाद]

***श्री प्रसन्न कुमार पाटसानी (भुवनेश्वर):** वर्ष 2015 जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर नए समझौतों को देखने के लिए तैयार दुनिया के साथ महत्वपूर्ण होने की संभावना है। सभी देशों पर लागू जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौते को महत्वाकांक्षी, व्यापक, न्यायसंगत और संतुलित होना चाहिए, जिसमें वित्तीय संसाधनों तक पहुंच और कम कार्बन तकनीकी विकल्पों सहित विकासशील देशों की विशाल विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत में, हाल के वर्षों में शुरू किए गए ऐतिहासिक पर्यावरणीय उपायों को नए वैज्ञानिक निष्कर्षों और वर्तमान आवश्यकताओं के आलोक में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नीतियों द्वारा पूरक किया जा रहा है।

वित्त मंत्री का विकास और इक्विटी पर ध्यान अधूरा है। उन्हें ऊर्जा की अभिस्वीकृत और पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता के बीच समझौते को स्वीकार करना चाहिए था। वित्त मंत्री ने प्राकृतिक गैस का कोई उल्लेख नहीं किया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि गैस सभी जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ है और अपर्याप्त गैस आपूर्ति और खराब पाइप लाइन बुनियादी ढांचे के कारण 20 गीगावाट उत्पादन क्षमता का संचालन नहीं किया गया है।

भारत जलवायु परिवर्तन पर खेल को बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में एक उल्लेखनीय और अभिनव दावा किया है, जो उन मानक मान्यताओं को उलट सकता है जिनके द्वारा जलवायु परिवर्तन को नकार दिया जाता है। इसने इंगित किया है कि भारत कार्बन-सब्सिडी शासन-काल से उस ओर बढ़ गया है जहाँ कार्बन उगलने पर कर लगाया जाता है। यह भारत को उन बहुत कम देशों में रखता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों में कार्बन कर जैसे वित्तीय तंत्र को शामिल किया है। यह बदलाव हाल के सरकारी उपायों के माध्यम से लाया गया है, जैसे कि, डीजल की कीमतों का नियंत्रण और उच्च उत्पाद शुल्क और पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाना। ये, जैसा कि सरकार ने सही ढंग

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से बताया है, उत्सर्जन पर एक कीमत डालने के बराबर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों पर देश का वास्तविक कार्बन कर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया गया शुल्क पेट्रोल के लिए 140 डॉलर प्रति टन और डीजल के लिए 64 डॉलर के कार्बन कर के बराबर है, जो वैश्विक प्रारंभिक कार्बनडाइऑक्साइड (सी.ओ.₂) उत्सर्जन कर मानदंड 25 डॉलर से 35 डॉलर प्रति टन से अधिक है। जब उत्सर्जन में कमी में अनुवाद किया जाता है, तो कराधान का यह स्तर एक वर्ष में 11 मिलियन टन सी.ओ.₂ निर्वहन की शुद्ध कटौती के बराबर है, या भारत के वार्षिक उत्सर्जन का 0.6 प्रतिशत है।

वन्य जीव संबंधी अपराधों से निपटने के लिए, निदेशक, वन्यजीव संरक्षण के तहत एक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है, जिसमें 5 क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जबलपुर और अमृतसर, गुवाहाटी और रामनाथपुरम में 3 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

मंत्रालय का वन्यजीव प्रभाग केंद्र प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास और केंद्रीय क्षेत्र योजना - वन्य जीव प्रभाग का सुदृढ़ीकरण और विशेष कार्यों के लिए परामर्श, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को अनुदान सहायता के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

प्रकृति के नियमों के अनुसार हम अपने शरीर और दिमाग को ठीक कर रहे हैं जब पर्यावरण को जहर दिया जाता है, तो मनुष्य का पूरा जीवन खतरे में पड़ जाता है। मुझे लगता है कि प्रत्येक पेड़ मानव की तुलना में मूल्यवान है। अगर एक पेड़ मर जाता है, तो मृत शरीर को जलते घाट तक कौन ले जाएगा? किसी भी पेड़ की लकड़ी रसोई से अंत तक बहुत उपयोगी होती है। इसलिए, हमें एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी पेड़ काट रहा है उसे दंडित किया जाना चाहिए। हम पेड़ काट रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं। पशु साम्राज्य प्यासा होगा। आजकल जंगलों में जानवरों के जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जब पेड़ का व्यष्टि हरा होता है तो जंगल हरा होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है। इसलिए हमें जंगल की रक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे भगवान जगन्नाथ लकड़ी से बने हैं। हम एक पेड़ काट रहे हैं इसका मतलब है

कि आप अपने भगवान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी तरह ईसाई धर्म में क्रॉस लकड़ी से बना है। जब आप जंगल को मार रहे हों तो आपको समाज के बारे में सोचना चाहिए। एक पेड़ हमें फल, पत्ते, छाया प्रदान कर रहा है। सरकार को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। यह तब हुआ जब राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों का निर्माण पहले ही हो चुका है। साथी यात्रियों की सुरक्षा के लिए तत्काल वृक्षारोपण शुरू किया जाना चाहिए था। हमारे राज्य में, इसकी अत्यधिक उपेक्षा की जाती है। निर्माण कार्य के कारण सौ साल के पुराने पेड़ नहीं रहे। इसलिए हम प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। क्योंकि हम जंगल, जंगल और प्रकृति के जीवन को हर दिन खराब कर रहे हैं, प्रकृति हमें दंडित कर रही है। हमारे राज्य में बड़े-बड़े जंगल हैं। इसलिए, बारिश समय पर होती है, कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होता है और पशु साम्राज्य का अस्तित्व रहता है। मनुष्य शांति से रह रहा है और अपने राज्य से प्यार कर रहा है। पर्यावरणीय स्थिति के कारण कि हम अनुकूलन नहीं कर रहे हैं, हम भूकंप, सूखे, बाढ़ और अकाल का सामना कर रहे हैं। वन जीवन के विकास के लिए सरकार जो कुछ भी मंजूरी दे रही है या अनुदान आवंटित कर रही है, वह पूरी तरह से खराब हो गया है क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित नहीं है।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के मंत्रालय में किए गए महान कार्यों के लिए भी उनकी सराहना करना चाहूंगा। मैं उन्हें जलवायु परिवर्तन समझौते पर बातचीत करने के विशेष अधिकारों पर विश्व नेताओं के साथ पिछले साल लीमा सम्मेलन में ली गई स्थिति के लिए बधाई देना चाहता हूँ और सम्मेलन में जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को अलग करने पर आम सहमति पर पहुंचा हूँ।

मैं स्थायी समिति की प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहूंगा जिसका मेरे पिछले अध्यक्ष भी उल्लेख कर रहे थे। मैं व्यापार करने में आसानी के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले, सरकार की नीतियां निवेशकों को दबाने के लिए थीं और पिछली सरकार में नीतिगत पक्षाघात था। नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जिन परियोजनाओं को पहले शुरू नहीं किया गया था, उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी न दी जाए। ई-पोर्टल प्रणाली के लिए धन्यवाद, मंत्री जी को नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है और पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदन लोगों द्वारा देखी जा सकती है। पहले लोग, निवेश करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने पैसे को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। अब, नई सरकार के आने के साथ, वे पर्यावरण मूल्यांकन समिति की प्रतिवेदन के कार्यवृत्त को देख सकते हैं और मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सतत विकास की बात की है। सतत विकास प्राप्त करने के लिए, माननीय मंत्री जी ने भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की पहल की है। स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने, यह सुनिश्चित किया है कि कोयला क्षेत्र जैसे गंभीर रूप से प्रदूषण फैलाने वाले 17 क्षेत्रों को निरंतर आधार पर अपशिष्ट और उत्सर्जन गुणवत्ता की निगरानी के लिए उपकरण स्थापित करने के लिए कहा गया है। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक साल में कोयले पर उपकर को दोगुना कर दिया है। मंत्री ने जैव विविधता के लिए वित्तपोषण बढ़ाने की भी बात की है।

जो पहले नहीं किया गया था। इसे बढ़ाकर 27.09 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पहले 13.08 करोड़ रुपये था।

भारत सरकार ने दिल्ली की हवा को साफ करने की बात कही है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या एक ऐसे समय में पैदा हुई है जो हमें विरासत में मिली है। आर्थिक और राजनीतिक सामाहिक प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो दिल्ली में प्रदूषण प्रति व्यक्ति लगभग 3.2 साल कम हो जाएगा। इसने हमारी श्वास और श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया है और सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 240 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

माननीय सभापति: कृपया समापन करें।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, मैंने अभी शुरुआत ही की है। कृपया मुझे दो अथवा तीन मिनट और दें।

माननीय मंत्री जी ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना के बारे में बात की है। उन्होंने एन.टी.पी.सी. से उत्सर्जन भार को दो-तिहाई से घटाकर एक-तिहाई करने के उपाय किए हैं। उन्होंने एशिया की पहली प्लाज्मा गैसीकरण योजना के बारे में भी बात की है। उन्होंने वायु गुणवत्ता नियंत्रण पर भी ध्यान दिया है; उन्होंने 10 शहरों में एक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक शुरू किया है जिसे आगे 46 शहरों में भी विस्तारित किया जा रहा है। हम 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा को देख रहे हैं। हम एगोरा एनर्जीविंडे द्वारा किए गए अध्ययन को देख रहे हैं जिसके द्वारा स्वच्छ ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकती है और इस तरह प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में भी बात की है जो किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 130 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया है। उन्होंने भारतीय वन अनुसंधान परिषद के काम को भी देखा है।

मैं कहना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन ने भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनियमित मौसम पैदा किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक प्रतिवेदन में

कहा गया है कि तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। इसलिए सरकार भी इस पर विचार कर रही है। स्थायी समिति की प्रतिवेदन में भी इस बारे में बात की गई है।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि हमने जंगलों के लिए क्या किया है। हमने हरित भारत मिशन के बारे में भी बात की है, जिसके द्वारा हम देश भर में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्ष आच्छादन बना सकते हैं। हम इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने और लोगों की मदद करने के लिए भारत के लोगों को रोजगार देने में मदद कर सकते हैं।

मैं प्रोजेक्ट टाइगर को देखने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके शासन-काल में बाघों की आबादी में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं प्रोजेक्ट हाथी को देखने के लिए मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह 38,000 करोड़ रुपये के सी.ए.एम.पी.ए. फंड को देखें, जिससे अगर वह एक नियामक तंत्र बना सकते हैं, तो राज्यों को इसका लाभ मिल सकता है। उन्हें एन.टी.सी.ए. पर भी ध्यान देना चाहिए। एन.टी.सी.ए. द्वारा पहले किए गए कार्य इष्टतम स्तर के नहीं थे। अब नई सरकार के आने से एन.टी.सी.ए. की व्यवस्था में सुधार हुआ है।

अंत में, मैं कहूंगा कि, हमें राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल को भी देखने की आवश्यकता है। मेरे पिछले वक्ताओं ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बात की थी। ठोस अपशिष्ट गैसीकरण प्रणाली के साथ, हम यहां अपनी प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। हमें इस देश के नदी बेसिनों, चंबल बेसिन और उन सभी को भी देखने की जरूरत है।

मैं सरकार द्वारा किए गए महान कार्य के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

***श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती):** पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए आवंटन 1681 करोड़ रुपये है, जो 2014-15 के बजट अनुमान से 25% कम है और 2014-15 के संशोधित अनुमान से भी कम है। पूरे वानिकी और वन्यजीव विभाग को 362.84 करोड़ रुपये दिए गए थे, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित की गई राशि से 21% कम है।

भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आवंटन, 136 करोड़ रुपये, 2014-15 में 161 करोड़ रुपये से लगभग 15% की कमी। जनवरी में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान प्रतिवेदन में कहा गया है कि बाघों की आबादी 2010 से 30% बढ़कर 2014 में 2,226 हो गई थी। यू.पी.ए. और एन.डी.ए. के 3 वर्षों के प्रयासों से ही हमें इस राज्य को प्राप्त करने में मदद मिली है। आवंटन में कटौती करके, हम स्थिति पर वापस नहीं जाना चाहते हैं। मैंने हाल ही में ताडोबा का दौरा किया है और यह देखकर हैरान हूँ कि कैसे इसने लोगों के लिए बहुत धन और आजीविका का निर्माण किया है।

वन रेंजर, उप वन रेंजर, वनपाल और वनरक्षक हमारे देश की बहुमूल्य वन और वन्य जीव संपदा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करने वाले अग्रिम पंक्ति के फील्ड स्तर के कर्मचारी हैं। वे जनता के साथ वन विभाग का संवादात्मक इंटरफेस हैं। जबकि उनकी नौकरी कठिन और मांग वाली है और इसमें उच्च जोखिम शामिल है, उन्हें खराब भुगतान किया जाता है, बिना उपकरण के, अप्रशिक्षित और परिणामस्वरूप डी-मोटिवेट किया जाता है। इसके अलावा वे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, संचार प्रणाली, सुरक्षात्मक वर्षा/शीतकालीन उपकरण और चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

मैं सुन रहा हूँ कि सरकार शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, बाघ को बाहर निकाल रही है जिसे 1972 से प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। मेरे अनुसार, यह बाघों को बचाने के अभियान को कमजोर करेगा और बाघ अभयारण्यों के पास औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बाघ भारत के 17 राज्यों में पाए जाते हैं, जबकि शेर केवल एक में पाए जाते हैं। भारत 2,200 से अधिक

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बाघों का घर है, जबकि एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या 411 है, जो गुजरात के गिर तक ही सीमित है। यदि हम वास्तव में शेर को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले कम से कम 10-15 प्राकृतिक आवासों को बहाल करना चाहिए जो शेरों के लिए उपयुक्त हैं। फिर शेरों को गिर से वहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में भारत में 374 प्रजातियों को असुरक्षित और 274 अन्य को लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय और विलुप्त होने के खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाथियों, तेंदुओं, गैंडों जैसे प्रसिद्ध स्तनधारियों से लेकर कई कम ज्ञात जानवरों, जैसे पेंगोलिन, कछुए और गेको सभी हमारे देश में लुप्तप्राय हैं। भारत में जंगल में सिर्फ 26,000 और 30,000 हाथी बचे हैं। डब्ल्यू.पी.एस.आई. के आंकड़ों के अनुसार, हाथी दांत की मांग को पूरा करने के लिए पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच 18 हाथियों का अवैध शिकार किया गया था। एजेंसी ने 2008 और 2011 के बीच अवैध शिकार के कारण 120 से अधिक हाथियों के नुकसान को दर्ज किया है। इसी अवधि के दौरान, डब्ल्यू.पी.एस.आई. के पास हाथी दांत के टुकड़ों और नक्काशीदार वस्तुओं के अलावा 781 किलोग्राम हाथी दांत और 69 दांतों की जब्ती का रिकॉर्ड है। अवैध शिकार और तस्करी वन्यजीवों के लिए एक बड़ा खतरा है। डब्ल्यू.पी.एस.आई., एक वन्यजीव संरक्षण संगठन, ने 20,000 से अधिक वन्यजीव अपराध के मामले दर्ज किए हैं। हमारे वन्यजीवों के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं यहां केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के आवंटन में 27.50 करोड़ रुपये से 5.8 करोड़ रुपये की भारी कटौती करने का कारण भी पूछना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी चिंता है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के लिए बजटीय आवंटन लगातार कम हो रहा है। यह बजट अनुमान 2013-14 में 160.26 करोड़ रुपये था, बजट अनुमान 2014-15 में 156.66 करोड़ रुपये था और अब इसे घटाकर 125.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वन क्षेत्र के संरक्षण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और अनुसंधान आवश्यकताओं का ध्यान रखने के उद्देश्य से परिषद की स्थापना की गई थी। इस तरह के महत्व के संस्थान को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

अब वायु प्रदूषण के बारे में बात करते हुए, मुझे वास्तव में दुख हुआ जब मैंने समाचार में पढ़ा कि वायु गुणवत्ता के निम्न स्तर के कारण, एक अटकल थी कि यहां अमेरिकी अधिकारी ओबामा की यात्रा के दौरान

उनकी "बाहरी गतिविधियों" को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कहा जाता है कि ओबामा ने दिल्ली में रहने के कारण अपने जीवन के 6 घंटे गंवा दिए। यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। औद्योगीकरण और पर्यावरण को साथ-साथ चलने की आवश्यकता है। भारत में 90 प्रतिशत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र पर्यावरण के मोर्चे पर असंतोषजनक रूप से कार्य करते हैं। वास्तव में भारत में सबसे अच्छे कोयला संयंत्र दुनिया भर में अपने समकक्षों की तुलना में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में औसत हैं। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की भी आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 2022 तक 175000 मेगावाट तक संशोधित किया गया है। हालांकि लक्ष्य बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन मुझे लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में संदेह है, खासकर जब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कटौती संशोधित बजट 2014-15 में 550 करोड़ रुपये से घटकर केवल 303 करोड़ रुपये रह गई है।

मैं प्रकाश प्रदूषण की अवधारणा की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रकाश प्रदूषण औद्योगिक सभ्यता का एक दुष्प्रभाव है। इसके स्रोतों में बाहरी और आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, विज्ञापन, वाणिज्यिक संपत्तियां, कार्यालय, कारखाने, स्ट्रीट लाइट और रोशन, खेल स्थल शामिल हैं। यह न केवल चमगादड़, उल्लू जैसे फोटिक आवास को नष्ट करता है, बल्कि एक बड़ा खगोलीय व्यवधान भी साबित होता है। इस संबंध में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों में सरकार को कम से कम लाइट फिक्सचर में फुल-कट ऑफ शील्डिंग का उपयोग करना चाहिए जो आवश्यक उपाय है। एक दीपक को अपने सभी प्रकाश को कमोबेश नीचे भेजना चाहिए जहां प्रकाश का उपयोग करने का इरादा है, न कि ऊपर की ओर अथवा बगल में।

भारत में हर वर्ष लगभग 60 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। केवल महानगरों में ही दस करोड़ टन कचरा उत्पन्न होता है। इनमें से अधिकांश शहरों का लैंडफिल पहले से ही भरा हुआ है, जिसमें ताजा कचरे के कचरे को समायोजित करने के लिए कोई जगह नहीं है। नए लैंडफिल साइटों का निर्माण एक समाधान है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अपने कचरे के निपटान और पुनर्चक्रण के लिए नए तरीकों पर विचार करना चाहिए। अधिकांश लैंडफिल साइटों के अत्यधिक बहने का कारण यह है कि वर्तमान अपशिष्ट

निपटान प्रणाली अक्षम है। अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से अपशिष्ट पृथक्करण की कमी के कारण पूरी क्षमता से नहीं चल रहे हैं, जिसने अपशिष्ट प्रबंधन को समस्याग्रस्त बना दिया है। स्रोत पर पृथक्करण ही एकमात्र समाधान है। पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट जैसे निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट जैसे जैविक अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट जैसे विषाक्त अपशिष्ट, सभी को एक साथ मिलाया जाता है। गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे से बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्करण ठीक से नहीं किया जाता है। अपशिष्ट का पृथक्करण कॉलोनी या पड़ोस के स्तर पर होना चाहिए, जब अपशिष्ट एकत्र किया जाता है। कचरे का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित करता है। भारत में लगभग 20% मीथेन गैस उत्सर्जन लैंडफिल के कारण होता है। अकार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन के कारण, भूजल दूषित हो जाता है। लीचेट की समस्या तब भी होती है जब बारिश लैंडफिल में कचरे के माध्यम से रिसती है।

स्वच्छ भारत अभियान वर्तमान में नागरिकों को शहरों को प्रदूषित नहीं करने और स्वच्छता के लिए कूड़ेदान का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन अपघटित और गैर-अपघटित पदार्थ के पृथक्करण के बारे में जागरूकता अभी भी एक दूर का सपना है। शहर की सफाई से पहले, सरकार को एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है जो पृथक्करण और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करे। उन सभी चीजों को संसाधित करें जिन्हें संसाधित किया जा सकता है और केवल अवशेष को लैंडफिल में डंप करें। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि मिशन के दायरे का विस्तार करें और स्वच्छता अभियान के साथ-साथ अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व पर जागरूकता फैलाना शुरू करें।

इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी., एम.ओ.एफ., जी.ओ.आई.) 'स्वच्छ भारत अभियान' के खिलाफ प्रतीत होता है क्योंकि सी.बी.ई.सी. भारत में अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाओं को सुरक्षित लैंडफिल (एस.एल.एफ.) बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं पर कानूनी रूप से वैध इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार कर रहा है। सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 (1) में इनपुट सेवाओं की परिभाषा प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है किसी भवन या सिविल संरचना अथवा उसके एक हिस्से के निर्माण या कार्य अनुबंध के निष्पादन को छोड़कर आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग की

जाने वाली कोई भी सेवा। जैसा कि आप जानते हैं, एस.एल.एफ. कचरा फेंकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाया गया है, यह न तो एक इमारत है और न ही एक नागरिक संरचना है। इसलिए, सीधे शब्दों में कहें तो अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं, जो अपनी सेवा आय पर सेवा कर का भुगतान कर रही हैं, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्रोतों पर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करने का मतलब है अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाओं के लिए अधिक लागत। उपरोक्त को देखते हुए, क्या सरकार दूसरों को 'स्वच्छ भारत अभियान' का पालन करने के लिए कहने से पहले अपने आंतरिक विभाग (सी.बी.ई.सी.) को व्यवस्थित कर सकती है।

माननीय सभापति: श्री जय प्रकाश नारायण यादव; कृपया तीन मिनट के भीतर समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, हम तो अभी खड़े ही हुए हैं। आपको इस विषय पर बोलने देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप हमें कम से कम पांच मिनट तो बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : हमारे पास समय नहीं है। बी.ए.सी. ने जो डिसाइड किया है, उसके अनुसार ही हमें चलना है।

... *(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति महोदय, कृष्ण भगवान ने अपनी मां से कहा था कि मइया तुम इन्द्र की पूजा मत करो, लेकिन मां नहीं मानी, पिता नहीं माने। जब कृष्ण जी आठ साल के बालक थे, तब उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। उन्होंने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? उस समय इन्द्र भगवान ने अपना प्रकोप दिखाया। हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम अपनी पूरी बात नहीं बोल पायेंगे। इन्द्र भगवान ने अपना सारा प्रकोप दिखाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा कि इन्द्र भगवान को जितना भी घमंड है, उसे प्रकृति तोड़ेगी, पहाड़ तोड़ेगा और जनता तोड़ेगी। उस समय इन्द्र भगवान हारे थे। हमारा कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्रकृति शाश्वत है, निरंतर है। आज मौसम में बदलाव हो रहा है। प्रकृति अजय है और हम उसके जीव हैं। लेकिन आज जीव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, उसके आंचल के नीचे रहना चाहिए, लेकिन आज हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वन, वृक्ष लगाने से हमारे पर्यावरण में सुधार हो सकता है। झील खत्म हो रही हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में झीलों का नुकसान हुआ है, तालाबों का नुकसान हुआ है। पहाड़ रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मालथस थ्योरी लागू हो जाएगी। भूकम्प आया, नेपाल से बिहार तक विनाशकारी लीला हुई। ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हुआ है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में ऐसा हुआ है। बाढ़ के समय सूखा और सूखे के समय बाढ़ आ जाती है।

ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। नवीनतम प्रयोग हो रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि मौसम क्यों बिगड़ रहा है। शहरीकरण हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। बर्फ की चादर खराब होती जा रही है। कार्बन बढ़ता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, हमें पेड़ लगाने हैं। पेड़ हमारा भविष्य है। सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्कूलों में पर्यावरण की पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। पर्यावरण के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होगा, इंस्पेक्टर राज से कुछ ठीक नहीं होगा। वातावरण के सही निर्माण करने से ही राष्ट्र को बेहतर बना सकते हैं। पर्यावरण को ठीक रखना हर आदमी का कर्तव्य है। फसल की बर्बादी हो रही है, जमीन की बर्बादी हो रही है। जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड आ रहा है। जान पर खतरा बन रहा है। कैसे मेक इन इंडिया बनेगा? कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? कैसे स्वस्थ भारत बनेगा? जब तक वन के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी, वन के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी, कुछ ठीक नहीं होगा।

बिहार में बाल्मिकी नगर, भीम बांध, बांका, लक्खीसराय में प्राकृतिक छटा का बहुत प्रभाव है। आज राष्ट्र का पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम भी बिगड़ रहा है। राष्ट्र का पर्यावरण जनता ठीक करेगी और मौसम को हम मिलजुल कर ठीक करेंगे।

कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी।

वन, पर्यावरण, जलवायु का मिजाज बिगड़ रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री धरम वीरा गांधी जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

श्री धर्मवीर गांधी (पटियाला): महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तनों की बात कर रही है, जो धरती माता को खतरे में डालते हैं, तो मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रतिष्ठित सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या बहुत कम है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने इस विषय को कई कोणों से छुआ है। मुझे लगता है कि, उन सभी ने इस विषय को केवल किनारे से छुआ है। मैं इसे अपने संक्षिप्त संबोधन के माध्यम से और इस मुद्दे की मूल बातों के माध्यम से स्पर्श करना चाहूंगा। तथ्य यह है कि विकास का वर्तमान मॉडल, जिसे हम विकास का पूंजीवादी मॉडल कहते हैं, धरती माता और उसके पर्यावरण के साथ सीधे विरोधाभास में आया है।

विकास के पूंजीवादी मॉडल का अर्थ है लाभ। यह मानव के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी निर्दयी है। इसलिए लाभ की अपनी निरंतर खोज में, पूंजीवाद न केवल मानव संसाधनों, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का भी बेरहमी से शोषण करता है। इसने मानव संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, इसने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, इसने हमारी मूल्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है और इसने शिक्षण और चिकित्सा जैसे महान व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया है। इसने इस पृथ्वी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरण क्षरण की मूल समस्या उत्पादन का वर्तमान तरीका है जो प्रकृति के विपरीत है। या तो यह मॉडल बना रहेगा अथवा प्रकृति बनी रहेगी। तो, यह मूल समस्या है, जिसे मैं छूना चाहूंगा और इसे उस कोण से लिया जाना चाहिए।

दूसरा, डॉ. माइकल चैडविक, एक जाने-माने पर्यावरणविद और एक महान पुरस्कार नामांकित व्यक्ति, ने कुछ साल पहले, "इस धरती पर जननी ग्रह की स्थिरता और जनसंख्या वृद्धि" पर एक शिखर सम्मेलन में कहा था कि यह विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जो पर्यावरणीय क्षरण के लिए दोषी हैं, न कि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं

* रिकार्ड नहीं किया गया.

या हमारे जैसे पिछड़े देश। यह धरती माता ग्रह कितना लुप्तप्राय है, इसका सबसे बड़ा पैमाना संसाधन मांग सूचकांक (आर.डी.आई.) पर निर्भर करता है, अर्थात् किसी विशेष देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कितना जोर या दबाव है। भारत का संसाधन मांग सूचकांक 0.25 प्रतिशत है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संसाधन मांग सूचकांक 4.17 प्रतिशत है। वे भारतीय उपभोक्ताओं की तुलना में 17 गुना अधिक खपत करते हैं।

हम, तीसरी दुनिया के देशों के लोग, थर्ड वर्ड सोसाइटी बहुत रूढ़िवादी हैं। मेरी माँ तेल का एक खाली टिन रखती थीं, जो कुछ समय बाद किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए हमारी दुकान में सुरक्षित रहता था। लेकिन 'यूज एंड थ्रो' संस्कृति, जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था की क्लासिक है, भारत में भी आ रही है। इसलिए, हमें अंधी आँखों से या उस गति से विकास के उस मॉडल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था को हमारी संस्कृति के अनुसार और हमारे तौर-तरीके और हमारे स्वदेशी तरीकों के अनुसार आगे ले जाने के लिए हमारे पास अपने स्वयं के नवाचार, हमारे अपने स्वदेशी विचार होने चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि कोपेनहेगन सम्मेलन में, 60 देशों के 20,000 लोगों द्वारा एक विशाल झंडा फहराया गया था, जिसमें महाद्वीपों में यह कहा गया था कि "पर्यावरण के लिए संघर्ष पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष है"।

अगर हमें अपने पर्यावरण को बनाए रखना है, अगर हमें अपनी धरती माता की रक्षा करनी है, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण क्षरण से बचना है और अगर हमें मानवता को बचाना है, तो हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए या हमें विकास के पूंजीवादी मॉडल का बहुत सावधानी से पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इस मंत्रालय के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं तथा चिंताएं भी बहुत हैं। मैं समझता हूं कि चुनौती तो ग्लोबल वार्मिंग की ही बहुत बड़ी है, क्लाइमेट चेंज की है और अनएक्सपेक्टेड जो आपदाएं आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए, जैसे जम्मू-कश्मीर में पहले बाढ़ आई और पीछे अभी 14 प्रदेशों में बेमौसमी बारिश हुई। पिछले दिनों में नेपाल, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में भूकम्प से नुकसान हुआ। इन मुश्किलों को भी चुनौतियों के तौर पर लेना होगा।

दूसरे, जो मैं यह समझता हूं कि इस मंत्रालय में एक तरफ तो विकास की बात है और दूसरी ओर मानवीय जिंदगी की बात है। हमें उसको बैलेंस में रखकर चलना होगा। सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण की है। जब प्रदूषण होता है, जैसे हवा में, पानी में, जमीन में और खाद्य पदार्थों में प्रदूषण होता है तथा दूसरी ओर हमें विकास प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करने हैं, जैसे कैमिकल्स से भी प्रदूषण फैलता है, उसको कंट्रोल करना होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जैसे अभी सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना चलाई है, मैं समझता हूं कि अगर यह योजना किसी तरह से पहले चली होती तो काफी नुकसान होने से बचा जा सकता था। कैंसर और जिगर की बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता था। मैं समझता हूं कि विकास के साथ साथ क्लियरेंस की भी बहुत जरूरत पड़ती है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन क्लियरेंस के नाम पर पिछली सरकार में जो ब्लैक-मेलिंग होती रही, उसके कारण बहुत से विकास के काम रुके। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मंत्री जी उसमें रिलेक्सेशन लाए और इस वजह से विकास शुरू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता तो मानवीय जिंदगी को देनी ही चाहिए, किंतु विकास को भी देखने की जरूरत है। इसके लिए कोई अल्टरनेटिव सोचना होगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम सड़क के लिए, फोरेस्ट के लिए क्लियरेंस देते हैं।...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आप ब्लैक-मेलिंग की क्या बात कह रहे हैं? आप विषय पर चर्चा कीजिए।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजर: मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन आपने पूछा है। पहले जो मंत्री थे, उन्होंने मेन क्लियरेंस नहीं दी थी।...(व्यवधान) उसके कारण मंत्रालय से मंत्री जी को हटाना पड़ा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: चंदूमाजरा जी, कृपया सभापति को संबोधित करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गौरव गोगोई : महोदय, ये विषय पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि गलत आरोप लगा रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री गोगोई जी, मैं इसकी जाँच करूँगा। अगर कुछ असंसदीय है तो हम उसे हटा देंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सड़क, अस्पताल, चैक डैम्स आदि चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए जहां भी अल्टरनेटिव फॉरेस्ट लैंड पड़ी हो, उसे दिया जा सकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र सेमी-हिल एरिया है। वहां 40 परसेंट हिस्से में दफा-4, दफा-5 लगी हुई है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात आपको बता सकता हूँ। दूसरे प्रदेशों हिमाचल या उत्तरांचल के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारे वहां अच्छे जंगल नहीं हैं और जमीन खाली पड़ी है। वहां से हमें मिट्टी का एक ढेला भी नहीं उठाने दिया जाता है। जमीन किसान की है लेकिन वह वहां कुछ नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है कि आप दफा-4 और दफा-5 को उठा कर कंडीशन लगा सकते हैं कि इस एरिया में 40 परसेंट फॉरेस्ट लगाना जरूरी होगा, प्लान्टेशन करनी जरूरी होगी, 60 परसेंट प्लान्टेशन करनी जरूरी होगी। आप किसान से एफिडेविट ले सकते हैं। बाकी जमीन पर आप उसे खेती करने दीजिए, क्योंकि जमीन अब कम हो रही है। चेयरमैन साहब यह महत्वपूर्ण बात है, हमारे

पंजाब में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। हमारे पास जमीन कम है। हम उस जमीन को कल्टीवेट कर पाएं, उसके लिए आप दोनों में बैलेंस रख कर कोई उपाय कर लें।

दूसरी बात, जंगलों में से जंगली जानवर निकल कर मैदान में आ जाते हैं। किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है और जानी नुकसान भी हो रहा है। जब हम कृषि मंत्री जी के पास जाते हैं, हमारी पंजाब सरकार ने एक योजना बना कर भेजी तो कृषि मंत्रालय ने कहा कि फॉरेस्ट मंत्रालय के पास जाओ। हमने दो सौ करोड़ रुपये की मांग की है कि या तो फॉरेस्ट को इनसर्किल कर लो या फिर किसानों के खेतों को इनसर्किल करने के लिए जालीदार तार लगाने के लिए कम से कम 50 परसेंट सब्सिडी भारत सरकार दे और 50 परसेंट शेयर पंजाब सरकार दे तो मैं समझता हूं कि किसान भी बच जाएगा और जंगली जानवरों से भी बचाव हो जाएगा। मैं एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विकास के लिए रिलेक्सेशन देकर बैलेंस तरीके से इनवायरमेंट के लिए काम किया है।

[अनुवाद]

***श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर):** हालांकि हमारे पास पर्यावरण और वन का एक अलग मंत्रालय है, लेकिन भारत में पर्यावरण की स्थिति बहुत दयनीय है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम बुरी तरह विफल रहे हैं।

हमारे देश में वायु प्रदूषण बढ़ से बढ़तर हो गया है। भारतीय शहर, जो दुनिया के शहरों का लगभग 1/4 वां हिस्सा हैं, औद्योगिक प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन वाहनों आदि की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

1984 की भोपाल गैस त्रासदी न केवल दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा है, बल्कि 30 वर्षों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली आपदाओं में से एक है, इस दुर्घटना के पीड़ितों को राहत और पर्याप्त मुआवजा अभी भी नहीं मिला है। विनाशकारी गैस रिसाव जिसमें लगभग 25,000 लोग मारे गए और 1.5 लाख अभी भी पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनमें से कई हमेशा के लिए अंधे हो गए हैं। यह एक क्लासिक मामला है जिसमें औद्योगिक सुरक्षा उपाय सबसे खराब कारण साबित हुए हैं और जिसमें तत्कालीन भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। फूल प्रूफ लायबिलिटी एक्ट की कमी के कारण, यू.एस. यूनियन कार्बाइड कंपनी को दुर्घटनाओं के पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने में सक्षम बनाया गया था।

वर्तमान सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी से कोई सबक नहीं सीखा है। परमाणु देयता अधिनियम को हाल ही में एक तंत्र के माध्यम से अमान्य कर दिया गया है जिसके द्वारा "प्रदूषक भुगतान" के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को छोड़ दिया गया है। इसके बजाय सरकार और उसकी एजेंसियां पूरा मुआवजा देंगी।

गोबर के उपले और जलाऊ लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन हर वर्ष अपने जहरीले धुएं के माध्यम से लाखों लोगों की जान लेते हैं। खाना पकाने के ईंधन के रूप में जैव-द्रव्यमान को जलाने से यातायात के धुएं और औद्योगिक धुएं सहित, अन्य सभी वायु प्रदूषकों की तुलना में कार्बन वायु प्रदूषण 3 गुना अधिक होता है। वायु प्रदूषण के कारण, भारतीयों के फेफड़े यूरोपीय लोगों की तुलना में 30% कम कार्य करते हैं। हर साल भारत में

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वायु प्रदूषण के कारण 6.27 लाख समय से पहले मौतें होती हैं, इसके अलावा हृदय रोग, कार्डियो-वैस्कुलर कष्ट, आदि प्रदूषण से संबंधित बीमारियां होती हैं। शहरी क्षेत्रों में यातायात के धुएं से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। फिर भी हम इसकी जाँच करने के लिए पर्याप्त मापदंड नहीं बना सके। दिल्ली के वाहनों में शुद्ध और वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली सी.एन.जी. को अन्य सभी प्रयोगों की तरह पूरा नहीं किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन, सरकार का स्वच्छता अभियान, स्वागत योग्य है। लेकिन जब तक पुनर्चक्रण और बायो डिग्रेडेबिलिटी के माध्यम से अपशिष्ट निपटान के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते हैं, कॉरपोरेट्स को भी शामिल करते हुए स्वच्छता कोष का निर्माण नहीं किया जाता है, यह मिशन एक और प्रचार स्टंट के रूप में समाप्त होगा। साफ-सफाई खराब परिस्थितियों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, खुले में शौच, जो देश के गौरव पर एक कलंक भी है, को पर्याप्त शौचालय उपलब्ध कराकर ही समाप्त किया जा सकता है। साफ-सफाई गरीबों के लिए एक विलासिता है और साफ-सुथरा न रहना उनकी पसंद नहीं है।

पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए वहाँ की प्रजातियों के साथ-साथ वनों का संरक्षण सबसे अधिक आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्संतुलन के विनाशकारी परिणाम होंगे। सड़कों, रेलवे पटरियों और बिजली की लाइनों जैसी रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो जंगलों में लंबे समय तक घुसपैठ करती हैं, बांधों द्वारा जलमग्न होने या खदानों के लिए निकासी के अलावा हमारे जंगलों के लिए एक नया खतरा हैं। ऐसी परियोजनाओं के मानदंडों को धीरे-धीरे कमजोर किया जाता है जिससे जंगलों का गंभीर विनाश, बड़े पैमाने पर भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और अंत में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है। इसलिए, पारिस्थितिकी के विकास और संरक्षण के बीच एक सही संतुलन बनाया जाना चाहिए, जो लंबे समय में टिकाऊ होगा।

मृदा संरक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछली शताब्दी में खेती को तेज करने से मिट्टी का क्षरण हुआ। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें तीव्र खेती की ऐसी ही एक घटना है। मिट्टी के तेजी से कटाव के कारण जी.एम. फसलें टिकाऊ नहीं होती हैं, हालांकि वे प्रारंभिक चरणों में भारी लाभ कमा सकती हैं। यू.एन.ओ.

की एक सम्मानित शाखा, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर ने हाल ही में घोषणा की, कि जी.एम. फसलों में उपयोग किए जाने वाले दो कीटनाशक मेलाथियान और डायज़िनॉन और राउंड अप के ब्रांड नाम में मनसांतो के जड़ी-बूटियों में ग्लाइफोस्टेट कैंसर का कारण बनते हैं। इसलिए, महोदया के मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में जी.एम. फसलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां तक कि फील्ड ट्रायल की भी अनुमति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने एक निष्कर्ष निकाला है कि मिट्टी के विनाश के कारण, दुनिया में औसतन, फसलों को उगाने के लिए केवल 60 साल और हैं। मिट्टी के क्षरण के कारण हर वर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। फसल आवर्तन, जैविक उर्वरकों का उपयोग और पारिस्थितिक रूप से सूचित प्रौद्योगिकी को एक साथ समूहबद्ध किया जाता है, जिसे कृषि पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है, रसायनों के उपयोग और मिट्टी के क्षरण को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।

तमिलनाडु सरकार ने मीथेन परियोजना को प्रभावी ढंग से रोक दिया, जिसने पूरे कावेरी डेल्टा को रेगिस्तान में बदल दिया होता। डी.एम.के. जिसने केंद्र की अनुमति से परियोजना को अपने शासन के तहत लाया, जिसमें वह एक भागीदार था, अब किसानों के कड़े प्रतिरोध के कारण परियोजना का विरोध कर रहा है।

हमारे जैसे उज्ज्वल धूप वाले देश में, हमने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया है। यहां तक कि गोबर जैसे बायोमास ईंधन का उपयोग बायोगैस, एक स्वच्छ और अधिक दक्ष ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में सबसे आगे रहने का गौरव हासिल किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसकी सराहना की गई है।

एक अन्य प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा सबसे खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग है। यदि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा से अधिक होने दिया जाता है, तो दुनिया को विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यदि लीमा जलवायु सम्मेलन का परिणाम कोई संकेत है, तो सभी संभावनाओं में, दिसंबर 2015 में पेरिस शिखर सम्मेलन पर समझौता एक कमजोर और गंभीर रूप से मुआवजा होगा जो सदी के अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का कारण बनेगा, विकासशील देशों को गंभीर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का

खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले क्योटो प्रोटोकॉल में अपनाए गए समानता सिद्धांत को गंभीर रूप से नष्ट कर दिया जाएगा और विकसित देश हुक से बच जाएंगे और हमेशा के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से बच जाएंगे।

क्योटो प्रोटोकॉल में अपनाए गए "सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं" के सिद्धांत में यह परिकल्पना की गई है कि जिन उद्योगपति देशों ने वातावरण को अधिकतम प्रदूषित किया है, उनके पास इसे भुनाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है जबकि अन्य देशों के पास कार्बन भंडारण को कम करने की समान जिम्मेदारी है। प्रमुख कार्बन उत्सर्जक, यू.एस.ए. एकमात्र देश है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को अस्वीकार कर दिया। अमेरिका किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को लगातार खारिज कर रहा है और क्योटो प्रोटोकॉल को ध्वस्त करने के लिए लगभग सब कुछ कर रहा है। विकसित देश अधिकांश वायुमंडलीय स्थान पर कब्जा कर लेंगे, जिससे विकासशील देशों में विकास की बहुत कम गुंजाइश रह जाएगी। इक्विटी का सिद्धांत अशिष्ट रूप से असंगत है। इसके बजाय अमेरिका द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाएँ 2020 से पेरिस समझौते का आधार बनेंगी। अमेरिका और विकसित देशों द्वारा वर्तमान कम प्रतिज्ञाएँ ग्रह को 3°-4°सेल्सियस तक ले जाने के लिए निश्चित हैं।

स्वैच्छिक प्रतिज्ञाएं इच्छित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (आई.एन.डी.सी.) का मुख्य आधार हैं, जो अमेरिका और उसके समूहों द्वारा एक नया वैकल्पिक सूत्र है। इन आई.एन.डी.सी. में 2020 के बाद की अवधि में विकासशील देशों को उनके शमन और अनुकूलन कार्यों में सहायता करने के लिए वित्तीय योगदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंधित तत्व शामिल नहीं हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल के मूल सिद्धांतों को अपनाए गए पाठ में शामिल किया गया है और ऐसा लगता है कि इसने लीमा सम्मेलन में सभी पक्षों को संतुष्ट किया है। भारत के पर्यावरण और वन मंत्री जी ने रिकॉर्ड में कहा है कि हमारी सभी चिंताओं का समाधान किया गया था और हमें वह मिला जो हम चाहते थे। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। "विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में"-वाक्यांश को क्योटो प्रोटोकॉल के सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत में जोड़ा गया है, जो विभिन्न व्याख्याओं के लिए जगह छोड़ता है, जो एक के

लिए उपयुक्त है। यह विकृति अमेरिका-चीन द्विपक्षीय समझौते में भी पाई जाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि उभरता हुआ समझौता आई.एन.डी.सी.(वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान) के इर्द-गिर्द केंद्रित होने जा रहा है। अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश करने का एक विचलित पाठ्यक्रम अपना रहा है, जिसे चीन और भारत ने अब तक अपनाए गए अव्यवहार्य एकतरफा दृष्टिकोण के बजाय अपनाया है। यह कदम किसी भी बहुपक्षीय समझौते को रद्द करने के लिए है जो अमेरिका के हित में नहीं होगा चीन की तरह, भारत ने भी अमेरिका के साथ इस खतरनाक सांठगांठ पर कदम रखा है चीन और भारत जैसे विकासशील देश आगे बढ़कर नेतृत्व करने में विफल रहे हैं और विकसित देशों के साथ विश्वासघात किया है।

चीन के लिए वर्तमान प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर, अमेरिका के लिए 17.6 टन की तुलना में 6.5 टन सी.ओ.₂ के बराबर है और अनुमानों के अनुसार, यह 2030 में अपने चरम वर्ष तक लगभग 12-14 टन होगा, जो प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय के समान है। यह औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक दो टन सीमा से काफी ऊपर है।

अंततः विकासशील देशों के दृष्टिकोण से लीमा सम्मेलन की स्पष्ट सफलता केवल प्रतीकात्मक है। मूल मसौदे में केवल रूप में सुधार किया गया है, लेकिन सार में नहीं। विकासशील देश, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोग, जो पहले से ही औद्योगीकरण शुरू होने के बाद से 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के प्रभावों का सामना कर रहे हैं, गंभीर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का खामियाजा भुगतेंगे। भारत के समुद्र तटीय महानगर कोलकाता, चेन्नई और मुंबई डूबने के खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 20 वीं शताब्दी में समुद्र के स्तर में कुल वृद्धि 0.17 मीटर है।

इसलिए भारत सरकार को पर्यावरण और जलवायु उपेक्षा की आपदा से उबरने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोजना होगा।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और वर्तमान की चुनौतियों और विकास के बीच में किस प्रकार से साम्यता लाई जाए, यह भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसको उन्हें देखना है। इस मंत्रालय के अंतर्गत वनस्पति, जीव-जंतु, वन और वन्य जीवों के संरक्षण और सर्वेक्षण का, प्रदूषण की रोकथाम और उसके नियंत्रण, वनरोपण और उसकी पुनरुत्पत्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा पशुओं के कल्याण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

अपराह्न 04.45 बजे

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

[हिन्दी] महोदय, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं- एक प्राकृतिक कारण है और दूसरा मानवीय कारण है। अंधाधुंध वनों की कटाई, अवैज्ञानिक विकास की सोच और परिवहन तंत्र के कारण भी वायुमंडलीय उत्सर्जन के कारण भी वायुमंडल में गैस और एरोसॉल्स एकत्रित हो जाते हैं, जिसने ग्रीन हाऊस इफेक्ट की स्थिति पैदा की है और इससे धरती का तापमान भी बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने एक चुनौती है क्योंकि समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, चक्रवाती तूफानों में तेजी आना, आज पूरा उत्तर भारत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में है। किसानों की फसलें उससे प्रभावित हुई हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अपने-आप में एक गंभीर चुनौती बनकर आया है। हम सबके सामने महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि लगातार वनों का क्षेत्रफल घटा है। कभी यह रेशियो 60 : 40 का था, आज इस देश में मात्र 23 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल ही वनों से आच्छादित है। स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के सामने यह एक गंभीर चुनौती है और ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हैं, इनको हम एक-दूसरे से अलग करके नहीं रख सकते हैं। जो अच्छी बातें सामने आयी हैं, वे ये हैं कि अगले पाँच वर्ष के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए मंत्रालय के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ है कि 1.7 लाख

करोड़ रुपये सरकारी बैंकों से सोलर और विंड एनर्जी पर खर्च करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है, मुझे लगता है कि इससे लगभग 34 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। आज सुबह ही माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि सरकार का टारगेट वर्ष 2022 तक एक लाख मेगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन और लगभग 60 हजार मेगावाट विंड एनर्जी के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इससे कोल पर निर्भरता कम होगी और उसका प्रभाव पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा क्योंकि जब हम कोल पर निर्भरता कम करेंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छी स्थिति होगी। ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने एक चुनौती है। यदि समय रहते हमने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो दुनिया की बड़ी आबादी भुखमरी की चपेट में आने वाली है और इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत जैसे विकासशील देश पर पड़ने वाला है क्योंकि आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद देश में गरीबी की स्थिति 32 प्रतिशत तक बनी हुई है।

हम विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के चलते इस देश के अंदर तापमान में वृद्धि की बात आ रही है। उस पर भी हमें अवश्य विचार करना चाहिए और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो हाल में ही खास तौर से अभी हम लोगों को देखने को मिले हैं। हमारे हिमालयन क्षेत्र ने अभी दो वर्ष पूर्व केदारनाथ में उत्तराखण्ड की त्रासदी को झेला है। अभी पूरा उत्तर भारत जलवायु परिवर्तन, जिसमें आति वृष्टि, ओलावृष्टि की परिस्थितियों को किसानों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेपाल में 25 अप्रैल को आये हुए भूकम्प की त्रासदी से न केवल उत्तर भारत, बल्कि पूरा नेपाल आज तबाही की कहानी रच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हिमालयन परिक्षेत्र के पर्यावरण के बारे में अवश्य विचार होना चाहिए क्योंकि अगर हिमालय की परिस्थिति के विषय को अभी से हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो भारत के उत्तरी क्षेत्र के लिए हिमालय से आने वाली सदानीरा नदियों के कारण रेगिस्तान बनने का खतरा आने वाले समय में पैदा हो सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नमामि गंगे के रूप में गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में जो बातें कही हैं, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए आवश्यक है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को हम प्रदूषण से मुक्त रखें और उनकी अविरलता को बनाए रखें। उसके लिए वहां से जितनी नदिया आती हैं, मैं पूर्वी

उत्तर प्रदेश को देखता हूं, वहां पर आमी नदी, राहेहिनी नदी, क्वानो नदी आदि सभी नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं, उनका जल पीने लायक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। जब तक हम लोग उद्योगों का कचरा नदियों में जाने से नहीं रोकेंगे, जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। हमारी नगरपालिकाओं ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या तो लगाए नहीं हैं, अगर लगाए हैं तो उनका उपयोग नहीं कर पाती हैं और पूरा कचरा नदियों में जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। हमें इन नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की कार्रवाई को करना होगा क्योंकि जल प्रदूषण तमाम प्रकार की जल जनित बीमारियों का कारण बन रहा है। प्रति वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग हजारों बच्चों को इंसेफेलाइटिस बीमारी की वजह से खोते हैं। इस बीमारी का जो नया विषाणु वर्तमान में चिन्हित हुआ है, उसका कारण प्रदूषित जल है। राज्य सरकार की प्रदूषण के लिए बनाई गयी इकाइयां और बोर्ड हैं, उनको प्रभावी भूमिका निभानी होगी।

प्राकृतिक झीलों के संरक्षण के लिए जो एन.एल.सी.पी. की योजना है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ राशि उपलब्ध कराई थी। उसी प्रकार से, रामगढ़ ताल की तर्ज पर बखिरा झील है, महेशरा ताल है, इन सभी के संरक्षण की भी योजना इसमें बनाई जाए...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। मंत्री जी को जवाब देना होगा। बहस बंदी वहाँ है। इसलिये, मुझे खेद है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अंत में, जो वन्य ग्राम हैं, उनके निवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था हो। पिछली बार एक योजना बनी थी कि 75 वर्ष से अधिक समय से वन्य ग्रामों में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनके लिए सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे 56 गांव हैं, उनका पुनर्वास अभी नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में रामगढ़ ताल, बखिरा ताल एवं अन्य तालों के संरक्षण के साथ-साथ उन वन्य ग्रामों के निवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए भी प्रावधान किया जाए।

[अनुवाद]

***श्री पी. आर. सुन्दरम (नमक्कल):** मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से वर्ष 2015-16 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

पिछले वर्षों के विपरीत, केंद्र सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन को कम कर दिया है और पिछले वर्षों की तुलना में आवंटन 2014 में 2043 करोड़ रुपये से लगभग 8 प्रतिशत घटकर इस वर्ष 1,681.60 करोड़ रुपये हो गया है।

यह मेरे लिए विचित्र बात है कि सरकार ने वनों की रक्षा के लिए कुल बजट का सिर्फ एक प्रतिशत आवंटित किया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 23 प्रतिशत है और इसे बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

प्रोजेक्ट टाइगर जैसी कुछ अन्य संबद्ध योजनाओं के लिए आवंटन में भी भारी कमी की गई है। आजकल, दूषित वातावरण, प्रदूषण और इससे संबंधित बीमारियां सरकार के लिए मुख्य चिंताएँ हैं। विशेष रूप से, हाल के वर्षों में मेट्रो शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। इसलिए, सरकार को देश भर में प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम और राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा दी गई सीमित प्रतिक्रिया के बारे में भी चिंतित हूँ, और आवंटन क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 150 करोड़ रुपये से बहुत कम है।

वन भूमि का क्षेत्रफल वर्ष दर वर्ष कम हो रहा है। इस स्थिति में, सरकार को प्रभावी वनों की कटाई कार्यक्रम शुरू करने चाहिए और राज्य सरकारों को वनों की कटाई के लिए आवश्यक निधि का आवंटन करने

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का लक्ष्य देना चाहिए। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए वन भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा किया जा रहा है जो राष्ट्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहे हैं।

वन क्षेत्रों में गिरावट से देश में सबसे खराब जलवायु की स्थिति पैदा होगी जो बदले में कृषि, उद्योगों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए, मैं सरकार से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के लिए आवंटन बढ़ाने और वनीकरण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने का आग्रह करना चाहूंगा।

यहां मैं आंध्र प्रदेश के कुछ गुलाब की लकड़ी के तस्करो की पुलिस के साथ सांठगांठ के बारे में सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। गुलाब की लकड़ी की तस्करी न्यूनतम 1000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और विभिन्न देशों में विशेष रूप से जापान और चीन में तस्करी की जाती है। लेकिन, कुछ निर्दोष लोगों को गुलाब की लकड़ी के तस्करो के लाभ के लिए पीड़ित किया जाता है और पीड़ितों को तमिलनाडु राज्य लकड़ी काटने के काम के बहाने ले जाता है। आम तौर पर, आंध्र पुलिस द्वारा मारे जाने वाले लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो हर दिन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन, किसी रहस्यमय व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए, इन लोगों को मार दिया गया। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही गुलाब की दुर्लभ प्रजातियों को तस्करो और माफियाओं से बचाने के लिए कार्रवाई की जाए।

संक्षेप में, सरकार को बजटीय आवंटन बढ़ाना चाहिए और देश में वन क्षेत्रों के विकास के लिए समान महत्व देना चाहिए। मौजूदा वन क्षेत्रों की रक्षा करने के साथ-साथ कुछ दुर्लभ प्रजातियों को समाज विरोधी कारकों के चंगुल से बचाना समय की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):** मैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। बजट में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सरकार ने जो पहल की है, वह स्वागत योग्य है। विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग से विशेष चिंतित है। हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस विषय पर उल्लेखनीय कार्य करने की योजना बनाई है। सौ स्मार्ट शहरों की स्थापना व नवीनीकरण सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसके प्रमुख अंग के रूप में है। हमें अपनी योजनाएं इस प्रकार से बनानी चाहिए कि विकासशील भारत को विकास की गति के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। सोलर मिशन को 20 हजार मेगावाट से 5 गुना बढ़ाना एक लाख मेगावाट करना इस विषय पर एक सार्थक कदम है।

वन के क्षेत्र का घटना चिंताजनक है। इसमें से मनरेगा को जोड़कर जो नया प्रावधान किया गया है, उससे वन क्षेत्र को बढ़ाने व उन्हें संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। देश में अवैध वनों के कटान को रोकने की और पर्याप्त योजना बनाए जाने व निचले स्तर के तंत्र को सक्रिय करने की जरूरत है। वन संरक्षण अधिनियम के कारण कोई विकास परियोजनाएं लंबित भी न हो तथा इसका कड़ाई से पालन भी हो, इस पर संतुलन रखने की जरूरत है। आज प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या है। कानून के दायरे में इसे लाने के बाद भी यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इससे जमीन अनुपजाऊ हो रही है तथा जानवर प्लास्टिक को खाकर बीमार होकर मर रहे हैं। जगह-जगह प्लास्टिक के कचरे के ढेर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को प्रभावित करने के साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अस्तु इस ओर सरकार को प्रभावी कदम उठाने की यथाशीघ्र जरूरत है। इसी के साथ, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) :** पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) पर कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं :-

1. गांवों में एम्बुलेंस रोड़ बनाने, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विद्यालय, महिला मंडल व अन्य छोटी-छोटी चीजों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता और गांवों के आस-पास जंगल की जमीनें पड़ी हैं और जमीनों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी इस प्रकार के कामों को भूमि नहीं दे रहे हैं। इसलिए सरकार ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाए कि यदि ग्राम सभा पारित करती है तो सीधे ग्राम पंचायत को यह अधिकार हो कि इन छोटे-छोटे स्थानीय कामों को कोई भी सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता न हो।
2. आज देखने में आ रहा है कि जंगली जानवर किसानों की फसलों को बुरी तरह तबाह कर रहे हैं खासकर बंदर, सुअर, नीलगाय आदि। आवारा पशु भी किसानों की फसलें तबाह कर रहे हैं। इस कारण किसानों ने अपनी खेती करनी बंद कर दी है। दूसरी ओर आवारा कुत्ते भी आज काफी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इन्हीं आवारा कुत्तों ने लोगों को काटना शुरू कर दिया है। गत दिनों आवारा कुत्तों ने कई स्थानों पर हमला कर उन्हें जखमी किया है। एक बच्ची जो शौच के लिए खेतों में गई थी उसे बुरी तरह काट कर मार दिया और उसे पूरी तरह खा लिया। कई स्थानों पर पागल कुत्तों का भारी आतंक है और वहां का प्रशासन उन्हें मार नहीं सकते, कानूनी तौर से। इसलिए सरकार को [अनुवाद] वन्य पशु (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [हिन्दी] को संशोधित करना चाहिए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):** भारत में ग्रामीण समुदाय जिसका जीवन-आधार वन कृषि व उसके उत्पादन पर निर्भर है, अक्सर कानूनी मान्यता के बिना इस संसाधन का प्रभावी विनियोग-व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में समुदायिक भागीदारी में भी अलग-अलग कानूनी प्रावधान हैं। बिना लाभ भूमि ग्राम सहकारी समिति को आवंटित की जा सकती है। चारागाह भूमि पर पंचायत का हक है और वन भूमि पर सामुदायिक प्रबंधन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1990 और हाल में आए वनाधिकार अधिनियम, 2006 है। देश की लगभग दस प्रतिशत भूमि के साथ राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य चार भौगोलिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है। पश्चिमी रेतीले क्षेत्र अरावली पर्वत माला और अन्य पहाड़ियां और पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार। राज्य में स्थित अरावली पर्वतमाला देश को अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के दो जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित करती है।

कृषि और पशुपालन राजस्थान में आजीविका के प्रमुख स्रोत होने के कारण एक खास महत्व रखते हैं तथा आजीविका संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक का कार्य करते हैं। राज्य के वर्तमान भू-उपयोग में लगभग 20 प्रतिशत भूमि बंजर श्रेणी में मानी जाती है, जो कि काफी खेद का विषय है। राष्ट्रीय वन नीति अनुसार जहाँ 33 प्रतिशत जमीन वन भूमि होनी चाहिए, वहीं राज्य में वर्तमान में वन क्षेत्र मात्र 7.71 प्रतिशत है, जो पारिस्थितिकीय मानदंड के अनुसार अपर्याप्त है। चारागाह भूमि कुल क्षेत्र का सिर्फ 4.95 प्रतिशत है, जो राज्य के 540.34 लाख जानवरों के पोषण के लिए अपर्याप्त है। राज्य में 7.35 प्रतिशत जमीन बंजर है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती। कृषि योग्य भूमि मात्र 13.88 प्रतिशत है तथा 6.77 प्रतिशत भूमि अन्य श्रेणी में आती है।

अपने चारों ओर के परिवेश को हमने इस कदर छोड़ा है कि बात अगर पर्यावरण की उठती है तो प्रदूषण का सवाल अपने आप ही आगे आ जाता है। मानव एवं सभी प्रकार के जीवन को ढोने वाली पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल मचाने वाली समस्या और प्रदूषण के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं: (क) विलुप्तप्राय जंतुओं का संकट, (ख) जल प्रदूषण, (ग) वायु प्रदूषण, (घ) स्थल एवं मृदा प्रदूषण, और (ड.) ध्वनि प्रदूषण

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जल ही जीवन है वाली कहावत और इसकी सच्चाई में अगर हम विश्वास करते हों तो जलीय पर्यावरण की पवित्रता का दायित्व भी हमारा ही है। पिछले दशकों में विश्व की जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि, शहरी जीवन जीने के प्रति ललक तथा विकास के नाम पर जल में बहाई जाने वाली गंदगी की नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़कर निश्चित हो लेते हैं। नतीजतन, समुद्री जल का बहुत बड़ा भाग और विश्व की लगभग सभी नदियां आज जीव संसार के लिए जीवन की तरलता नहीं बल्कि मौत की कठोरता लेकर बह रही हैं। यही स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र की भी है। सम्पूर्ण जिले में लूनी बेसिन का एक भाग है। उसकी सहायक जवाईं सूकड़ी खारी बाण्डी तथा साग नदियां जिले के प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। दुर्भाग्य से यह सभी नदियां बरसाती है जो मानसून के बाद सूख जाती हैं जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है।

हानिकारक गैसों, आतिसूक्ष्म धूलकण या सूक्ष्म रूप से विसरित तरल पदार्थों का वायुमंडल में उसके अपसरन की दर से ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसके बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। मानवीय छेड़छाड़ या प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर इसका विस्तार स्थानीय, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा ग्लोबल रूप में हो रहा है। हालात यही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बाजार से शुद्ध ऑक्सीजन का पैकेट लेकर हम सांस लेते फिरेंगे। कुछ वर्ष पूर्व क्या हम यह सोचते थे कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा?

समाज के विकास की घड़ी की सुईयों को थोड़ा पीछे की ओर घुमाकर देखें तो कुछ दशक पूर्व इस स्थल में प्रदूषण का कहीं कोई नामो-निशान नहीं था। औद्योगिक कचड़ों तथा प्लास्टिक कहे जाने चमत्कारिक वैज्ञानिक खोज ने अपना यह जलवा दिखलाया है कि शहर की कौन पूछे। आज गांव में भी आप चले जाएं तो स्थल प्रदूषण की बानगी दिखाई दे जाएगी। टीन के डब्बे, प्लास्टिक, कागज, सीसे की बनी छोटी वस्तुओं से लेकर लोहे की बनी कार या ट्रक तक के कचड़ों का एक स्थान पर जमाव या बिखराव भूमि प्रदूषण कर रहे हैं।

मैं राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र से आता हूं। माउंट आबू गुजरात और राजस्थान का दिल है। जैसे भारत के लिए कश्मीर है उसी तरह से माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर है। आज माउंट आबू में सबसे बड़ी

समस्या 1982 से वहां नक्शे के लिए कोई परमिशन नहीं मिली है। जो वहां के रहने वाले हैं, उनका परिवार बढ़ा हो रहा है लेकिन मकान नहीं बना सकते हैं। ईको सेंसिटिव जोन बना कर हमारे साथ अन्याय किया गया है। जब ईको सेंसिटिव जोन से छुट्टी मिली और मास्टर प्लान बनाने की बात हुई तो पहले की सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी वहां हजारों पर्यटक आते हैं। वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान लागू करके माउंट आबू की जो रौनक है, उसे वापस लौटाई जाए। वहां के लोगों को रहने के लिए जो घर बनाने की परमिशन चाहिए। यह घर की बात है और घर नहीं होगा तो सभी बेघर हो जाएंगे। वर्ष 1982 के बाद से जिन बच्चों ने जन्म लिया है, उसे रहने के लिए तो घर चाहिए। 1982 से अब तक कोई परमिशन नहीं मिल रही है, बच्चे कहां रहेंगे? क्या कोई सास-ससुर और बाप-बेटा साथ में रह पाएंगे। मेरा निवेदन है कि जो भी कार्यवाही हो, वह जल्द से जल्द लागू हो।

आज दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम स्वरूप दुनियाभर के लोग प्रकृति का कहर झेलने को मजबूर हैं। 23 साल पहले 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था। तभी से जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन अब तक हम इन खतरों से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति पर क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है। जो भी निर्णय हुए, केवल सैद्धान्तिक स्तर पर ही टिके हैं। उनका जमीनी धरातल पर उतरना बाकी है। आज गर्मियों में तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिना मौसम के बरसात हो जा रही है। प्रकृति के साथ लगातार छेड़-छाड़ के कारण अत्यधिक बाढ़, सूखा, भूकम्प, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अपना विकराल रूप दिखा रही हैं। आज धरती के बारे में अत्यधिक गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा):** मैं वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारा पृथ्वी के प्रति प्रेम, आत्मचिंतन और संजीदगी का दिन है। पृथ्वी हमारे जीवन का केन्द्र है इसलिए इसे महज एक दिन के लिए करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं की जा सकती।

पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण क्षरण हुआ और इसके नवें दशक तक विकासशील देशों और छठे, सातवें दशक तक विकसित देशों में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या शायद ही देखी गई हो। आठवें दशक के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को गंभीर मामले के रूप में देखना शुरू हुआ।

ओजोन परत के क्षरण के अलावा पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण क्षरण भी देखा गया है। लगभग 80 प्रतिशत उपभोग की वस्तुएं मसलन जीवाश्म ईंधन से लेकर स्टील ऐल्युमिनियम, तांबा जेसे खनिजों और कार जैसी चीजों का उपभोग विकसित देशों की 20 प्रतिशत आबादी कर रही है। आज इन्हीं सबका नतीजा जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के रूप में दिखाई दे रहा है।

आज मानव लोभ से धरती के संसाधनों का क्षय और क्षरण जारी है। प्राणवायु दमघोटू हो चली है। अमृत समान जल मौतों और रोगों की बड़ी वजह बन चुका है और हमारी पृथ्वी को विषैले रसायन से नष्ट होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और आकार में इजाफा हो रहा है। धरती पर बढ़ते इन खतरों ने जन जीवन पर अपना दुष्परिणाम डालना शुरू किया तो इंसानों को चेतना आई।

अंतरराष्ट्रीय संस्था आई.पी.सी.सी. के अध्ययन के मुताबिक धरती का औसत तापमान 1.4 फारेनहाइट बढ़ चुका है। अगले सौ साल के दौरान इसके बढ़कर 2 से 11.5 फारेनहाइट होने का अनुमान है। इसी तरह धीरे-धीरे पृथ्वी गरम हो रही है। यह मामूली वृद्धि जलवायु और मौसम प्रणाली में व्यापक रूप से विनाशकारी बदलाव ला सकती है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह बढ़ता हुआ तापमान केवल इंसानी जीवन पर ही असर डाल रहा हो ऐसा नहीं है। इसका असर हमारी फसलों पर भी पड़ रहा है। 5-15 प्रतिशत तक फसल की पैदावार कम हो रही है। 3-10 प्रतिशत भारी बरसात के दौरान बारिश की मात्रा में वृद्धि जारी है। 5-10 प्रति नदियों के बहाव में कमी है और 200-400 प्रतिशत जंगलों में लगने वाली आग से प्रभावित खतरों में होने वाली वृद्धि है।

मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि यदि पिछली सदी इंसानी जरूरतों के चलते धरती को हुए सर्वाधिक विनाश के लिए जानी जाएगी तो हम आज से ही मिलकर कुछ ऐसा करें कि वर्तमान सदी उन चूकों, उन गलतियों को सुधारने के लिए जानी जाए। इसके साथ ही 15 साल पुराने, जिसके कारण हमारे पर्यावरण और धरती पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर होता है, इन वाहनों पर रोक लगाकर हम अपनी धरती को तोहफा दे सकते हैं।

जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने बीते सप्ताह एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रारम्भ करवाया। अमेरिका, चीन, मैक्सिको और फ्रांस के बाद भारत पांचवां देश बना जहां यह तय होगा कि हवा श्वास लेने लायक है कि नहीं। मेरी मांग है कि दिल्ली की तरह ही हर राज्य में पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कार्बन रहित व न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन पर आधारित तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जैसे कि सोलर सेल। कोयला और अन्य जीवाश्म आधारित ईंधन का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए।

परिवहन, वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ रियायतें देनी चाहिए। निजी वाहनों की संख्या घटाई जानी चाहिए। अक्षय ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। विकसित देशों को आगे आकर विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए।

पर्यावरण के तहत भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। भारत शहरीकरण की ओर बढ़ने की दहलीज पर खड़ा है। 2030 तक भारत में 59 करोड़ लोग बसते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में यू.एन. की महासभा में कहा था कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए। वैश्विक समुदाय, सामूहिक कार्यवाही-समान किन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों के सुंदर संतुलन पर सहमत है। यह हमारे अनवृत्त कार्य का आधार होना चाहिए।

विश्व के प्रथम जलवायु सम्मेलन 1979 में जलवायु परिवर्तन को एक तात्कालिक वैश्विक समस्या के रूप में पहचाना गया। 1992 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय नामक अंतरराष्ट्रीय संधि में कई देश शामिल हुए और 1997 में क्योटो सम्मेलन में अतिरिक्त विकसित देशों के लिए उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों वाली बाध्यता हुई।

ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री स्तर, बर्फ की चादर, वर्षा को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन पर सुझाए गए महत्वपूर्ण साधनों में कार्बन करों का प्रारम्भिक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में 2010 में कोयले पर एक स्वच्छ ऊर्जा उपकरण का प्रारम्भ किया है। 2015-16 के बजट में भी यह 100 से बढ़ाकर 200 करने के प्रस्ताव की मैं सराहना करती हूँ।

पर्यावरण संबंधित प्रक्रियाओं की ऑनलाइन मंजूरी करने का केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा, वह भी एक सराहनीय कदम है। जिससे निवेश बढ़ेगा, निवेश से रोजगार बढ़ेगा। पर्यावरण कानूनों में बदलाव के तहत पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. समिति की अध्यक्षता में उच्च समिति गठित की गई। उस समिति ने पर्यावरण मंजूरी के संबंध में देश में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए सिफारिश की है और मंत्रालय वन शब्द की परिभाषा भी पुनः तय करने पर विचार कर रहा है। यह भी एक सराहनीय सोच है, मैं इसका स्वागत करता हूँ।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई.ई.ए.) के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन वर्ष 2013 की तुलना में घटकर 2014 में 323 अरब टन रह गया है। वह भी अच्छे भविष्य को प्रतीत करता है। ग्रीन इंडिया मिशन के साथ मनरेगा को जोड़ने की बात भी अत्यंत प्रभावी कदम है। जिससे फारेस्ट एरिया बढ़ेगा और

रोजगार भी बढ़ेगा। हरियाली की हिफाजत करनी अत्यंत जरूरी है क्योंकि सभी जगह सीमेंट, कंक्रीट के कारण हरे भरे पेड़ सूख जाने का मामला सामने आया है।

वन मंत्री जी आपके द्वारा हरित कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात भी धन्यवाद की पात्र है। प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में वन मंत्रालय के प्रयास सराहनीय हैं।

दुनिया के तमाम जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। उन वैज्ञानिकों का आकलन है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को थामा न गया तो जल्दी ही दुनिया गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ जाएगी।

2020 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 100 स्मार्ट सिटी हासिल करने के लिए सरकार की ओर से की गई पहल एक उल्लेखनीय कदम है। सितम्बर 2015 में पेरिस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होने की उम्मीद है जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक नजरिया बदलने का आह्वान किया है वह भी समयोचित है। उन्होंने कहा कि दुनिया को कार्बन ब्रेडिट की सोच छोड़ कर ग्रीन क्रेडिट की सोच अपनानी चाहिए। सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं वाले देशों का एक कंसोर्टियम (संघ) बनाने की जरूरत है। आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर उससे ऊर्जा संरक्षण को व्यापक ढंग से समाहित करने पर बल भी दिया है।

मेरी मांग है कि गुजरात राज्य में स्टेचू ऑफ यूनिटी सुलपानेश्वर अभ्यारण को इको सेन्सेटिव जोन बनाया जाए। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण शुरू हो गया है। इसका पास सुलपानेश्वर अभ्यारण पड़ता है। वहां वन्य प्राणी अभ्यारण की सरहद से 10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा कदमों के तहत सुलपानेश्वर अभ्यारण जो पहले दुमखल रीच अभ्यारण के नाम से जाना जाता था। उसका क्षेत्रफल 150.8 के वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 607.7 वर्ग किलोमीटर किया गया है। गुजरात सरकार के वन पर्यावरण विभाग ने सुलपानेश्वर अभ्यारण को इको सेंसेटिव जोन जाहिर करने की दरखास्त 2010 और 2013, 2015 में की है।

सी.एन.जी. की पाइप लाइन की मंजूरी के तहत राज्य सरकार को सत्ता मुहैया कराई जाए। जो भोपाल से कार्यवाही होती है, उस क्षेत्रीय आफिस का बोझ हल्का करने के लिए गुजरात सरकार को सत्ता दी जाए।

एशियाटिक लायन का संरक्षण करने के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता मिले, जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है। इसके तहत सूचित प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कुल धनराशि 150 करोड़ की है। इसमें केन्द्र का हिस्सा 135 करोड़ की दरखास्त भारत सरकार के पास लंबित है।

अभ्यारण क्षेत्र के आस-पास इको सेंसेटिव जोन जाहिर करने की गुजरात सरकार की कुल 12 दरखास्तें (थोल, बालाराम-अंबाजी, बरडा, सुलपानेश्वर, बेलावदर, गोगा, खिचडिया, जेसोल, पोरबंदर, रामपरा, हिंगोलगढ़, नल सरोवर) 2013-14 तक केन्द्र सरकार को पत्राचार हुआ है। लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर निर्णय लेना अत्यंत जरूरी है।

रिकवरी प्लान फॉर ग्रेट इंडियन बसटर्ड (गोराड) के लिए केन्द्रीय आर्थिक धनराशि 187.13 करोड़ की दरखास्त केन्द्र में निर्णय के लिए पेंडिंग है। यह दरखास्त 10 साल के लिए तैयार की गई है, जिसमें गोराड पक्षी का संरक्षण, संवर्धन, आवास सुधारण, राष्ट्रीय स्तर का संवर्धन केन्द्र बनाना, इको डवलपमेंट तथा उनके लिए पानी और खुराक की सुविधा के तहत आर्थिक सहायता मंजूर की जाए।

गिर वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन जोन आम्बरडी के लिए सी.जेड.ए. की मंजूरी के लिए 2013-14 से केन्द्र सरकार के पास दरखास्त लंबित है। इस पर कार्यवाही की जाए।

मेरा यह सुझाव है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,71,82 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.48 प्रतिशत है उसको बढ़ाकर 33 प्रतिशत लाने का प्रावधान करना चाहिए।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, पिछले साल भी जब हमने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की थी तो हरियाणा के विषय में एक ही चीज आई थी कि यमुना नदी में बहुत ज्यादा तादाद में सिल्ट आता है। निरंतर उसकी माइनिंग की जरूरत है, अन्यथा फ्लड एरिया हरियाणा की ओर बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माइनिंग खुली पड़ी है। उस समय भी निवेदन किया गया था कि आपकी मिनिस्ट्री अगर एन.ओ.सी. देने में थोड़ा सा ईज-आउट कर देगी तो हमारे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी तर्ज पर फरीदाबाद, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, भिवानी जिलों में जो नॉन-अरावली हिल्स हैं, वहां पर भी कई ऐसे एरियाज हैं जो अरावली में नहीं आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन मात्र आपकी गाइडलाइन्स में जो सख्ती है, हार्डनेस है, उसके कारण आज बहुत से युवा बेरोजगार बैठे हैं। बहुत से ऐसे एरियाज हैं, जहां पर सात रुपये से दस रुपये फुट के रेट पर बजरी मिलती थी, सिर्फ आपकी एन.ओ.सी. के कारण आज वह 40 रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां एन.ओ.सी. के प्रति थोड़ी सी लिनिएन्सी आप बरतें, जिससे जो बीस-तीस हजार युवा यू.पी.ए. की सरकार में पिछले दस साल में बेरोजगार हुए थे, वे दोबारा अपने हाथ में रोजगार ले पाएं। आपकी सरकार के एक साल हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर आपकी सरकार गाइडलाइन्स को कुछ ईजी करे। जहां नेचर की बात आती है, हम हर रोज टी.वी. पर देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी है।

मैं निवेदन करूंगा और एक आइडिया आपको देता हूँ कि जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एकाध गली ऐसी होती है जहां गाड़ियां नहीं आती-जातीं, ट्रैफिक फ्री जोन रहता है। उसी तरह से दिल्ली में भी ट्रायल बेस पर आप ऐसी कोई गली या सड़क लें, जहां जीरो ट्रैफिक हो। लोग वहां पैदल जाकर क्लीन इन्वायरन्मेंट में चाहे शॉपिंग करें या भोजन करें।

जहां तक पर्यावरण की बात आती है हरियाणा में पूरे देश में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है। अगर लैंड की परसेंटेज कंपेयर करें तो लगभग सवा तीन प्रतिशत एरिया हरियाणा का फॉरेस्ट के रूप में है। मैं निवेदन करूंगा

कि वहां आपकी सरकार है, उसे गाइडलाइंस दें, जिससे प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने का काम किया जा सके। वहां काफी एरिया ऐसा है, जो फॉरेस्ट एरिया के तहत विकसित हो सकता है, मगर वहां सरकार का ध्यान नहीं गया है। अभी मेरे से पूर्व स्वामी जी भी पर्यावरण के बारे में बताने रहे थे। जहां हम सोलर और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का बहुत सा एरिया रेगिस्तानी है। आपकी प्रदेश सरकार द्वारा वहां रिनूवल एनर्जी के प्लांट्स लगाए जाएं, जिसके तहत वहां के लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जो वेस्ट या डेजर्टेड लैंड है, रिनूवल एनर्जी जेनरेट हो सकती है और जो हम थर्मल के माध्यम से प्रदूषण बढ़ाते हैं, उससे भी आपकी सरकार को फायदा हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक और आइडिया देना चाहूंगा। हमारे यहां फॉरेस्ट टूरिज्म आपकी हरियाणा सरकार द्वारा एक भी जगह नहीं बनाया गया। वहां मोरनी हिल्स हैं, शिवालिक की डाउन हिल्स हैं, जैसे आपने काजीरंगा और अन्य जगहों पर ट्यूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हैं, मोरनी को भी विकसित करने का काम करे, जिसके तहत मोरनी के आसपास पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी टूरिज्म के आधार पर फायदा होगा।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू.) की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जनता दल (यू.) ऐसी पार्टी है, जिसने विगत सात पहले यह तय किया था कि यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है और उसकी फोटो लेकर जाता है, तब ही वह इसका सदस्य बनता है। इसलिए बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पर्यावरण की चिंता पहले से की है। आज पूरी धरती पर पर्यावरण का खतरा साफ नज़र आ रहा है और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। उससे कैसे निपटा जाए, यह हमारे सामने चिंता का विषय है।

हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि वृक्ष धरती की अमूल्य धरोहर हैं और लगातार हम उसे काटते चले गए। सरकार ने इसे गम्भीरता से कभी नहीं लिया। प्रकृति की भयावह स्थिति आज भूकम्प की त्रासदी के रूप में, चक्रवर्ती तूफान के रूप में, ओले के रूप में, बेमौसम बरसात और बेमौसम बाढ़-सुखाड़ के रूप में हम सब पर लगातार प्रहार कर रही है। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो हम सब कुछ तहस-नहस होता देखते

रहते हैं। अगर हम वृक्षों को सहेज कर रखें तो प्रकृति में आ रहे बदलाव को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी कामयाब हो सकते हैं।

महोदय, सब यह भी जानते हैं कि वन की कटाई के कारण जीव-जंतुओं पर असर हुआ है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। आज बाघ, हाथी और चील आदि जीव-जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए जो भी कदम उठा रही है, यहां मंत्री जी बैठ हुए हैं, उनकी तरफ से भी इस बारे में सुझाव आए हैं कि कैसे हम 2020 तक पर्यावरण को सुधार कर अपने इस विशाल देश को आगे ले जाएंगे। मैं भी इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आज तमाम राज्यों की समुचित मदद करने की जरूरत है। आज ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज ऋतुएं आगे-पीछे हो रही हैं। जिसके कारण जाड़ा, गर्मी या बरसात समय से पहले या समय के बाद आ रही हैं। जैव विविधता संरक्षण की ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें और भी सुधार करने की जरूरत है। वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध करने की जरूरत है। देश की नदियों और झीलों में जो प्रदूषण है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

अपराह्न 05.00 बजे

[हिन्दी] सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वृक्षारोपण है। सरकार इन परियोजनाओं में हमारे नवयुवकों को जोड़कर कार्यक्रम चलाए ताकि प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ स्थानीय युवकों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हों। मेरा सुझाव होगा कि एन.एच. और रेलवे लाइन्स के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है।

अंत में मेरा सुझाव होगा कि सरकार देश के नवयुवकों को इस कार्यक्रम से जोड़े और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी(हैदराबाद): महोदय, सरकार ने पहले ही एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की प्रतिवेदन को लागू करना शुरू कर दिया है। यह टी.एस.आर. सुब्रमण्यम प्रतिवेदन अपनी अनिवार्य समीक्षा से परे चली गई है। इसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण और वन अधिनियमों सहित हरित कानूनों की, समीक्षा और पूर्ण सुधार का आह्वान किया है। अगर टी.एस.आर. सुब्रमण्यम प्रतिवेदन लागू हो जाती है, हमारे वन क्षेत्र का 97 प्रतिशत खनन के लिए खोल दिया जाएगा और केवल तीन प्रतिशत ही बचेगा। क्या समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल मुद्दों के संबंध में सरकार का यही संघीय दृष्टिकोण है?

महोदय, सरकार ने कहा है कि उद्योगों को मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन अनुपालन की सख्त निगरानी होगी। पर्यावरण मंत्रालय को पिछले वर्ष की तुलना में 500 रुपये कम मिले हैं। उनके दस क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारियों के अधीन हैं। पर्यावरणीय मानदंडों के संबंध में किस तरह का सख्त अनुपालन होगा? मानव शक्ति बढ़ाने और धन प्रदान करने के बजाय, अब सरकार पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में उद्योगों द्वारा तीसरे पक्ष और स्व-सत्यापन पर चर्चा कर रही है। यह प्रधानमंत्री के 'शून्य प्रभाव और शून्य दोष' के मंत्र को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है, जिसके तहत विनिर्माण का मतलब होगा कि हम एक देश के रूप में प्रभावों की निगरानी करना बंद कर देंगे। तो, हमारे पास कोई नहीं होगा।

महोदय, हरित भारत मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम था कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए हमारे प्रयास क्या हैं। इसके लिए हजारों करोड़ रुपये की जरूरत है, लेकिन उन्होंने 64 करोड़ रुपये दिए हैं।

उन्होंने महत्वपूर्ण नदियों की सफाई के लिए 294 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 40 करोड़ रुपये दिए हैं। यह उनके द्वारा उनके संरक्षण के लिए दी गई राशि है। यह एक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता है।

धन की अल्पता एक अलग बात है, लेकिन सरकार के पास राजनीतिक इरादे या स्पष्टता भी नहीं है। सरकार ने कहा कि वे गंगा नदी के पर्यावरण-नाजुक क्षेत्र में किसी भी हाइड्रो-डैम को बनने नहीं देंगे। अब, वे अदालत में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक साल के व्यापक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है और वे बांधों को बनने देंगे। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने विश्व बैंक को अपना बयान नहीं दिया है कि वे सहमति खंड के खिलाफ हैं जो वन भूमि लेने पर ग्राम सभा से आवश्यक है। उन्होंने विश्व बैंक को एक लिखित दस्तावेज दिया है। क्या यह भी सच नहीं है कि इस सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनजातीय मंत्रालय को एक मसौदा आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राम सभा से सहमति खंड की आवश्यकता नहीं है? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे यह अंतर क्यों पैदा कर रहे हैं जब अनुसूची वी.ए. कहता है कि सब कुछ वन क्षेत्र है? यह इस सरकार का दोहरापन है कि मंत्री बाहर कुछ कहते हैं और विश्व बैंक को दिए गए मसौदा आदेश और लिखित प्रस्तुतियाँ पूरी तरह से अलग बात कहती हैं।

यह सरकार रोजगार पैदा करने के वादे पर आई थी। ऐसा क्यों है कि, उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहचाने गए 675 उद्योगों में से 310 मुस्लिम अल्पसंख्यक और दलितों के हैं? क्या वे उन्हें बंद करना चाहते हैं? वे चार से पाँच लोगों को काम पर रखते हैं। वे उनसे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, जिसकी लागत 30 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच होगी, जबकि उनका वार्षिक कारोबार 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है। उन्होंने जनता से किस तरह के वादे किए हैं? वे छोटे उद्योगों को बेरोजगार बना रहे हैं, जिनमें दस से बारह लोग काम करते हैं। इसका बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, ये वे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि एक बार जब मंत्री जी खड़े होंगे, तो वे मेरे द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं का जवाब देंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, हम ऐसे समय में पर्यावरण और वन मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान माँग पर चर्चा कर रहे हैं जब नेपाल में भूकंप आया है और 4,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

कल भी, पूरे सभा ने सर्वसम्मति से अपनी चिंता व्यक्त की और आपदा पर दुख भी व्यक्त किया। कोहिमा बांध आपदा से लेकर नेपाल बांध आपदा तक, यह बहुत स्पष्ट है कि हम अपने देश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को महत्व और प्रमुखता नहीं दे रहे हैं।

इसलिए, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, आइए हम भारतीय पर्यावरण परिदृश्य की जांच करें। भारत सरकार 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की सिफारिशों का पूरी तरह से सम्मान कर रही है, और आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे देश में पर्यावरण प्रणाली की रक्षा के लिए एक बहुत मजबूत संवैधानिक प्रणाली के साथ-साथ कानूनी प्रणाली भी है। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1974 का जल अधिनियम, 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1981 का वायु अधिनियम और 1927 का वन अधिनियम, ये छह अधिनियम हमारे देश में पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण के संबंध में पिरामिड विधान हैं।

42^{वें} संशोधन में, हमने संविधान के भाग 3 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में एक नया अनुच्छेद 48 ए. के रूप में शामिल किया है जो सरकार को हमारे देश में वन/वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। एक अन्य नया अनुच्छेद भी 42^{वें} संशोधन, यानी संविधान के, 51 ए के आधार पर शामिल किया गया है - नागरिक के मौलिक कर्तव्य, और यह प्रावधान करते हुए कि पर्यावरण, वन्यजीव और हमारी प्रकृति की रक्षा करना एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। यदि ऐसा है तो, मैं माननीय मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और सरकार से यह जानना चाहूंगा। भारत सरकार की नीति क्या है? मुझे उचित रूप से आशंका है कि पर्यावरण संरक्षण की नीति में भारी बदलाव आया है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में लगभग सभी देश पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए कड़े कानून बना रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, मुझे आशंका है कि पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी करते हुए विकास के नाम पर उद्योग और निवेश को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह आशंका है, जो मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

ऐसा क्यों हो रहा है? यदि हम अनुदान की मांगों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका उद्देश्य किसी भी मुख्य पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना नहीं है, जिसका सामना हमारे देश कर रहा है। कोई रणनीति और दृष्टिकोण नहीं है, और बजट की एकमात्र हरित पहल कोयले पर उपकर को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति टन करना है। यह एकमात्र हरित पहल है, जिसे हम, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट में देख सकते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कोई आवंटन या वित्तीय उपाय नहीं हैं।

इसलिए, सरकार का इरादा बहुत स्पष्ट है, और इरादा तब स्पष्ट हो गया जब श्री ओवैसी ने अभी टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति के बारे में बताया है। सबसे पहले, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करें। यदि टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह इस देश के लिए एक पर्यावरणीय आपदा होगी। यह समिति क्यों नियुक्त की गई है? कृपया समिति का गठन देखें। एक पूर्व कैबिनेट सचिव, श्री टी.एस.आर. सुब्रमण्यम वहाँ हैं, और कोई अन्य पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं है; कोई अनुभवी व्यक्ति वहाँ नहीं है; और ढाई महीने के भीतर उन्होंने बिना किसी परीक्षा, वैज्ञानिक अध्ययन, क्षेत्र भ्रमण विश्लेषण, आदि के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दी है।

महोदय, कृपया संदर्भ की शर्तें देखें। संदर्भ का पहला शब्द यह है कि 'पर्यावरण कानून को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा आवश्यकता को पूरा किया जा सके'। उस समिति के संदर्भ की शर्तें अस्पष्ट, अस्पष्ट और किसी अन्य उद्देश्य या इरादे के साथ हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौजूदा आवश्यकता क्या है? संदर्भ की शर्तों में मौजूदा आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति ने यह पता लगा लिया है कि मौजूदा आवश्यकता क्या है। समिति की प्रतिवेदन में कहा गया है कि 'परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाना'। जहाँ तक सिफारिश का संबंध है, यह वर्तमान आवश्यकता है।

उच्च स्तरीय समिति ने 'व्यवसाय करने में आसानी' के लिए सरकार के हित के अनुरूप काम किया, और तदनुसार कुछ सिफारिशों के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत की। कृपया नंबर एक की सिफारिश देखें। अगर मैं

गलत हूं तो कृपया मुझे सही करें। वन शब्द को फिर से परिभाषित करना होगा? मौजूदा परिभाषा क्या है? मौजूदा परिभाषा यह है कि 'मौजूदा प्राकृतिक वन या कोई भी क्षेत्र, जिसे सरकार द्वारा वन घोषित किया गया है'। सिफारिश से पता चलता है कि 70 प्रतिशत से अधिक चंदवा आवरण वाले क्षेत्रों को वन माना जाना चाहिए। इसका क्या असर होगा? अभी, श्री ओवैसी जी ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण की प्रतिवेदन है। भारतीय राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण की प्रतिवेदन में, यह बहुत स्पष्ट है। यह 2013 की प्रतिवेदन है; कृपया इसे देखें। 70 प्रतिशत से अधिक चंदवा आच्छादित वन क्षेत्र केवल तीन प्रतिशत है। इसका मतलब है कि 97 प्रतिशत घने वन क्षेत्र से बाहर है। इसका असर होगा।

दूसरी सिफारिश एक व्यापक कानून बनाने की है जिसे पर्यावरण कानून प्रबंधन अधिनियम (ई.एल.एम.ए) कहा जाएगा। इरादा क्या है? यह पिछले दशकों के दौरान अदालतों द्वारा जारी किए गए सभी विरोधाभासी निर्णयों और देश में प्रचलित किसी भी पर्यावरण कानून के सभी प्रावधानों पर हावी होगा। उच्चतम न्यायालय के फैसलों या न्यायिक फैसलों को ओवरराइड करने के साथ-साथ पर्यावरण कानूनों के मौजूदा प्रावधानों को ओवरराइड करने के लिए, इस पर्यावरण कानून प्रबंधन अधिनियम को लागू किया जा रहा है।

एक अन्य सिफारिश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समाप्त करने की है। उनके स्थान पर, नए प्राधिकरण अस्तित्व में आएंगे— एक एन.ई.एम.ए. और दूसरा एस.ई.एम.ए. है। एन.ई.एम.ए. का अर्थ है 'राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण' और एस.ई.एम.ए. का अर्थ है 'राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण'। परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए पूरा प्राधिकार और शक्तियां इन दोनों प्राधिकरणों के पास निहित की जा रही हैं।

एन.ई.एम.ए. और एस.ई.एम.ए. के आदेशों के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। केवल समीक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शाखाओं को कम कर दिया गया है और जहां तक एन.जी.टी. का संबंध है, कोई मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहाँ भी, केवल समीक्षा शक्ति है।

अंत में, एक और सिफारिश 'परम सद्भावना' के बारे में बताती है। इसका मतलब है कि परियोजनाओं की मंजूरी के लिए जो भी आवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है, सरकार को परियोजना डेवलपर्स की पूरी सद्भावना के साथ विचार करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है 'व्यवसाय करने में आसानी'। इसके अलावा, *कुल मिलाकर*, उच्च स्तरीय समिति की प्रतिवेदन न्यायिक जांच से सरकारी निर्णय को अलग करने का एक स्पष्ट प्रयास है।

यदि इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह देश के लिए एक आपदा होगी। यह समाज के लिए एक संतुलित पारिस्थितिकी प्रणाली, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के नाम पर, उच्च स्तरीय समिति उद्योग में पूर्ण विश्वास और विश्वास व्यक्त करती है और लोगों के विचारों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों में भारत की प्रतिबद्धता का स्पष्ट उल्लंघन है। माननीय मंत्री और सरकार को मेरा एकमात्र निवेदन है कि इस प्रतिवेदन को स्वीकार न करें। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह प्रतिवेदन को पूरी तरह से *खारिज* कर दे। इन शब्दों के साथ, मुझे बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

***श्री अर्का केशरी देव (कालाहांडी):** मैं ओडिशा के जिला कालाहांडी से आता हूँ। यहाँ कई वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य हैं। मैं वन्य जीवों और पर्यावरण पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे लिए भविष्य और अगली पीढ़ी के लिए हैं। सरकार को ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों और वनों को बचाने और पुनः लगाने के लिए अधिक धन देना चाहिए। सोनाबेड़ा बाघ अभयारण्य नामक एक अभयारण्य है जो माओवादियों द्वारा प्रभावित है और लकड़ी के माफियाओं द्वारा पेड़ों को काटने से परेशान है। इसलिए मैं मंत्री जी से तत्काल कार्रवाई करने और उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए और बल देने का अनुरोध करता हूँ।

आप जानते होंगे कि चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर होती रहती हैं क्योंकि इसका एक कारण पेड़ों की कटाई और अवैध खनन और अवांछित बोरिंग की खुदाई है, इसलिए सरकार को अवैध खनन को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए और लकड़ी माफिया के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए जो पर्यावरण और जंगलों के मुख्य विध्वंसक हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे कालाहांडी जिले में लकड़ी माफियाओं द्वारा नष्ट किए जा रहे सोनाबेड़ा और कारलापत अभयारण्यों के लिए विशेष पैकेज घोषित करें और गश्त बढ़ाएं और हर 10 किलोमीटर पर चेक प्वाइंट बनाएं और सी.आर.पी.एफ. जवानों को दें। ओडिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैंग्रोव वन भितरकनिका है जो मगरमच्छ और पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए मैं सरकार से उन क्षेत्रों को देखने और अभयारण्य की रक्षा करने का अनुरोध करता हूँ।

हाल ही में चिल्का झील में जो भुवनेश्वर से 180 किलोमीटर दूर है और भारत की सबसे बड़ी झील और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य साइबेरियाई देशों से आने वाली प्रवासी बत्तखों की अवैध मछली पकड़ने और अवैध शिकार से प्रभावित हो रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वन्यजीवों और वनों को बचाने में विशेष रुचि ली है और राजमार्गों के अलावा पेड़ लगाने में भी विशेष रुचि ली है। मेरी ओर से मंत्री जी को एक सुझाव है कि सभी ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए आम के बागों और कीमती पेड़ों को उगाने के लिए 30 एकड़ जमीन छोड़ने का नियम बनाया जाए। मैं यह

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भी कहना चाहता हूं कि किसानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें अधिक बगीचे, फलदार पेड़ उगाने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसे कि कॉफी उत्पादकों और चाय उत्पादकों का नियम है, कॉफी उत्पादकों और चाय उत्पादकों के लिए भूमि को सील नहीं किया गया है। सरकार को आम के लिए एक नियम बनाने के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए या किसी भी फल उगाने वाले बगीचे को कुछ एकड़ भूमि तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें बिना किसी सीलिंग के फल उगाने वाले पेड़ और जड़ी-बूटियों के पेड़ लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। गहरे आरक्षित वनों में नक्सलों के लिए एक बड़ी समस्या है। मैं गृह मंत्री जी से माओवादियों से प्रभावित जिलों में और विशेष रूप से पेड़ों को उगाने के लिए और अधिक आई.ए.पी. कोष देने का अनुरोध करता हूं।

श्री सी. एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित कुछ टिप्पणियाँ भी करना चाहूँगा।

नेपाल और उत्तर भारत में वर्तमान भूकंप पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा की हमारी पूरी लापरवाही के कारण मानवता के लिए होने वाली बड़ी आपदाओं की चेतावनी देता है। विकास के नाम पर दुनिया भर की सरकारें विनाशकारी रास्ते पर चल रही हैं। हममें से कोई भी विकास के विरुद्ध नहीं है। हम सभी संधारणीय विकास चाहते हैं जो गरिमा पूर्ण मानव अस्तित्व के लिए न्यूनतम संतोषजनक घटक सुनिश्चित करेगा। दुर्भाग्य से, विकास के समर्थक अपने लाभ को अधिकतम करने की राह पर हैं। हम प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की पूरी तरह से कॉर्पोरेट लूट के युग को देख रहे हैं और इस तरह खुद मानवता का अस्तित्व है।

एन.डी.ए. सरकार और उसके माननीय प्रधानमंत्री, श्री मोदी, और उनकी नीतियाँ भारत की पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। जब आपने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी किया है, तो आपने भारत की पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा के ताबूत पर एक और रेल लगा दी है। कृषि भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण करते समय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में, आपका इरादा पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा का स्पष्ट निषेध है। विशाल औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों के बारे में आपके सभी भव्य विचारों ने इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी प्रभावों के बारे में कभी नहीं सोचा है। जबकि आप भारतीय स्टेट बैंक को श्री अडानी को भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनी कोयला खदान परियोजना के लिए बैंकिंग के इतिहास में सबसे बड़ी राशि पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दों पर पूरी तरह से उपेक्षा का एक और स्पष्ट उदाहरण है।

केरल के बहुसंख्यक लोग अपने राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए प्रस्तावित अरनमुला हवाई अड्डे का विरोध करते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि यह एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिस पर केरल में कम्युनिस्ट, भा.ज.पा., आर.एस.एस. और सभी धार्मिक संगठन एक साथ खड़े हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह अधिकांश लोगों के हितों को न रौंदे। मैं अनुरोध करूँगा कि पर्यावरण सुरक्षा

के लिए इस तरह की अवांछित परियोजना की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको संसद में ही घोषित किया जाए।

[हिन्दी]

***श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) :** किसी भी जीवन को जीने के लिए आक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वनों की आवश्यकता होती है। अतः वन ही जीवन है।

मैं भारत सरकार व माननीय वन मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मांगों में इसकी काफी चिंता की गई है।

सभी माननीय सदस्यों के द्वारा काफी चिंता की जा रही है। प्राकृतिक आपदाये बढ़ रही है। इसमें चिंतन करने की आवश्यकता भी है। मेरा मानना है कि पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश को अपने कुल भू-भाग से 40% भू-भाग को वन क्षेत्र घोषित करना चाहिए। प्रदेशों में वृक्षारोपण अभियान चलाकर प्रकृति संतुलन बनाना आवश्यक है।

मेरा उत्तराखंड प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां देश से भिन्न है। मेरे प्रदेश में लगभग 65% भू-भाग वनों से आच्छादित है। अतः इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को जाता है कि उन्होंने वनों को कटने नहीं दिया। वन क्षेत्र का संरक्षण किया है। इस प्रकार से पूरे भारत की चिंता उत्तराखंड राज्य कर रहा है। इसकी कारण से हिमालय सुरक्षित है। जिससे निकलने वाली नदियों से भारत का बहुत बड़े भू-भाग सिंचित होता है। पीने का पानी मिलता है। भारतीय उपग्रह डेटा के अध्ययन से पता चला है कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 75.779 वर्ग किमी. हिमाच्छादित क्षेत्र में 34.919 हिमनद है। इसी कारण से पूरे देश में ग्लेशियर आधारित नदियां बहती है।

जहां उत्तराखंड राज्य देश को इतना कुछ देता है वहीं विकास से पिछड़ता जा रहा है। इसका कारण है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की सारी नियमावली उत्तराखंड राज्य में सख्ताई (कड़ाई) से पालन की जाती है जिससे विकास में पिछड़ता जा रहा है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राज्य के मोटर मार्ग/स्वास्थ्य अस्पताल/स्कूल भवनों, जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित फाइलें पत्रावली वर्षों-वर्षों तक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उत्तराखंड वासियों को सुविधाएं न मिलने के कारण पिछड़ता जा रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि पर्यावरण व वनों की रक्षा करने वाले लोगों को भी सुविधाएं मिले। इसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः मैं वन एवं पर्यावरण की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):** मैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। [हिन्दी] हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करती हूँ। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों जैसे पर्यावरण संरक्षण, वनस्पति जीव-जन्तु, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण तथा सर्वेक्षण, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, विकृत क्षेत्रों में वन रोपण एवं पुनर्नोत्पत्ति आदि को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए बधाई देती हूँ।

मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू एक शुष्क क्षेत्र है। यहां पर हरित कानूनों को सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए। झुंझुनू में रिन्यूएबल एनर्जी की पूर्ण भौगोलिक संभावनाएं मौजूद हैं, इस कारण यहां सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, को लागू करने के लिए मांग करती हूँ।

वर्तमान दौर में रेडिएशन एक गम्भीर समस्या है अतः आप इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोबाइल टावर्स को पब्लिक एरिया से दूर स्थापित करने के लिए कदम उठाए।

वन एवं पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण जरूरत पानी की होती है। अतः इसके लिए सरकार झुंझुनू को नदियों से जोड़ने के लिए कदम उठाए। नगरपालिका क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से निजात दिलाने के लिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जो भी उचित योजनाएं हैं उनको लागू कराने के लिए मदद करें।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदान माँगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे विरोधी दलों के लोग बहुत सी बातें कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बहुत तेजी से काम क्यों कर रही है? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस हालत में देश हम लोगों को अस्त-व्यस्त स्थिति में मिला था, उसके लिए अगर इतनी तेजी से काम नहीं किया जाए तो परिस्थितियाँ इतनी जल्दी सुधरती नहीं हैं। आज निश्चित रूप से पृथ्वी की जलवायु को लेकर बहुत सारी चिंताएँ हैं। जलवायु हमेशा बदलती है, कुछ प्राकृतिक कारणों से बदलती है, कभी-कभी कटाई, उद्योग और परिवहन के कारण भी वायुमंडल में परिवर्तन आते हैं। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर चिंता है। निश्चित रूप से आज सबसे ज्यादा वही देश ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंतित हैं, जो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम सब जानते हैं कि यूरोप के तथाकथित विकसित देश और स्वयं अमेरिका ने पिछली सदी में जबरदस्त औद्योगिकीकरण करके दुनिया को इस हालत में पहुँचाया है, लेकिन आज वही देश सबसे ज्यादा भारत और चीन के ऊपर पर्यावरण के इस असंतुलन के लिए उंगलियाँ उठा रहे हैं।

मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम कर रही है। अभी मोदी जी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गए थे, उन्होंने अपने भाषण में पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी फ्रांस और कनाडा गये। वहाँ उन्होंने यूरेनियम के आयात के लिए इन दोनों देशों से जो बड़े समझौते किए, वह भारत के पर्यावरण को सुधारने में, जलवायु को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार का सिद्ध होने जा रहा है।

महोदय, हमारे देश में जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना भी हमने बनाई है, जिसमें आठ मिशन को लिया गया है। उसमें एक मिशन के अनुसार हम लोग वृक्षारोपण और वनावरण, जमीन में ज्यादा से ज्यादा वनों का आवरण हो, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। 7 लाख 71 हजार 821 वर्ग किलोमीटर में अभी इस देश में वन हैं, जो कुल भू-भाग का 23.48 प्रतिशत ही है। हमारी सरकार ने मनरेगा को ग्रीन इन्डिया मिशन के तहत जोड़ा है। जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि वर्ष 2020 तक एक करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे 30 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। यह भारत सरकार की योजना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यहाँ पर सरकार से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो वन हैं, वनों के अन्दर बहुत सारे गाँव बसे हुए हैं। जिनमें परम्परागत तरीके से बहुत सारे लोग निवास करते हैं, लेकिन उन गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा नहीं प्राप्त है, जिसके कारण वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। वहाँ सड़कें नहीं बन पा रही हैं, वहाँ पर हैंडपम्प और शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, वहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह माँग है कि उन गाँवों को जो जंगलों में परम्परागत रूप से बसे हैं, उनको राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए। जंगल तथा उसके आसपास जो गाँव बसे हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को घास-फूस, जलौनी लकड़ी और जो वन के उत्पादन होते हैं, उन्हें लेने की छूट दी जाए। उसके साथ-साथ जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा और अपनी जान-माल की रक्षा का अधिकार दिया जाए। जब भी जानवरों के द्वारा घरेलू पशु, गाय-भैंस आदि या मानवों का शिकार होता है, उसका ठीक-ठाक मुआवज़ा दिया जाए। जो फसलें नष्ट हो जाती हैं, उनका मुआवज़ा दिया जाए। पिछले कुछ समय से जो सर्वेक्षण और रिपोर्ट आ रही हैं, वह इशारा करती हैं कि देश और दुनिया की आबो-हवा व जलवायु पर इसका खराब प्रभाव पड़ रहा है, तथा धीरे-धीरे स्थिति भयावह होती जा रही है। परंतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अपने देश की जलवायु के साथ साथ पूरी दुनिया की जलवायु को शुद्ध करने के लिए जो संभव होगा, वे सारे प्रयास करेंगे और ऐसी प्रतिबद्धता हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी दर्शायी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

***श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** आज वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुदान मांगो पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

आज मानवता के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह रूप में खड़ी है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, ऑटोमोबाइल्स के बढ़ते प्रयोग, न्यूक्लियर पदार्थों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, वाहनों से निकलने वाला धुँआ और शोर, कल कारखानों से उठने वाला धुँआ, वन संपदा का विनाश, कीटनाशक औषधियाँ, रासायनिक खाद, आनियोजित व अवैज्ञानिक विकास, विलासी जीवन आदि कारणों से निरंतर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। नित्य जीवन में बढ़ते प्लास्टिक का प्रयोग तथा मानवता का प्रकृति से दूर होते चले जाना इत्यादि कारणों ने समस्या को अत्यंत भयावह बना दिया है। ग्रीन हाउसिंग गैस के उत्सृजन से ओजोन परत को खतरा उत्पन्न हो गया है। संपूर्ण विश्व इस विषय में चिंता व्यक्त कर रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति में पर्यावरण की रक्षा पर विशेष बल दिया जाता था।

पांच भूतों (तत्वों) से सृष्टि का निर्माण होता है। इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। ये हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन तत्वों में जल, वायु व पृथ्वी ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका सीधा-सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। ये दोनों ही हमारे प्रमुख आहार हैं। इसके अतिरिक्त, अन्न, फल, शाक, सब्जी आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में उपस्थित खनिज व रसायनों का प्रभाव इन सभी खाद्य पदार्थों में आता है। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है तथा जैसा मन होता है वैसा ही कर्म होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है आहार-शुद्धो सत्व शुद्धि।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में भूमि को माता कहा गया है। वेद कहता है 'माता भूमि पुत्रोहम् पृथिव्याः।' वेदों में भूमि को माता के समान पवित्र माना गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान से भूमि की पवित्रता के लिए ही है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसी प्रकार जल को पवित्र माना गया है। जल का मुख्य स्रोत नदी है। ऋग्वेद में नदी को भी माता की तरह श्रेष्ठ माना गया है। कहा है 'नद्यो मातृतयाः।' शायद इसी से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा की सफाई का अभियान किया है। वृक्ष भी वायुमंडल की पवित्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को दस पुत्रों के समान माना गया है - कहा है - दशपुत्रसमं तरुः।

इसी पुराण में औषधियों व वनों के विषय में इन्हें नमन किया गया है। वनानां पतये नमः। औषधीनां पतये नमः। वृक्षाणां पतये नमः। अरण्यानां पतये नमः।

वैदिक ऋषियों ने वायु को आहार कहा है। वायु को पिता के समान रक्षा करने वाली कहा गया है। - प्रण आयुषि तारिषत्।

आकाश में शब्द विचरण करते हैं। अतः ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः ध्वनि में पवित्रता तथा नियंत्रण होना भी आवश्यक है।

अथर्ववेद के भूमि सूक्त में इन पंच तत्वों की पवित्रता तथा प्रकृति महत्व पर विशेष बल दिया गया है।

पर्यावरण संतुलन में जीव जंतुओं का भी विशेष महत्व है तथा इन सबकी रक्षा हेतु जंगलों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। प्रकृति के अनुचित दोहन का परिणाम ही है कि नित्य प्रति अकाल, आति वृष्टि, तूफान तथा भूकंप जैसी त्रासदियां हमें झेलनी पड़ रही है। अतः विकास की सोच के साथ-साथ प्रकृति संतुलन पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारत सरकार इस विषय में कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि इस विषय में महत्वपूर्ण कदम है। अतः मानवता की ही नहीं अपितु प्राणी मात्र की रक्षा हेतु वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ध्यान में रखना होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीकर व प्रांत राजस्थान में पर्याप्त वन क्षेत्र है परंतु उसमें वृक्षों का अभाव है। इसके अतिरिक्त जहां वन है वे सुरक्षित नहीं हैं। इन वनों को सुरक्षित करने हेतु तथा गायों की रक्षा हेतु तो अभयारण्य

विकसित किए जावे। वनों में ऐसे वृक्ष लगाये जावें जिनसे पक्षियों को भोजन मिल सके तथा औषधि प्राप्त हो सके जैसे नीम, पीपल, वट, बिल्व, जामुन, हरड़, बहेड़ा, आंवला इत्यादि।

[अनुवाद]

***श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत(जोधपुर):** भारत में कई पर्यावरणीय मुद्दे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरा और प्राकृतिक पर्यावरण का प्रदूषण भारत के लिए सभी चुनौतियां हैं। 1947 से 1995 के बीच स्थिति बदतर थी। 1995 से 2010 के बीच विश्व बैंक के विशेषज्ञों के डेटा संग्रह और पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, भारत ने अपने पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने और अपनी पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करने में दुनिया में सबसे तेजी से प्रगति की है। फिर भी, भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समान पर्यावरणीय गुणवत्ता तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। प्रदूषण भारत के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर बना हुआ है। पर्यावरणीय मुद्दे भारत के रोगों, स्वास्थ्य मुद्दों और दीर्घकालिक आजीविका प्रभाव के प्राथमिक मामलों में से एक हैं।

कुछ लोगों ने पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में आर्थिक विकास को कारण बताया है। अन्य लोगों का मानना है कि भारत के पर्यावरण प्रबंधन में सुधार और देश के प्रदूषण को रोकने के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या भारत के पर्यावरणीय क्षरण का प्राथमिक कारण है। व्यवस्थित अध्ययन इस सिद्धांत को चुनौती देते हैं। जापान, इंग्लैंड और सिंगापुर जैसे देशों के अनुभवजन्य साक्ष्य, जिनमें से प्रत्येक का जनसंख्या घनत्व भारत के समान या उससे अधिक है, फिर भी प्रत्येक का पर्यावरणीय गुणवत्ता भारत की तुलना में काफी बेहतर है, यह सुझाव देते हैं कि जनसंख्या घनत्व भारत के मुद्दों को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक नहीं हो सकता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे वन और भूमि का कृषि क्षरण, संसाधनों की कमी (जल, खनिज वन, रेत, चट्टानें आदि) हैं। पर्यावरण क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता का नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन का नुकसान, गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा।

भारत में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में ईंधन की लकड़ी और बायोमास का बड़े पैमाने पर जलना शामिल है जैसे कि ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में पशुधन से सूखे कचरे, संगठित कचरा और अपशिष्ट हटाने की सेवाओं की कमी, सीवेज उपचार कार्यों की कमी, बाढ़ नियंत्रण और मानसून जल निकासी प्रणाली की कमी, उपभोक्ता कचरे को नदियों में मोड़ना, प्रमुख नदियों के पास दाह संस्कार प्रथाएं, अत्यधिक प्रदूषणकारी पुराने सार्वजनिक परिवहन की सरकार द्वारा अनिवार्य सुरक्षा, और 1950 से 1980 के बीच निर्मित भारत सरकार के स्वामित्व वाले उच्च उत्सर्जन संयंत्रों द्वारा निरंतर संचालन।

वायु प्रदूषण, अपशिष्ट का खराब प्रबंधन, पानी की बढ़ती कमी, गिरते भूजल स्तर, जल प्रदूषण, वनों का संरक्षण और गुणवत्ता, जैव विविधता की हानि और भूमि/मिट्टी का क्षरण आज भारत के सामने आने वाली कुछ प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय मुद्दों और इसके संसाधनों पर दबाव बढ़ाती है।

जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के बारे में अध्ययन और बहस का एक लंबा इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए, एक ब्रिटिश विचारक माल्थस के अनुसार, बढ़ती आबादी कृषि भूमि पर दबाव डालती है, जिससे पर्यावरण का क्षरण होता है, और गरीब के साथ-साथ खराब गुणवत्ता वाली भूमि की खेती को मजबूर किया जाता है। यह पर्यावरणीय क्षरण अंततः कृषि उपज और खाद्य उपलब्धता को कम कर देता है, अकाल और बीमारियों और मृत्यु का कारण बनता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो जाती है।

जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि यह पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता पर दबाव बढ़ा सकती है, इसे वायु, जल और ठोस-अपशिष्ट प्रदूषण के प्रमुख कारण के रूप में भी देखा जाता है। परिणाम, माल्थस के सिद्धांत के अनुसार, एक संतुलन आबादी है जो आय और पर्यावरणीय गुणवत्ता दोनों के निम्न स्तर का आनंद लेती है।

माल्थस ने खराब कानूनों को समाप्त करने के साथ-साथ मानव आबादी के सकारात्मक और निवारक जबरन नियंत्रण का सुझाव दिया।

1798 और 1826 के बीच प्रकाशित माल्थस सिद्धांत का तब से विश्लेषण और आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी विचारक हेनरी जॉर्ज ने माल्थस को खारिज करते हुए अपनी विशिष्ट तीक्ष्णता का अवलोकन किया: "जयहॉक और आदमी दोनों मुर्गियां खाते हैं; लेकिन जितना अधिक जयहॉक, उतना ही कम मुर्गियां, जबकि जितना अधिक पुरुष, उतना ही अधिक मुर्गियां।" इसी तरह, अमेरिकी अर्थशास्त्री जूलियन लिंकन साइमन ने माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास के तथ्यों ने माल्थस और नव-माल्थूसियन की भविष्यवाणियों को त्रुटिपूर्ण साबित किया है। 20वीं शताब्दी में भारी ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप माल्थूसियन तबाही नहीं हुई। संभावित कारणों में शामिल हैं: मानव ज्ञान में वृद्धि, उत्पादकता में तेजी से वृद्धि, नवाचार और ज्ञान का उपयोग, कृषि विधियों में सामान्य सुधार (औद्योगिक/कृषि) कार्य का मशीनीकरण (ट्रैक्टर) गेहूं और अन्य पौधों की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत (हरित क्रांति) फसल कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग।

हाल ही में विद्वानों के लेखों में यह स्वीकार किया गया है कि हालांकि इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण क्षरण में योगदान कर सकती है, लेकिन इसके प्रभावों को आर्थिक विकास और आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पर्यावरण अर्थशास्त्र में अनुसंधान ने पर्यावरण की गुणवत्ता के बीच एक संबंध का खुलासा किया है, जिसे वायु प्रदूषकों की परिवेशी सांद्रता और प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जाता है। यह तथाकथित पर्यावरण कुंजनेट वक्र समानता के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के लगभग 5,000 \$ तक पर्यावरण की गुणवत्ता खराब होती है, और उसके बाद सुधार होता है। इसे सही ठहराने के लिए प्रमुख आवश्यकता तकनीकी को निरंतर अपनाना और संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में उत्पादकता में निरंतर वृद्धि, उद्यमशीलता नवाचार और आर्थिक विस्तार है।

अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि जनसंख्या घनत्व का पर्यावरणीय गुणवत्ता और मानव जीवन की गुणवत्ता से बहुत कम संबंध है। भारत का जनसंख्या घनत्व, 2011 में, लगभग 368 मानव प्रति वर्ग किलोमीटर

था। भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कई देशों में पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ-साथ मानव जीवन की गुणवत्ता भी भारत की तुलना में कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए: सिंगापुर (7148/वर्ग किलोमीटर), हांगकांग (6349/वर्ग किलोमीटर), दक्षिण कोरिया (487/वर्ग किलोमीटर), नीदरलैंड्स (403/वर्ग किलोमीटर), बेल्जियम (355/वर्ग किलोमीटर), इंग्लैंड (395/वर्ग किलोमीटर) और जापान (337/वर्ग किलोमीटर)

भारत में जल प्रदूषण की बड़ी समस्याएं हैं। भारत में सतह और भूजल के प्रदूषण के लिए अनुपचारित सीवेज का निर्वहन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में घरेलू अपशिष्ट जल के उत्पादन और उपचार के बीच एक बड़ा अंतर है। समस्या यह है कि भारत में न केवल पर्याप्त उपचार क्षमता की कमी है, बल्कि यह भी है कि जो सीवेज उपचार संयंत्र मौजूद हैं, वे काम नहीं करते हैं और उनका रखरखाव नहीं किया जाता है। अनुपयुक्त डिजाइन या खराब रखरखाव या संयंत्रों को संचालित करने के लिए विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति की कमी के साथ-साथ अनुपस्थित कर्मचारियों और खराब प्रबंधन के कारण अधिकांश सरकारी स्वामित्व वाले सीवेज उपचार संयंत्र ज्यादातर समय बंद रहते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्ट जल आम तौर पर मिट्टी में रिस जाता है या वाष्पित हो जाता है। असंकलित अपशिष्ट शहरी क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं जो अस्वच्छ परिस्थितियों का कारण बनते हैं और प्रदूषकों को छोड़ते हैं जो सतह और भूजल में रिसते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के 3,119 कस्बों और शहरों में से केवल 209 में आंशिक सीवेज उपचार सुविधाएं हैं, और केवल 8 में पूर्ण अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं हैं। 100 से अधिक भारतीय शहर अनुपचारित सीवेज को सीधे गंगा नदी में डालते हैं। भारत में प्रतिदिन 29000 मिलियन लीटर सीवेज और प्रतिदिन केवल 6000 मिलियन लीटर की उपचार क्षमता के बीच की खाई को पाटने के लिए निवेश की आवश्यकता है।

जल प्रदूषण के अन्य स्रोतों में भारत की नदियों और झीलों के किनारे कृषि अपवाह और छोटे पैमाने के कारखाने शामिल हैं। उत्तर-पश्चिम में कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक नदियों, झीलों और भूजल में पाए गए हैं। मानसून के दौरान बाढ़ भारत की जल प्रदूषण समस्या को और खराब कर देती है, क्योंकि यह सभी प्रकार के ठोस कचरे और दूषित मिट्टी को धोकर नदियों और आर्द्रभूमि में ले जाती है।

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है, जिसके प्रमुख स्रोत ईंधन की लकड़ी और बायोमास जलाना, ईंधन में मिलावट, वाहन उत्सर्जन और यातायात जाम हैं। वायु प्रदूषण भी एशियाई भूरे बादल का मुख्य कारण है, जिसके कारण मानसून में देरी हो रही है। भारत ईंधन लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और ऊर्जा उद्देश्यों के लिए बायोमास का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पारंपरिक ईंधन (ईंधन लकड़ी, फसल अवशेष और गोबर के उपले) ग्रामीण भारत में घरेलू ऊर्जा उपयोग पर हावी है और कुल का लगभग 90% हिस्सा है। शहरी क्षेत्रों में, यह पारंपरिक ईंधन कुल का लगभग 24% है। ईंधन लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और बायोमास के जलाने से हर साल भारत की इनडोर और आउटडोर हवा में 165 करोड़ टन से अधिक दहन उत्पादन होता है। भारत में ये बायोमास आधारित घरेलू चूल्हे भी जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत, उत्तर भारत और पूर्वी पाकिस्तान में मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक वार्षिक फसल जलाने की प्रथा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख मौसमी स्रोत है। लगभग 500 मिलियन टन फसल अवशेष खुले में जलाया जाता है, जिससे धुआं, कालिख, एन.ओ.एक्स., एस.ओ.एक्स., पी.ए.एच. और कण पदार्थ हवा में निकलते हैं। यह जलना पंजाब, दिल्ली जैसे शहरों और पश्चिम बंगाल के माध्यम से नदियों के किनारे प्रमुख जनसंख्या केंद्रों पर सर्दियों के दौरान धुंध और धुंध की समस्याओं का एक प्रमुख कारण पाया गया है। भारत के अन्य राज्यों में, चावल के पुआल और अन्य फसल अवशेषों को खुले में जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है।

वाहनों का उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक अन्य स्रोत है। ईंधन में मिलावट और यातायात जाम और गुणवत्ता के कम घनत्व, प्रति 1000 लोगों पर उच्च गति वाले सड़क नेटवर्क से खराब ईंधन दहन क्षमता के कारण वाहन उत्सर्जन और खराब हो जाता है।

प्रति व्यक्ति आधार पर, भारत कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस का एक छोटा उत्सर्जक है। 2009 में, आई.ई.ए. का अनुमान है कि इसने प्रति व्यक्ति लगभग 1.4 टन गैस का उत्सर्जन किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति व्यक्ति 17 टन की तुलना में, और प्रति व्यक्ति 5.3 टन का विश्व औसत। हालांकि, 2009 में भारत 1.65

जी.टी. प्रति वर्ष के साथ चीन (6.9 जी.टी. प्रति वर्ष) और संयुक्त राज्य अमेरिका (65.2 जी.टी. प्रति वर्ष) के बाद कुल कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक था विश्व की 17 प्रतिशत आबादी के साथ, भारत ने मानव-स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान दिया; जबकि चीन की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1981 में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम पारित किया गया था और इसमें कुछ मापने योग्य सुधार हुए हैं। तथापि, 2012 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ने भारत को 132 देशों में से सबसे खराब सापेक्ष वायु गुणवत्ता के रूप में स्थान दिया।

भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा और कचरा एक आम दृश्य है। यह प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। अकेले भारतीय शहर एक वर्ष में 100 करोड़ टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करते हैं। गली-मोहल्लों में कचरे का ढेर लगा है। सार्वजनिक स्थानों और फुटपाथ को गंदगी और कूड़े से भर दिया जाता है, नदियाँ और नहरें कचरे के ढेर के रूप में काम करती हैं। आंशिक रूप से, भारत का कचरा संकट बढ़ती खपत से है। भारत की कचरे की समस्या भी शासन की आश्चर्यजनक विफलता की ओर इशारा करती है।

2000 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने सभी भारतीय शहरों को एक व्यापक अपशिष्ट-प्रबंधन कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया जिसमें अलग किए गए कचरे का घरेलू संग्रह, पुनर्चक्रण और खाद बनाना शामिल होगा। इन निर्देशों की अनदेखी की गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परिकल्पित प्रकार का कोई भी प्रमुख शहर व्यापक कार्यक्रम नहीं चलाता है।

वास्तव में, भारत के उच्चतम न्यायालय के अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण निर्देश को भूल जाओ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का अनुमान है कि भारत में 40 प्रतिशत तक नगरपालिका अपशिष्ट केवल असंकलित रहता है। यहां तक कि चिकित्सा अपशिष्ट, सैद्धांतिक रूप से कड़े नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके लिए अस्पतालों को भस्मक संचालित करने की आवश्यकता होती है, नियमित रूप से नगरपालिका के कचरे के साथ डंप किया जाता है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत के लगभग आधे चिकित्सा

अपशिष्ट का अनुचित तरीके से निपटान किया जाता है। भारतीय शहरों और कस्बों में नगर पालिकाओं में अपशिष्ट संग्रह कर्मचारी हैं। हालांकि, ये संघबद्ध सरकारी कर्मचारी हैं और उनके कार्य प्रदर्शन को न तो मापा जाता है और न ही निगरानी की जाती है।

भारत के प्रमुख शहरों के पास कुछ ठोस कचरा लैंडफिल हैं जो ओवरफ्लो हो रहे हैं और खराब तरीके से प्रबंधित हैं। वे मक्खियों, मच्छरों, तिलचट्टे, चूहों और अन्य कीटों जैसे रोग वाहक के लिए ग्रीनहाउस उत्सर्जन और प्रजनन स्थलों के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। 2011 में, कई भारतीय शहरों ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड और जापान में उपयोग की जाने वाली कचरे से ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली शहर के कचरे की समस्या को बिजली संसाधन में बदलने के उद्देश्य से दो भस्मक परियोजनाओं को लागू कर रही है। इन संयंत्रों का शहर की अधिकता अनुपचारित कचरे और बिजली की कमी की पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वागत किया जा रहा है। उनका उन लोगों द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है जो जल प्रदूषण, स्वच्छता की समस्याओं को रोकने और सड़े हुए कचरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन का उत्पादन करते हैं। अपशिष्ट संग्रह श्रमिकों और स्थानीय संघों द्वारा इन परियोजनाओं का विरोध किया जा रहा है, जिन्हें डर है कि बदलती तकनीक उन्हें अपनी आजीविका और जीवन शैली से वंचित कर सकती है।

कचरे से ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ, पुणे, महाराष्ट्र जैसे कुछ शहर और कस्बे कचरे के निपटान के लिए प्रतिस्पर्धा और ठोस कचरा संग्रह, सड़क की सफाई संचालन और जैव-खनन के निजीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि सरकारी निजी भागीदारी, भारतीय संदर्भ में, ठोस कचरा प्रबंधन में अधिक उपयोगी है। इस अध्ययन के अनुसार, सरकार और नगर निगमों को ठोस कचरे के संग्रह, परिवहन और पृथक्करण और निपटान के माध्यम से पी.पी.पी. आधारित स्थानीय प्रबंध को प्रोत्साहित करना चाहिए।

लगातार वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता दुरुपयोग न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का एक बड़ा मुद्दा है। यह हमारी संचयी जिम्मेदारी है जिसे हम सभी को इस युग में समझना

होगा कि हमें प्रकृति को परेशान किए बिना या अपनी आने वाली पीढ़ियों को कम से कम परेशान किए बिना स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। यहां हमें इस बात की खुशी है कि 1990 से 2000 तक, एफ.ए.ओ. ने पाया कि भारत दुनिया में वन कवरेज में पांचवां सबसे बड़ा लाभकर्ता था; जबकि 2000 से 2010 तक, एफ.ए.ओ. भारत को वन कवरेज में तीसरा सबसे बड़ा लाभकर्ता मानता है, लेकिन फिर भी हमें पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी को बचाने के लिए जुनून के साथ मीलें चलना होगा।

[हिन्दी]

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** अगर हमारे देश की फॉरेस्ट विभाग की समस्याओं को देखा जाए तो जहां तक मेरी जानकारी है हमारे देश में 20.55 प्रतिशत विस्तार कवर होता है। जबकि आवश्यकता 33 प्रतिशत की होती है। अपने देश में वन्य उत्पादन की जो डिमांड है उससे उत्पादन कम होता है। जैसे कि अपने जंगलों की वार्षिक पैदावार 0.5 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर है जबकि अमरीका में 1.25 क्यूबिक हेक्टर और जापान में 1.8 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर और फ्रांस में 3.9 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर है। इस कारण से जो वन्य चीजों की कटाई होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। मेरा मान्यवर मंत्री महोदय से आग्रह है कि वन्य पेदाशों को बढ़ाने हेतु एवं उसके ऊपर का अवलंबन कम करने हेतु प्रयास किए जाए। साथ ही साथ, वन्य क्षेत्र में उनको मुख्य ग्रामीण एवं शहरी विस्तार से जोड़ने हेतु उचित प्रबंध किए जाए। साथ ही वन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के अनुरूप उत्पादन एवं चीजों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए।

वन्य क्षेत्र में इतनी बारिश होती है वह आम तौर पर पता ही नहीं चलता। जिसके कारण वह पानी जब एक साथ बहता है तो पुर की नौबत आती है। जिसका अनुभव पिछले दिनों में हो चुका है और वन्य संपदा का भी काफी नुकसान हमें झेलना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि वन्य विस्तारों में गेज स्टेशनों जैसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए ताकि ज्यादा बारिश के बाद होने वाली तबाही से बचा जा सके।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे देश का बहुत ही बड़ी मात्रा में वन्य संपत्ति का नुकसान वन में लगने वाली आग से होता है। मेरा सुझाव है कि वन में रहने वाले एवं आस-पास रहने वाले लोगों को इस विषय में शिक्षित और जागृत किया जाए। जिस तरह से आदमी बीमार होता है उसी प्रकार पेड़-पौधे भी और वन्य जीव जन्तु भी बीमारी का शिकार होते हैं। उस का ध्यान में रखते हुए संशोधन, मैपिंग एवं व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। साथ ही साथ, वनों के संरक्षण हेतु ज्यादा से ज्यादा विज्ञान का सहारा लेकर व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। वन में रहने वाले लोगों को उनके आस-पास के पेड़-पौधों को रख-रखाव, उस के प्रोडक्ट के ऊपर अधिकार का शिक्षण एवं लाइसेन्स देना चाहिए। ताकि वन में रहने वाला व्यक्ति ही वन का संरक्षक बने।

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण) : श्री उपाध्यक्ष, महोदय, मुझे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

हमारे अस्तित्व के लिए पर्यावरण और वनों की रक्षा करना आवश्यक है। जब तक हम अपने वनों, वन्यजीवों, जल निकायों की रक्षा नहीं करते और प्रदूषण को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हमारे पास अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, भारत में वनों और पर्यावरण की रक्षा करने में कई चुनौतियां हैं। पर्याप्त बजट के बिना, चुनौती बड़ी हो गई है। महोदय, मैं अपनी मातृभाषा कन्नड़ में अपना भाषण जारी रखना चाहूंगा।

*महोदय, मैं कर्नाटक राज्य की समस्याओं की ओर माननीय पर्यावरण और वन मंत्री और सभा का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, बजट पेश करते हुए माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि 14^{वें} वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय अनुदान के हस्तांतरण में 10% की वृद्धि की है। तदनुसार, कर्नाटक राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में 24,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अगर हम केंद्र प्रायोजित

* मूल रूप से कन्नड़ में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

योजनाओं के तहत किए गए आवंटन को देखें तो मेरे राज्य को इस वर्ष लगभग 8146 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह विभिन्न केंद्र प्रायोजित चल रही योजनाओं के लिए धन के आवंटन में कमी के कारण है। अब राज्य सरकार पर काम पूरा करने के लिए उन सभी कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने का बोझ है। इस तरह से कर्नाटक को 14^{वें} वित्त आयोग की सिफारिशों से लाभ नहीं हुआ है, लेकिन भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कर्नाटक राज्य में प्रचुर मात्रा में वन और वन्यजीव संसाधन हैं। मैं निधियों के आवंटन में कटौती के प्रभाव के बारे में सभी विवरण देना चाहता हूँ। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इन सभी आंकड़ों के विवरण में नहीं जा रहा हूँ। हालांकि मैं सभा के पटल पर कुछ तथ्यों का उल्लेख करूंगा। नवीनतम बाघ गणना से पता चलता है कि कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा बाघ कर्नाटक राज्य में बाघों की आबादी में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। लेकिन बाघ परियोजना के लिए आवंटन 25% कम हो गया है। 2015-16 के बजट में, परियोजना बाघ के लिए आपने केवल 136.46 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कर्नाटक सहित देश में बाघों की आबादी के संरक्षण और संरक्षण के लिए आवंटन बढ़ाएं।

महोदय, मेरा अगला बिंदु वन सर्वेक्षण के लिए आवंटन के बारे में है। इस बजट में वन सर्वेक्षण के लिए 17.61 रु. करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जबकि वर्ष 2014-15 में यह 20.39 करोड़ रुपये था। देश में राजस्व और वन भूमि के बीच सीमाओं के स्पष्ट सीमांकन के अभाव में भूमि के मुद्दों पर किसानों, राजस्व और वन अधिकारियों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। किसान और आदिवासी बिना किसी गलती के पीड़ित हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे को हमेशा के लिए हल करने के लिए राजस्व और वन दोनों विभागों को शामिल करते हुए एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाए। 17.61 करोड़ रुपये के अल्प आवंटन से यह संभव नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि राजस्व और वन भूमि की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण के लिए आवंटन बढ़ाएं।

महोदय, मैं यू.पी.ए. सरकार द्वारा पारित बहुत महत्वपूर्ण कानून के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वन अधिकार अधिनियम-2006 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (**वन अधिकारों** की मान्यता) **अधिनियम, 2006**, यह श्रीमती सोनिया गांधी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार द्वारा लाया गया वन कानून का एक प्रमुख हिस्सा है। हमारी सरकार ने दशकों से वनों पर निर्भर हजारों वनवासियों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति और गरीब लोगों की आजीविका के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया है। अब एन.डी.ए सरकार वनवासियों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून के प्रावधानों में अनियमितताओं को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

महोदय, लगभग 2, 60,000 गरीब लोगों ने दशकों तक वन भूमि पर अपने कृषि क्षेत्र के रूप में दावा किया था। इसमें से केवल 6,800 लोगों को ही उन भूमि का अधिकार दिया गया था। शेष आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान एन.डी.ए. सरकार गरीब लोगों और किसानों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, बल्कि निजी दलों और कॉरपोरेट का पक्ष ले रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह किसान विरोधी और जनविरोधी सरकार है। यह बहुत चिंता का विषय है कि सरकार इन मुद्दों पर इच्छुक नहीं है और यह सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया है जो मुझसे पहले बोल चुके हैं। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह सतर्कता निगरानी समिति (वी.एम.सी.) के तहत इस अधिनियम को लागू करने के लिए कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थी लाभान्वित हों।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी को जवाब देना होगा। हमें देर हो रही है।

श्री डी. के. सुरेश: महोदय, मैं हमारे अन्नदाता, किसानों की आजीविका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ टिप्पणियाँ कर रहा हूँ। कृपया मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कुछ और समय दें।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मंत्री, अपना जवाब देना शुरू कर सकते हैं।

श्री डी. के. सुरेश: अपने जंगल को बचाने के लिए, हमें उन किसानों की पीड़ा को कम करने की आवश्यकता है जो जंगल पर निर्भर हैं। महोदय, किसानों, वनवासियों और आदिवासियों की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह वनवासियों को बिना किसी और देरी के भूमि अधिकार प्रदान करे।

महोदय, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाएँ हैं। विशेष रूप से जंगली सूअर के खतरे ने कर्नाटक में तबाही मचा दी है। जंगली सूअर खड़ी फसलों को नष्ट कर देते हैं और किसानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह बहुत चिंता का विषय है कि सरकार ने जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नष्ट करने की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं किया है। जंगली सूअर को वन्यजीव अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है भले ही किसी किसान को जंगली सूअर के खतरे के कारण पीड़ित होने पर क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने और जंगली सूअर के हमले से फसल के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

इसी तरह भालू के हमले और सांप के काटने से पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने का विचार किए बिना, चाहे घटनाएँ कहीं भी हों।

महोदय, माशीर मछली के संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि शिवनसमुद्र और मेकेदातु कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं, जो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से होकर बहती है। यह व्यापक रूप से प्रसिद्ध माशीर मछली के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (डब्ल्यू.ए.एस.आई.) ने कई दशकों से इस क्षेत्र में माशीर और अन्य जंगली जानवरों की रक्षा की है। पिछले दशक में दुनिया भर से लोग माशीर खेल मछली पकड़ने के लिए आते थे। यह स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता था और सरकार को राजस्व भी देता था। अब, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य बन गया है और वन विभाग ने क्षेत्र में माशीर मछली पकड़ने के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस मुद्दे पर गौर करे और माशीर मछली

पकड़ने को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। आजकल शहरी क्षेत्रों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अनियोजित विस्तार पूरे देश में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहा है। इन मुद्दों से निपटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक धन दिया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, बेंगलोर शहर के पास दो नदियाँ हैं, वृषभावती और दक्षिण पिनकिनी नदियाँ। बेंगलोर शहर से निकलने वाला सारा कचरा और सीवेज इन नदियों में चला जाता है। इसके परिणामस्वरूप इन जल में सीसा/पारा की मात्रा देखी जाती है। तथापि, मंत्रालय द्वारा इन नदियों की पहचान प्रदूषित नदियों के रूप में नहीं की गई है। इन नदियों के कायाकल्प के लिए आपको धन उपलब्ध कराना होगा।

महोदय, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते समय अथवा अपने पशुओं को चराते समय जंगली जानवरों द्वारा लोगों की हत्या की घटनाएं होती हैं। ऐसे पीड़ितों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। वन अधिकारी यह कहते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति देने से इनकार करते हैं कि वन क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इस संयोजन में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वन अधिकारियों ने मवेशियों और भेड़ों को चराने और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति दी थी। जब जंगली जानवरों के हमले से लोगों की मौत की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो वही वन अधिकारी यह कहते हुए क्षतिपूर्ति से इनकार करते हैं कि यह संरक्षित क्षेत्र में होता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विचार करने और जंगलों में जंगली जानवरों के हमलों के कारण जान गंवाने वाले लोगों को क्षतिपूर्ति देने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में अपने मवेशियों के चारे और चराई के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि जंगली जानवरों के हमले के कारण जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजा 2 लाख रुपये तय किया गया है। महोदय, यह बहुत अपर्याप्त है और इसलिए मैं केंद्र सरकार से जंगली जानवरों के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजे को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का आग्रह करता हूँ।

महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि बेंगलुरु में बन्नेरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पास हक्की-पीक्की आदिवासी कॉलोनी है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में है। इस कॉलोनी के आदिवासियों को लगभग 360 एकड़

जमीन 50-60 साल पहले आवंटित की गई है। हालांकि वन और राजस्व अधिकारियों दोनों के अभिलेख में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। आज तक इन आदिवासियों के पास अपनी भूमि पर दावा करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, जिसका वे दशकों से आनंद ले रहे हैं। अब वन अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस मुद्दे पर गौर करने और आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री जी को कई पत्र लिखे।

माननीय उपाध्यक्ष: कटौती प्रस्ताव भी हैं। आप पहले ही पाँच मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री डी.के. सुरेश: महोदय, महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार, जो बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उक्त कॉलोनी के पास स्थित रागिहल्ली गांव का चयन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री डी. के. सुरेश : महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात कर रहा हूँ। कृपया मुझे अपना भाषण पूरा करने दें।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, वे समापन कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री डी. के. सुरेश: महोदय, मैं केंद्र सरकार से हक्की-पीक्की कॉलोनी में रहने वाले आदिवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

हमारे देश में, 18 राज्य ऐसे हैं जहां बाघ हैं। 1973 से बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि नवगठित पशु कल्याण बोर्ड शेर को राष्ट्रीय पशु के रूप में अनुशंसित कर रहा है। शेर केवल गुजरात में पाया जाता है। भारत केवल गुजरात के बारे में नहीं है। इसलिए, कृपया इस मामले को देखें।

धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

***एडवोकेट जॉइस जॉर्ज (इडुक्की):** पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वनों की रक्षा के महत्व और आवश्यकता को देखते हुए, 12वीं योजना के दौरान मंत्रालय के लिए 17,874 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है जो पिछली योजना के 79% से अधिक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10,724.24 करोड़ रुपये के सापेक्ष केवल 6903 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं, जबकि वास्तविक उपयोग केवल 5200 करोड़ रुपये ही हुआ है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं के व्यापक कारणों के लिए धन आवंटित करने में अनिच्छुक है तथा मंत्रालय आवंटित धन का उपयोग करने के प्रति उदासीन है।

जब हम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू.एन.एफ.सी.सी.) के तहत 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से इस वर्ष के अंत में पेरिस कन्वेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश विशेष रूप से स्वदेशी लोगों, किसानों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लाभ के लिए कार्बन बाजारों के उपयोग के संबंध में स्पष्टता लाने की अधिक आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, कार्बन व्यापार के बाजार आधारित तंत्र के तहत, विकसित राष्ट्र हमारे देश में पर्यावरणीय उपनिवेशवाद या सहायक उपनिवेशवाद को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बड़े उद्योग और सरकारें, बड़े संरक्षण संगठनों और वित्तीय संस्थानों के साथ, सस्ते ऋण खरीदने और लाभ प्राप्त करने में सक्षम हैं, जबकि परियोजनाओं से प्रभावित समुदाय भूमि और मानवाधिकारों के उल्लंघन, विस्थापन, भूमि हड़पने आदि से प्रभावित होंगे। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यू.जी.ई.ई.पी.) प्रतिवेदन और उच्च स्तरीय कार्य समूह (एच.एल.डब्ल्यू.जी.) प्रतिवेदन के माध्यम से पश्चिमी घाट में संरक्षण पहल उपनिवेशवाद के उद्देश्य से संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं सरकार से पश्चिमी घाटों के संरक्षण के संबंध में डब्ल्यू.जी.ई.ई.पी. और एच.एल.डब्ल्यू.जी. प्रतिवेदन के आधार पर उठाए गए सभी कदमों को छोड़ने का आग्रह करता हूँ।

जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद की 19 जनवरी, 2015 को हुई बैठक में कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन में कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। पिछले कुछ वर्षों से, विकसित देश विकासशील देशों को

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कृषि और पशुधन से उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मजबूर करने का अभियान चला रहे हैं। हम अपने किसानों की सुरक्षा के लिए कृषि उत्सर्जन को जलवायु कार्रवाई के दायरे में लाने का पुरजोर विरोध करते रहे हैं, जो ज्यादातर छोटे और सीमांत भूमि धारक हैं। यह लंबे समय से हमारी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु स्थिति का महत्वपूर्ण घटक रहा है। यदि नया प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है, तो यह मामले पर हमारी स्थिति को कमजोर कर देगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि का कुल योगदान उत्सर्जित 2486 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड में से केवल 14% है। हम 2013 के वारसॉ जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए उत्सर्जन लक्ष्यों को अपनाने के अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं। विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बातचीत पर केंद्रित होनी चाहिए और दुर्भाग्य से बातचीत अब जानबूझकर वर्तमान उत्सर्जन पर केंद्रित है जो विकासशील देशों को बढ़ने और विकसित करने के उनके मूल अधिकार से वंचित करता है। इसलिए, हमें विकास करने और पर्याप्त ऊर्जा होने के अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करना होगा।

संरक्षण की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न वन और पर्यावरण कानूनों में संशोधन करना भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए वन शब्द की व्याख्या संबंधित की सनक और कल्पनाओं के अनुसार की जा रही है और इसलिए वृक्षारोपण, कृषि भूमि और बसे हुए क्षेत्रों को छोड़कर 'वन' की स्पष्ट और स्पष्ट परिभाषा देने के लिए एक संशोधन किया जाना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए, जिसमें मानव-पशु संघर्षों से बचने के लिए वैज्ञानिक तरीके से अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वनों की वहन क्षमता के भीतर शिकार और शिकारी दोनों वन्यजीवों को नियंत्रित करने के प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए और वन्य जीवन द्वारा फसल के हमलों से नुकसान की स्थिति में किसानों को स्थायी विकास और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और अन्य हित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में कानूनी अनपढ़ों को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए एन.जी.टी. अधिनियम 2005 में संशोधन किया जाना है।

मंत्रालय के तहत वन्य जीव विभाग का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय धन प्राप्त करने के लिए किया गया है और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लाभ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, वन्य जीव विभाग यू.एन.डी.पी. के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जी.ई.एफ.) से वित्तीय सहायता के साथ इंडिया हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप (एच.आर.एम.एल.) नामक एक परियोजना को लागू करने की कोशिश कर रहा था, जिसका उद्देश्य प्रतिबंधों और नियंत्रणों के माध्यम से कृषि समुदाय को उनकी भूमि पर अधिकार से वंचित करना था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से पी.टी.आर. और अन्य आस-पास के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में की जाने वाली गतिविधियों में कोई अपवाद नहीं है। वन्य जीव विभाग माफिया के रूप में अभिनय कर रहा है और वन विभाग समानांतर सरकार चला रहा है। यदि वन विभाग के अनियंत्रित और गुप्त कृत्यों को रोका नहीं जाता है, तो यह बड़े पैमाने पर आंदोलनों और प्रतिरोधों का कारण बनेगा, और अंततः पहल प्रतिकूल होगी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कृषि समुदाय के भूमि पर उनके अधिकार की रक्षा करके आजीविका के विकल्पों पर विचार करते हुए प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूँ कि वे उन इच्छुक समूहों और संगठनों पर नजर रखें जो पर्यावरण उपनिवेशवाद को थोपने की कोशिश कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय धन पर नजर रखने वाले उपनिवेशवाद की सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

***डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मौसम परिवर्तन जैसे ज्वलंत समस्या से निपटने हेतु व्यापक रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने हेतु सरकार की संकल्पबद्धता और प्रतिबद्धता जतायी है। भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मौसम परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर पूरी गंभीरता से स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपनाया जाना हम सबके लिए गौरव का विषय है।

मैं माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जिनके कुशल नेतृत्व में उनके मंत्रालय द्वारा मौसम परिवर्तन हेतु बजट को बढ़ाकर 10 करोड़ से 16 गुणा बढ़ाकर 160 करोड़ कर दिया गया है।

हमें देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के पूर्ण समर्पण का पता इस बात से लग सकता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष 240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो कि गत वर्ष से 148 करोड़ अधिक है। इसी श्रृंखला में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों में कोयले पर 100 मीट्रिक टन पर स्वच्छ ऊर्जा सेस को 100 रुपए बढ़ाया है जिससे कि देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए चल रहे प्रकल्पों को मदद दी जा सके।

मैं सामरिक और संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेश से आता हूँ जहां यह प्रदेश दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरा है वहीं यह प्रदेश नियमित रूप से प्राकृतिक आपदा की मार झेलता है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास की गम्भीर समस्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस कठिनाई को कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं पर्यावरण व वन मंत्री के समक्ष उठाया था। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र से सटी सड़कों के निर्माण हेतु पर्यावरण संबंधी अनुमति की कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। इससे सीमा क्षेत्रों में रह रहे हमारे वे लोग लाभान्वित होंगे जो द्वितीय पंक्ति में देश की रक्षा करते हैं। मैं माननीय

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मंत्री जी को अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके इस कदम से सीमाक्षेत्रों की हमारी संपर्क मार्ग की योजनाएं बिना विलंब के पूरी हो सकेगी। संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड राज्य में जहां 67 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं वहां पर्यावरण की रक्षा के लिए लगभग 12500 वन पंचायतों का गौरवमयी इतिहास रहा है। इन बारह हजार पांच सौ वन पंचायतों में ढाई लाख से अधिक नागरिक तमाम खतरों का सामना करते हुए अपने निजी वनों को सुरक्षित रखते हैं। अपने सीमित संसाधनों में भी लोग बच्चों से ज्यादा अपने वनों की चिंता करते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वन पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की जाए और अन्य पर्वतीय राज्यों में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए वन पंचायतों की अनूठी योजना तैयार की जाए।

मैं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अभिनव योजनाएं सृजित और क्रियान्वित किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पर्यावरण संरक्षण से प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए कई सफल और अभिनव प्रयोग किए। धर्म और अध्यात्म का विश्व प्रसिद्ध केन्द्र बद्रीनाथ धाम में हमने एकता वन की स्थापना की जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों में अपने राज्यों की तरफ से वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में जिलास्तर पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्यालय और महाविद्यालय को सम्मानित करने की अनूठी योजना बनाई गई। प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु एन.सी.सी. और एन.एस.एस. समेत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेते हुए मेलों का आयोजन किया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक प्रकार के फलदार पौधे उपलब्ध कराकर उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश के सभी विद्यालयों में ईको क्लबों की स्थापना कर विद्यार्थियों को जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया गया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। भारतीय सेना के ईको टास्क फोर्स के साथ मिलकर बद्रीनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्रों के वृक्षारोपण का व्यापक अभियान हाथ में लिया गया जिसमें सकारात्मक परिणाम निकले हैं। मेरा मानना है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय को सतत पर्यावरण विकास के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित कर नवीन और अनूठी योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए।

सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में आ रही भीषण प्राकृतिक विपदाओं के चलते एवं पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए एवं मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभावों को बचाने के लिए हिमनद विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाए। इससे न केवल विदेशी शोध पर हमारी निर्भरता समाप्त होगी और हम अपनी योजनाओं और संसाधनों का समुचित क्रियान्वयन और विकास भलीभांति कर पाएंगे। इस संस्था के माध्यम से जहां हम एशिया के जल टावर का संरक्षण कर पाएंगे, वहीं डैम, जल विद्युत परियोजना, सिंचाई परियोजना, पर्यटन की विभिन्न योजनाओं हेतु संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाने में सफल होंगे। सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में आ रही भीषण आपदाओं के चलते पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु, हिमनदों को मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए देश में हिमनदों का व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन की नितान्त आवश्यकता है। अपने सर्वेक्षणों और अध्ययन के आधार पर हम अपने जल संसाधनों संबंधी योजनाओं का उचित सृजन एवं क्रियान्वयन कर पाएंगे। यह प्राधिकरण सफलतापूर्वक राज्य सरकारों के साथ मिलकर निगरानी नेटवर्क की स्थापना कर समुदाय आधारित प्रबंधन मानव संसाधन का विकास करके आपदा प्रबंधन की सफल रणनीति का सृजन एवं क्रियान्वयन कर पाएगा। चूंकि वाटर टावर हिमालय के जल अपवाह में उत्तराखंड के हिमनदों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा अनुरोध है कि यह महत्वपूर्ण प्राधिकरण उत्तराखंड में ही स्थापित किया जाए। मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में हिमनद प्राधिकरण बनाया था लेकिन वर्तमान उत्तराखंड की सरकार उसे आगे नहीं बढ़ा सकी जिसका मुझे दुख है।

जैव वैविध्य के क्षेत्र में हिमालय सबसे अधिक विविधता वाले क्षेत्रों में आता है जो कि देश में 2387590 (तेईस लाख सतासी हजार पांच सौ नब्बे) वर्ग कि.मी. के भू-भाग को आच्छादित करता है। विश्व के 130 करोड़ लोग हिमालयीय संसाधनों और अपवाह पर निर्भर हैं। वनों से आच्छादित इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय के अनुकूल विकास हेतु अलग से योजना का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

हमें यह समझना होगा कि बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र की जहां एक ओर अपनी विषम पारिस्थितिकी है, वहीं दूसरी ओर यह सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्गम परिस्थितियों एवं आपदा की निरंतर मार सहती उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से ग्रस्त है। जहां हम दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरे हैं वहीं प्राकृतिक

आपदा के कारण व बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में 67 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण कृषि और उद्योग धंधों की काफी कमी है। भीषण आपदाओं और वन्य जन्तु संरक्षण के तहत जो गांव पूरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास होकर उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किए जाने की एक व्यापक कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि आपको विदित है कि ईको टास्क फोर्स एक विशेष बल है जिसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के साथ स्थानीय जनता को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक करना है। इसके अतिरिक्त देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे जांबाज सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद यह सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने का उत्तम माध्यम है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पर्यावरण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठित किए जाने वाले ईको टास्क फोर्स की नई बटालियन सृजित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले बजट में प्रस्तावित हिमालयी मिशन की स्थापना अविलंब की जाए ताकि हिमालय क्षेत्रों के अध्ययन के साथ समग्र विकास हेतु नीतियों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। हिमालय क्षेत्र में आ रही भीषण विपदाओं के मद्देनजर ऐसे संस्थानों की स्थापना अति आवश्यक है। चाहे वह केदारनाथ की 2013 की जल प्रलय रही हो या जम्मू कश्मीर की भयंकर अतिवृष्टि या फिर हाल ही में आया नेपाल का विनाशकारी भूकंप। इन सभी त्रासदियों से हमें हिमालय स्थित प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिकी के अनुरूप दोहन का संदेश मिलता है। हिमालयी मिशन का यह प्रस्तावित संस्थान क्षेत्र के सुनियोजित विकास की अवधारणा को साकार कर पाएगा।

यह अत्यंत चिंताजनक विषय है कि प्रदेश में कितनी ही जल विद्युत परियोजनाएं कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बंद कर दी गई हैं। ऐसे में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं एवं ऊर्जा संकट से निपटने की सरकार की मुहिम को गहरा धक्का लगा है। मेरा आग्रह है कि ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में मिनी एवं माइक्रो हॉइडल परियोजनाओं को बढ़ावा दें ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ हम ऊर्जा संकट से निजात पा सकें।

मैं बताना चाहूंगा कि मेरे प्रदेश में जहां 67 प्रतिशत भाग वन आच्छादित है वहीं लगभग 30 प्रतिशत से कम भूमि कृषि योग्य बचती है। इस बची-खुची भूमि पर हमारे किसानों को बंदर और सुअरों सहित अनेक जंगली जानवरों के आतंक को झेलना पड़ता है। एक ओर इससे हमारे कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इन जानवरों के हमलों से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

प्रदेश के कई अंचलों में सड़कों की योजनाएं पर्यावरण स्वीकृति के कारण लटकी पड़ी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति लेने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उसका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सामरिक और संवेदनशील दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों की सड़क योजनाओं की स्वीकृति वरीयता के आधार पर दी जाए।

भीषण आपदाओं और वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत जो गांव पूरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किया जाए। ऐसे में राज्य सरकारों के साथ मिलकर वन भूमि के समुचित उपयोग हेतु अभिनव योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वनों से आच्छादित हिमालयी प्रदेशों में क्षेत्रीय पारिस्थितिकी के अनुकूल विकास हेतु अलग से योजना का प्रावधान ग्रीन बोनस के रूप में किया जाए ताकि वनों से प्रभावित या उन पर निर्भर लोग पलायन न करें। दुर्गम परिस्थितियों और अपदा की निरंतर मार सहती जनता के लिए ग्रीन बोनस के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। इससे न केवल देशभक्त क्षेत्रीय जनता राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रोत्साहित और समर्पित होगी बल्कि वह संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण में बढ़-चढ़कर अपना योगदान देगी। मेरा मानना है कि हिमालयी प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्द्धन में मील का पत्थर साबित होगी।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए विश्वास प्रकट करता हूं कि वह मेरी उपर्युक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

***श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर):** बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स पर अपने विचार रखने का मौका दिया।

हमारी सरकार का लक्ष्य है- देश को समृद्ध बनाना, किन्तु साथ ही अपनी माँ भूमि एवं पर्यावरण की पूर्ण रूप से रक्षा करना। हमारी सरकार ने , यू.पी.ए. सरकार के उलट, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से गरीबी को दूर करना और गरीबी दूर कर पर्यावरण को संरक्षित करने का जो इस बजट में काम किया है, इसके लिए मैं सांसद के ही नाते नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के नाते भी उन्हें बहुत-बहुत नमन और साधुवाद देता हूँ। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि वन और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए हमें जन भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि इस मामले में बिना जन भागीदारी के कुछ भी करना संभव नहीं हो सकेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा किया- "सबका साथ, सबका विकास। " यह हमारे देश को आपसी सामंजस्य और सतत् विकास की ओर ले जाने वाला सबसे ठोस कदम होगा।

मैं एनवायरनमेंट एण्ड फोरेस्ट मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्राण्ट्स का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक ट्वीट के साथ समाप्त करता हूँ कि 'आइए, हम ट्रस्टी के रूप में काम करें, जहां वर्तमान में अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करते वक्त आगामी पीढ़ियों की खुशियां भी सुनिश्चित करें। '

***श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत):** मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सोनीपत की ओर दिलाना चाहता हूँ।

यमुना नदी मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत से होकर गुजरती है। यमुना नदी का पानी यमुनानगर में नीला रंग का होता है और यह सोनीपत आते-आते काला, दूषित और जहरीला हो जाता है। जिसके कारण पीने के पानी तथा सिंचाई का पानी दूषित होने के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

उद्योगों का गंदा पानी यमुना नदी में गिरने के साथ-साथ नदी में खनन की गतिविधियों का कार्य बहुत अधिक जोर पर चलता है। जिससे बहुत बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं और आस-पास के पेड़-पौधे भी उखाड़ दिए जाते हैं। इससे भविष्य में और अधिक पर्यावरण को खतरा बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण आधिक दूषित होता जा रहा है।

खनन व दूषित पानी के कारण पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जमीन पेड़ विहिन तथा ऊंची-नीची होती जा रही है। जिस कारण पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने में कठिनाई पैदा हो रही है।

पर्यावरण में बदलाव के कारण ही भूकम्प और बिन मौसम की बरसात जैसी प्राकृतिक आपदा आती है। जिसके कारण वहां की जनता के साथ-साथ देश को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है।

अतः मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने से बचाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए।

[अनुवाद]

***श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):** हमारे देश में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरा और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, मिट्टी के क्षरण, खराब भूमि प्रबंधन और प्रतिकूल सिंचाई के कारण भारत के सकल कृषि उत्पादन का लगभग 30% हर साल खो जाता है। आर्द्रभूमि और झीलों भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। मुख्य रूप से एक दशक पहले भारत में आई औद्योगिक उछाल के कारण, मुख्य समस्याएं औद्योगिक कचरे जैसे रसायनों आदि का अनुचित निपटान हैं। यह हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक रहस्योद्घाटन है।

वायु प्रदूषण हमारे देश में एक गंभीर समस्या है जिसका प्रमुख स्रोत ईंधन की लकड़ी और बायोमास जलाना, ईंधन में मिलावट, वाहन उत्सर्जन और यातायात जाम है। वायु प्रदूषण भी एशियाई भूरे बादल का मुख्य कारण है, जिसके कारण मानसून में देरी हो रही है। हमें इस समस्या पर नजर रखने और लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।

हमें विकास की आवश्यकता है, हमें देश के आर्थिक विकास के लिए कारखाने, उद्योग और संयंत्र स्थापित करने चाहिए, लेकिन साथ ही हमें पर्यावरण के मुद्दे को संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो देश के लिए आपदा का कारण बन सकती है। हमें उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कानून और नियमों का उल्लंघन करते हैं।

नदियां भारत में प्रदूषण की अग्रिम पंक्ति में हैं। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं, लेकिन वे धीरे-धीरे सीवेज, रसायनों और अन्य कृषि और औद्योगिक कचरे से प्रदूषित और नष्ट हो रहे हैं। अनुपचारित सीवेज का निर्वहन देश में सतह और भूजल के प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। शहरी क्षेत्रों में जमा होने वाले अपशिष्ट अस्वच्छ परिस्थितियों का कारण बनते हैं और प्रदूषकों को छोड़ते हैं जो सतह और भूजल में रिसते हैं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के 3,119 कस्बों और शहरों में से केवल 209 में आंशिक सीवेज उपचार सुविधाएं हैं, और केवल 8 में पूर्ण अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं हैं। 100 से अधिक भारतीय शहर अनुपचारित सीवेज को सीधे गंगा नदी में डालते हैं। मानसून के दौरान बाढ़ आने से जल प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि यह सभी प्रकार के ठोस कचरे और दूषित मिट्टी को धोकर नदियों और आर्द्रभूमि में ले जाती है। इसलिए हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा।

हम दुनिया भर से पर्यटकों को अपने देश में आकर्षित करने की बात करते हैं, लेकिन यह एक कड़वा तथ्य है कि प्रदूषित वातावरण के कारण पर्यटक हमारे देश आने में संकोच करते हैं। पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण को रोकने के उपायों की कमी के कारण गोवा, मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों जैसे पर्यटक केंद्र बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विशेष रूप से इन शहरों में पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय करें।

वनों की कटाई भारत में एक और अत्यधिक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है। यह भविष्यवाणी की गई है कि आजादी के बाद से लगभग 5.3 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। इसमें से अधिकांश को आवास, औद्योगीकरण और नदी परियोजनाओं के लिए काट दिया जा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले 20 वर्षों में मैंग्रोव वनों की संख्या आधे से अधिक हो गई है।

पहाड़ों, पहाड़ियों और जंगलों का उनके अस्तित्व में बहुत महत्व है। पहाड़ पृथ्वी को भूकंप से बचाते हैं और जंगल मनुष्य के लिए ताजी हवा देते हैं। इसी तरह पशु पर्यावरण को ताजा और शुद्ध रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट खाते हैं जो प्रदूषण को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही वे मनुष्यों के लिए हवा को फ़िल्टर भी करते हैं।

लेकिन दुर्भाग्य से औद्योगिक वृद्धि के नाम पर हम पहाड़ों और जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। इसी तरह, हम बाघ और गैंडा आदि जैसे जानवरों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। देश में विशेष रूप से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और गैंडों का अवैध शिकार चल रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में लुप्तप्राय

एक सींग वाले गेंडे की सबसे बड़ी आबादी का घर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उद्यान में अवैध शिकार एक बड़ी समस्या बन गई है।

रिकॉर्ड के अनुसार, असम में 2,505 की कुल आबादी में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2,186 गेंडे हैं। पिछले दशक के दौरान उस राज्य में कुल 524 गेंडों को उनके सींगों के लिए मार दिया गया है। अभी तक इस साल लगभग 22 गेंडे मारे गए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विशेष ध्यान दें और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। मैं माननीय मंत्री जी से पर्यावरण और वन संरक्षण के संबंध में मौजूदा कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाने का भी अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

***श्री ददन मिश्रा (श्रावस्ती):** मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

सामान्य धारणा यह है कि पर्यावरण और वन अनंत प्राकृतिक उपहार हैं, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की सेवा, सहायता तथा उन्हें जीवित रखने की एक चिरकालिक क्षमता है, चाहे उनके साथ कितना भी क्रूर, अपमानजनक और अवेहलनात्मक बर्ताव किया जाए। इस तरह की संतोषजनक अवधारणा तथा निश्चितता पूर्ण रवैये का परिणाम न केवल अवश्यंभावी बल्कि तत्काल आपदा को निमंत्रण देना है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्यावरण और वनों में अलौकिक और अंतर्निहित सामर्थ्य तथा शक्ति यह है कि उनका पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, पुनर्मरण तथा पुनरुत्थान हो जाता है, परन्तु यह सामर्थ्य अनंत और चिरकालिक नहीं है। यह प्रक्रिया उतनी तेजी से नहीं हो सकती है, जितनी तेजी से हमारी आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि लालच के कारण इस पर निर्भरता और असावधानीपूर्वक कहर ढाया जा रहा है। यहां तक कि आज के परिदृश्य में यदि इसी प्रकार अंधाधुंध बर्बादी होती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि जब न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवों को जीवन के लिए गंभीर और निश्चित खतरा पैदा हो जाएगा।

मैं देश के उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ, जिनको प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण प्रकृति की गोद में पलने-बढ़ने का अवसर मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के जिस श्रावस्ती क्षेत्र में आता हूँ, उसके अंतर्गत आने वाले दोनों जिले श्रावस्ती एवं बलरामपुर वन एवं खनिज संपदा से परिपूर्ण हैं। श्रावस्ती में जहां 17 हजार 186 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट है, वहीं 23 हजार हेक्टेयर सेंचुरी फॉरेस्ट भी है। इसी प्रकार बलरामपुर में 5 हजार हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट एवं 45 हजार हेक्टेयर सेंचुरी फॉरेस्ट है।

मैं वनों के बीच पला बढ़ा हूँ, इसलिए जंगल एवं वन से हमको बढ़ा लगाव है। परन्तु आज जब मैं वनों के चौतरफा ही रहे विनाश को देखता हूँ तो हमें बहुत ही हार्दिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इसकी रखवाली तथा इसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों, सत्ता पक्ष के नेताओं एवं वन माफियाओं का एक बहुत ही मजबूत गठजोड़ का कॉकस बन गया है जो वनों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। आज हम देखते हैं कि वनों की अंधाधुंध अवैध कटाई एवं अवैध खनन उक्त गठजोड़ की अवैध कमाई का प्रमुख साधन बन गया है। अगर इसी तरह से अंधाधुंध अवैध कटाई होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वन एवं जंगल सिर्फ किताबों और किस्से कहानियों में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे, जिसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में न तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन हो रहा है और न ही सेवा नियमावली का पालन किया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारी एक ही स्थान पर 20-20 साल जमे रहकर वहीं से प्रमोशन लेकर के रिटायर भी हो जाते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का तथा सेवा नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करा करके वनों को बचाने एवं संरक्षित करने का काम करें।

हमारे क्षेत्र के भिनगा वन प्रभाग में विजयशाल नामक पेड़ पाया जाता है, जिसकी लकड़ी का गिलास बना करके उसमें पानी भरकर रख दिया जाता है तो वन पानी सुबह लाल रंग का हो जाता है और वह पेट संबंधी बीमारियों की रामबाण दवा है। इसकी भी अंधाधुंध अवैध कटाई वन माफियाओं द्वारा की जा रही है, जिसको संरक्षित करने की व्यवस्था की जाए।

भिनगा वन प्रभाग में ही उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, उनको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपने निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ।

पर्यावरण परिवर्तन और कृषि दो संबंधित प्रक्रिया है जो एक वैश्विक पैमाने पर अपनी जगह बना रहे हैं। पर्यावरण परिवर्तन कृषि को अलग-अलग तरीकों जैसे औसत तापमान, वर्षा, कीट और रोगों में परिवर्तन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जमीनी स्तर पर ओजोन सांद्रता में परिवर्तन और समुद्र के स्तर में परिवर्तन से प्रभावित करता है।

भारत में कृषि और संबद्धित क्षेत्र करीब 18 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देते हैं और करीब 70 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है।

जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर पर किसानों के लिए सबसे दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक है। जलवायु जोखिम भारतीय कृषि के लिए आम हैं। यह सूखे के लिए अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि 2/3 कृषि भूमि वर्षा पर आधारित है और सिंचित प्रणाली भी मानसून पर निर्भर है। बाढ़ भी बार-बार कई भागों में विशेष रूप से पूर्वी भारत में होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में ठंड मध्य और उत्तरी भागों में गर्म तरंगों और पूर्वी तट में चक्रवात का काफी कहर अक्सर पाया गया है।

मेरे संसदीय क्षेत्र 44 अकबरपुर लोकसभा में जनपद कानपुर नगर की कल्याणपुर, महाराजपुर, बिठूर एवं घाटमपुर तथा जनपद कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सम्मिलित है। मेरी लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जी.टी. रोड़, कानपुर-सागर राजमार्ग, कानपुर-आगरा राजमार्ग एवं कालपी रोड़ पर कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें सैकड़ों औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं। इन औद्योगिक संस्थानों से प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिष्ट पदार्थ एवं लाखों लीटर प्रदूषित जल के साथ-साथ धुएं की धुंध एवं धूल निकलती है। पर्यावरण एवं प्रदूषण के निस्तारण के मानकों के लगातार उल्लंघन एवं मिल मालिकों व विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त एवं गंभीर घातक बीमारियों से ग्रस्त हो गया है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया था।

ज्ञात हो कि कानपुर नगर के ग्राम बिनौर में स्थित महादेव पेपर मिल एवं पी.आर. इंडस्ट्रीज तथा कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में स्थित कानपुर एडिबल ऑयल, आर.एस.पी.एल. व जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में रनिया में पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंसायी नेरोलैक आदि सहित सैकड़ों ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों, प्रदूषित जल, पानी के खनन एवं कचरे का यथाउचित निस्तारण न किए जाने के कारण पूरे क्षेत्र में गन्दगी का साम्राज्य कायम हो गया है। जहरीला धुंआ, उगलती चिमनियों से आम आदमी का सांस लेना दूभर हो गया है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारियों एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को दिनांक 15.10.2014 को पत्र लिखकर औद्योगिक इकाइयों द्वारा मानकों के विपरीत की जा रही कार्यवाहियों को तत्काल रोके जाने का आग्रह किया था। परन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी तक इस गंभीर परिस्थिति को नजरअंदाज कर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

निष्कर्ष स्वरूप पर्यावरण, परिवर्तन फसल उत्पादन को अधिक विश्वसनीय और कम उम्मीद के मुताबिक कर देगा। आने वाले समय में ज्यादातर फसलों की पैदावार कम होने की संभावना है एवं हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भयंकर बीमारियों के कारण आमजन के जीवन पर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुकूल प्रथाओं को प्रभावी बनाने के लिए समय लिया जाए। अतः हमें अब अभिनय की जरूरत है।

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):** मैं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अनुदान की मांगों 2015-16 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूँ।

वर्ष 2015-16 में प्लान मद में 1446.60 करोड़ रुपए और नॉन प्लान में 235.00 करोड़ सहित 1681.60 करोड़ रखा गया है। आज जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास का मुद्दा वैश्विक हो गया है। 2013 में सम्पूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संबंध में चीन, यू.एस.ए. और यूरोपीय संघ पहले तीन स्थानों पर हैं, जबकि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का स्थान 196 देशों में से नीचे के 100 देशों में आता

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में है। हमने अनुकूलन कार्यों के सहायतार्थ 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ "राष्ट्रीय अनुकूलन निधि" स्थापित की है, ताकि कृषि, जल और वन आदि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

समग्र और एकात्म विकास के लिए आवश्यक है कि एथिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी का समन्वय और संतुलन मानवीय जरूरतों के अनुरूप हो। मानव समाज और आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए प्रकृति के प्रति सरकार का और हमारा दृष्टिकोण संतुलित होने के साथ-साथ व्यवहारिक होना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही चिरस्थायी विकास की मानववादी संकल्पना साकार हो सकती है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा झारखंड प्रदेश का वन बहुलता वाला क्षेत्र है। मेरे ही क्षेत्र में पलामू टाईगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है। कृपया इस क्षेत्र में मानव वन्य प्राणी संघर्ष को कम करने के लिए सुविधा और मुआवजा बढ़ाया जाए। रिजर्व वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा और आजीविका की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और वन्य पशु अवलोकन हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाएं। इसमें स्थानीय आबादी की भागीदारी से पर्यावरण और वन जीवों के विकास में सुविधा होगी। वन्य जीवों और पारिस्थितिकीय विकास समर्थित आजीविका को बढ़ावा देने की योजना बनानी चाहिए। संरक्षित वन क्षेत्र (बेतला) में ही स्थित राजा मेदनीराय का किला और कमलदह झील है और यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। कृपया स्थानीय लोगों की जागरूकता पर्यावरण के प्रति बढ़े, इस दृष्टि से पालमू किला, कमलदह झील और मेले को वन पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की योजना बनाई जाए।

लातेहार, चतरा और पलामू में वन उत्पादकता, उत्पादन और जैव विविधता के दीर्घकालिक प्रबंधन में सुधार लाया जाए और इसमें स्थानीय लोगों का साथ लाभ में समान भागीदारी के आधार पर हो, वह योजना बने। वन क्षेत्र की भूमि एवं चारागाह का पुनरुद्धार हो तथा वन के किनारों पर बसे गांवों के आसपास सामुदायिक चारागाह और खेल के मैदान विकसित किया जाना चाहिए। वन पर्यटन और वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम वन समितियों और संयुक्त वन क्षेत्र प्रबंधन समितियों का निर्माण करना चाहिए।

मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा का पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की दृष्टि से ग्रीन बोनस की राशि उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि भविष्य में उस राशि से वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थित नेतरहाट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। नेतरहाट नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य का अन्यतम उदाहरण है, पर आज अपनी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। नेतरहाट को पर्यावरण और वन पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई जाए। इसमें नेतरहाट का प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय सहायक होगा, जिसके छात्र आज समाज-जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं। कृपया नेतरहाट में वन एवं पर्यावरण से संबंधित संस्थान की स्थापना की पहल की जाए।

प्रकृति और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं है। इसलिए मेरे क्षेत्र में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल जलाशय योजना जो 1972 से ही प्रस्तावित है और इसका कार्य अधूरा पड़ा है उसे वन विभाग से स्वीकृति देने की कृपा करें। इस योजना से वन का ही संरक्षण होगा। साथ ही, चतरा लोक सभा जो अत्यंत पिछड़ा और चरम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसकी बिजली से संबंधित अनेक योजनाएं स्वीकृति के अभाव में लंबित हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान करें।

उत्तर कोयल नदी के जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार 10574 वर्ग किलोमीटर है जबकि उपलब्ध जल की क्षमता 2227 मिलियन घन मीटर है और भूगर्भ जल की क्षमता 680 मिलियन घन मीटर है। इससे 111800 हेक्टेयर जमीन का सिंचन होगा, जिसमें से झारखंड का 11200 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगा। साथ ही लातेहार और पलामू, जहां जल का संकट है, वहां भूगर्भ जल स्तर में सुधार होगा और पेयजल संकट से छुटकारा मिलेगा।

वन भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकार को सुनिश्चित कर उन्हें इसका लाभ दिया जाए। बाघ एवं हाथी द्वारा किए गए नुकसान यथा - जीव, कृषि भूमि, फसल इत्यादि में मुआवजा बाजार दर पर दें और इन मामलों का शीघ्र निपटारा हो।

इसके साथ में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन द्वारा सदन में रखे गए अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ।

***श्री ओम बिरला (कोटा):** मौजूदा आकलनों के अनुसार भारत में वन क्षेत्र लगभग 78.29 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.8 प्रतिशत है। यदि 2009 की तुलना में वर्ष 2011 में जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर तुलना की जाए तो देश में लगभग 367 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी आई है।

भारत में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम 1952 में पहली नीति बनी थी तथा उसके पश्चात बदलते परिवेश को देखते हुए 1978 में दूसरी वन नीति बनाई गई। 1978 के पश्चात् औद्योगीकरण व विभिन्न कारकों के चलते वर्तमान वन नीति की पुनः समीक्षा कराया जाना आवश्यक है। भारत में खनन, कोयला, राजमार्ग, रेल सेवा, ऊर्जा व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न प्रोजेक्ट एवं वर्तमान वन एवं पर्यावरण संबंधित नीतियां एक दूसरे की पूरक न होकर प्रायः अंतर्द्वंद्व प्रकट करती है, जिसके कारण कई महत्ती परियोजनाएं वन विभाग के क्लीयरेंस के अभाव में सालों साल लम्बित हो रही है।

वर्तमान में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927, सहित विभिन्न अधिनियमों में किए गए कुछ प्रावधान वन्य क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों /वन वासियों के मौलिक अधिकारों की भी उपेक्षा करते हैं। इन क्षेत्रों में सदियों से बसे नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में वन विभाग के नियम आड़े आते हैं। इनकी समीक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि वन सीमा में रह रहे नागरिकों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

इसी प्रकार, दुर्लभ एवं लुप्तप्रायः वन्य जीवों के संरक्षण वाले राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाना आवश्यक है, जिसके कारण न केवल वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकेगी, वहीं पर्यटकों के आगमन से ईको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा एवं स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिलेगा।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राजस्थान सहित देश के कई कृषि प्रधान इलाकों में रोजडों (नील गाय), जंगली सुअर आदि जानवरों द्वारा बड़ी मात्रा में किसानों की फसलें नष्ट कर दी जाती हैं जिससे उनको गंभीर आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस समस्या पर मुझे सहित देश के कई सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में मेरा आग्रह है कि वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों जैसे बाड़ा बंदी, तारबंदी आदि प्रबंधों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए और फसल बीमा में भी उक्त जोखिम को शामिल करने का प्रयास किया जाए।

मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा से जुड़े कुछ लम्बित विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कोटा, बूंदी, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ जिलों में दरा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य व राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्रफल जोड़कर मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व की घोषणा की गई थी। उक्त रिजर्व में वर्तमान में कोई भी टाईगर बसाया नहीं गया है। वहीं राजस्थान के दूसरे नेशनल टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर बाघों की बढ़ती हुई संख्या के कारण बाघों के आपसी झगड़े व विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सरिस्का के समान यहां भी बाघों का विस्थापन सवाई माधोपुर से कर दिया जाए तो न केवल बाघों का संरक्षण अच्छे से किया जा सकेगा, वहीं पर्यटन की दृष्टि से एक नया क्षेत्र विकसित होगा।

कोटा के इटावा क्षेत्र, बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी गेंता माखिदा की पुलिया के निर्माण की स्वीकृति लम्बे समय से लम्बित चल रही है। उक्त स्वीकृति से संबंधित समस्त औपचारिकताएं कई बार पूरी करके राज्य सरकार द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। किंतु विभिन्न छोटे-छोटे आक्षेपों के चलते अब तक स्वीकृति न मिलने से क्षेत्र के लोगों को 130 किलोमीटर की अनावश्यक यात्रा करने को विवश होना पड़ता है। कोटा से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे संख्या 12 के फोरलेन का कार्य भी वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में लम्बित है। जिसका निस्तारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बूंदी शहर का अधिकांश भाग जो कि रामगढ़ अभयारण्य की सीमा में आने से सभी मूलभूत आवश्यकताओं व विकास कार्यों से वंचित है, उक्त संबंध में केन्द्रीय समिति द्वारा निरीक्षण करके शहर को वन्य सीमा से मुक्त करने

के संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दी है जो कि विचाराधीन है। उक्त क्षेत्र को यदि वन्य सीमा से मुक्त कर दिया जाए, तो लगभग डेढ़ लाख की आबादी को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।

चम्बल नदी पर घड़ियालों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से उत्तरी भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों के कुल 425 किलोमीटर लंबाई तक फैले क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी के रूप में वर्ष 1979 में घोषित किया गया। चम्बल नदी पर बनाए गए कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम से केशवरायपाटन के बीच के हिस्से को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त रखा गया है। किन्तु चम्बल नदी की अपस्ट्रीम से जवाहर सागर की ओर का हिस्सा अभी भी घड़ियाल सेंचुरी में आता है। वहां निवास कर रहे लोगों को विभिन्न मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली कनेक्शन, पट्टे व अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। अतः कोटा बैराज के अपस्ट्रीम वाले क्षेत्र तथा केशवराय पाटन से सुल्तानपुर, इटावा वाले क्षेत्र का सर्वे कराकर घड़ियाल सेंचुरी का पुर्नसीमांकन कराया जाए और ऐसा क्षेत्र जो कि अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और घड़ियालों के प्रजनन के अनुकूल नहीं है उसे सेंचुरी से मुक्त किया जाए।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह है कि उक्त विषयों के संदर्भ में कार्य योजना बनाई जाए, तो वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन सहित वन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के जीवन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।

***श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** प्रकृति के पांच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं पृथ्वी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं जिनका आपस में गहरा सम्बन्ध है। इन पांचों तत्वों में किसी एक का भी असंतुलन पर्यावरण के लिए अपूर्णनीय क्षति कारक और विनाशकारी है। पर्यावरण दो शब्दों पर और आवरण से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, परिस्थितियां या शक्तियां विद्यमान हैं, वे मानवीय क्रियाकलापों का प्रभावित करती हैं और उसके लिए दायरा सुनिश्चित करती हैं। इसी दायरे को पर्यावरण कहते हैं।

पर्यावरण के अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट का उद्भव फ्रांसीसी भाषा के इनविरोनिर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है घेरना। एनवायरनमेंट का समानार्थक शब्द है बिटैट है, जो लैटिन भाषा के हैबिटायर शब्द से निकला है। हैबिटैट शब्द पर्यावरण के सभी घटकों को स्थानीय रूप से लागू करता है इसका प्रभाव आवास स्थल तक सीमित है, जबकि एनवायरनमेंट शब्द हैबिटैट की तुलना से अधिक व्यापक है।

देखा जाए तो पर्यावरण को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जैविक अर्थात् बायोटिक जिसमें समस्त प्रकार के जीव-जन्तु व वनस्पतियां (एक कोशिकीय से लेकर जटिल कोशिकीय तक) हैं। दूसरे प्रकार के घटक में भौतिक अर्थात् अजैविक जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल वायुमंडल सम्मिलित हैं। इन सभी घटकों में सृष्टि में मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में उत्पत्ति की है। अतः मानव सम्पूर्ण जीव जगत का केंद्र बिंदु है। पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण घटक मानव को परावृत्त करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यावरण के प्रभावों को परिलक्षित करती हैं। वस्तुतः अनुवांशिकी एवं पर्यावरण ये दो महत्वपूर्ण कारक मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव होने के नाते मनुष्य ने प्रकृति की प्राकृतिक सम्पदाओं का सदियों से भरपूर दोहन किया है। लेकिन वर्तमान दौर में बढ़ती जनसंख्या, पश्चिमी उपभोक्तावाद एवं वैश्विक भूमण्डलीकरण के मकड़जाल में फंसकर मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सुख को खोता जा रहा है। वह नहीं जान पा रहा कि कंकरीट का शहर बसाने की चाहत के बदले में वह अपना भविष्य दांव पर लगा बैठा है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रकृति के समस्त संसाधन प्रदूषण की चपेट में हैं। हवा, जल और मिट्टी जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना बेमानी है, आज अपना मौलिक स्वरूप एवं गुण खोते जा रहे हैं। पर्यावरण की छतरी अर्थात् ओजोन परत जो हमें सौरमंडल से आने वाली घातक किरणों से बचाती है उसमें छेद होना, वातावरण में बढ़ती कार्बन डाईऑक्साईड की मात्रा से उत्पन्न समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, दिनोंदिन घातक बीमारियों का प्रादुर्भाव व स्वास्थ्य संकट ये सब मानव के समक्ष एक विकराल दानव का रूप ले चुके हैं जो भस्मासुर की तरह समस्त मानव जाति को लीलने को आतुर हैं, जिसमें सावधान होना बहुत जरूरी है।

जैव मंडल में मौजूद संसाधनों में जल सर्वाधिक मूल्यवान है क्योंकि यह केवल मानव ही नहीं अपितु सभी जीवों तथा वनस्पति के लिए उपयोगी है। प्रकृति में जल तीन रूपों में विद्यमान है ठोस, तरल एवं गैस। ठोस के रूप में बर्फ जल का शुद्ध रूप है। इसके बाद वर्षा का जल, पर्वतीय झीलों, नदियां एवं कुएं शुद्धता क्रम में आते हैं। धरातल पर प्रवाहित तथा झीलों, तालाबों आदि के रूप में उपलब्ध स्वच्छ जल की मात्रा केवल 7 प्रतिशत है। लेकिन बढ़ती संख्या, कुकरमुत्ते से उगे बहुमंजिला इमारतों, खेती में रसायनों का उपयोग तथा रासायनिक फेक्ट्रियों से निकला पानी नदियों, तालाबों, झरनों को प्रदूषित कर रहा है, जो मानव जाति सहित जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जल को प्रदूषित करने वाले तत्व जल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर जल को पीने योग्य नहीं रहने देते।

वसुन्धरा को माता का दर्जा दिया गया है जो अपने गर्भ में मौजूद तमाम आवश्यक धातुओं, अधातुओं, खनिज लवणों के सहयोग से बीज का पोषण कर खाद्य पदार्थ के रूप में विकसित करती है जो समस्त जीव जन्तुओं में जीवन का संचार करते हैं। भूमि या मिट्टी भी जल की भांति सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि विश्व के 71 प्रतिशत खाद्य पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। यह संसाधन इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता कि सम्पूर्ण ग्लोब के मात्र 2 प्रतिशत भाग में ही कृषि योग्य भूमि है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए खाद्यान्नों की बढ़ती मांग के कारण कृषि उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके कारण विश्व में खाद्यान्न की समस्या पर काफी हद तक काबू किया जा सका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग, नित नए रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक

कीटनाशकों के प्रयोग के कारण धरती की उर्वरता कम हो गई है। शहरों व महानगरों से निकला अपशिष्ट पदार्थ जैसे पॉलीथिन, कूड़ा-करकट, राख, औद्योगिक अपशिष्ट, दफ्ती, चमड़ा, शीशा, रबड़ आदि के कारण मिट्टी के प्रदूषण को तेजी से बढ़ावा दिया है।

पृथ्वी के चारों ओर गैसों का घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसमें लगभग 73 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन एवं 0.03 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सभी तत्व पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। पृथ्वी पर मौजूद पेड़-पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर प्रकाश की उपस्थिति में एवं जड़ों के माध्यम से जल एवं आवश्यक खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। बदले में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यही ऑक्सीजन वायुमंडल में मिलकर मानव जाति के लिए प्राणवायु का काम करती है। मनुष्य एवं जीव-जन्तु भी जब वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि पेड़-पौधों के लिए भोजन बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में मौजूद सभी घटक सिम्बायोटिक तरीके से एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और इस प्रकार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन विकसित देशों की प्रभुता की लालसा ने अंधाधुंध परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा करने, रासायनिक हथियार बनाने की होड़ ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य ने वनों को काटकर कंकरीट की बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली। ऐसा कर उसने अपने भविष्य का नाश कर दिया। पेड़ों के कटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ने से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के तापमान को भी नियंत्रित करती है। पेड़ों के कटने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर बढ़ती मात्रा के कारण वातावरण के तापमान को दिनोंदिन बढ़ाती जा रही है जो अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा, सर्दी, गर्मी के चक्र को भी प्रभावित कर रही है। निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर इस हद तक बढ़ जायेगा कि समुद्र के किनारे बसे समूचे शहरों को लील जाए तो आतिशयोक्ति न होगी।

पर्यावरण के इस असंतुलन की जिम्मेदारी हमारी समस्त मानव जाति है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए वेद मनीषियों ने भी द्यूलोक से लेकर व्यक्ति तक शांति की प्रार्थना की है।

औ द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः पृथ्वी शान्तिरापः

शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः

शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव

शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ (शुक्ल यजुर्वेद)

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** राजस्थान में खेजड़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है। खेजड़ी आस्था और श्रद्धा का भी विषय है राजस्थान के रेगिस्तान इलाके के लोग खेजड़ी को पूजते भी है। खेजड़ी पर उगने वाली सांगरी भी मनुष्य प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है। अतः खेजड़ी की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है।

***श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा):** प्रदूषण देश के समक्ष एक बड़ी समस्या है और इसके साथ ही विकास की चुनौतियां हैं। ऐसी विषम स्थितियों में भी सरकार पर्यावरण रक्षा का झंडा और विकास एजेंडा लिए चल पड़ी है। मैं ऐसी सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

पर्यावरण की रक्षा को जन आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए। देश में वन क्षेत्र दिनों दिन कम होता जा रहा है। जंगलों में अवैध कटानों एवं अतिक्रमण पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, घने वन और अच्छी वर्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, अधिक से अधिक क्षेत्र पर वनों का विकास करें तथा सामाजिक वानिकी पर विशेष ध्यान दें। वनीय क्षेत्रों को गैर-कानूनी खनन से बचाने तथा दुर्लभ औषधीय पौधों को बचाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। भू-क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी इंतजाम जरूरी है। पौध रोपण की महत्ता और जरूरत के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के दैनिक आचरण एवं क्रियाकलापों में शामिल होना चाहिए। स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु वनों का सतत प्रबंधन किया जाना तथा वनों का संरक्षण करना हमारा दायित्व होना चाहिए। कैम्पा फंड की राशि राज्यों को मिलनी चाहिए, वन बंधु योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही स्थायी विकास संभव है आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य हाथियों की समस्या से ग्रसित हैं - क्यों?

पर्यावरण संबंधी सरकारी मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए ही परियोजनाओं को मंजूरी दिया जाना चाहिए। जो उद्योग नदियों को प्रदूषित करते हैं उन पर भारी दंड लगाना चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने पर उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना में अपनी अप्रयुक्त श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करना चाहिए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वायु प्रदूषण मानसून में विलम्ब का कारण है और ग्रीन हाउस का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रण आवश्यक है।

मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर ले जाना चाहती हूं जो धान का कटोरा है, प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण से जंगली जानवरों विशेषकर हाथियों के कारण जशपुर, सरगुजा, कोरबा जैसे कुछ क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र जांजगीर-चाम्पा, प्रदेश में सबसे अधिक 76 प्रतिशत कृषि सिंचित है, पावर प्लांटों के कारण वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है।

सरकार औद्योगिक प्रदूषण कम करने, वायु गुणवत्ता बनाए रखने, ठोस अपशिष्टों का उचित उपयोग करने, सड़कों का डाबरीकरण करने, वृक्षारोपणी करने, नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार हजार स्कूलों में इको क्लब गठन करने, पालीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए।

मैं सरकार से पर्यावरण संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जो बजट डिमांड है, उन्हें अनुपूरक मांगों में शामिल किए जाने की मांग करती हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर):** समय के साथ यह देखा गया है कि हमारी पृथ्वी पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से बहुत बिगड़ती जलवायु स्थिति का सामना कर रही है, जिसके कारण वनों की कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसका कारण औद्योगीकरण, शहरीकरण और वन क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास के लिए शुरू किए गए कदमों की कमी है। हम पूरे देश में उद्योग लगाकर विकास की बात कर रहे हैं जो किसी भी देश के लिए विकास और रोजगार पैदा करने में सहायक होता है, लेकिन यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वन प्रबंध प्रथाएं जिनमें वनीकरण, पुनर्वनीकरण और वन बहाली आदि शामिल हैं। नीतियों और कार्यक्रमों का उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। हम जानते हैं कि स्थायी प्रबंध प्रथाएं वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभ प्रदान करने की क्षमता को बनाए रखना सुनिश्चित कर सकती हैं। इसलिए, प्रबंध प्रथाओं को सक्रिय रूप से नियोजित करने, प्रत्येक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और विकसित स्थितियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक दोहन और वन क्षरण से बचा जा सके। वन प्रबंध योजनाओं और प्रथाओं को भी जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले संशोधनों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक मेरा संबंध है, उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने और वन भेद्यता को कम करने के लिए अतिसंवेदनशीलता वन प्रबंधन आवश्यक होगा।

मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जगतसिंहपुर में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, जहां उर्वरक कंपनियाँ, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड आदि जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं लेकिन वे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की अपेक्षित नीतियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। वे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीक भी स्थापित नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पर्यावरण को बचाने के लिए समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है। आजकल

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हर जगह प्राकृतिक आपदाओं का परिदृश्य बन रहा है जिससे हमारी पृथ्वी की प्रकृति प्रभावित हो रही है। इस बिगड़ती प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग हमारे देश के गरीब लोग हैं क्योंकि उन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी स्वास्थ्य के खतरों से पीड़ित हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सरकार को औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण होने वाले प्रदूषण के दृष्टिकोण से सतर्क रहने के लिए आगे आना चाहिए और संबंधित राज्यों को पर्याप्त राशि के साथ उपचारात्मक उपाय आमंत्रित किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि सदन में सभी पार्टियों के हमारे 22 साथियों ने भाषण दिये। श्री निनॉग ईरिंग हमारे मित्र हैं, उन्होंने शुरुआत की, श्री भगत सिंह कोशियारी, श्री राधाकृष्णन, श्रीमती ममता संघमित्रा, श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान, श्री राहुल शिवाले, श्री विश्वेश्वर रेड्डी, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी, कु. सुष्मिता देव, श्री दुष्यंत सिंह, श्री जयप्रकाश नारायण यादव, श्री धर्मवीर गांधी, प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा, योगी आदित्यनाथ, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री ओवैसी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री जयदेवन, श्री अजय मिश्रा, श्री डी.के. सुरेश, [अनुवाद] मैं वास्तव में आप सभी का आभारी हूँ क्योंकि आपने अपनी राय व्यक्त की है और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं।

[हिन्दी] जो मुझे यहां उठाए गए हैं, उनमें से बहुत से मुद्दों का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी बीस मिनट का ही समय है। जिसका जवाब यहां नहीं दिया जा सकेगा, उसे हम लिखित रूप में भेजेंगे। चार-पांच माननीय सदस्यों ने लिखित भाषण भी दिए हैं। कल ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आयी है, जिसके चेयरमैन अश्विनी कुमार जी हैं। इस रिपोर्ट का भी मैंने पूरा अध्ययन किया है। सभी ने पर्यावरण के प्रति जो चिंता जताई है और प्रेम व्यक्त किया है, यही मुझे आगे जाने का आधार लगता है।

सभी ने एक चिंता और व्यक्त की है कि इसमें बजट कम हो गया है। बजट के कम होने के दो-तीन रेफरेंस हैं। इसे समझना चाहिए। पहला तो यह है कि हमारे पास गंगा नदी के रिवर बेसिन डेवलपमेंट का कार्यक्रम है। लेकिन, नई सरकार के आने के बाद गंगा नदी के लिए अलग मंत्रालय बना तो हमारे मंत्रालय का गंगा का बजट 800-1000 करोड़ रुपये का होता था और गंगा का बजट अब उस नए मंत्रालय में गया है। इसलिए हमारा बजट कम नहीं हुआ है, बल्कि यह बढ़ा है। यह कैसे बढ़ा है, यह भी मैं बताऊंगा। जिन कार्यक्रमों में बजट कम हुआ है, ऐसा लगता है, उसमें मैं आपको आश्चस्त करना चाहूंगा कि दो बार पूरक मांगें होंगी। पर्यावरण की रक्षा के लिए इस देश में फण्ड्स की कमी नहीं होगी, यह भी मैं आपको आश्चस्त करना चाहता हूँ।

एक और भी बात कहना चाहता हूं कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज को 100 करोड़ रुपये, क्लाइमेट चेंज एण्ड अडैप्टेशन के लिए 175 करोड़ रुपये, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपये, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए 164 करोड़ रुपये और 539 करोड़ रुपये नए कार्यक्रमों के लिए है। जब हम सबको मिलाकर देखते हैं तो बजट में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक ही बदलाव हुआ है कि 14वें वित्त आयोग के बाद सेंट्रल स्कीम्स को स्टेट्स के साथ फण्डिंग शेयर करने का पैटर्न बदल गया है। उतना ही बदलाव आया है और बाकी कोई कमी नहीं की है। मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण के प्रति हम ज्यादा सजग हैं। आपके साथ चलकर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें फाइनैस की कोई कमी नहीं होगी।

[अनुवाद]

अपराह्न 05.32 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

[हिन्दी] हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था - [अनुवाद] “हमें यह पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है। यह आने वाली पीढ़ियों से ऋण पर है। और इसलिए, हमें उन्हें धरती वापस करनी चाहिए जैसा कि हमें विरासत में मिला है अथवा वास्तव में इसे बेहतर बनाना है”। महात्मा गांधी जी ने यही कहा था। यही हमारा आदर्श सिद्धांत है जिस पर हम 'वॉक द टॉक' करना चाहते हैं। [हिन्दी] पांच तत्वों - आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, आग्नि - का अनेक लोगों ने उल्लेख किया। इसी से हम बने हैं, सारी सृष्टि बनी है। प्राणी, वनस्पति, हम सब इसी से बने हैं। मुझ से अगर कोई पूछता है कि आपके एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का मंडेट क्या है तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूं कि इन पांच तत्वों की रक्षा करना और इन पांच तत्वों के बीच संतुलन पैदा करना - यही हमारा मंडेट है। अगर इसे दूसरी भाषा में कहूं तो अभी-अभी वेंकैया जी आए हैं और जैसे वेंकैया जी कहते हैं - 'एक हाथ में पर्यावरण का झंडा, दूसरे हाथ में विकास का एजेंडा।' इसका एक बड़ा मिथ तैयार किया गया कि मानो विकास पर्यावरण के खिलाफ है। पर्यावरण की रक्षा का मतलब विकास को बंद करना -

ऐसा नहीं है। हमारी धारणा है - [अनुवाद] पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों। विनाश के बिना विकास हमारा आदर्श वाक्य है। [हिन्दी] इसलिए इसका कार्यक्रम क्या है? जो आप सभी ने बताया, वही इसका कार्यक्रम है - [अनुवाद] स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और अधिक हरिता। [हिन्दी] मुझे लगता है कि ये ही हमारे पांच सूत्र हैं, जिनके आधार पर हम चलना चाहते हैं।

अब मैं लीगेसी की बात नहीं करूँगा कि कैसे मिला, लेकिन कभी-कभी गलत जानकारी के आधार पर या असत्य जानकारी के आधार पर लोग कुछ भी कहना शुरू करते हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम आती है। वे बोले कि आप आने के बाद क्लियरेंस ही देने लगे हैं। मैं केवल तीन आँकड़े बताता हूँ और जिन्होंने यह उठाया है, वे इसे ध्यान में रखें। वर्ष 2012 में 1,522 परमीशंस दी गईं और एरिया डायवर्ट हुआ 25 हजार हेक्टेयर, वर्ष 2013 में नम्बर ऑफ प्रपोजल्स 1,317 को मान्यता दी गई, एरिया डायवर्ट किया 41 थाउजेंड हेक्टेयर, वर्ष 2014 में नम्बर ऑफ प्रपोजल्स सैंक्शंड 783 हैं, क्योंकि पिछले साल चुनाव भी था और बाद में हम आए तो इतना ही हुआ है। पहले तीन महीने में वीरप्पा मोइली जी थे और एरिया डायवर्टेड 35 हजार हेक्टेयर, यह कम हुआ है तो 1500, 1300 और 783 हुए हैं। लेकिन क्या परमीशन देना गुनाह होता है? पर्यावरण की रक्षा की शर्तें रखकर, पहले क्या होता था और आज फर्क इतना ही हुआ कि हमने प्रोसेस ट्रांसपेरेंट किए हैं। हमने प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से की हैं, ऑनलाइन कर दी हैं। ऑफिस-ऑफिस खेल बन्द कर दिया है। इसलिए लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था, वह नहीं देना पड़ता है। ...*(व्यवधान)* [अनुवाद] यह बिना कमीशन के मिशन है। यही अंतर है। यही हम कर रहे हैं। ... [हिन्दी] *(व्यवधान)*

गौरव भाई, मैं इस पर भी आता हूँ। मैं मूल मुद्दे पर कहना चाहता हूँ कि हम काम क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि फॉरेस्ट राइट डाइलूट किया। अरे भाई, फॉरेस्ट राइट के मंत्री इधर बैठे हैं, फॉरेस्ट राइट का डोमेन उनका है, मैं उनके कानून बदल नहीं सकता हूँ। कहीं भी वर्ल्ड बैंक को हमने कुछ लिखकर नहीं दिया। कुछ भी पेपर में आ गया, उसे सच समझकर हम बोलने लगे तो जरा गड़बड़ होती है। एन.बी.डब्ल्यू.एल. के लिए कहा कि यह पूरी हुई ही नहीं, एन.बी.डब्ल्यू.एल. पूरी हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी मुझे मिले। हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की। मनमोहन सिंह जी ने 17 प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके रखा था।

एन.बी.डब्ल्यू.एल. की 17 महीने बैठक ही नहीं हुई थी, मैंने बैठक की। ...*(व्यवधान)* पहले ही दिन, मैं झगड़े के मूड में नहीं कहना चाहता, आपसे अपील कर रहा हूँ, ...*(व्यवधान)* आप समझ लीजिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये 17 प्रोजेक्ट्स पहले ही दिन, क्योंकि पहले से ही एजेंडा था, पूर्व प्रधानमंत्री जी के प्रायोरिटाइज 17 प्रोजेक्ट्स देश के हित के थे, लेकिन उनके समय में मान्यता नहीं मिली थी, हमने वह पहले ही दिन दे दी। हमने क्या गलत किया?

अब रक्षा की बात आती है। पूरे भारत की सीमा, सीमा सुरक्षा के रास्ते, बॉर्डर रोड्स 6 हजार किलोमीटर के पेंडिंग थे। [अनुवाद] वे वर्षों से लंबित क्यों हैं? [हिन्दी] हमने कहा कि पॉलिसी डिजीजन होना चाहिए, देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा। हमने पॉलिसी डिजीजन लेकर सारी बॉर्डर रोड्स को जनरल अप्रूवल दे दिया, 6 किलोमीटर की रोड्स दिए, लेकिन पर्यावरण की शर्तों के साथ समझौता नहीं किया।

कारवार में ऑपरेशन सी-बर्ड प्रोजेक्ट है, जो नेवी के लिए महत्वपूर्ण है। दस साल से नेवी उसे मांग रही है। आपके भी सदस्य मेरे साथ रक्षा मंत्रालय की कमिटी में थे। हम देख रहे थे कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कभी भी हमला होता है, [अनुवाद] हमें मुंबई के अलावा दो अन्य केन्द्रों की आवश्यकता है। [हिन्दी] इसलिए एक कारवार का करना था, इसके प्रोजेक्ट की फाइल तीन साल पेंडिंग रही, मैंने तीन दिन में क्लियर किया, मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई गलत काम किया। यह देश कि लिए किया। इसमें क्या गलत है? [अनुवाद] यह किया जाना चाहिए। [हिन्दी] हम सबको करना चाहिए।

फॉरेस्ट डेफिनेशन की बात की गई। हमने कोई फॉरेस्ट डेफिनेशन नहीं बदली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? हम स्टेट को पूछ रहे हैं। सभी स्टेट्स के जवाब आए हैं। सब राज्यों के जवाब को हम सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे कि सभी राज्यों ने यह कहा है कि ऐसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति खुद प्लांटेशन करेगा, उसको भी फॉरेस्ट मानोगे, ऐसा पहले कोई अर्थ लगाया था। यह गलत है। [अनुवाद] हरे रंग का आवरण जंगल के बाहर है।

[हिन्दी] यह कहा गया कि ट्राइबल की ग्राम सभा का राइट रद्द कर दिया, हमने ऐसा नहीं किया। [अनुवाद]
मुझे एक दस्तावेज दिखाएं जहाँ हमने ग्राम सभा को समाप्त कर दिया है। [हिन्दी] हमने ऐसा नहीं किया है।
आदिवासियों के लिए मैंने काम किया। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैया नायडू): महोदया, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा कि, पहले यह निर्णय लिया गया था कि हमें आज छह बजे गिलोटिन मिलेगी और तब तक माननीय मंत्री जी को अपना जवाब पूरा करना होगा। लेकिन कई माननीय सदस्य सुबह और दोपहर में भी मुझसे मिले थे और अभी यह कहते हुए कि स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि इसे गिलोटिन किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि हम चर्चा जारी रखेंगे और हम स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर भी चर्चा करेंगे और फिर हम कल उसी समय गिलोटिन लेंगे और फिर कल के बाद वित्त विधेयक पर विचार करेंगे... (व्यवधान) हम इसे कल शाम 5.30 बजे तक पूरा कर सकते हैं और फिर अन्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, मेरी एक बात है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री वेणुगोपाल, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। झगड़ा नहीं। लेकिन पहले मैंने श्रीमती टीचर को बुलाया है।

श्रीमती पी. के. श्रीमती टीचर (कन्नूर) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा पर कुछ मिनट के लिए बोलनी चाहती हूँ... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदया, कार्य मंत्रणा समिति ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि गिलोटिन 28 अप्रैल, 2015 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। इसे आज के ऑर्डर पेपर में भी सूचीबद्ध किया गया है। कल से हम एक विस्तृत चर्चा के लिए बहस कर रहे हैं लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि समय की कमी है और स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करना संभव नहीं है। अब सरकार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने

की क्या तात्कालिकता है? (व्यवधान) अब सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कल होगी और जब भी सरकार ऐसा कर रही है। सभा को हल्के में लिया जा रहा है। कार्य मंत्रणा समिति की कोई भूमिका नहीं है... (व्यवधान) क्या सरकार को कल वित्त विधेयक लाने में कोई असुविधा हो रही है? उन्हें बता दें कि... (व्यवधान)

श्री एम. वेकैया नायडू: सरकार की सराहना करने के बजाय आप सरकार को दोष दे रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: क्या कल वित्त विधेयक लाने में सरकार को कोई असुविधा हो रही है?... (व्यवधान)

श्री एम. वेकैया नायडू: यह आश्चर्यजनक है। सदस्य और संसद सर्वोच्च हैं। जब सभा के माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करना चाहते हैं और मैं उस पर सहमत हूँ, तो आपको क्या समस्या है?... (व्यवधान) मैं समझ नहीं पा रहा हूँ... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहले हमने इसके लिए तर्क दिया था और उस समय सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी।.. (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं हाउस की राय ले लेती हूँ। [अनुवाद] श्री वेणुगोपाल, मैंने आपको भी सुना है। इस पर और कोई चर्चा नहीं। सिर्फ श्रीमती टीचर ही नहीं, इसके लिए बहुत सारे अनुरोध थे। माननीय सदस्य चाहते थे कि स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की मांगों पर भी चर्चा की जाए। मैंने उस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री के साथ चर्चा की, या आप सरकार कह सकते हैं।

[हिन्दी]... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उनसे भी बात की है और कहा है कि अगर हाउस के बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं, आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और हाउस इसके लिए एग्री करता है तो [अनुवाद] हम कल गिलोटिन लेंगे और कल के बाद सभा वित्त विधेयक पर विचार

करेगी। यही कारण है कि वे सहमत हैं। अब, अगर सभा आज सहमत होती है तो हम इस मंत्रालय को पूरा कर लेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया था और यदि वह सभा में आता है तो सभा निर्णय लेगी। सभा सर्वोच्च है और हमारे पास वित्त विधेयक को पारित करने के लिए इस महीने की 30 तारीख तक का समय है। इसलिए समय आ गया है। यदि सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए सहमत हो रही है, तो यह अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष: आपके लिए मैंने वास्तव में उसके साथ चर्चा की और वह इसके लिए सहमत हो गये हैं और यदि आप चाहें तो हम इसे पूरा करेंगे।

... (व्यवधान)

डॉ. एम. थम्बीदुरई (करूर): मैंने पहले अनुरोध किया था कि सभी छह मंत्रालयों की मांगों पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए, आइए हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मांगों को भी लें। जैसा कि कहा गया है, यह सभा सर्वोच्च है। सभा विचार-विमर्श के लिए होता है। उस मामले में मंत्री जी को जवाब देने का अवसर मिलेगा। यहीं पर स्थायी समितियों की प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। मंत्री स्थायी समितियों का हिस्सा नहीं है। इस बार हमने छह मंत्रालयों को लिया है। मैं माननीय महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष अगले बजट सत्र में अधिक मंत्रालय लेंगे ताकि सदस्यों को सभा में मांगों पर चर्चा करने के अधिक अवसर मिलें और संबंधित मंत्री जवाब देंगे, जिससे सदस्यों को जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ... (व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एकतरफा निर्णय नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदया से मुलाकात की; कुछ सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की और मुझसे बात की।

माननीय अध्यक्ष: मैंने एक अनुरोध किया क्योंकि आप भी अनुरोध कर रहे थे।

... (व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: मैं श्री वेणुगोपाल जी के साथ साझा कर सकता हूं कि मुझे एक व्यावहारिक समस्या है। हमारे मंत्री जी को राहत उपायों की देखभाल के लिए कल बिहार जाने के लिए कहा गया है। फिर भी, मैंने उनसे कहा कि चूंकि यह सदस्यों की एक लोकप्रिय मांग है, इसलिए वह रुक सकते हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। ऐसा होने पर, जब सदस्य अनुरोध करते हैं, तो सभा सर्वोच्च होता है और वह इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री वेणुगोपाल, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं।

... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: फिर आपके पास पर्यावरण और वन मंत्रालय पर चर्चा के लिए अधिक समय है। आप इसके लिए समय बढ़ा सकते थे। ... (व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: स्वास्थ्य धन है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं अब सभा का विचार जानना चाहूंगी। यदि सभा को यह उचित लगता है, तो हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा कर सकते हैं और फिर, कल शाम 5.30 बजे के आसपास, हमारे पास गिलोटिन होगा।

क्या यही सदन की भावना है?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : दो-तीन मुद्दे और उठाए गए। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जानकारी देने के लिए जवाब दे रहा हूं। [अनुवाद] ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहां तर्क नहीं जीतना चाहता; मैं आपका विश्वास जीतना चाहता हूं क्योंकि हम सभी को पर्यावरण की रक्षा करनी है। इसलिए, मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। टी.एस.आर. के बारे में सुब्रमण्यम समिति की प्रतिवेदन, [हिन्दी] लोगों को ऐसे लगा जैसे

कानून बन गया है। नहीं बना है। [अनुवाद] यह एक प्रमुख इनपुट है। [हिन्दी] कहीं तो शुरुआत होगी। बीस-बीस साल पुराने कानून हो गए हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं। एनवायरमेंट पर ज्यादा खतरा है। कानून में सख्त बदलाव जरूरी है कि एनवायरमेंट की रक्षा करें। इसके लिए अगर हम एक कमेटी नियुक्त करते हैं तो [अनुवाद] समिति हमारी चर्चा का आधार बनती है। [हिन्दी] मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट भेजी, सबकी राय ली है। जिनकी नहीं आई है, 30 अप्रैल तक वह भी आ जाएगी। [अनुवाद] इसलिए, हम सभी से परामर्श कर रहे हैं। यह कानून नहीं है।

अरनमुला हवाई अड्डे के बारे में, केरल के मेरे दोस्त को पता है कि भारतीय संविधान है। [हिन्दी] यू.पी.ए. सरकार ने अरनमुला एयरपोर्ट को परमिशन दी थी। एन.जी.टी. ने उसे निरस्त किया। [अनुवाद] उच्चतम न्यायालय ने भी एन.जी.टी. के फैसले को बरकरार रखा। [हिन्दी] लेकिन कानून में उन्हें पुनः ऐप्लीकेशन देने की परमिशन है। उसे मैं नहीं निकाल सकता। [अनुवाद] इसलिए, उन्होंने आवेदन किया है लेकिन हमने टी.ओ.आर को भी मंजूरी नहीं दी है। [हिन्दी] कहीं मुद्दा है। एयरपोर्ट से हवाई जहाज तुरंत दौड़ने लगे, ऐसे मत कहिए। कुछ नहीं हुआ है। ओवेसी जी हमारे मित्र हैं। टेनरी, कानपुर, गंगा मैली हो गई। पहले गाना था कि गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते-धोते। यह सच नहीं है। गंगा मैली इसलिए हो गई है या देश में सभी नदियां मैली हो गई हैं। सी.ए.जी. की एक रिपोर्ट है। हमने सी.ए.जी. के 2जी, कोल और बाकी रिपोर्ट पढ़ीं, लेकिन [अनुवाद] भारत में जल प्रदूषण की स्थिति, [हिन्दी] यह बेहतरीन रिपोर्ट तीन साल पहले दी। जिसमें उन्होंने कहा है [अनुवाद] औद्योगिक प्रदूषण का लगभग एक तिहाई हिस्सा जल निकायों में अनुपचारित हो जाता है; घरेलू कचरे का आधा हिस्सा, क्योंकि इसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है, अंततः जल निकायों में चला जाता है; उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाला दो-तिहाई कृषि अपशिष्ट नीचे की ओर रिसता है और जल निकायों में जाता है। यह भारत में जल प्रदूषण का कारण है। [हिन्दी] फ्लोराइड बढ़ा है, आर्सेनिक बढ़ा है, पानी जो खराब हुआ है, उसकी यह कहानी है। आप सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़िए। मुद्दा है कि अगर इसे ठीक करना है तो हमें नदी में सारे प्रदूषण आने से रोकने चाहिए। टेनरी की स्थिति मालूम है कि सब बड़े उद्योगपति नहीं हैं। टेनरी के लिए हमने स्पेशल पैकेज किया। उनके साथ मीटिंग हुई। राज्य सरकार भी साथ

है। 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है। वह कुछ कौन्ट्रीब्यूट कर रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देगी। यह सब मिलकर होना है। जहां लोन्स की फैसिलिटी है, वह होगी। लेकिन पानी शुद्ध रखना है या नहीं। आपने आह्वान किया कि पानी शुद्ध रखिए। उसके लिए उपाय करेंगे तो थोड़ी कॉस्ट लगेगी। लोग कॉस्ट भी देने के लिए तैयार हैं इसलिए आप दिक्कत पैदा न करें। आज देश और दुनिया की हवा बहुत ही खराब है। सारी दुनिया में पोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही पोल्यूशन है और दुनिया के बाकी शहर पाक-साफ हैं। यह सैंकड़ों शहरों की बीमारी है। हर पांच से आठ साल में विहकलों की संख्या बढ़ जाती है। दिल्ली के आसपास जो स्टबल बर्निंग होता है उससे भी पोल्यूशन होता है। दिल्ली की हवा में खराबी आने का एक और कारण कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली डस्ट है। आप सभी को सदन से पूछना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हो?

मैं बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने दो सप्ताह पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स लांच किया, जिसमें केवल एक पैरामीटर नहीं है बल्कि आठ पैरामीटर बनाए गए हैं। जिसका उल्लेख मेरे एक मित्र ने किया है, इसमें एस.ओ.एक्स.-नॉक्स, बेंजाइन, पी.एम. पार्टिकल 2.5 सबको मिलाकर एक काम्प्रिहेन्सिव एयर क्वालिटी, एक कलर, एक कोड में मिलता है। दस शहरों में इसकी शुरुआत हुई है। हम एक साथ सात शहरों का बुलेटिन रोज सुबह 12 बजे देंगे कि पिछले 24 साल की हवा कैसी थी। उसका पूरा विस्तार से बुलेटिन होगा, उसे भी आप छापें। यह ऑफिशियल डाटा होगा। हमें जनता से कुछ भी छुपाना नहीं है। जनता को अवेर करना है, उन्हें भी पार्टिसिपेट कराना है, इस एक्शन में उनकी भी सहभागिता जरूरी है। हमने कंस्ट्रक्शन के रूल्स तैयार किए हैं। हमने अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। हम मेट्रो का काम देखने गए थे। मेट्रो में रोज टनेलिंग होती है, लेकिन उससे धूल नहीं निकलती है, क्यों? श्रीधरन जी ने उसके लिए नियम-कानून ठीक बनाए। अगर मेट्रो का कारोबार अच्छी तरह से चलता है तो हम क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन बेस्ड रूल्स बना सकते हैं? हमारा ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है, वह जल्द ही वेबसाइट पर आ जाएगा और जल्द ही कंस्ट्रक्शन बेस्ड रूल्स लागू हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन बेस्ड धूल दिल्ली की हवा खराब नहीं कर पाएगी। हरियाणा और पंजाब सरकार ने स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए प्रोत्साहन दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने इसे रोकने के लिए काम करने का भरोसा दिलाया है। स्टबल बर्निंग नहीं होने से हम स्वच्छ हवा ले सकते हैं। हरियाणा में तीन जगहों पर

एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है। हम सब को मिलकर एक्शन लेना है। मैंने दो मीटिंग की, डी.डी.ए., दिल्ली गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, तीनों कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस इन सभी का इसकी रोकथाम में अहम रोल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक दिन साइकिल चलाओ, साइकिल चलाना चाहिए। इन्होंने शुरू भी किया है, इनकी सेहत भी अच्छी हो गई है। जनता को भी लेन डिसीजन का पालन करना चाहिए। [अनुवाद] यह एक सार्वजनिक कार्रवाई है जो हवा को साफ करेगी। [हिन्दी] सीमेंट इंडस्ट्री के नियम को हमने काफी स्ट्रिन्जेंट किया है, पहले यह काफी पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी। 1,75,000 रिन्यूएबल इनर्जी क्रिएट करने के लिए हमने सात साल का कार्यक्रम बनाया है। दुनिया में किसी देश ने ऐसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नहीं बनाया है। इससे 350 मिलियन टन इमिशन कम होगा। हम एनर्जी एफीशेंसी बढ़ा रहे हैं।

महोदया आपको पता होगा कि अंडमान में 70 मेगावाट बिजली लगती है, जो डीजल से पैदा होती है। उससे प्रदूषण होता है। अंडमान में हम बायो मास एनर्जी को वुडवेस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। [अनुवाद] हम इस वर्ष एक पायलट परियोजना शुरू कर रहे हैं। [हिन्दी] मुझे विश्वास है कि दो साल में हम दुनिया को ग्रीन कोल क्या होता है, यह दिखायेंगे। हम अंडमान को पूरी तरह से बायो मास एनर्जी दे सकते हैं। हम इस तरह के कार्यक्रम करना चाहते हैं और यह हमारी प्रतिबद्धता है। मैंने भी इसमें काम किया है। मैंने जल संवर्धन का काम किया है। मैं देहात में रहा हूँ और मैंने आदिवासियों के साथ भी काम किया है। मैं जंगल में भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। मैं दुनिया के दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ। मैंने पानी की शुद्धता के बारे में बात की। कुछ लोगों ने तालाब, झील, वेटलैंड्स आदि बहुत अच्छे सुझाव दिये। इनकी रक्षा के लिए भी जन-आंदोलन, जल साक्षरता चाहिए, क्योंकि लोगों को पानी की बचत करने के बारे में सीखना चाहिए। साथ ही साथ पानी को साफ रखने के लिए भी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। हम नया तंत्र ज्ञान में भी लायेंगे, नये कार्यक्रम भी लायेंगे और जनता का भी सहभाग लेंगे। हम नदियां भी साफ करेंगे। गंगा की सफाई तो अभी शुरूआत है। बाकी नदियों की सफाई भी क्रम से शुरू होगी। स्वच्छ भारत का यही अर्थ है। हमारा मिशन ही क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है, इसलिए हम इसे करेंगे।

महोदया, पानी के बाद वेस्ट बड़ा प्रॉब्लम है। हम समझ नहीं रहे, जैसे एक बहन ने सीवरेज ट्रीटमेंट का उल्लेख किया। उन्होंने सच कहा कि हमारे देश में कैपसिटी कितनी है? हमारे देश में लगभग 35-40 फीसदी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है और वे भी आधी-अधूरी चल रही हैं, यानी सब नहीं चल रही हैं। सीवरेज ट्रीट नहीं होता, तो वह नदियों में जाकर मिलता है, इसलिए पानी खराब है। हमने इसका बड़ा कार्यक्रम लिया है। प्रधान मंत्री जी ने शौचालय के निर्माण में बहुत जोर दिया। वह भी हैल्थ का मुद्दा है। हमें इसे भी करना है। अब हम सॉलिड वेस्ट कैसे करेंगे? मैं आपसे कहूंगा कि आप आज कृपया हमारी वेबसाइट एम.ओ.ई.एफ. पर जाइये। इस मिनिस्ट्री का पहले मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरन्मेंट एंड फॉरेस्ट नाम था, इसलिए अभी तक वेबसाइट का नाम वही है। आप एम.ओ.ई.एफ.ओ.आर.जी. में जाइये। मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। हमने अपनी मिनिस्ट्री वेबसाइट पर पांच नये ड्राफ्ट रूल्स प्रकाशित किये हैं--सॉलिड वेस्ट रूल, बायो मेडिकल वेस्ट रूल, ई वेस्ट रूल, अब ई वेस्ट की समस्या भी हमें समझनी चाहिए। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में सौ करोड़ मोबाइल फोन हो गये। अब सौ करोड़ मोबाइल फोन हो गये तो तीन साल में ये सौ करोड़ मोबाइल कचरे में जाने वाले हैं। यदि आज वे कूड़े में जाते हैं, तो वे उसका कूड़े में केवल प्रेशियस मेटल निकालते हैं और बाकी सारी चीजें लीच करके सारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इस ई वेस्ट को कौन ठीक करेगा? हम नये रूल्स लेकर आये हैं। प्लास्टिक वेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि 15 हजार टन रोज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से नौ हजार टन कलैक्ट होता है और छः हजार टन वैसे ही पड़ा रहता है। हमने इस पर काम नहीं किया तो हमें आगे बताना पड़ेगा। आपसे कोई पूछेगा कि अरे, आप कहां रहते हो, तो हम कहेंगे कि वह प्लास्टिक का बड़ा ढेर है, हम उसके पीछे रहते हैं। हमें यह काम करना पड़ेगा। हमने प्लास्टिक वेस्ट के रूल किये हैं, बायो मेडिकल वेस्ट के रूल किये हैं, हैज़र्डस वेस्ट के रूल किये हैं। ये सारे ड्राफ्ट्स हैं। अभी डेढ़ महीना उसका बाकी है, इसलिए आप भी उसे पढ़िये और सुझाव दीजिए। यह कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा नहीं है, यह देश है। हमें देश के वेस्ट को ट्रीट करना है। यही पर्यावरण की रक्षा है। मैं और किरीट सौमेया मुम्बई के डंपिंग ग्राउंड में गये। वहां 10 हजार टन वेस्ट इकट्ठा होता है। इस 10 हजार टन वेस्ट पर हजारों रैगपीकर्स थे। मैंने उन सबसे बात की। मैंने कहा कि आप प्लास्टिक क्यों नहीं उठाते, तो उन्होंने कहा कि छोटा प्लास्टिक जो पतली पनी का है, उसे यदि हम चार सौ

इकट्ठा करेंगे तब जाकर हमारा एक किलो वजन होता है। उससे हमारा पेट नहीं भरता और चार सौ बार हमें झुकना पड़ता है। देश में जब कोई व्यवस्था नहीं थी तब से रैगपीकर्स ने इस देश में अच्छे कूड़े-कचरे की व्यवस्था की। मैं रैगपीकर्स को सम्मानित करना चाहता हूं। हम उन्हें सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे और स्किलिंग भी करेंगे। यह करने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* वे दोनों बैठे हैं और एक दूसरे का दर्द भी समझते हैं। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : एक का लेफ्ट हैंड है और दूसरे का राइट हैंड है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश जावड़ेकर : हां, स्वास्थ्य मंत्री जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सायं 06.00 बजे

[हिन्दी]

सबने उल्लेख किया, हम कैबिनेट के सामने कैम्पा बिल ला रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए जमा हैं। दस साल प्रश्न क्यों नहीं उठा, यह मुझे आप सबसे पूछना है।

माननीय अध्यक्ष : छः बज गए हैं। अगर आप सबकी अनुमति हो तो यह पूरा होने तक हाउस एक्सटेंड कर देते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, कर दीजिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: कैम्पा फंड का 35,000 करोड़ रुपया राज्यों को बांटा जाएगा। 35,000 रुपए राज्यों को बांटने की चर्चा हो रही थी, इसमें से 90 परसेंट बांटने की बात थी। ...*(व्यवधान)* बिल क्यों लाना पड़ रहा है क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम राज्यों का पैसा राज्यों को देना चाहते हैं, वहां एफोरेस्टेशन होगा, वाइल्ड लाइफ के केयर होगी, बाकी स्कीम्स में पैसा मिलेगा। राज्य सरकार के बजट का कुछ भी हिस्सा कम नहीं करना चाहिए। एडीशनल फंड एडीशनल एफोरेस्टेशन के लिए होना चाहिए। उत्तराखंड के बारे में पूछा

गया, 35,000 करोड़ रुपए में से इसके लिए 2400 करोड़ है, आंध्र प्रदेश के लिए 2700 करोड़, अरुणाचल प्रदेश के लिए 1400 करोड़ रुपया है। हर राज्य का पैसा मिलेगा। मुद्दा यह है कि हम कैम्पा फंड को बांटना चाहते हैं क्योंकि हम एक्शन में बिलीव करते हैं। हम ग्रीनरी ज्यादा एग्रेसिवली चाहते हैं इसलिए डिग्रेडिड फोरेस्ट को ग्रीन करने की अनेक योजनाएं बना रहे हैं। हमें इसमें आप सबका सहयोग चाहिए।

एक बड़ी दिक्कत यह थी कि जंगल की प्रोटेक्टिड एरिया की सीमा कितनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक राज्य और केंद्र सरकार बफर जोन का सही सीमांकन नहीं करेंगी तब तक दस किलोमीटर का दायरा होगा। दस किलोमीटर तो ठप्प हो गया। हमने इस प्रॉसेस को जल्दी शुरू किया। हमने सब राज्यों से बात की, वर्कशाप्स ली। मैंने कहा कि पत्राचार से काम नहीं होगा, सबको बुलाओ, आमने-सामने बैठकर जो कमियां हैं उसे दूर करो लेकिन जस्टीफाइड बफर जोन तैयार करो। बफर जोन तैयार हुआ, हमने 130 बफर जोन की परमिशन दी है और डिफाइन किया है। इसकी सराहना कोर्ट ने भी की कि ऐसे काम होना चाहिए था, इतने सालों से नहीं हुआ, अब हो रहा है, अच्छा है।

माननीय सदस्य ने कार्बन क्रेडिट का उल्लेख किया। हम तो ग्रीन क्रेडिट देना चाहते हैं। कोश्यारी जी ने इसका सुझाव दिया। यह तो ऐसे हुआ कि पाप करो, कार्बन पैदा करो, हवा में छोड़ो और पैसे देकर पाप से मुक्ति पाओ। ऐसे नहीं होता है। आपको ग्रीन क्रेडिट ग्रीन एक्शन से मिलेगा, हम इस ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोच रहे हैं। फोरेस्ट कवर कैसे बढ़े? इसमें एन्क्रोचमेंट की समस्या है। डिग्रेडिड फोरेस्ट लैंड लगभग तीन करोड़ हैक्टेयर है। हमें तीन करोड़ हैक्टेयर लैंड को ग्रीन करना है। शहरों में जंगल जमीन पर एन्क्रोचमेंट होता है। हमने कम्पाउंड करने का निर्णय लिया। जनता की सहभागिता से स्मृति वन का काम शुरू किया। लोग पैसा भी देंगे, पेड़ भी लगाएंगे। प्रिय लोग, जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके स्मरण में लगाएंगे। अर्बन ग्रीन, रूरल ग्रीन करेंगे। डिग्रेडिड फोरेस्ट को घना करेंगे और कैम्पा फंड भी देंगे। एफोरेस्टेशन का काम करेंगे क्योंकि सारे देश को हरा भरा करना है।

वाइल्ड लाइफ की चिंता यहां पर अनेक लोगों ने की। यह सही है कि हमने अभी दो नये टाइगर पास किये। एक देश को अभिमान होना चाहिए कि आज दुनिया के 70 फीसदी बाघ अपने भारत देश में हैं और भारत

दूसरों को दे भी सकता है क्योंकि 2026 हैं और उसमें 1700 बाघों की तस्वीरें हमारे पास हैं। यह आइडेंटिटी अलग अलग होती है। ये आज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। आपने बजट की बात पूछी। एक्सटिंक्ट होने वालों के लिए हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनियों के पास भी गये और हरेक ने एक एक बर्ड के रिहैबिलिटेशन का काम लिया है, इंटरेस्ट दिखाया है। हम इसको आगे ले जाएंगे। एक एक जो एक्सटिंक्ट होने वाली प्रजाति है, उसकी हमें रक्षा करनी है। यह पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी होगा। हम भी उस पर ध्यान देंगे, कोआर्डिनेट करेंगे।

अब जैसे ह्यूमन एनीमल कांफ्लिक्ट है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। वर्ष 2014 में 500 लोग प्राणियों के हमले में मरे हैं। हम लोग उस बारे में कोई चर्चा कभी नहीं करते। क्या मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है? किसी अन्य देश में 500 लोग मरे होते तो उन देशों ने क्या किया होता? लेकिन हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मुझे लोगों ने बताया कि सर, प्राणी इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि अंदर पानी नहीं मिल रहा है या घास नहीं मिल रही है तो इस कारण से वहां प्रे नहीं आते हैं। इसलिए हम अभी यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जंगल में घास ज्यादा पैदा हो और पानी ज्यादा रहे। हम इस वाइल्ड लाइफ की तरफ ध्यान देंगे। हम इसको अच्छा बनाएंगे।

हमें एक प्रेशर समझना चाहिए। आप सब लोग इस बात को कृपया याद रखें कि दुनिया का केवल 2.5 प्रतिशत ही लैंड मास हमारे पास है। [अनुवाद] हमारे पास भूमि का केवल 2.5 % हिस्सा है। लेकिन हमारे पास दुनिया की 17 प्रतिशत मानव आबादी और 17 प्रतिशत मवेशियों की आबादी है। [हिन्दी] दुनिया की 17 फीसदी आबादी ढाई फीसदी जमीन पर रह रही है तो प्रेशर तो बनेगा। लेकिन इसका मतलब जंगल की एक इंच जमीन भी हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जंगल की जमीन अगर हम नहीं देंगे और अगर कहीं डाइवर्ट होता है तो उसके बदले में दुगुनी जमीन उसको देनी पड़ती है। वह नियम कायम है और यह बायोडायवर्सिटी ऐसी है कि दुनिया की आठ फीसदी बायोडायवर्सिटी हमारे देश में है। कितनी प्रजातियां हैं? कितने प्राणी और कितने फूल हैं तथा कितने नये प्राणियों की जानकारी तेलंगाना में दी गई।

मैं अभी श्रीशेलम में गया था। वह बॉर्डर में है। वह थोड़ा आन्ध्र प्रदेश में है और थोड़ा तेलंगाना में है। मैं वहां पर गया और वहां पर भी मैंने नयी प्रजातियां देखीं। यह नोगोया प्रोटोकॉल जो हुआ, अभी 6 महीने पहले

नोगोया प्रोटोकॉल में बायोडायवर्सिटी का प्रोटेक्शन और बेनेफिट एक्सेस तथा हमारे देश में इतनी अपार सम्पदा है, उसका फायदा भी हमें मिलेगा अगर दुनिया उसका यूज करेगी। इसलिए नोगोया प्रोटोकॉल को भी पचास देशों ने रैटिफाई किया है, वह लागू हो गया है। हम राज्यों को ताकत देना चाहते हैं। 40 हेक्टर फॉरेस्ट का अगर डाइवर्जन करना है तो हर फाइल मेरे पास आती थी। एक हैक्टर, दो हैक्टर, मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है? ये राज्यों के पास क्यों नहीं होता? वहां व्यवस्था विकेंद्रित होनी चाहिए। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि सर, अपने पास फिर फाइल ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि नहीं आने दो। मुझे फाइल में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट काम जल्दी होने में है...(व्यवधान) इसलिए हमने सारी रीजनल कमेटियां बनाई जिसमें हर राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसमें फॉरेस्ट के और रेवेन्यू के दोनों अधिकारी उसके मेंबर्स रहेंगे। हमने एक मल्टी स्टेट होल्डर कमेटी बनाई। उस कमेटी के आधार पर [अनुवाद] 90 प्रतिशत फाइल कार्य अब क्षेत्रीय और राज्य केंद्रों को सौंपा गया है। यही हम कर रहे हैं। [हिन्दी] हम अपने पास नहीं रख रहे हैं। हमने काम खुला किया है कि काम प्रामाणिकता से करो। लोगों ने चिंता व्यक्त की कि हम कहीं विश्व मंच के दबाव में तो नहीं आ रहे हैं। ओबामा जी के सामने एक पत्रकार ने मोदी जी से पूछा: [अनुवाद] 'श्रीमान, प्रधानमंत्री जी, क्या कोई दबाव है?' प्रधानमंत्री ने कहा, 'कोई दबाव नहीं है और हम दबाव नहीं लेते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर जलवायु परिवर्तन का दबाव, दबाव और दबाव है। [हिन्दी] उसके लिए हम काम करते हैं और उसमें हमारे जो एक्शन हैं, आज दुनिया सराह रही है कि आज भारत इतना एक्शन कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीमा में जो लड़ाई आखिरी दो दिन हुई, मैं बाकी किसी के लिए नहीं कहता कि कौन क्या करता था, मैं पहले दिन से सुबह 9 बजे से रात तक जब भी समाप्त होगा, मैं वहां बैठा रहा। सब देशों से बात करता रहा। सबसे नाता जोड़ा, नैट-वर्किंग की। पिछले महीने में 58 अफ्रीकन देशों की कांग्रेस हुई। उनके सभी पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने अफ्रीका के बाहर के केवल दो नेशंस बुलाए। उसमें एक फ्रांस था क्योंकि वह पेरिस का होस्ट है और एक ही कंट्री बाहर की बुलाई जो कि भारत था। हमें अभिमान होना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे हमदर्द हैं। हमने हमदर्दी दिखाकर वह काम किया और नेटवर्किंग की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत यू.एन. फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) का मेनडेट है, जो सी.बी.डी.आर. है, जो इक्विटी

है, इन प्रिंसीपल्स को ही हमने दुनिया को बताया है कि इसके अलावा नहीं चलेगा। फाइनल ड्राफ्ट में वही आया है। यू.एन.एफ.सी.सी.सी की इक्विटी भी आई, सी.बी.डी.आर. भी आया, मिटिगेशन भी आया, रेपुटेशन भी आया, फाइनेंस भी आया, टेक्नोलॉजी भी आया, कैपेसिटी भी आया। आज हम काम करके बताते हैं कि हम 2020 के पहले इतना एक्शन ले रहे हैं। हम कहते हैं कि आप भी आगे जा कर यह काम करो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण भारतीय लोगों की 'वे आफ लाइफ' है और इसे आगे ले कर जाना हम सब का काम है। पृथ्वी का और पांच तत्वों की रक्षा करना और संतुलन करना हमारा काम है। विकास बनाम पर्यावरण रक्षा का झगड़ा मत पैदा कीजिए, ऐसा नहीं है। दोनों काम साथ हो सकते हैं, दोनों की जरूरत है और हम दोनों एक साथ करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं केवल एक सदस्य से एक स्पष्टीकरण की अनुमति दूंगा। श्री गौरव गोगोई।

श्री गौरव गोगोई : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने वायु गुणवत्ता सूचकांक लागू करने के सरकार के प्रस्ताव के बारे में बात की थी, जिसे 37 विभिन्न स्थानों के 10 शहरों में लागू किया जा रहा है। यह प्रस्ताव अधूरा प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास पहले से ही अपना वायु निगरानी उपकरण है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु प्रदूषण की श्रेणी पर्यावरण मंत्रालय के वायु गुणवत्ता सूचकांक से अलग है। इन दोनों मंत्रालयों के वायु प्रदूषण की श्रेणियां वैश्विक मानकों से अलग हैं। [हिन्दी] जनता कन्फ्यूज है कि वह अर्थ साइंसिज़ पर, पर्यावरण पर या ग्लोबल हैल्थ पर किस पर विश्वास रखे। अगर हम यह सब डेटा ले भी लें तो हमें जनता को बताना पड़ेगा कि इतने प्रदूषण का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या जनता मास्क पहनना शुरू करे? जनता को कैसे प्रिकाशन और प्रोटेक्शन चाहिए [अनुवाद] हवा बहुत खतरनाक है। [हिन्दी] हमें इस बात से भागना नहीं चाहिए। [अनुवाद] हमें इसका सामना करने का साहस रखना चाहिए। [हिन्दी] हमें सिटिजन्स में मास अवेयरनेस पैदा करनी है, उसके लिए इस बजट में क्या प्रोग्राम है। जो खतरनाक हवा है, उससे हम जनता को कैसे बचा सकते हैं, इसे जनता को बताना पड़ेगा।

[अनुवाद]

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। मेरा दिल उसके साथ है। वह मस्तिष्क है; इसलिए मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक से स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। हमारा देश अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का उपयोग कर रहा है। इतना ही नहीं, हमने पूरे देश में सी.एफ.एल बल्बों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लगातार हम सी.एफ.एल लैंप के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूलों में भी, शिक्षक स्कूली बच्चों से कहते हैं, 'गुंडू बल्बों' का उपयोग न करें आप सी.एफ.एल. लैंप का उपयोग करते हैं। इसलिए, मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से आपसे जो स्पष्टीकरण चाहता हूँ, वह यह है। जब हम अधिक से अधिक पारा लैंप और सी.एफ.एल लैंप का उपयोग कर रहे हैं, तो वैसे भी यह एक और पारिस्थितिकी खतरा पैदा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, जैसा कि आपने सदन में कहा है, पारा एक अत्यधिक जहरीला और खतरनाक पदार्थ है। तो एक सी.एफ.एल. लैंप जो निष्क्रिय हो गया है, जिसका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसे जलाया नहीं जा सकता है, लोग क्या करते हैं कि वे इसे घर के बाहर फेंक देते हैं। वे इसे जमीन पर या जल संसाधन में कहीं फेंक देते हैं। पारा लैंप या सी. एफ. एल. लैंप का एक छोटा सा टुकड़ा भी भूमि और पानी को प्रदूषित करके आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक अपशिष्ट पैदा कर सकता है। यदि कोई कानून है तो उन कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम कुछ यूरोपीय देशों की तरह एक विधि अपना सकते हैं। वहाँ, सरकार विक्रेताओं को सामग्री वापस लेने के लिए कहती है, ताकि लोगों को इसे दुकानों पर वापस लाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जा सके। तो इस प्रकार के उपयोगकर्ता-विक्रेता संबंध, इस तरह की विधि को भारत में भी अपनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में बमुश्किल 30-35 ऐसे जिले होंगे, जिन्होंने रिज़र्व फॉरेस्ट रखा है। मैंने चार क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है, जहाँ पर रिज़र्व फॉरेस्ट है। 48 प्रतिशत फॉरेस्ट वाला

क्षेत्र- बालाघाट, छिन्दवाड़ा, सिवनी और वर्तमान में दमोह है, जहाँ पर दो अभयारण्य हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप ग्रीन क्रेडिट की बात करते हैं, ऐसे जिले देश में बमुश्किल 50 होंगे, क्या इनको ग्रीन क्रेडिट मिलेगी? हमें सड़क के परमिशन के लिए भी आना पड़ता है।

दूसरी बात, जो टाइगर रिज़र्व है, सर्वाधिक टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश में है, उसके बावजूद भी, पुरानी परम्परा है कि लोग उसकी हत्या करते हैं, इसलिए उसकी तस्करी होती है और अमूल्य चीजों को जलाने का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन जिलों को उनके विकास के लिए वही रास्ता मिलेगा और जो शेरों के अंग-प्रत्यंग जलाये जाते हैं, क्या उनको सरकार प्रेज़र्व नहीं कर सकती है? इतनी बहुमूल्य चीजों को क्यों जलाना चाहिए? सिर्फ़ इस डर से कि उनकी तस्करी होगी। इस कारण से ऐसे कानून बनते हैं, क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन(कोल्लम): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं लीमा सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की पूरी तरह से सराहना करता हूँ। मैं सरकार द्वारा उठाए गए रुख के साथ-साथ माननीय मंत्री श्री जावड़ेकर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ। लेकिन मैं उस चिंता को व्यक्त करना चाहूँगा जो हम अपने देश में अनुभव कर रहे हैं। सभी पर्यावरणविद और पूरा देश जानना चाहेगा कि क्या टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। मैंने अपने भाषण में विशेष रूप से कहा कि अगर इस टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की प्रतिवेदन को सरकार द्वारा लागू या स्वीकार किया जाता है तो यह निश्चित रूप से देश के लिए एक पर्यावरणीय आपदा होगी। यह संवैधानिक दायित्वों के साथ-साथ उन कानूनी दायित्वों का उल्लंघन होगा जो हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए किए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण या विशिष्ट उत्तर चाहता हूँ कि टी. एस. आर. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

डॉ. एम. थंबीदुरई: माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत पीने के पानी की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। हम इस समस्या का सामना क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी नदियां प्रदूषित हैं। न केवल गंगा और कावेरी बल्कि भारत की अन्य नदियाँ भी प्रदूषित हैं। वे प्रदूषित क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग अपना अपशिष्ट नदियों में छोड़ रहे हैं। इसके अलावा, हमारी नगर पालिकाओं में जो भी जल निकासी है, वह भी नदियों में जा रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, क्या सरकार उद्योगों को नदियों में अपना अपशिष्ट छोड़ने से रोकने और आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून लाने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक नैशनल पार्क, एक टाइगर रिजर्व और एक अभ्यारण्य- ये तीन फॉरेस्ट रिजर्व हैं और लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि घास और पानी की व्यवस्था करूंगा। मेरे क्षेत्र में उन जंगलों को खड़ा रखने के लिए एक सिंचाई योजना पिछले 42 साल से वन कानूनों के कारण लम्बित है। उससे 1,11,800 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी साथ ही साथ जंगल भी बढ़ेंगे। लेकिन उस योजना को वर्ष 1972 में स्वीकृति मिली थी, तब टाइगर प्रोजेक्ट नहीं लगा था। आज टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर उस योजना को पिछले 42 वर्षों से लम्बित रखा जा रहा है। यह चतरा में लातेहार जिले की योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के योजनाओं की स्वीकृति कैसे होगी?

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): अगर आप हमें हमारे द्वारा दिए गए, कटौती प्रस्तावों में से किसी एक पर बोलने की अनुमति दे रहे होते तो मैं आपसे समय नहीं मांगता। यही कारण है कि मुझे आपसे समय मांगना है। मैंने सीरियल नंबर 3 पर एक कटौती प्रस्ताव दिया था।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कट मोशन पर नहीं बोलना है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: मैं कटौती प्रस्ताव नहीं पढ़ूंगा। नई दिल्ली सहित महानगरीय शहरों में वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी हमें दुनिया भर की यात्रा पर ले गए हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका में लीमा में क्या हुआ और कैसे वे सुबह से रात के 2 बजे तक जागते रहे। मैं इस सब की सराहना करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस अपना स्पष्टीकरण पूछें।

प्रो. सौगत राय: महोदया, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं स्थायी समिति की प्रतिवेदन का हवाला दे रहा हूँ।

इसमें कहा गया है :

“स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक माने जाने वाले पी.एम. 2.5 सूक्ष्म धूसन कणों की सांद्रता दिल्ली में सबसे अधिक 153 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि डब्ल्यू.एच.ओ. मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। दिल्ली में पी.एम. 10 (मोटे कण) की सांद्रता लगभग 286 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।....”

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, आप केवल एक स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं इसे एक मिनट में समाप्त करूंगा। मैं एक बहुत ही सीमित विषय पर बोल रहा हूँ, जिस पर मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया है।

मैं मंत्री जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष हाल ही में दायर एक हलफनामे में कहा है कि नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की चुनौती

से निपटने के लिए अभी तक कोई अंतिम कार्य योजना नहीं है। स्थायी समिति ने यह भी सुझाव दिया कि एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

प्रो. सौगत राय: कृपया मुझे बोलने दें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे स्थायी समिति की प्रतिवेदन से पढ़ रहे हैं। आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

प्रो. सौगत राय: महोदया, जब तक मैं संदर्भ नहीं बनाता, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? ... (व्यवधान) मैं कोई अप्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछता। यह मेरी आदत नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए वाहनों को कम करने की कोई योजना है? आप दिल्ली के नागरिकों के जीवन को थोड़ा स्वस्थ कैसे बना सकते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, हाल ही में, बाघ गणना का परिणाम सामने आया था। उस गणना के परिणाम में, यह उल्लेख किया गया था कि बाघों की आबादी अत्यधिक बढ़ गई है। हमारा इससे कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह सब उल्लेख करता है कि ओडिशा में बाघों की आबादी में कमी आई थी जो तीन साल पहले थी। हमारे वन विभाग और ओडिशा सरकार ने इस पर आपत्ति जताई, और स्पष्ट रूप से कहा-मुझे लगता है, माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत हैं-कि ये तीन वन हैं- नवापारा का सतकोशिया वन, मयूरभंज का सिमलीपाल जीवमंडल, क्यौंझर और बालासोर-जहां वास्तविक गणना नहीं हुई है और बाघों की गिनती करने का तरीका संदिग्ध है।

महोदया, मैंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक नोटिस दिया है और मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन वैसे भी वह नहीं आया है। हम जो गणना हुई है उस पर इतना अधिक श्रेय ले रहे हैं। यह कथन कि इस

अवधि के भीतर हमारे बाघों की आबादी कई गुना बढ़ गई है, हमारे अपने वन विभाग द्वारा संदिग्ध हो गया है। इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए, क्या मंत्री जी कदम उठाएंगे और एक पूर्ण गणना के साथ सामने आएंगे और उन तथ्यों के साथ भी आएंगे कि किस राज्य में आज कितने बाघ हैं?

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि गांवों से लगे हुए वनों में इस वक्त रोज और सुअरों की संख्या बहुत बढ़ गयी है, क्योंकि उनमें छः महीने में प्रजनन होता है। रोज नीलगाय को कहते हैं। उनका प्रजनन इतना ज्यादा हो गया है कि वे किसानों के लिए समस्या बन गए हैं। इस समस्या के बारे में क्या माननीय मंत्री जी कोई समाधान कर रहे हैं?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जो वन का इलाका है - बाँका। वन की कटाई से, जलवायु में परिवर्तन से तथा पर्यावरण में प्रदूषण से देश का भारी नुकसान हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कौन से व्यापक एवं बड़े उपाय किए गए हैं? क्या दुनियाभर के वैज्ञानिकों से समन्वय करके इससे बचाव के उपाय करने के बारे में सरकार कोई विचार रखती है, क्योंकि तभी मेक इन इंडिया सफल होगा?

[अनुवाद]

डॉ. बूरा नरसैया गौड़ (भोंगीर) : महोदया, मैं इस अवसर पर, माननीय मंत्री श्री जावड़ेकर जी को धन्यवाद देता हूं। तेलंगाना एक बिजली की कमी वाला राज्य है। हमारे पास 6,500 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर परियोजना थी। सभी माननीय सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि माननीय मंत्री जी ने केवल 45 दिनों में 2,000 एकड़ के लिए वन मंजूरी दे दी है। मैं वास्तव में माननीय मंत्री जी का आभारी हूं।

साथ ही, उनका विभाग उत्तर और दक्षिण में काम कर रहा है। पर्यावरण मंत्री परियोजनाओं को साफ करने के लिए इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, एक काली चोटी की सड़क है। हैदराबाद में एक वन क्षेत्र है। पिछले आठ साल से ऊपर की काली सड़कों में बहुत सारे गड्ढे थे। हमारी सरकार ने ब्लैक

टॉप रोड के लिए बजट जारी किया है। मैंने डी.एफ.ओ से बात की है। यह पहले से ही एक मौजूदा सड़क है। यह एक बी.टी. सड़क है। लेकिन वे कभी भी मौजूदा सड़क पर सड़क की अनुमति नहीं देते। मुझे लगता है कि यह एक विरोधाभासी विभाग है। उनकी व्यवहार शैली जमीनी स्तर तक भी पहुंचनी चाहिए। यह मेरी अपील है।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): महोदया, मेरा एक विशिष्ट प्रश्न है। मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। वहां काफी अतिक्रमण हुआ है। परिसर की दीवार भी टूट गई है। अतिक्रमण जारी है। दरवाजे बनाए जा रहे हैं। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यह एक प्राथमिक प्रश्न है, जिस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

मेरा दूसरा सवाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में है। रत्नागिरी जिले में जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना बन रही है। वह परमाणु परियोजना भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत है। यह सरकार के भूवैज्ञानिक विभाग की प्रतिवेदन है जिसमें कहा गया है कि 1985 से 2005 तक 3.5 से 5.5 रिक्टर पैमाने पर 92 भूकंप आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह विश्व में बायोडायवर्सिटी में नम्बर एक पर है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 90 प्रतिशत फॉरेस्ट है, करीब छः से सात प्रतिशत अंडमान में रेवेन्यू/फॉरेस्ट लैंड पर आबादी है। मेरे दो सवाल हैं। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में वहां का दौरा किया था, तो उन्होंने कहा था कि देश में एक लाख करोड़ पाम ऑयल पड़ोसी देशों से आयात किया जाता है, जिसमें थाइलैंड और म्यांमार प्रमुख हैं। मेरी मांग है कि अंडमान में निकोबार आइलैंड में ग्रीन ग्रास लैंड है, डेजर्ट लैंड है, क्या वहां वृक्षारोपण की इजाजत देंगे या पोर्ट ब्लेयर में इसकी इजाजत देंगे? अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर डीमड फॉरेस्ट की घोषणा की थी कि उसे दोबारा डीरिजर्व किया जाएगा, करीब 61 हेक्टेयर लैंड है, क्या उसे डीफॉरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अंडमान-निकोबार के फॉरेस्ट को बचाया जाए, यह मेरा तीसरा प्रश्न है।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): काजीरंगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मंत्री जी अभी असम गए थे, तो हमने उनसे कहा था कि असम में राइनो जो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज है, उसे मारकर खत्म किया जा रहा है। पिछले दस साल में कितने ही राइनो मारे गए हैं। आप वहां के न्यूजपेपर्स में पढ़ सकते हैं कि रोजाना दो-तीन राइनो की हत्या होती है। इसके अलावा टाइगर्स मारे जा रहे हैं, हाथी मारे जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में मंत्री जी क्या एक्शन ले रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदया, जलवायु परिवर्तन के संबंध में, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पंचायत है, जिसे मांडू द्वीप समूह कहा जाता है। हाल ही में, समुद्र का पानी निवास क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। कई घरों को तोड़ा गया है। सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि, क्या भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वहां कोई अध्ययन किया है और कोई समाधान निकाला है।

श्री के. एन. रामचंद्रन : ई-कचरे को लेकर दहशत और दयनीय स्थिति है। ई-कचरे के मामले में हम दुनिया में पांचवें स्थान पर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ई-कचरे की इस भयावह एवं दयनीय स्थिति का कोई ठोस समाधान है।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हजारों-लाखों सालों से यह माना गया है कि अगर हवा की शुद्धि करनी है, हवा को अगर प्योरिफाई करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन यज्ञ और हवन है। यह कोई धार्मिक विधि नहीं है, लेकिन हवा और पर्यावरण को शुद्ध करने का सबसे इफैक्टिव मैथड है।

क्या माननीय मंत्री जी यज्ञ और हवन को ऑफिशियल रूप से मान्यता देंगे और उसे बढ़ावा देंगे?

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदया, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1974 है। हिली एरियाज में जंगली जानवर खासकर बंदर, सूअर और नीलगाय बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं हिमाचल की बात कहूं तो आज वहां पर 70 प्रतिशत किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आवारा कुत्ते इतने ज्यादा बढ़ गये हैं कि वे लोगों पर हमला कर रहे हैं और अगर कुत्ते पागल हो रहे हैं तो वहां की म्युनिसिपैलिटी या पंचायत उन पर काबू नहीं पा रही है। अभी हाल ही में पिछले महीने शिमला के मॉल रोड पर, जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिड एरिया है, वहां पर पचास लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया और वहां की लोकल म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकी। क्योंकि वहां का कानून उन्हें मारना अलाऊ नहीं करता है।

इसलिए मंत्री जी मेरा यह कहना है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो जंगली जानवरों को बचाया जा रहा है, क्या उसमें आप कोई संशोधन करेंगे?

[अनुवाद]

श्री सुरेश सी. अंगड़ी (बेलगावी): यह मानव के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कर्नाटक में खानपुर में बहुत घना जंगल है। यह महाराष्ट्र, गोवा और बेलगाम से घिरा हुआ है। दो महीने पहले, एक बाघ जंगल से खुले क्षेत्र में खेतों में आया था। रास्ते में कुछ हाथी भी आए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन किसानों को कोई सुरक्षा दी जा रही है। पहले से ही एक महिला की मौत हो चुकी थी क्योंकि एक बाघ ने महिला पर हमला किया था। सरकार ने अभी तक कोई जांच नहीं की है। इस मामले की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिये, सबकी बात आ गई है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं बहुत लम्बा उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन सब मुद्दे बताऊंगा। [अनुवाद] सी.पी.सी.बी. ने पहले ही सी.एफ.एल. लैंप के सुरक्षित व्ययन के लिए दिशा-निर्देश विकसित कर लिए हैं। [हिन्दी] इसके अलावा

जो ई.-वेस्ट रूल्स है, जो ड्राफ्ट है, उसे सम्पत जी आप भी पढ़िये। सम्पत जी, आप अच्छे हो तो उसे पढ़ो और हमें सुझाव दो और अगर कुछ बदलाव करना है तो बताइये, हम वह करेंगे।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी का जो मुद्दा है, एक्शन यह तय किया है। यहां चार कारणों से पॉल्यूशन होता है, एक व्हीकलर पॉल्यूशन, दूसरा स्टबल बर्निंग, तीसरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट और चौथा जो धूल आती है, जो रेगिस्तान से भी आती है, ऐसे बहुत से कारण हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो बायोमास जलाते हैं तो हम दिल्ली में बायोमास न जलायें, इसके लिए स्वीपर्स के प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिल्ली सरकार और कारपोरेशंस ने तय किया है। उसमें सबको अवेयर भी करेंगे और लोगों को यह भी कहा गया है कि व्हाट्स एप पर तुरंत लेकर बताइये और लोगों ने दिखाना शुरू भी किया है और उस पर तुरंत एक्शन भी हो रहा है। ...*(व्यवधान)* व्हीकलर पॉल्यूशन की बाबत फ्यूल की एफिशिएंसी और यूरो नॉर्म्स को लीपफ्रॉग करना है, यह एक बड़ा इश्यु है। [अनुवाद] संबंधित मंत्री और मंत्रालय दोनों इस मामले से अवगत हैं। हमें उम्मीद है कि यह बहुत जल्द एक अच्छी खबर लाएगा। यह दूसरी बात है।

[हिन्दी] एन.एच.ए.आई. और हरियाणा सरकार ने जो रिंग रोड बनाने की जरूरत है कि नॉन-डेस्टाइन व्हीकल्स दिल्ली में नहीं आने चाहिए, जो दस हजार की संख्या में आते हैं। वे बाहर से ही जाएं, इसके लिए दो साल में यह रास्ता पूरा होगा, तब होगा। सौगत राय जी आपको मालूम है कि दिल्ली की हवा दस महीने में नहीं बिगड़ी। यह बहुत सालों का परिणाम है। इसलिए अब हमने एक्शन शुरू किया है और इसका परिणाम आएगा, आप देखेंगे। पहला परिणाम तीन महीने का एक्शन प्रोग्राम है, उसका रिजल्ट हम जुलाई में ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: आप इसे डब्ल्यू.एच.ओ. मानकों तक लाते हैं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैं आपको यही बताता हूँ। सौगत राय जी, आपके लिए मेरे मन में सबसे अधिक सम्मान है। [हिन्दी] हमारी साइक्लॉजी ऑक्सिड इलाज की है। एक बार दिल्ली के प्रदूषण की बहुत चर्चा हुई, उस समय जगमोहन जी मंत्री थे, लोगों ने कहा उद्योगों से प्रदूषण होता है, उन्होंने उद्योग बाहर किए। ...*(व्यवधान)* दूसरी

बार फिर हुआ कि प्रदूषण बढ़ता रहा तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि सी.एन.जी. लागू की जाए तो सी.एन.जी. आ गई, फिर लोगों को लगा कि अब प्रदूषण का खतरा खत्म हुआ है। ऐसा नहीं होता है। फिर आया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदलना चाहिए तो मेट्रो आई। अब तीस लाख लोग मेट्रो से जा रहे हैं। [अनुवाद] यह एक स्वच्छ यात्रा है लेकिन फिर भी यह समस्या पर लगाम नहीं लगाती है। आपको रोजमर्रा के सुधार और कार्रवाई करनी होगी, और हम आपके साथ मिलकर ऐसा करना जारी रखेंगे। [हिन्दी] यह हम करेंगे। एयर क्वालिटी के बारे में गौरव जी ने पूछा है। इन दोनों विभागों में कोई अंतर नहीं है, हम एक साथ काम कर रहे हैं। जो अभी नए इंडेक्स की सारी जानकारी आ रही है, [अनुवाद] हम इसके साथ तालमेल बना रहे हैं [हिन्दी] कभी-कभी पेपर में आधी जानकारी के आधार पर न्यूज़ आती है, उस पर हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, सबने सवाल पूछा है कि जंगलों में जब प्राणी बढ़ते हैं तो खेती के किसानों को नुकसान होता है, यह एक सही प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने आदेश दिया है कि राज्य सरकार स्पेसिफिक क्षेत्र में स्पेसिफिक महीनों के लिए या एक साल के लिए अगर कहेगी कि तो हम इसको करेंगे। पहले तो यह ब्लू बुल है, उसको गाय मत कहो, वह रोज है, जो भी शब्द यूज करना है करो, लेकिन वह गाय नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसलिए इनको वर्मिंग डिक्लियर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है तो हम तुरंत बंदर हो या रोज हो, जहां आतंक है, वह तुरंत हम उसको मंजूरी दे रहे हैं। उस पर लोकल एक्शन होगा। ...*(व्यवधान)* आपने जंगल में सड़क के बारे में पूछा है, जो उदाहरण आपने हैदराबाद का बताया है, मैं तुरंत चेक करूंगा, क्योंकि छह महीने पहले हमने आदेश निकाला है। [अनुवाद] राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड [हिन्दी] की मीटिंग हुई, पहले यह नियम बनाया था कि जंगल में अगर सड़क बनी है तो कभी भी उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें गड़बड़ हो गए हैं। मैंने बैठक में पूछा कि यह तो आदिवासियों के ऊपर अन्याय है। आदिवासी रहते हैं, क्या उसको अच्छा रास्ता नहीं चाहिए? पॉलिसी डिजीज़न ले कर [अनुवाद] मौजूदा सड़कों का उन्नयन [हिन्दी] को हमने अलाऊ किया है, जहां पर नैशन हाईवे बहुत जरूरी हैं, अगर वहां नैशन हाईवे हैं, तो उसकी वाइडनिंग को भी मंजूर किया है, [अनुवाद] पर्याप्त शमन उपायों के साथ। [हिन्दी] उसमें रेलवे भी है। [अनुवाद] सभी रैखिक परियोजनाएं, [हिन्दी] चाहे इरिगेशन के लिए पानी ले जाना हो, पीने के लिए पानी लेना हो या ट्रांस्मिशन तार ले जानी हो, [अनुवाद] पारेषण लाइनें या सभी

पाइपलाइनें [हिन्दी] और रोड़ एण्ड रेल, ये लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, जो जाएंगे। मिटिगेशन मेज़र्स लेंगे और दोनों की रक्षा करेंगे, तो इसमें अभी यह नहीं रखा है। रिवर पॉल्यूशन एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हमने दो मैथड बनाए हैं। जो नदी के किनारे उद्योग हैं, उनको हम 24/77 घंटे चलने वाली [अनुवाद] प्रदूषण निगरानी उपकरण, [हिन्दी] से जोड़ेंगे। यह नई टेक्नोलॉजी है, ये 11 यंत्र अलग-अलग टाईप के अभी आए हैं, लोग चूज़ कर सकते हैं, तो ये यंत्र लगा कर जहां से एफ्युलेंट बाहर निकलता है, वहां लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी जब जाते हैं, उस दिन एकदम साफ पानी बहता है। जब वे वापस जाते हैं तो फिर गंदा पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह न हो इसलिए उस टेक्नोलॉजी से 24 घंटे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में दोनों जगह दिखेगा और अगर पांच मिनट भी उसका पॉल्यूशन ज्यादा हुआ तो एस.एम.एस. जाएगा और 15 मिनट ज्यादा होगा तो उस पर लीगल एक्शन शुरू होगा। टेक्नोलॉजी के आधार पर भी क्रप्शन को खत्म कर सकते हैं। यह जो फजिंग था, उसको भी समाप्त कर सकते हैं, यह मैकेनिज्म हम ला रहे हैं। इरिगेशन के बारे में जो पूछा, वह एकदम सही है। मैं तेलंगाना में गया था तो कृष्णा-भीमावरम् प्रोजेक्ट है, उसमें यह हुआ कि प्रोजेक्ट तैयार है, इरिगेशन डैम तैयार है, आदिवासियों को पानी मिलना है, पानी है, सब कुछ है, कैनाल रेडी है, लेकिन पांच साल से पड़ा है, उपयोग में हो रहा है। एक कैनाल बनाने में एक जंगल की जमीन जा रही थी, तो परमीशन लेने के पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया, वाइलेशन हो गया। अब किसी अधिकारी पर क्रिमिनल जिम्मेदारी डालनी है, अधिकारी खुद थोड़े ही क्रिमिनल जिम्मेदारी लेते हैं, वह फाइल घूम रही है, लोगों पर क्राइम हो रहा है, हमने इसको बदला है, हमने परमीशन दी है। इस तरह के वायलेशन का कोई अर्थ नहीं होता है।

दूसरा, एक रिवर रेग्युलेटरी मैनेजमेंट जोन यानी रिवर रेग्युलेशंस भी कुछ कर रहे हैं कि किनारे पर क्या हो और क्या न हो। टाइगर का जो है ओडिशा का, उसके संबंध में एक क्वेश्चन राज्य सभा में भी है, हम उसका डिटेल उत्तर परसों दे रहे हैं, लेकिन उसमें कैमरा ट्रैप में और जो तीन प्रकार से उसकी काउंटिंग चलती है, वह काउंटिंग सारे देश में ठीक हुई, लेकिन एक जंगल में जहाँ बाघ ज्यादा है, वहाँ फॉल्ट समझ में भी आया और

उसके करेक्शन के लिए ऑलरेडी सरकार को बताया है। वहाँ के अधिकारी वह काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आते ही वह एजेंडा जोड़ा जाएगा।

टेक्नॉलाजी के संबंध में मैंने कहा। संजय गाँधी पार्क और जैतापुर का ईश्यू है, वह कोई नया प्रपोजल नहीं है, यह इनक्रोचमेंट है, यह एक बड़ा ईश्यू है। देश में लगभग तीन लाख हेक्टेअर वन जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और यह अतिक्रमण बढ़ रहा है। यह नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने बहुत कुछ सोचा है और वह आप सबके सहयोग से करेंगे।

काजीरंगा के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा, पिछले साल 22 डेथ्स हुई हैं, लेकिन हमारे पास संख्या भी तीन हजार है। वहाँ 20 राइनो का पोचिंग हुआ, लेकिन 22 पोचर्स को भी मार गिराया गया है। बंदूकों का उपयोग करके पोचर्स को मार भी गिराया है तो सख्त एक्शन भी चल रहा है, यह भी हमें समझना चाहिए। जो मनरो आइलैंड के बारे में आपने कहा, सुंदरवन के बारे में भी चर्चा में कहा, इन आइलैंड्स को बचाने के लिए हम जरूर अलग से काम कर रहे हैं। मेरी वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात भी हुई है। सुंदरवन के लिए भारत और बांग्लादेश, दोनों को मिलकर कुछ काम करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमारी चर्चा चल रही है। सारे विषयों का मैंने जवाब दिया है, जो बचे हैं, उनका जवाब मिलेगा।...(व्यवधान) अंडमान के बारे में मैंने कहा है। अंडमान में पॉम का ट्री लगाने में मुझे नहीं लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई मुद्दा है।...(व्यवधान) अगर है तो आप जरूर प्रपोजल भेजिए, आप आइए, हम चाय पिएंगे और आपको सोल्यूशन भी देंगे।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सदस्यों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग के लिए कई कटौती प्रस्ताव पेश किए गए हैं। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए एक साथ रखूंगी।

यदि आप सहमत हैं, तो मैं उन्हें अलग रखूंगी।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: हाँ, महोदया मैं मेरा कटौती प्रस्ताव नंबर. .1 दबा रहा हूँ ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 1 को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत किया गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा पेश प्रस्ताव संख्या 8 से 13 को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा पेश प्रस्ताव संख्या 14 को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत किया गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं अन्य सभी कट प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए रखूंगी, जिन्हें एक साथ पेश किया गया है।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि आदेश पत्र के चौथे कॉलम में दर्शाई गई राजस्व खाते और पूंजी खाते की राशियों से अधिक न होने वाली संबंधित राशियां, भारत के समेकित कोष में से राष्ट्रपति को प्रदान की जाए, ताकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32 के विरुद्ध दूसरे कॉलम में दर्ज मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के क्रम में आने वाले प्रभारों का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशियों को पूरा किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पारित की जाती है।

सायं 06.46 बजे**अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

माननीय अध्यक्ष : सभा के स्थगन से पहले, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि जैसा कि सहमति बनी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर कल विचार किया जाएगा और शाम 5.30 बजे गिलोटिन का आयोजन किया जाएगा।

वित्त विधेयक, 2015 पर अब 29 अप्रैल, 2015 के बजाय 30 अप्रैल, 2015 को चर्चा की जाएगी।

अब, सभा को कल, 29 अप्रैल, 2015 को सुबह 11.00 बजे फिर से बैठक में स्थगित कर दिया गया है।

सायं 06.47 बजे

इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही बुधवार, 29 अप्रैल, 2015 / वैशाख 9, 1937 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/lb>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
